

PIB संकलन

सितंबर 2026

चार साप्ताहिक संस्करण • 29 अगस्त – 25 सितंबर 2026
133+ समाचार

नीतियाँ.
कार्यक्रम.
प्रगति.
एक मज़बूत
भारत की ओर.



शासन और
सामाजिक कल्याण



अर्थव्यवस्था, उद्योग
और रोजगार



अवसंरचना
और संपर्क



पर्यावरण, जल
और कृषि



विज्ञान, प्रौद्योगिकी
और नवाचार



रक्षा और सुरक्षा



अंतराष्ट्रीय संबंध
और वैश्विक सहयोग



इस संकलन में

सप्ताह 1	29 अगस्त - 4 सितंबर 2026 • 37 समाचार	3
सप्ताह 2	5 - 11 सितंबर 2026 • 34 समाचार.....	77
सप्ताह 3	12 - 18 सितंबर 2026 • 28 समाचार.....	144
सप्ताह 4	19 - 25 सितंबर 2026 • 34 समाचार.....	198

हर सप्ताह अपने परिचय पृष्ठ और विषय-सूची से शुरू होता है। किसी भी पंक्ति पर क्लिक करके सीधे उस पृष्ठ पर जाएँ।



SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

SITOK IAS • PIB साप्ताहिक संकलन

अब, एक नया सप्ताह

सप्ताह 1

29 अगस्त - 4 सितंबर 2026

37 PIB समाचार • सम्माननीय उल्लेख और अभ्यास प्रश्न

सप्ताह 1 / 4

29 अगस्त - 4 सितंबर 2026

01	'RAKSHA' रक्षा कूटनीति दस्तावेज़ – भारत का 10-वर्षीय रणनीतिक रोडमैप.....	6
02	भारत-बेल्जियम रक्षा द्विपक्षीय – सह-विकास और सह-उत्पादन.....	7
03	16वाँ एयरो इंडिया 2027 घोषित – बेंगलुरु, 8-12 फरवरी.....	8
04	LOKAYAN 2026 – INS सुदर्शिनी बार्सिलोना पहुँची.....	10
05	प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान राजकीय यात्रा – संयुक्त बयान, परिणाम + UPI उज़्बेकिस्तान में ..	11
06	PM SCO शिखर सम्मेलन, बिश्केक में – रूस, किर्गिज़, आर्मेनिया, ईरान के साथ द्विपक्षीय.....	13
07	भारत-चिली CEPA वार्ता आगे बढ़ी.....	14
08	भारत-बेल्जियम संयुक्त बयान – रणनीतिक साझेदारी परिणाम	16
09	भारत Q1 FY2026-27 GDP – 7.8% वृद्धि.....	17
10	भारत की साख रेटिंग 'A-' तक उन्नत – जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	19
11	GIFT IFSC – \$52.8 अरब FCNR(B) जुटाया; अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग केंद्र.....	20
12	NLMC – RINL की 459 भूमि पार्सल की ई-नीलामी, विशाखापट्टनम	22
13	GSLV-F17 ने EOS-05 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया	23
14	C-DOT ने संचार सुरक्षा के लिए 14 स्वदेशी क्वांटम उत्पाद अनावरण किए	25
15	ताप-से-विद्युत रूपांतरण की सदी-पुरानी सीमा पार – अति-संवेदनशील तापमान संवेदन.....	26
16	विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम 2026 – 'एक राष्ट्र, एक समय'	28
17	CSIR-CRRI का 60% RAP प्रौद्योगिकी NH-716 पर – पुनर्नवीनीकृत डामर फुटपाथ का मील का पत्थर	29
18	BIO-NIVESH लॉन्च – जैव-प्रौद्योगिकी निवेश और विस्तार के लिए.....	31
19	लघु आणविक स्विच – स्व-संचालित स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रकृति-प्रेरित जैव-सामग्री.....	32
20	शून्य-उत्सर्जन शिपिंग गलियारे – बंदरगाह हरित ईंधन तैयारी में तेजी लाएं	34
21	एजेंटिक AI कौशल – NIELIT और Intel India राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च.....	35
22	स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 2026 – 5वाँ संस्करण, महासागर संरक्षण आंदोलन	37
23	बाघ परिदृश्य कार्यशाला – संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी पर्यटन	38
24	गृह सचिव ने हिमालयी राज्यों की GLOF और हिमस्खलन तैयारी की समीक्षा की	40
25	भारत-जर्मन पर्यावरण फोरम – ज्ञान, समाधान, संस्थागत क्षमता.....	41
26	संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा शिक्षा – UGC ने NCAHP के तहत 33 नई डिग्री अधिसूचित की	43
27	मिशन रंगीन मछली 2031 – सजावटी मत्स्य पालन के लिए रणनीतिक कार्ययोजना.....	44
28	PM-JANMAN समीक्षा + DA-JGUA – जनजातीय विकास पहल.....	46
29	SUMAN रोडमैप 2030 – मातृ और नवजात देखभाल में तेजी	47
30	नागरिक विमानन – अहमदाबाद से हब एंड स्पोक अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन.....	49
31	पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना + प्रति बूंद अधिक फसल	50
32	पृष्ठभूमि: भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र	52
33	पृष्ठभूमि: साइबर-भौतिक प्रणालियाँ	53
34	पृष्ठभूमि: भूतापीय ऊर्जा.....	55
35	पृष्ठभूमि: सहकारी क्षेत्र में विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना	56

36	पृष्ठभूमि: निर्यात केंद्र के रूप में जिले	58
37	पृष्ठभूमि: Q1 FY2026-27 GDP अनुमान को समझना	60
सम्माननीय उल्लेख		62
अभ्यास प्रश्न		68
10 Prelims प्रश्न – UPSC शैली		68
2 मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं आदर्श उत्तर		72
Prelims उत्तर एवं व्याख्या		74



SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

'RAKSHA' रक्षा कूटनीति दस्तावेज़ – भारत का 10-वर्षीय रणनीतिक रोडमैप

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'RAKSHA' का अनावरण किया – भारत का पहला औपचारिक रक्षा कूटनीति दस्तावेज़ – जो अगले दशक में वैश्विक रक्षा साझेदारियों के लिए एक रणनीतिक दृष्टि रखता है। यह एक ऐतिहासिक कदम है: भारत ने इससे पहले कभी अपनी रक्षा जुड़ाव की विचारधारा को एक प्रकाशित दस्तावेज़ में नहीं समेटा था। RAKSHA क्या कहता है? रक्षा निर्यात, रक्षा औद्योगिक साझेदारी, सैन्य-से-सैन्य सहयोग, और साझेदार देशों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग का ढाँचा। यह भारत के हथियार आयातक से रक्षा साझेदार बनने के बदलाव को दर्शाता है – हथियार आपूर्तिकर्ताओं के साथ लेन-देन के रिश्ते से संरचनात्मक, सह-विकास आधारित रक्षा संबंधों की ओर।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
RAKSHA दस्तावेज़	भारत का पहला औपचारिक रक्षा कूटनीति ढाँचा; 10-वर्षीय दृष्टि; रक्षा निर्यात, सह-विकास, सैन्य-से-सैन्य सहयोग, प्रौद्योगिकी साझेदारी; सितंबर 2026 में रक्षा मंत्री द्वारा जारी
रक्षा कूटनीति	रक्षा और सैन्य उपकरणों से विदेश नीति आगे बढ़ाना; संयुक्त अभ्यास, हथियार निर्यात, अड्डा पहुँच, सैन्य प्रशिक्षण शामिल; भारत का रक्षा निर्यात = ₹23,622 करोड़ (FY2024-25), \$5 अरब लक्ष्य
आयातक से साझेदार तक	भारत ऐतिहासिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक; RAKSHA संकेत देता है – खरीदने से सह-विकास की ओर; 'मेक इन इंडिया' रक्षा, आत्मनिर्भर भारत से संरेखित
सह-विकास / सह-उत्पादन	दो देशों के बीच संयुक्त डिज़ाइन और निर्माण; भारत-फ्रांस (MMRCA 2.0), भारत-USA (GE F414 इंजन ToT), भारत-इज़राइल (मिसाइल प्रणाली); RAKSHA इसे भारत का पसंदीदा जुड़ाव मॉडल बनाता है

DPSU + निजी क्षेत्र	रक्षा सार्वजनिक उपक्रम (HAL, BEL, BDL, BEML) + निजी क्षेत्र (टाटा, L&T, भारत फोर्ज); RAKSHA दोनों को अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदारी के वाहन के रूप में देखता है
रणनीतिक स्वायत्तता	RAKSHA स्पष्ट रूप से गुट-निरपेक्ष – USA, रूस, फ्रांस, इज़राइल, UAE सभी के साथ साझेदार; बहु-संरेखण भारत की रक्षा साझेदारी दर्शन को मजबूत करता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- UPSC कोण: RAKSHA आत्मनिर्भर भारत रक्षा का सीधा परिणाम है – DPP 2020, DPEPP 2020, \$5 अरब निर्यात लक्ष्य, रक्षा गलियारा नीति, और DRDO ToT (पिछले सप्ताह) को एक रणनीतिक दृष्टि दस्तावेज़ में जोड़ता है
- Prelims: भारत का रक्षा निर्यात लक्ष्य = 2028-29 तक \$5 अरब; RAKSHA = पहला औपचारिक रक्षा कूटनीति दस्तावेज़; सितंबर 2026 में जारी
- Mains GS2/GS3: भारत का 'रणनीतिक खरीदार' से 'रक्षा साझेदार' में बदलाव – रणनीतिक स्वायत्तता, मेक इन इंडिया, प्रमुख साझेदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव

भारत-बेल्जियम रक्षा द्विपक्षीय – सह-विकास और सह-उत्पादन

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों की मुख्य माँग एक ही थी: सरल खरीद-बिक्री के बजाय गहरा रक्षा औद्योगिक सहयोग – विशेष रूप से सह-विकास और सह-उत्पादन। बेल्जियम आमतौर पर भारत के रक्षा विमर्श में प्रमुख नहीं होता, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है: FN Herstal (विश्व प्रसिद्ध छोटे हथियार निर्माता – SCAR, Minimi, MAG), Safran Belgium (वायुयान इंजन घटक), John Cockerill Defence (बख्तरबंद वाहन)। बेल्जियम EU का सदस्य और NATO सहयोगी भी है – भारत के लिए बेल्जियम के साथ रक्षा सहयोग यूरोपीय रक्षा औद्योगिक नेटवर्क और मानकों तक पहुँच देता है। संयुक्त बयान ने उसी भाषा में बात की जो RAKSHA दस्तावेज़ में है – व्यवहार में RAKSHA की दृष्टि का पहला बड़ा उदाहरण।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
बेल्जियम का रक्षा उद्योग	FN Herstal (SCAR राइफल, Minimi, MAG – भारतीय विशेष बलों में प्रयुक्त); Safran Belgium (वायुयान घटक); John Cockerill Defence (बख्तरबंद वाहन, बुर्ज); विशिष्ट लेकिन उच्च गुणवत्ता
NATO सदस्यता का महत्व	बेल्जियम = NATO संस्थापक सदस्य; NATO-मानक अंतर-संचालनीयता; बेल्जियम फर्मों के साथ सह-उत्पादन = NATO रक्षा औद्योगिक मानकों से अंतर्निहित संरक्षण
EU रक्षा औद्योगिक आधार	EU का यूरोपीय रक्षा कोष (EDF); यूरोपीय रक्षा एजेंसी (EDA); बेल्जियम दोनों में सक्रिय; भारत-बेल्जियम सह-उत्पादन EU रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुँच दे सकता है
भारत का यूरोपीय रक्षा विविधीकरण	प्राथमिक यूरोपीय साझेदार: फ्रांस (Rafale, पनडुब्बी), इज़राइल (मिसाइल, ड्रोन), रूस (ऐतिहासिक); बेल्जियम एक नया नोड जोड़ता है; एकल-स्रोत निर्भरता से बचाव
रक्षा गलियारे	भारत के दो समर्पित रक्षा औद्योगिक गलियारे: UP (लखनऊ-आगरा-अलीगढ़) और तमिलनाडु (चेन्नई-कोयंबटूर); बेल्जियम OEM यहाँ विनिर्माण स्थापित कर सकते हैं

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय = भारत का भूराजनीतिक ब्लॉक में रक्षा औद्योगिक साझेदारी बनाने का प्रयास; बेल्जियम NATO/EU का केंद्र; व्यवहार में बहु-संरक्षण
- GS3 रक्षा: सह-विकास बनाम ToT बनाम सरल खरीद – क्रम समझें; सह-विकास = सबसे गहरा प्रौद्योगिकी एकीकरण; RAKSHA इसे भारत की घोषित प्राथमिकता बनाता है

16वाँ एयरो इंडिया 2027 घोषित – बेंगलुरु, 8-12 फरवरी

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय

PIB तिथि: 1 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

एयरो इंडिया का 16वाँ संस्करण येलहंका वायु सेना स्टेशन, बेंगलुरु में 8-12 फरवरी 2027 को आयोजित होगा। एयरो इंडिया केवल एक वायु प्रदर्शनी नहीं है – यह भारत का प्राथमिक मंच है: रक्षा निर्यात प्रोत्साहन (भारतीय रक्षा कंपनियाँ विदेशी खरीदारों को क्षमता दिखाती हैं); रक्षा औद्योगिक साझेदारी (भारतीय और विदेशी एयरोस्पेस फर्मों के बीच समझौता ज्ञापन); कूटनीतिक संकेत (कौन से देश अपना वरिष्ठतम प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं, यह द्विपक्षीय रक्षा गर्मजोशी का संकेत है); और मेक इन इंडिया प्रदर्शन (HAL, DRDO, निजी क्षेत्र स्वदेशी प्रणालियाँ दिखाते हैं)। एयरो इंडिया 2025 (15वाँ संस्करण) में 100+ देश, 800+ प्रदर्शक, और ₹1 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापन हुए।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
एयरो इंडिया	द्विवार्षिक एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी; येलहंका वायु सेना स्टेशन, बेंगलुरु; DRDO, HAL, निजी क्षेत्र, विदेशी OEM; रक्षा निर्यात मंच; एशिया की सबसे बड़ी वायु प्रदर्शनी
येलहंका वायु सेना स्टेशन	IAF अड्डा, बेंगलुरु; 1996 से एयरो इंडिया का स्थायी स्थान; HAL मुख्यालय के निकट – भारत के एयरोस्पेस विनिर्माण केंद्र के साथ प्रतीकात्मक सह-स्थान
एयरो इंडिया 2025 के परिणाम	15वाँ संस्करण; 100+ देश, 800+ प्रदर्शक; ₹1 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापन; iDEX चुनौतियाँ; रक्षा निर्यात सौदे; DPEPP 2020 के बाद पहला बड़ा प्रदर्शन
DPEPP 2020	रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020; 2028-29 तक \$5 अरब निर्यात लक्ष्य; एयरो इंडिया = DPEPP के निर्यात प्रोत्साहन अध्याय का प्राथमिक कार्यान्वयन मंच
iDEX – रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार	एयरो इंडिया में स्टार्टअप चुनौतियाँ; MoD रक्षा तकनीक स्टार्टअप को समर्थन देता है; iDEX विजेताओं को वित्त पोषण + संभावित खरीद; एयरो इंडिया = स्टार्टअप-MoD इंटरफेस मंच

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- Prelims: एयरो इंडिया = द्विवार्षिक; येलहंका, बेंगलुरु; 16वाँ संस्करण = फरवरी 2027; एशिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस प्रदर्शनी; रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित
- GS3: एयरो इंडिया DPEPP 2020, iDEX, मेक इन इंडिया रक्षा का कार्यान्वयन वाहन – नीति को व्यवहार से जोड़ता है

LOKAYAN 2026 – INS सुदर्शिनी बार्सिलोना पहुँची

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय / भारतीय नौसेना

PIB तिथि: 1 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारतीय नौसेना का नौपरिवहन प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शिनी – LOKAYAN 2026 के तहत स्पेन के बार्सिलोना बंदरगाह पर पहुँचा। LOKAYAN (संस्कृत में 'लोक' = संसार, 'यान' = यात्रा) भारतीय नौसेना की वार्षिक/आवधिक लंबी दूरी की नौपरिवहन प्रशिक्षण और सद्भावना यात्रा है। INS सुदर्शिनी एक तीन-मस्तूल बाक्वर्टीन जहाज है (2012 में कमीशन; कोच्चि आधारित) जो अधिकारी प्रशिक्षुओं को समुद्री प्रशिक्षण देता है। यह तैनाती कई उद्देश्य पूरी करती है: नौसैनिक कूटनीति (बंदरगाह यात्राएं = कूटनीतिक जुड़ाव), समुद्र में अधिकारी प्रशिक्षण (वास्तविक नेविगेशन, नौपरिवहन, महासागर पारगमन), और समुद्री विरासत प्रक्षेपण (पाल जहाज युद्धपोत की तुलना में अलग किस्म की नरम शक्ति लेकर आते हैं)। बार्सिलोना = स्पेन का सबसे बड़ा बंदरगाह और भूमध्यसागरीय केंद्र।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
INS सुदर्शिनी	भारतीय नौसेना का नौपरिवहन प्रशिक्षण जहाज; तीन-मस्तूल बाक्वर्टीन; 2012 में कमीशन; कोच्चि आधारित; अधिकारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण; LOKAYAN 2026 में तैनात
LOKAYAN 2026	भारतीय नौसेना की सद्भावना और प्रशिक्षण तैनाती; बहु-बंदरगाह विदेशी यात्रा; 'लोक' (संसार) + 'यान' (यात्रा); पाल जहाज के माध्यम से नौसैनिक कूटनीति
बाक्वर्टीन	3 या अधिक मस्तूल वाला पाल जहाज; अगला मस्तूल पूरी तरह वर्गाकार-रिग, शेष अगले-पिछले रिग; महासागर पारगमन के लिए संकर रिग; INS सुदर्शिनी = भारत का एकमात्र बाक्वर्टीन

नौसैनिक कूटनीति	पाल जहाज बंदरगाह यात्राओं के माध्यम से नरम शक्ति; युद्धपोत की तरह लड़ाकू संकेत नहीं; विरासत, परंपरा, युवा प्रशिक्षण – कूटनीतिक प्रभाव के लिए प्रभावी माध्यम
बार्सिलोना / भूमध्यसागरीय महत्व	स्पेन = EU, NATO सदस्य; बार्सिलोना = भूमध्यसागरीय शिपिंग केंद्र; भारत की उपस्थिति = हिंद महासागर से परे भूमध्यसागरीय जुड़ाव का विस्तार

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- Prelims: INS सुदर्शिनी = नौपरिवहन प्रशिक्षण जहाज, बाक्वैटीन, 2012 में कमीशन; LOKAYAN = भारतीय नौसेना की नौपरिवहन प्रशिक्षण/सद्भावना तैनाती
- GS2/GS3: पाल जहाजों के माध्यम से नौसैनिक कूटनीति और नरम शक्ति; भारत का समुद्री जुड़ाव भूमध्यसागर तक विस्तार

प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान राजकीय यात्रा – संयुक्त बयान, परिणाम + UPI उज़्बेकिस्तान में

मंत्रालय: प्रधानमंत्री कार्यालय / विदेश मंत्रालय

PIB तिथि: 30 अगस्त 2026

सरल भाषा में समझें

प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान राजकीय यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले। सबसे चर्चित सम्मान: PM को उज़्बेकिस्तान का विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान 'ओली दाराजली दोस्तलिक' आदेश (मित्रता का सर्वोच्च क्रम) मिला। भारत-उज़्बेकिस्तान संबंध 2011 की रणनीतिक साझेदारी से 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक गहरे हुए हैं। मुख्य परिणाम: दवा (भारत उज़्बेकिस्तान को \$300+ मिलियन जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है), IT, वस्त्र, कृषि में समझौते; संपर्क – अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और चाबहार बंदरगाह; और एक ऐतिहासिक वित्त-प्रौद्योगिकी विकास – NPCI International और उज़्बेकिस्तान के NIPC ने UZQR (उज़्बेक QR भुगतान मानक) के माध्यम से उज़्बेकिस्तान में UPI भुगतान सक्षम करने की साझेदारी की।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
-----------	---------

'ओली दाराजली दोस्तलिक' आदेश	उज़्बेकिस्तान का विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च राज्य सम्मान; 'दोस्तलिक' = उज़्बेक में मित्रता; अगस्त 2026 की राजकीय यात्रा के दौरान PM मोदी को प्रदान
भारत-उज़्बेकिस्तान संबंध	रणनीतिक साझेदारी (2011) → व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2022); मध्य एशिया में सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी (~15,000); भारतीय दवा, IT, वस्त्र निर्यात; ताशकंद = महत्वपूर्ण भारत संबंध (ताशकंद घोषणा 1966, लाल बहादुर शास्त्री)
INSTC – अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा	बहुमार्गीय मार्ग: भारत → ईरान (चाबहार) → अज़रबैजान → रूस → मध्य एशिया / यूरोप; 7,200 किमी; INSTC के माध्यम से भारत-उज़्बेकिस्तान संपर्क महत्वपूर्ण
चाबहार बंदरगाह	ईरान का गहरे पानी का बंदरगाह; भारत ने शहीद बेहेशती टर्मिनल विकसित किया; भारत-ईरान-अफगानिस्तान संपर्क; मध्य एशिया पहुँच; US प्रतिबंध छूट; INSTC का मुख्य नोड
UPI उज़्बेकिस्तान में – UZQR एकीकरण	NPCI International + उज़्बेकिस्तान का NIPC; UZQR (उज़्बेक QR मानक) के माध्यम से UPI भुगतान; उज़्बेकिस्तान 18वें+ देश के रूप में UPI एकीकरण में शामिल
SCO संदर्भ	उज़्बेकिस्तान = 2001 से SCO सदस्य; भारत = 2017 से पूर्ण SCO सदस्य; ताशकंद घोषणा 1966 – भारत-पाकिस्तान 1965 युद्ध के बाद शांति समझौता; सोवियत संघ द्वारा मध्यस्थता; PM शास्त्री उसी रात ताशकंद में निधन हुए

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: भारत-उज़्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी; INSTC; चाबहार बंदरगाह; भारत की मध्य एशिया Connect नीति; SCO सदस्यता
- GS3 अर्थव्यवस्था: उज़्बेकिस्तान में UPI = भारत का डिजिटल भुगतान निर्यात; NPCI International का वैश्विक विस्तार; वित्त-प्रौद्योगिकी कूटनीति

- **Prelims:** 'ओली दाराजली दोस्तलिक' = विदेशी नेताओं को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान; UZQR = उज़्बेक QR भुगतान मानक; ताशकंद घोषणा 1966
- **Mains:** भारत की मध्य एशिया संलग्नता – क्यों महत्वपूर्ण, भारत की बाधाएं (कोई सीधी भूमि सीमा नहीं), भारत के समाधान (चाबहार, हवाई गलियारे, INSTC)

PM SCO शिखर सम्मेलन, बिश्केक में – रूस, किर्गिज़, आर्मेनिया, ईरान के साथ द्विपक्षीय

मंत्रालय: प्रधानमंत्री कार्यालय / विदेश मंत्रालय

PIB तिथि: 1-2 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिज़ गणराज्य के बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लिया और हाशिये पर राष्ट्रपति पुतिन (रूस), किर्गिज़ राष्ट्रपति, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। SCO शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क और आतंकवाद-रोधी पर ध्यान केंद्रित था। भारत की भागीदारी हमेशा ध्यान से देखी जाती है: भारत SCO का उपयोग चीन-पाकिस्तान धुरी के ढाँचे के बाहर रूस और मध्य एशिया के साथ जुड़ने के लिए करता है। मुख्य द्विपक्षीय: रूस – S-400, Su-30MKI पुर्जे, तेल खरीद, Kudankulam विस्तार; ईरान – चाबहार बंदरगाह प्रगति, रुपये में व्यापार; आर्मेनिया – भारत ने पिनाका MBRL बेचा (भारत का रूस-निर्भरता से परे रक्षा निर्यात का उभरता यूरोपीय बाजार)।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
SCO – शंघाई सहयोग संगठन	यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा संगठन; 2001 में स्थापित; 9 पूर्ण सदस्य: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कज़ाखस्तान, किर्गिज़, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस; भारत 2017 से पूर्ण सदस्य
बिश्केक महत्व	किर्गिज़ गणराज्य की राजधानी; SCO मुख्यालय यहाँ नहीं (सचिवालय बीजिंग में); पिछले SCO शिखर: समरकंद 2022, नई दिल्ली 2023 (भारत SCO अध्यक्षता), अस्ताना 2024, बिश्केक 2026

भारत-रूस द्विपक्षीय	विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी; S-400 Triumf दिया गया (US CAATSA प्रतिबंध चिंता); Kudankulam परमाणु संयंत्र विस्तार (इकाई 5-6); रुपये-रुबल व्यापार
भारत-ईरान (हाशिये पर)	चाबहार बंदरगाह प्रगति; रुपये में भारत-ईरान व्यापार; US प्रतिबंध – भारत को चाबहार के लिए छूट; ईरान 2023 से SCO पूर्ण सदस्य
भारत-आर्मेनिया द्विपक्षीय	आर्मेनिया = भारत का उभरता रक्षा निर्यात साझेदार; भारत ने पिनाका MBRL बेचा; आर्मेनिया 2020 नागोर्नो-कराबाख के बाद रूस-निर्भरता से दूर; NATO आकांक्षी; GS2 कोण: छोटे राज्य का बचाव, भारत की रक्षा निर्यात रणनीति
RATS – SCO आतंकवाद-रोधी संरचना	क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना; ताशकंद; भारत भाग लेता है; SCO का प्राथमिक आतंकवाद-रोधी तंत्र; भारत सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा यहाँ उठाता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: SCO का भारत के लिए महत्व – बहु-संरेखण, रूस जुड़ाव, मध्य एशिया संपर्क, आतंकवाद-रोधी; SCO में भारत की चुनौतियाँ (चीन-पाकिस्तान धुरी)
- Prelims: SCO सदस्य (9 पूर्ण + पर्यवेक्षक + वार्ता भागीदार); भारत 2017 से; सचिवालय बीजिंग में; RATS ताशकंद में; 26वाँ शिखर = बिश्केक 2026
- Mains: SCO में भारत का दृष्टिकोण – Quad सदस्यता के साथ SCO जुड़ाव का संतुलन; यूक्रेन-उत्तर संदर्भ में रूस के साथ द्विपक्षीय; चाबहार रणनीतिक बुनियादी ढाँचे के रूप में
- आर्मेनिया लिंक: भारत ने आर्मेनिया को पिनाका MBRL बेचा – UPSC ने इसके बारे में पूछा है; आर्मेनिया = NATO आकांक्षी, भारत का उभरता यूरोपीय रक्षा निर्यात बाजार

भारत-चिली CEPA वार्ता आगे बढ़ी

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

PIB तिथि: 30 अगस्त 2026

सरल भाषा में समझें

भारत और चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की वार्ता में आगे बढ़े – वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने चिली की उप-मंत्री पाउला एस्टेवेज वेनस्टीन से मुलाकात की। चिली लैटिन अमेरिका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (ब्राजील के बाद) – द्विपक्षीय व्यापार लगभग \$3 अरब। चिली क्यों महत्वपूर्ण है? ताँबा – चिली के पास दुनिया के सबसे बड़े ताँबे के भंडार (~27% वैश्विक) और वह दुनिया का सबसे बड़ा ताँबा उत्पादक है; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण और EV विनिर्माण के लिए ताँबा आयात करता है; चीन चिली का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और भारत एक वैकल्पिक व्यापार संबंध विकसित करने की कोशिश कर रहा है। लिथियम – चिली के पास दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार (अटाकामा मरुस्थल के नमक के मैदान) हैं; EV बैटरी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण; भारत का क्रिटिकल मिनरल्स मिशन स्पष्ट रूप से लैटिन अमेरिका को लिथियम स्रोत के रूप में लक्षित करता है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
CEPA – व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता	वस्तु, सेवाएं, निवेश, बौद्धिक संपदा को कवर करने वाला व्यापार समझौता – FTA से व्यापक; भारत के CEPA: UAE, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस, जापान, दक्षिण कोरिया; चिली CEPA = दक्षिण अमेरिका में पहला
चिली की खनिज संपदा	दुनिया के सबसे बड़े ताँबे के भंडार (~27% वैश्विक); दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार (अटाकामा; ~42% वैश्विक); कोबाल्ट, चाँदी, मोलिब्डेनम भी; सभी भारत के EV और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिज
लिथियम त्रिभुज	चिली + अर्जेंटीना + बोलीविया = लिथियम त्रिभुज; ~65% विश्व लिथियम भंडार; चिली का अटाकामा = सर्वोच्च सांद्रता; भारत का क्रिटिकल मिनरल्स मिशन इस क्षेत्र को आपूर्ति विविधीकरण के लिए लक्षित करता है
भारत-चिली द्विपक्षीय व्यापार	~\$3 अरब; भारत निर्यात: दवाएं, मशीनरी, जैव रसायन; चिली निर्यात: ताँबा, मोलिब्डेनम, आयोडीन, मछली का आटा; CEPA इसे दोगुना कर सकता है; चिली प्रशांत लैटिन अमेरिका तक तरजीही पहुँच देता है

प्रशांत गठबंधन

चिली, पेरू, कोलंबिया, मेक्सिको = प्रशांत गठबंधन; उनके बीच मुक्त व्यापार; चिली के साथ CEPA = प्रशांत गठबंधन अर्थव्यवस्थाओं तक प्राथमिकता पहुँच मार्ग

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: भारत की लैटिन अमेरिका संलग्नता; भारत की महत्वपूर्ण खनिज कूटनीति; CEPA व्यापार वास्तुकला उपकरण के रूप में
- GS3 अर्थव्यवस्था: ताँबा और लिथियम = भारत के EV परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिज; चिली CEPA = आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा; दक्षिण अमेरिका में पहला CEPA
- Prelims: लिथियम त्रिभुज = चिली + अर्जेंटीना + बोलीविया; चिली = दुनिया का सबसे बड़ा ताँबा AND लिथियम उत्पादक; भारत-चिली द्विपक्षीय = ~\$3 अरब

भारत-बेल्जियम संयुक्त बयान – रणनीतिक साझेदारी परिणाम

मंत्रालय: विदेश मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत और बेल्जियम ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें सहयोग के कई क्षेत्र शामिल थे। बेल्जियम एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है: यह NATO मुख्यालय (ब्रसेल्स) का घर है, EU संस्थाओं (यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद) का केंद्र है, और एक महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी समुदाय (~60,000+) है। संयुक्त बयान के प्रमुख क्षेत्र: रक्षा औद्योगिक सहयोग (सह-विकास, सह-उत्पादन – RAKSHA दस्तावेज़ से जुड़ा); डिजिटल अर्थव्यवस्था; व्यापार और निवेश (भारत-EU BTIA वार्ता जारी); और शिक्षा और अनुसंधान (KU Leuven, गैट विश्वविद्यालय = बेल्जियम के शोध विश्वविद्यालय)। अंटवर्प = विश्व का हीरा व्यापार केंद्र (~85% कच्चे हीरे यहाँ व्यापार होते हैं – भारत-बेल्जियम हीरा व्यापार महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
-----------	---------

बेल्जियम का रणनीतिक महत्व	NATO मुख्यालय ब्रसेल्स में; EU संस्थागत केंद्र (यूरोपीय आयोग, संसद, परिषद); हीरा व्यापार (अंटवर्प = विश्व हीरा व्यापार केंद्र, ~85% कच्चे हीरे यहाँ; भारत-बेल्जियम हीरा व्यापार महत्वपूर्ण)
भारत-EU BTIA	व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौता; 2022 में दशक के लंबे ठहराव के बाद वार्ता फिर शुरू; बेल्जियम = EU सदस्य = BTIA प्रगति भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय में परिलक्षित
भारत-EU TTC	व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद; जून 2023 में स्थापित; अर्धचालक, AI, स्वच्छ तकनीक, डिजिटल मानकों पर ध्यान; भारत-बेल्जियम = TTC कार्यान्वयन का नोड
अंटवर्प हीरा व्यापार	अंटवर्प = विश्व हीरा व्यापार केंद्र; ~85% कच्चे हीरे यहाँ से गुजरते हैं; भारत विश्व के ~90% हीरे काटता और पॉलिश करता है (सूरत); भारत-बेल्जियम हीरा व्यापार = प्रमुख द्विपक्षीय आर्थिक संबंध
KU Leuven	कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुवेन; बेल्जियम का शीर्ष शोध विश्वविद्यालय; वैश्विक शीर्ष 50 में; जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, AI में मजबूत; भारत-बेल्जियम शैक्षणिक अनुसंधान संबंध

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: भारत-बेल्जियम संयुक्त बयान; बेल्जियम NATO/EU केंद्र के रूप में; भारत-EU BTIA; भारत-EU TTC; यूरोपीय जुड़ाव में बेल्जियम की भूमिका
- Prelims: NATO मुख्यालय = ब्रसेल्स; अंटवर्प = विश्व हीरा व्यापार केंद्र; KU Leuven = बेल्जियम का शीर्ष विश्वविद्यालय; बेल्जियम = EU संस्थापक सदस्य

भारत Q1 FY2026-27 GDP — 7.8% वृद्धि

मंत्रालय: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

PIB तिथि: 31 अगस्त 2026

सरल भाषा में समझें

भारत की GDP Q1 FY2026-27 (अप्रैल-जून 2026) में 7.8% बढ़ी – छह तिमाहियों में सबसे तेज़ विकास। यह FY2025-26 के पूर्ण-वर्ष विकास 6.4% से ऊपर है। 7.8% किसने चलाया? विनिर्माण (GDP का ~16%) ने मजबूत वृद्धि दर्ज की – IIP डेटा (जुलाई 2026 में 7.2% विनिर्माण वृद्धि) के अनुरूप; सेवा क्षेत्र निरंतर मजबूत; सरकारी पूँजी व्यय ऊँचा (₹11.11 लाख करोड़); और शहरी उपभोग में अर्थपूर्ण सुधार। चिंताएं: ग्रामीण उपभोग COVID-पूर्व प्रवृत्ति से नीचे; निजी निवेश को पूरी तरह से पकड़ने की जरूरत; और वैश्विक अनिश्चितता (US ब्याज दर वातावरण, चीन मंदी) निर्यात के लिए बाधाएं पैदा करती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है – चीन ने उसी अवधि में 4.7% वृद्धि दर्ज की।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
GDP गणना पद्धति	GDP = C + I + G + (X-M); उत्पादन पद्धति (GVA + कर - सब्सिडी = GDP) भी; MoSPI अग्रिम, पहले संशोधित, दूसरे संशोधित अनुमान जारी करता है; आधार वर्ष 2011-12
Q1 FY2026-27	अप्रैल-जून 2026; 7.8% वास्तविक GDP वृद्धि; छह तिमाहियों में सबसे तेज़; FY2025-26 पूर्ण वर्ष (6.4%) से ऊपर; चीन ने उसी अवधि में 4.7% वृद्धि दर्ज की; भारत = सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था
GVA – सकल मूल्य वर्धन	GVA = GDP - उत्पाद कर + उत्पाद सब्सिडी; क्षेत्रीय विभाजन: कृषि, उद्योग (विनिर्माण, निर्माण, खनन), सेवाएं; GDP शीर्षक के पीछे की संरचनात्मक कहानी GVA वृद्धि से सामने आती है
पूँजी व्यय धक्का	Union Budget FY2026-27 पूँजी व्यय = ₹11.11 लाख करोड़ (GDP का 3.4%); सरकारी पूँजी व्यय निजी निवेश को प्रेरित करता है; गुणक प्रभाव GDP वृद्धि पर; सड़क, रेल, बंदरगाह प्राथमिक प्राप्तकर्ता
IIP संबंध	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (जुलाई 2026) = 6.7% वृद्धि; विनिर्माण 7.2%; पूँजीगत वस्तुएं 12.3% – Q1 GDP औद्योगिक शक्ति की पुष्टि; IIP मासिक, GDP त्रैमासिक – IIP = अग्रणी संकेतक
निजी उपभोग सुधार	शहरी उपभोग सुधर रहा है (IIP में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं +9.8%); ग्रामीण उपभोग धीमे सुधर रहा है; PMJDY + DBT कल्याण हस्तांतरण

सुनिश्चित कर रहे हैं; FMCG कंपनियाँ ग्रामीण सुधार 'धीरे-धीरे' रिपोर्ट करती हैं

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था: GDP संरचना, चालक, पद्धति; भारत की विकास कहानी; पूँजी व्यय गुणक; निजी निवेश सुधार
- Prelims: Q1 FY2026-27 GDP = 7.8%; आधार वर्ष = 2011-12; MoSPI GDP डेटा जारी करता है; GVA + शुद्ध कर = GDP; भारत = सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था
- Mains: भारत के आर्थिक विकास का विश्लेषण – इसे क्या बनाए रख रहा है, जोखिम क्या हैं, क्या सुधार चाहिए

भारत की साख रेटिंग 'A-' तक उन्नत – जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

PIB तिथि: 2 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (JCR) ने भारत की संप्रभु साख रेटिंग 'BBB+' से 'A-' स्थिर परिदृश्य के साथ उन्नत की – किसी भी प्रमुख साख रेटिंग एजेंसी से पहली बार भारत को 'A' श्रेणी की रेटिंग मिली। यह महत्वपूर्ण है: 'A' श्रेणी का अर्थ है 'वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की मजबूत क्षमता' – 'BBB' जो न्यूनतम निवेश श्रेणी है उससे ऊपर। भारत की लंबे समय से शिकायत रही है कि Moody's, S&P, और Fitch उसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के बावजूद 'BBB' में रखते हैं। JCR का उन्नयन भारत के राजकोषीय समेकन (राजकोषीय घाटा 6.4% FY2020-21 से 4.9% FY2025-26 तक), मजबूत GDP वृद्धि, और बेहतर ऋण गतिशीलता को मान्यता देता है। यह जापानी संस्थागत निवेशकों (GPIF सहित जिसे गोयल की टोक्यो यात्रा में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया) के लिए भी महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
संप्रभु साख रेटिंग	देश की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा का मूल्यांकन; साख रेटिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा निर्धारित; सरकारी बॉन्ड की उधार लागत निर्धारित करता है; FDI और FPI प्रवाह को प्रभावित करता है

JCR – जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	जापान की अग्रणी CRA; जापानी संस्थागत निवेशकों (GPIF, जापानी बैंक, बीमा कंपनियों) के लिए महत्वपूर्ण; 'बिग थ्री' में नहीं (Moody's, Fitch, S&P) लेकिन एशियाई बाजारों में प्रभावशाली
रेटिंग स्केल	AAA (सर्वोच्च) → AA → A → BBB (न्यूनतम निवेश श्रेणी) → BB और नीचे (सट्टा/जंक); भारत JCR द्वारा BBB+ से A- तक उन्नत; Moody's/Fitch/S&P के पास अभी भी BBB- से BBB
'बिग थ्री' CRA आलोचना	Moody's, Fitch, S&P पर भारत को मूल तत्वों के सापेक्ष कम रेट करने का आरोप; India GDP = \$3.7 ट्रिलियन (5वीं सबसे बड़ी), सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था – रेटिंग में पूरी तरह परिलक्षित नहीं
राजकोषीय समेकन पथ	भारत का राजकोषीय घाटा: 6.4% FY2020-21 (COVID शीर्ष) → 5.8% FY2022-23 → 5.1% FY2023-24 → 4.9% FY2025-26 → 4.5% लक्ष्य FY2026-27; विकास त्याग के बिना स्थिर समेकन
उन्नयन के निहितार्थ	संप्रभु बॉन्ड के लिए कम उधारी लागत; जापानी संस्थागत पूंजी (GPIF निवेश चर्चा) के लिए संकेत; भारतीय ऋण में FPI प्रवाह; भारत का 'बिग थ्री' CRA से मामला मजबूत

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था: संप्रभु साख रेटिंग की यांत्रिकी; भारत का राजकोषीय समेकन; भारत की रेटिंग क्यों महत्वपूर्ण; 'बिग थ्री' CRA की भारतीय नीतिनिर्माताओं की आलोचना
- Prelims: JCR ने भारत को A- (किसी भी प्रमुख CRA से पहली 'A' श्रेणी) तक उन्नत; 'बिग थ्री' = Moody's, Fitch, S&P; BBB = न्यूनतम निवेश श्रेणी; स्थिर परिदृश्य

GIFT IFSC – \$52.8 अरब FCNR(B) जुटाया; अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग केंद्र

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय / IFSCA

PIB तिथि: 2 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

GIFT IFSC (गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त तकनीक नगर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) ने RBI की FCNR(B) स्वैप सुविधा के तहत \$52.8 अरब से अधिक, \$11.62 अरब ECB में, और \$11.12 अरब बॉन्ड सूची में जुटाया। GIFT IFSC भारत का पहला और एकमात्र IFSC है – वित्तीय सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जहाँ भारतीय और विदेशी वित्तीय संस्थाएं सुव्यवस्थित नियामक ढाँचे के साथ विदेशी मुद्राओं में लेनदेन कर सकती हैं। FCNR(B) जमाओं का पैमाना उल्लेखनीय है: FCNR(B) = विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा – NRI द्वारा प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर विदेशी मुद्रा सावधि जमा। GIFT IFSC विमान पट्टे (विश्व के \$70 अरब के विश्व विमान पट्टे बाजार का हिस्सा लेने की भारत की कोशिश – 85% वर्तमान में आयरलैंड और सिंगापुर से) और वैकल्पिक निवेश कोषों (AIF) को भी आश्रय देता है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
GIFT IFSC	गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त तकनीक नगर IFSC; गांधीनगर, गुजरात; भारत का पहला IFSC; IFSCA (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण) द्वारा विनियमित; विशेष आर्थिक क्षेत्र
IFSCA	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण; 2020 में स्थापित; GIFT IFSC के लिए एकीकृत नियामक (IFSC गतिविधियों के लिए RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA की जगह); मुख्यालय गांधीनगर
FCNR(B) जमा	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा; NRI द्वारा विदेशी मुद्रा सावधि जमा; प्रतिस्पर्धी ब्याज; RBI की स्वैप सुविधा रुपये में परिवर्तित – घरेलू बैंकिंग प्रणाली के लिए डॉलर तरलता उपकरण
ECB – बाहरी वाणिज्यिक उधारी	विदेशी स्रोतों से भारतीय संस्थाओं द्वारा उधारी; RBI द्वारा विनियमित; GIFT IFSC = ECB के लिए पसंदीदा मार्ग; GIFT IFSC के माध्यम से \$11.62 अरब = महत्वपूर्ण
विमान पट्टा	वैश्विक विमान पट्टा बाजार = ~\$70 अरब; 85% आयरलैंड (शैनन) और सिंगापुर से; भारत हिस्सा चाहता है – GIFT IFSC ने विमान पट्टा व्यवस्था स्थापित की; Air India, IndiGo GIFT के माध्यम से पट्टे लेना शुरू

सिंगापुर/दुबई प्रतिस्पर्धा

GIFT IFSC सिंगापुर (MAS), दुबई (DIFC), लंदन से प्रतिस्पर्धा करता है; फायदे: भारत की \$3.7T अर्थव्यवस्था तक पहुँच, NRI-केंद्रित उत्पाद, कर संधियाँ; नुकसान: नया, अभी तरलता और प्रतिभा पूल बना रहा है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था: GIFT IFSC – संरचना, IFSCA, उत्पाद; FCNR(B) यांत्रिकी; विमान पट्टा; भारत की वित्तीय सेवा महत्वाकांक्षा
- Prelims: GIFT IFSC = गांधीनगर, गुजरात; IFSCA = नियामक; FCNR(B) = NRI द्वारा विदेशी मुद्रा जमा; भारत का पहला IFSC

NLMC – RINL की 459 भूमि पार्सल की ई-नीलामी, विशाखापट्टनम

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय / NLMC

PIB तिथि: 1 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण निगम (NLMC) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) – विजाग स्टील प्लांट (VSP) चलाने वाले इस्पात PSU – की 459 भूमि पार्सल की ई-नीलामी की सुविधा देगा। RINL गंभीर वित्तीय संकट में है: ₹16,000 करोड़ से अधिक संचित घाटा, ₹25,000+ करोड़ का कर्ज, और रणनीतिक विनिवेश के कई विफल प्रयास (कैबिनेट ने 2021 में मंजूरी दी लेकिन खरीदार नहीं मिले)। भूमि मुद्राकरण – RINL के विशाखापट्टनम के आसपास महत्वपूर्ण भूमि जोत हैं – पूर्ण निजीकरण के बिना नकद उत्पन्न करने का प्रयास है। NLMC (2022 में स्थापित) केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSE) और सरकारी विभागों की अधिशेष भूमि मुद्राकरण के लिए केंद्रीय एजेंसी है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
NLMC	राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण निगम; अगस्त 2022 में स्थापित; DIPAM (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) की सहायक; CPSE और सरकारी विभागों की अधिशेष भूमि मुद्राकरण करता है

RINL – राष्ट्रीय इस्पात निगम	विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (विजाग स्टील); भारत का एकमात्र तटीय एकीकृत इस्पात संयंत्र; 1992 में चालू; 7.3 MTPA क्षमता; आंध्र प्रदेश में प्रमुख नियोक्ता; ₹16,000+ करोड़ संचित घाटा
DIPAM	निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग; वित्त मंत्रालय; विनिवेश, PSE संपत्ति मुद्रीकरण प्रबंधन; राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) = ₹6 लाख करोड़ पाइपलाइन 2021-25; NLMC DIPAM के अंतर्गत
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)	₹6 लाख करोड़ संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन (FY2022-25); सड़क, रेल, बिजली पारेषण, गैस पाइपलाइन, हवाई अड्डे, दूरसंचार; भूमि = अलग NLMC ट्रैक; मुद्रीकरण ≠ निजीकरण
भूमि मुद्रीकरण बनाम निजीकरण	भूमि मुद्रीकरण: भूमि बेचना/पट्टे पर देना, संयंत्र बनाए रखना; निजीकरण: पूरी संस्था बेचना; RINL भूमि नीलामी = मुद्रीकरण, इस्पात संयंत्र का विनिवेश नहीं; राजनीतिक रूप से अलग

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था: NLMC, DIPAM, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन; RINL का वित्तीय संकट; राजकोषीय उपकरण के रूप में भूमि मुद्रीकरण; PSU पुनर्गठन
- Prelims: NLMC = राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम; RINL = राष्ट्रीय इस्पात निगम = विजाग स्टील; DIPAM विनिवेश प्रबंधित करता है; NMP = ₹6 लाख करोड़ पाइपलाइन

GSLV-F17 ने EOS-05 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया

मंत्रालय: अंतरिक्ष विभाग / ISRO

PIB तिथि: 4 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

ISRO के भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV-F17) ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा (GTO) में सफलतापूर्वक स्थापित किया। PM मोदी ने ISRO की सराहना की। EOS-05 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है – ISRO की पुनर्नामित EOS श्रृंखला (पहले RISAT, Cartosat, ResourceSat, OceanSat नाम से) का हिस्सा। पृथ्वी

अवलोकन उपग्रह कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं: कृषि (फसल क्षेत्र अनुमान, सूखा निगरानी), आपदा प्रबंधन (बाढ़ मानचित्रण, चक्रवात ट्रैकिंग), शहरी नियोजन, रक्षा निगरानी, और पर्यावरण निगरानी। GSLV-F17 स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (CE-20 इंजन) का उपयोग करता है – वह प्रौद्योगिकी जिसे भारत ने 1990 के दशक में रूस के मना करने के बाद स्वदेशी रूप से विकसित किया (ISRO-Glavkosmos विवाद)।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
GSLV – भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान	भारत का मध्यम-उठान प्रक्षेपण यान; 3 चरण (ठोस + तरल + क्रायोजेनिक); GTO को भार: ~2.5 टन; स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (CE-20 इंजन); GSLV Mk III (अब LVM3) से अलग
EOS शृंखला	ISRO की एकीकृत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शृंखला; पिछले RISAT (SAR इमेजिंग), Cartosat (ऑप्टिकल), ResourceSat, OceanSat को कवर करती है; EOS-04 = SAR, EOS-06 = OceanSat-3, EOS-05 = नवीनतम
क्रायोजेनिक ऊपरी चरण	क्रायोजेनिक प्रणोदक = द्रव हाइड्रोजन + द्रव ऑक्सीजन; उच्चतम दक्षता (Isp ~450s); भारत ने CE-7.5 और CE-20 स्वदेशी रूप से विकसित किए; 1990 के दशक में रूस की प्रौद्योगिकी अस्वीकृति से 15 साल की देरी लेकिन अंततः स्वदेशी विकास
ISRO-Glavkosmos प्रकरण	1992-93: USA ने रूस (Glavkosmos) पर भारत को क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण रद्द करने का दबाव बनाया; ISRO को स्वतंत्र रूप से विकसित करना पड़ा; APJ Abdul Kalam युग – अंततः CE-7.5 इंजन 2014 तक विकसित
GTO – भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा	भूस्थिर कक्षा में उपग्रह स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दीर्घवृत्तीय कक्षा; अपभू ~200 किमी, उपभू ~35,786 किमी; फिर उपग्रह अपनी प्रणोदन से GEO में घुमाता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- Prelims: GSLV = भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान; क्रायोजेनिक चरण = CE-20 (द्रव H_2 + द्रव O_2); GTO = भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा; GSLV बनाम LVM3 – अलग वाहन
- GS3 विज्ञान: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के मील के पत्थर; क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी विकास इतिहास; EOS उपग्रह शासन में अनुप्रयोग

C-DOT ने संचार सुरक्षा के लिए 14 स्वदेशी क्वांटम उत्पाद अनावरण किए

मंत्रालय: संचार मंत्रालय / DoT

PIB तिथि: 31 अगस्त 2026

सरल भाषा में समझें

दूरसंचार विकास केंद्र (C-DOT) – भारत का दूरसंचार R&D केंद्र – ने भारत के संचार नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 14 स्वदेशी क्वांटम प्रौद्योगिकी उत्पादों का अनावरण किया। इनमें क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) प्रणालियाँ, क्वांटम यादृच्छिक संख्या जनरेटर (QRNG), और क्वांटम-सुरक्षित संचार उपकरण शामिल हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? शास्त्रीय एन्क्रिप्शन (RSA, AES) सैद्धांतिक रूप से क्वांटम कंप्यूटरों के प्रति संवेदनशील है – एक पर्याप्त शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर RSA एन्क्रिप्शन को घंटों में तोड़ सकता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, विशेष रूप से QKD, क्वांटम यंत्रविज्ञान का उपयोग करती है जिससे किसी भी अवरोधन का पता लगाना संभव है। C-DOT का QKD स्वदेशीकरण दूरसंचार बुनियादी ढाँचा सुरक्षा, सरकारी संचार सुरक्षा, और रक्षा संचार एन्क्रिप्शन के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
QKD – क्वांटम कुंजी वितरण	एन्क्रिप्शन कुंजी वितरित करने के लिए क्वांटम गुणों (फोटोन ध्रुवीकरण) का उपयोग; कोई भी अवरोधन क्वांटम अवस्थाओं को बाधित करता है – पता लगाया जा सकता है; सैद्धांतिक रूप से अटूट; ऑप्टिकल फाइबर या मुक्त-स्थान पर तैनात
C-DOT	दूरसंचार विकास केंद्र; 1984 में स्थापित; भारत का प्रमुख दूरसंचार R&D केंद्र; 1980-90 के दशक में स्वदेशी ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज विकसित किए; अब 5G, क्वांटम, AI दूरसंचार R&D

QRNG – क्वांटम यादृच्छिक संख्या जनरेटर	वास्तविक यादृच्छिक संख्याएं उत्पन्न करने के लिए क्वांटम घटनाओं का उपयोग; क्रिप्टोग्राफिक कुंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण; शास्त्रीय pseudo-RNG सैद्धांतिक रूप से पूर्वानुमानित
क्वांटम के बाद क्रिप्टोग्राफी	क्वांटम कंप्यूटर हमलों के प्रति प्रतिरोधी एल्गोरिदम; NIST ने 2024 में मानक अंतिम किए; भारत को सरकारी प्रणालियों को माइग्रेट करने की जरूरत
क्वांटम खतरे की समयसीमा	बड़े पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटर 2030-2035 तक आ सकते हैं; 'अभी हार्वेस्ट करो, बाद में डिक्रिप्ट करो' खतरा = प्रतिद्वंद्वी आज एन्क्रिप्टेड डेटा एकत्र कर रहे हैं; तात्कालिकता वास्तविक है
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन	भारत का NQM (2023, ₹6,003 करोड़, 2023-31); 4 थीम: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम सामग्री; C-DOT के QKD उत्पाद = क्वांटम संचार ट्रैक परिणाम

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान/प्रौद्योगिकी: क्वांटम क्रिप्टोग्राफी; QKD यांत्रिकी; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन; क्वांटम के बाद क्रिप्टोग्राफी की तात्कालिकता
- Prelims: C-DOT = दूरसंचार विकास केंद्र; NQM = राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (₹6,003 करोड़, 2023-31); QKD = क्वांटम कुंजी वितरण; QRNG = क्वांटम यादृच्छिक संख्या जनरेटर

ताप-से-विद्युत रूपांतरण की सदी-पुरानी सीमा पार – अति-संवेदनशील तापमान संवेदन

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

PIB तिथि: 31 अगस्त 2026

सरल भाषा में समझें

भारतीय वैज्ञानिकों ने ताप को विद्युत में बदलने की एक सदी पुरानी सैद्धांतिक सीमा को पार किया – जिससे अति-संवेदनशील तापमान संवेदन संभव हो गया। यह सफलता ऊष्मा-विद्युत सामग्री (thermoelectric materials) से संबंधित

है जो तापमान प्रवणता को विद्युत वोल्टेज में बदलती हैं। पारंपरिक सीमा – शास्त्रीय ऊष्मागतिकी से व्युत्पन्न (Seebeck प्रभाव) – ने ऊष्मा-विद्युत ऊर्जा रूपांतरण की दक्षता को सीमित किया था। नए दृष्टिकोण में विशेष रूप से इंजीनियर सामग्रियों में क्वांटम प्रभावों का दोहन किया गया। व्यावहारिक अनुप्रयोग: अति-संवेदनशील तापमान सेंसर (चिकित्सा निदान, औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण), अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति (औद्योगिक अपशिष्ट ताप को विद्युत में बदलना), और पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स (शरीर की गर्मी → IoT उपकरणों को शक्ति देना)।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
Seebeck प्रभाव	ऊष्मा-विद्युत प्रभाव: दो असमान चालकों/अर्धचालकों के बीच तापमान अंतर वोल्टेज उत्पन्न करता है; ऊष्मा-विद्युत जनरेटर (TEG) और थर्मोकपल का आधार; 1821 में Thomas Seebeck द्वारा खोजा गया
ऊष्मा-विद्युत सामग्री	उच्च Seebeck गुणांक, कम विद्युत प्रतिरोध, कम ताप चालकता = उच्च ZT (आकृति of merit); bismuth telluride (Bi_2Te_3) = वर्तमान सर्वश्रेष्ठ; क्वांटम सामग्री = नया मोर्चा
ZT – आकृति of Merit	ऊष्मा-विद्युत दक्षता का आयामहीन माप: $ZT = S^2\sigma T/\kappa$; $ZT > 1$ = व्यावहारिक; क्वांटम दृष्टिकोण शास्त्रीय ZT सीमाओं से आगे जा सकते हैं
अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति	वैश्विक रूप से उत्पन्न ~60% ऊर्जा ताप के रूप में खो जाती है; औद्योगिक निकास, वाहन निकास पर ऊष्मा-विद्युत जनरेटर महत्वपूर्ण ऊर्जा पुनर्प्राप्त कर सकते हैं
ANRF – अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष	2023 में स्थापित; ₹50,000 करोड़ 5 वर्षों में; SERB की जगह; भारत का प्राथमिक प्रतिस्पर्धी अनुसंधान वित्त पोषण निकाय; इस प्रकार का सामग्री विज्ञान अनुसंधान ANRF वित्तपोषित करता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान: Seebeck प्रभाव; ऊष्मा-विद्युत सामग्री; अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति अनुप्रयोग; क्वांटम सामग्री
- Prelims: Seebeck प्रभाव = ताप से विद्युत; ZT = ऊष्मा-विद्युत दक्षता की आकृति of Merit; ANRF = अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष (₹50,000 करोड़)

विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम 2026 – 'एक राष्ट्र, एक समय'

मंत्रालय: उपभोक्ता कार्य मंत्रालय / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

PIB तिथि: 30 अगस्त - 2 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

उपभोक्ता कार्य विभाग ने विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 अधिसूचित किए – 'एक राष्ट्र, एक समय' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। भारत वर्तमान में एक ही समय क्षेत्र (IST = UTC+5:30) पर संचालित होता है लेकिन दो समय क्षेत्रों की लंबे समय से बहस रही है। 'एक राष्ट्र, एक समय' धक्का विपरीत दिशा में है: IST को सभी आधिकारिक घड़ियों, उपकरणों और उपकरणों पर कानूनी माप विज्ञान मानक के रूप में मानकीकृत करना। नियम NTP (नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल) समकालीकरण को भी संबोधित करते हैं – यह सुनिश्चित करना कि भारत की डिजिटल घड़ियाँ राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL), नई दिल्ली के साथ समकालीकृत हों।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
IST – भारतीय मानक समय	UTC+5:30; कोई दिन के समय बचत नहीं; पूरे भारत के लिए एकल समय क्षेत्र; NPL (राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला), नई दिल्ली = भारत का प्राथमिक समय मानक रखवाला; 82.5°E देशांतर (मिर्ज़ापुर, UP) पर आधारित
विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009	बाट, माप और संबंधित उपकरणों को विनियमित करता है; उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा लागू; राज्य विधिक माप विज्ञान अधिकारी स्थानीय स्तर पर लागू; अब समय मानकीकरण तक विस्तारित
NPL – राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	CSIR संस्थान, नई दिल्ली; भारत का राष्ट्रीय माप संस्थान; लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान के प्राथमिक मानक बनाए रखता है; भारत की सीज़ियम परमाणु घड़ी = IST प्राथमिक मानक

NTP – नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल	नेटवर्क पर घड़ियाँ समकालीकृत करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल; NPL पर IST NTP सर्वर आधिकारिक समय स्रोत; उपकरण NPL NTP के साथ समकालीकृत → डिजिटल बुनियादी ढाँचे में IST एकरूपता
दो समय क्षेत्र बहस	पूर्वोत्तर भारत (अरुणाचल प्रदेश में IST से 2 घंटे पहले सूर्योदय/सूर्यास्त) के लिए तर्क दिया गया; CSIR-NPL ने 2016 में अध्ययन किया, दो क्षेत्रों की सिफारिश नहीं की; सरकार ने लगातार दो-क्षेत्र प्रस्ताव को अस्वीकार किया
'एक राष्ट्र' नीति परिवार	एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक ग्रिड, एक राष्ट्र एक गतिशीलता कार्ड, एक राष्ट्र एक समय – एकीकृत राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे की थीम

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- Prelims: IST = UTC+5:30; 82.5° E देशांतर (मिर्ज़ापुर) = आधार; NPL = भारत का प्राथमिक समय मानक; NTP = नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल; विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009
- GS2/GS3: एक राष्ट्र एक समय – 'एक राष्ट्र' नीति परिवार से जोड़ें; संघवाद आयाम; पूर्वोत्तर समय क्षेत्र बहस; भारत की माप बुनियादी ढाँचे में NPL की भूमिका

CSIR-CRRI का 60% RAP प्रौद्योगिकी NH-716 पर – पुनर्नवीनीकृत डामर फुटपाथ का मील का पत्थर

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय / MoRTH

PIB तिथि: 2 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

CSIR-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI), OSEPL, और Ooms India ने राष्ट्रीय राजमार्ग 716 पर 60% पुनर्नवीनीकृत डामर फुटपाथ (RAP) प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया। RAP में पुरानी सड़कों की मिली हुई सामग्री को नई सड़क निर्माण में पुनः उपयोग करना शामिल है। 60% RAP का मतलब है कि नई सड़क सतह में 60% सामग्री पुरानी सड़क से पुनर्नवीनीकृत है – ताजे बिटुमेन (एक पेट्रोलियम उत्पाद, इसलिए महंगा और कार्बन-गहन) और कुंवारी समुच्चय की जरूरत को नाटकीय रूप से कम करती है। वर्तमान में भारत सड़क निर्माण में 10-20% RAP का उपयोग करता है।

लाभ: कम सड़क निर्माण लागत (ताजा बिटुमेन ₹40,000-50,000 प्रति टन), कम कार्बन उत्सर्जन, कम खनन दबाव।

भारत में 1.46 लाख किमी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं – आवधिक पुनः सतह से उपलब्ध RAP संसाधन विशाल है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
RAP – पुनर्नवीनीकृत डामर फुटपाथ	पुरानी सड़क सतह की मिलिंग, प्रसंस्करण, और नई सड़क में पुनः उपयोग; ताजे बिटुमेन और समुच्चय की आवश्यकता कम करता है; 60% RAP = नई फुटपाथ का 60% पुनर्नवीनीकृत; भारत वर्तमान में 10-20% उपयोग करता है
CSIR-CRRI	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान; नई दिल्ली; CSIR संस्थान; भारत का प्रमुख सड़क अनुसंधान संस्थान; सड़क निर्माण मानक, फुटपाथ डिज़ाइन; RAP प्रौद्योगिकी विकास
बिटुमेन	डामर सड़कों में समुच्चय बांधने वाली चिपचिपी काली पेट्रोलियम-व्युत्पन्न सामग्री; भारत ~45% बिटुमेन जरूरतें आयात करता है; अत्यधिक कार्बन-गहन; ₹40,000-50,000/टन; RAP से बिटुमेन उपयोग कम = लागत और कार्बन बचत
हरित राजमार्ग	MoRTH की हरित राजमार्ग नीति 2015; NHAI के हरित राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार (उसी सप्ताह); RAP + पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक सड़क + फ्लाई ऐश उपयोग = टिकाऊ सड़क निर्माण एजेंडा
NH-716	राष्ट्रीय राजमार्ग 716; 60% RAP प्रदर्शन स्थान; NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए रखता है; भारत में 1.46 लाख किमी NH; आवधिक पुनः सतह = बड़ा RAP संसाधन उत्पन्न करता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण/बुनियादी ढाँचा: RAP प्रौद्योगिकी; टिकाऊ सड़क निर्माण; हरित राजमार्ग नीति; भारत की बिटुमेन आयात निर्भरता; निर्माण में चक्रीय अर्थव्यवस्था
- Prelims: CSIR-CRRI = केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान; RAP = पुनर्नवीनीकृत डामर फुटपाथ; भारत के NH नेटवर्क = 1.46 लाख किमी; बिटुमेन = पेट्रोलियम-व्युत्पन्न सड़क बंधक सामग्री

BIO-NIVESH लॉन्च – जैव-प्रौद्योगिकी निवेश और विस्तार के लिए

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने BIO-NIVESH लॉन्च किया – भारत के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को प्रेरित करने का एक मंच। BIO-NIVESH (NIVESH = हिंदी में निवेश) जैव-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, निवेशकों (VC, PE, रणनीतिक निवेशक), और सरकारी समर्थन प्रणालियों (BIRAC, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग – DBT) के बीच एक संरचित इंटरफेस है। भारत का जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र महत्वपूर्ण है: ~\$130 अरब उद्योग (2024), 2030 तक \$300 अरब लक्ष्य; टीके (Serum Institute, भारत बायोटेक), बायोसिमिलर (भारत = दुनिया का सबसे बड़ा बायोसिमिलर उत्पादक), कृषि जैव-प्रौद्योगिकी, और औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी। क्षेत्र को प्रारंभिक चरण में अधिक जोखिम पूँजी की जरूरत है – BIO-NIVESH एक संरचित मिलान मंच बनाता है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
BIO-NIVESH	भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रेरित करने का मंच; स्टार्टअप + निवेशक + BIRAC/DBT को जोड़ता है; सितंबर 2026 लॉन्च; जैव-प्रौद्योगिकी विस्तार के लिए संरचित मिलान
BIRAC	जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद; DBT का उद्योग-इंटरफेस; वित्त पोषण (BIPP, SBIRI योजनाएं), ऊष्मायन, नियामक समर्थन; ~₹5,000 करोड़ तैनात
भारत का जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र	~\$130 अरब उद्योग (2024); 2030 तक \$300 अरब लक्ष्य; एशिया-प्रशांत में तीसरा सबसे बड़ा जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र; टीके (SII, भारत बायोटेक), बायोसिमिलर, कृषि जैव-प्रौद्योगिकी, औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी

बायोसिमिलर	पहले से अनुमोदित जैविक दवाओं के समान (समान नहीं) दवाएं; जटिल अणु (प्रोटीन, एंटीबॉडी); भारत = दुनिया का सबसे बड़ा बायोसिमिलर उत्पादक; USA, EU, विनियमित बाजारों में प्रमुख निर्यात
DBT – जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय; भारत का प्राथमिक जैव-प्रौद्योगिकी प्रशासन निकाय; BIRAC, जैव-प्रौद्योगिकी क्लस्टर, BioE3 नीति (2024), राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन
BioE3 नीति 2024	अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी; भारत की व्यापक जैव-प्रौद्योगिकी औद्योगिक नीति; जैव-विनिर्माण, जैव-ईंधन, जैव-आधारित रसायन, कृषि-जैव-प्रौद्योगिकी को लक्षित करती है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान/अर्थव्यवस्था: भारत का जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र; BIRAC; BioE3 नीति 2024; बायोसिमिलर; गहरी तकनीक में जोखिम पूँजी; जैव-प्रौद्योगिकी के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र
- Prelims: BIRAC = जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद; भारत जैव-प्रौद्योगिकी = ~\$130 अरब; 2030 लक्ष्य \$300 अरब; भारत = दुनिया का सबसे बड़ा बायोसिमिलर उत्पादक; BioE3 नीति 2024

लघु आणविक स्विच – स्व-संचालित स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रकृति-प्रेरित जैव-सामग्री

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारतीय शोधकर्ताओं ने एक लघु आणविक स्विच का प्रदर्शन किया जो स्व-संचालित स्वास्थ्य सेवा उपकरणों के लिए परिवेश ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में सक्षम प्रकृति-प्रेरित जैव-सामग्री को सक्षम बनाता है। यह आणविक स्विच पर्यावरणीय उत्तेजनाओं (pH, तापमान, प्रकाश, यांत्रिक तनाव) के प्रति प्रतिक्रिया करता है – उन जैविक प्रणालियों की नकल करता है जो कार्य करने के लिए आकार बदलती हैं। परिणामी 'स्मार्ट जैव-सामग्री' कर सकती हैं: शरीर की गति से यांत्रिक ऊर्जा (पिजोइलेक्ट्रिक प्रभाव) या शरीर की गर्मी (ऊष्मा-विद्युत प्रभाव) से परिवेश ऊर्जा एकत्र करना; और शारीरिक

परिवर्तनों पर स्वायत्त रूप से प्रतिक्रिया करना। अनुप्रयोग: स्व-संचालित पहनने योग्य स्वास्थ्य मॉनिटर, प्रत्यारोपण योग्य बायोसेंसर जिन्हें बैटरी प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं, और उत्तरदायी दवा वितरण प्रणाली।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
आणविक स्विच	उत्तेजना (प्रकाश, pH, तापमान, यांत्रिक बल) के प्रति प्रतिक्रिया में संरचना/गुण बदलने वाला अणु; जैविक स्विच की नकल; 'स्मार्ट' सामग्री व्यवहार सक्षम करता है
जैव-सामग्री	जैविक प्रणालियों के साथ बातचीत के लिए इंजीनियर सामग्री; प्रत्यारोपण, बायोसेंसर, दवा वितरण प्रणाली, ऊतक मचान; 'स्मार्ट जैव-सामग्री' शारीरिक संकेतों पर प्रतिक्रिया करती हैं
पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव	यांत्रिक तनाव → विद्युत वोल्टेज उत्पादन; क्वार्ट्ज = क्लासिक पीजोइलेक्ट्रिक; शरीर की गति (चलना, दिल की धड़कन) → पहनने योग्य उपकरणों को शक्ति देना; बैटरी की जरूरत नहीं
स्व-संचालित उपकरण	परिवेश ऊर्जा (शरीर की गति, गर्मी, प्रकाश) से संचालित उपकरण; प्रत्यारोपण योग्य के लिए महत्वपूर्ण (बैटरी बदलने के लिए सर्जरी नहीं) और दूरदराज़ क्षेत्र पहनने योग्य
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)	भारत का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र; स्वास्थ्य ID, रजिस्ट्री, टेलीमेडिसिन; ABDM में फीड करने वाले स्व-संचालित पहनने योग्य सेंसर = बुनियादी ढाँचे निर्भरता के बिना ग्रामीण स्वास्थ्य निगरानी
ANRF	अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष; 2023 में स्थापित; ₹50,000 करोड़ 5 वर्षों में; SERB की जगह; भारत का प्राथमिक प्रतिस्पर्धी अनुसंधान वित्त पोषण निकाय

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान: स्मार्ट जैव-सामग्री; पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव; स्व-संचालित पहनने योग्य; ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में अनुप्रयोग

- Prelims: पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव = यांत्रिक तनाव → विद्युत; ANRF = अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष (₹50,000 करोड़); ABDM = आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

शून्य-उत्सर्जन शिपिंग गलियारे – बंदरगाह हरित ईंधन तैयारी में तेजी लाएं

मंत्रालय: बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शून्य-उत्सर्जन शिपिंग गलियारों का मार्ग तैयार किया और बंदरगाहों को हरित ईंधन तैयारी में तेजी लाने के निर्देश दिए। भारत का समुद्री क्षेत्र – मात्रा के हिसाब से ~95% व्यापार और मूल्य के हिसाब से ~70% संभाल रहा है – कार्बन-मुक्ति के बढ़ते दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की संशोधित GHG रणनीति (2023): 2030 तक 20-30% GHG कमी, 2040 तक 70-80%, और 2050 तक शुद्ध-शून्य। हरित शिपिंग ईंधन: अमोनिया (शून्य कार्बन दहन, लेकिन विषैला), मेथनॉल (आसान संचालन, Maersk पहले से तैनाती कर रही है), LNG (कम-उत्सर्जन संक्रमण ईंधन), और हरित हाइड्रोजन। भारत के प्रमुख बंदरगाहों – JNPT, मुंद्रा, चेन्नई, विशाखापट्टनम – को हरित ईंधन के लिए बंकरिंग बुनियादी ढाँचा विकसित करना होगा।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
शून्य-उत्सर्जन शिपिंग गलियारे	निर्दिष्ट शिपिंग मार्ग जहाँ जहाज केवल शून्य/निकट-शून्य उत्सर्जन ईंधन का उपयोग करते हैं; हरित शिपिंग चुनौती (COP27, 2022); Clydebank घोषणापत्र
IMO GHG रणनीति 2023	अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन; 2030 तक 20-30% कमी, 2040 तक 70-80%, 2050 तक/के आसपास शुद्ध-शून्य; 2018 रणनीति से अधिक महत्वाकांक्षी
हरित शिपिंग ईंधन	अमोनिया (शून्य कार्बन, विषैला, नया बुनियादी ढाँचा), मेथनॉल (आसान संचालन, Maersk तैनाती), LNG (संक्रमण ईंधन, अभी भी जीवाश्म), हरित हाइड्रोजन (सर्वोच्च वादा); प्रत्येक को अलग जहाज इंजन और बंदरगाह बंकरिंग बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता

बंकरिंग बुनियादी ढाँचा	बंदरगाहों पर जहाज ईंधन भरने की सुविधाएं; पारंपरिक = पेट्रोलियम बंकर; हरित बंकरिंग = अमोनिया, मेथनॉल, LNG भंडारण + हस्तांतरण; विशाल बुनियादी ढाँचा निवेश आवश्यक
भारत का हरित ईंधन अवसर	भारत की नवीकरणीय क्षमता (सौर, पवन) → हरित हाइड्रोजन → हरित अमोनिया या मेथनॉल; कम लागत वाली हरित ऊर्जा = प्रतिस्पर्धी हरित शिपिंग ईंधन उत्पादन; जापान, दक्षिण कोरिया, EU को निर्यात
JNPT	जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट (नवी मुंबई); भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह; भारत का ~55% कंटेनरीकृत माल; हरित ईंधन बंकरिंग तैयारी के लिए पहला बंदरगाह

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण/अर्थव्यवस्था: IMO GHG रणनीति 2023; हरित शिपिंग ईंधन; बंकरिंग बुनियादी ढाँचा; भारत का हरित अमोनिया अवसर; सागरमाला + हरित शिपिंग
- Prelims: IMO = अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन; हरित शिपिंग ईंधन = अमोनिया, मेथनॉल, LNG, हरित हाइड्रोजन; JNPT = भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह; सागरमाला = बंदरगाह-नेतृत्व विकास

एजेंटिक AI कौशल – NIELIT और Intel India राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च

मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

NIELIT (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) और Intel India ने भारत के कार्यबल को एजेंटिक AI युग के लिए तैयार करने हेतु राष्ट्रीय नेतृत्व संवाद और एजेंटिक AI कौशल कार्यक्रम लॉन्च किए। 'एजेंटिक AI' उन AI प्रणालियों को संदर्भित करता है जो स्वायत्त रूप से कार्यों के अनुक्रम ले सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और जटिल बहु-चरणीय कार्य पूरे कर सकती हैं – केवल संकेतों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय। उदाहरण: AI एजेंट जो स्वायत्त रूप से वेब ब्राउज़ करते हैं, कोड लिखते हैं, परीक्षण चलाते हैं और सॉफ्टवेयर तैनात करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में ~58 लाख IT पेशेवर हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी प्रतिभा पूल है; एजेंटिक AI के लिए इस कार्यबल को कुशल बनाना भारत को अगली उत्पादकता सीमा के लिए तैयार करता है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
एजेंटिक AI	AI प्रणालियाँ जो बहु-चरणीय कार्यों को पूरा करने के लिए स्वायत्त रूप से कार्य करती हैं; 'उपकरण' (वेब खोज, कोड निष्पादन, फ़ाइल प्रबंधन) का उपयोग करती हैं; चैटबोट/प्रॉम्प्ट-प्रतिक्रिया AI से अलग
NIELIT	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान; MeitY के अंतर्गत स्वायत्त निकाय; भारत में ICT कौशल; CCC (कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम) = भारत का सबसे व्यापक रूप से लिया गया कंप्यूटर साक्षरता पाठ्यक्रम; दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे भारत में केंद्र
Intel का AI कौशल	Intel Core Ultra (NPU के साथ) + OpenVINO AI टूलकिट; AI कौशल के लिए सरकारों के साथ भागीदारी; भारत भागीदारी = महत्वपूर्ण पैमाना
भारत का IT कार्यबल	~58 लाख IT पेशेवर; दुनिया का सबसे बड़ा तकनीक प्रतिभा पूल; NASSCOM रिपोर्ट; वर्तमान में 60-70% पारंपरिक सॉफ्टवेयर विकास में; एजेंटिक AI = अगली उत्पादकता लहर
IndiaAI मिशन	₹10,372 करोड़; AI कौशल स्तंभ = 3 वर्षों में 5 लाख AI कौशल लक्ष्य; NIELIT कार्यान्वयन एजेंसी; Intel भागीदारी निजी क्षेत्र के संसाधन और हार्डवेयर जोड़ती है
NPU – न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट	AI अनुमान के लिए समर्पित चिप; Intel Core Ultra, Apple M-सीरीज, Qualcomm Snapdragon X में उपस्थित; बादल के बिना स्थानीय रूप से AI मॉडल चलाता है; एजेंटिक AI के लिए महत्वपूर्ण

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान/अर्थव्यवस्था: एजेंटिक AI; भारत का IT कार्यबल कौशल; NIELIT; IndiaAI मिशन; AI कौशल स्तंभ
- Prelims: NIELIT = राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान; एजेंटिक AI = स्वायत्त बहु-चरणीय AI; IndiaAI मिशन = ₹10,372 करोड़; NPU = न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट

स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 2026 – 5वाँ संस्करण, महासागर संरक्षण आंदोलन

मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

PIB तिथि: 1 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर' का 5वाँ संस्करण लॉन्च किया – महासागर संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी जन-आंदोलन। यह अभियान तटीय और समुद्र तट सफाई, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण जागरूकता, और महासागर स्वास्थ्य शिक्षा पर केंद्रित है। भारत की 7,517 किमी तटरेखा और एक विशाल समुद्री अर्थव्यवस्था है: नीली अर्थव्यवस्था GDP का ~4% योगदान देती है (लक्ष्य: GDP का 10%)। समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या है – भारत की नदियाँ अनुमानित 0.4 मिलियन टन प्लास्टिक सालाना महासागर तक पहुँचाती हैं। यह अभियान SDG 14 (समुद्र के नीचे जीवन) और चल रही वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता से जुड़ा है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर	राष्ट्रव्यापी तटीय सफाई + महासागर संरक्षण अभियान; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; 5वाँ संस्करण 2026; समुद्र तट सफाई, समुद्री प्लास्टिक जागरूकता, नागरिक सहभागिता; राष्ट्रीय समुद्री दिवस (1 सितंबर) पर लॉन्च
भारत की नीली अर्थव्यवस्था	महासागर-आधारित आर्थिक गतिविधियाँ: मत्स्य पालन (₹1.7 लाख करोड़), शिपिंग, बंदरगाह, अपतटीय ऊर्जा, तटीय पर्यटन, समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी; ~GDP का 4%; 10% GDP लक्ष्य
गहरे महासागर मिशन	₹4,077 करोड़, 5 वर्षीय; 6 थीम: गहरे समुद्री खनन, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार, समुद्री जैव विविधता, गहरे महासागर सर्वेक्षण, महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी, उन्नत समुद्री स्टेशन; समुद्रयान (मानवयुक्त पनडुब्बी) इसके अंतर्गत

वैश्विक प्लास्टिक संधि (INC)	UNEA संकल्प 5/14 (2022): कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए INC; INC-5 बुसान नवंबर 2024; भारत की स्थिति: अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान, उत्पादन सीमा पर नहीं
समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण	भारत की नदियाँ = ~0.4 मिलियन टन प्लास्टिक/वर्ष महासागर को; गंगा विश्व की शीर्ष प्लास्टिक-प्रदूषण करने वाली नदियों में; एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध (भारत 2022, 19 वस्तुएं); EPR ढाँचा
SDG 14 – समुद्री जीवन	महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग; लक्ष्यों में समुद्री प्रदूषण कम करना, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा; MoES द्वारा भारत की प्रगति की निगरानी

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण: नीली अर्थव्यवस्था; समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण; वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता (INC); SDG 14; गहरे महासागर मिशन; समुद्रयान
- Prelims: स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर = पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; गहरे महासागर मिशन = ₹4,077 करोड़; INCOIS = भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र; SDG 14 = समुद्री जीवन

बाघ परिदृश्य कार्यशाला – संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी पर्यटन

मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

PIB तिथि: 2 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 'बाघ परिदृश्य: आजीविका और आय सृजन के लिए संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी पर्यटन' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह कार्यशाला एक महत्वपूर्ण ढाँचे में है: यह 'केवल संरक्षण के रूप में बाघ संरक्षण' से आगे बढ़कर 'आर्थिक संपत्ति के रूप में बाघ परिदृश्य' की ओर जाती है। भारत में ~3,682 बाघ हैं (2022 जनगणना) – विश्व की जंगली बाघ आबादी का 70% – 54 बाघ अभयारण्यों में। जैव-अर्थव्यवस्था का पहलू: बाघ परिदृश्य गैर-इमारती वन उत्पाद, कार्बन क्रेडिट (बाघ वन = महत्वपूर्ण कार्बन सिंक), और

पारिस्थितिकी पर्यटन का समर्थन करते हैं। 'आय सृजन' का ढाँचा महत्वपूर्ण है: यह स्थानीय समुदायों को बाघ संरक्षण के आर्थिक हितधारक बनाता है – मानव-वन्यजीव संघर्ष की मूल समस्या को सीधे संबोधित करता है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
Project Tiger	1973 में लॉन्च; भारत के सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक; बाघ आबादी: 1973 (1,827) → 2006 (1,411, संकट) → 2018 (2,967) → 2022 (3,682); 54 बाघ अभयारण्य; NTCA पर्यवेक्षण
NTCA	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (2006 में संशोधित) के तहत वैधानिक निकाय; Project Tiger, बाघ अभयारण्य प्रबंधन, M-STrIPES निगरानी प्रणाली
जैव-अर्थव्यवस्था	जैविक संसाधनों से व्युत्पन्न आर्थिक गतिविधि; बाघ परिदृश्य जैव-अर्थव्यवस्था = NTFP, कार्बन क्रेडिट, औषधीय पौधे, बाँस; अनुमानित ₹50,000+ करोड़ क्षमता
बाघ वनों से कार्बन क्रेडिट	बाघ अभयारण्य = घने वन = महत्वपूर्ण कार्बन सिंक; स्वैच्छिक कार्बन बाजार मुद्रीकरण सक्षम करता है; REDD+ (वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन में कमी) तंत्र
पारिस्थितिकी पर्यटन	बाघ अभयारण्यों में वन्यजीव पर्यटन; Jim Corbett (~5 लाख आगंतुक/वर्ष), Ranthambore (~3 लाख), Kaziranga, Bandhavgarh; सामुदायिक-आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन = स्थानीय आय
मानव-वन्यजीव संघर्ष	वन किनारे क्षेत्रों में बाघ के पशुधन और कभी-कभी मनुष्यों पर हमले; जवाबी हत्या = बाघ मृत्यु दर का प्रमुख कारण; बाघ संरक्षण के आर्थिक लाभार्थी बनाना संघर्ष कम करता है – इस कार्यशाला का मूल तर्क

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण: Project Tiger; NTCA; बाघ जनगणना 2022 (3,682); बाघ परिदृश्यों से जैव-अर्थव्यवस्था; कार्बन क्रेडिट; मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान

- Prelims: भारत = विश्व के 70% जंगली बाघ; 54 बाघ अभयारण्य; NTCA Project Tiger की देखरेख करता है; 2022

जनगणना = 3,682 बाघ; M-STrIPES = बाघ निगरानी प्रणाली

गृह सचिव ने हिमालयी राज्यों की GLOF और हिमस्खलन तैयारी की समीक्षा की

मंत्रालय: गृह मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय गृह सचिव ने हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) और हिमस्खलन के लिए तैयारी की समीक्षा की। GLOF तब होता है जब एक हिमनदी झील अचानक जल छोड़ती है जब उसका बांध (मोराइन या बर्फ) टूट जाता है – आमतौर पर झील में भूस्खलन, हिम हिमस्खलन, या ग्लेशियर झील विस्तार के कारण। भारत के हिमालयी राज्य (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, J&K, लद्दाख) जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पीछे हटने से तेजी से GLOF-प्रवण हो रहे हैं। हाल की प्रमुख GLOF घटनाएं: चमोली आपदा (फरवरी 2021, उत्तराखंड) – ~200+ की जान; South Lhonak Lake GLOF (अक्टूबर 2023, सिक्किम) – Teesta नदी बाढ़, प्रमुख बाँध क्षति।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
GLOF	हिमनदी झील विस्फोट बाढ़; जब झील बांध (मोराइन, बर्फ, भूस्खलन मलबा) टूटता है तो अचानक पानी का छोड़ना; जलवायु तापमान के साथ बढ़ती आवृत्ति
हाल की भारतीय GLOF	चमोली (फरवरी 2021, उत्तराखंड): चट्टान/बर्फ हिमस्खलन से मलबा प्रवाह, ~200+ की मौत, Rishiganga और Dhauliganga बाँध क्षतिग्रस्त; South Lhonak Lake GLOF (अक्टूबर 2023, सिक्किम): Teesta बाढ़, ~100 मौतें

NDMA	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण; PM की अध्यक्षता में; GLOF, हिमस्खलन, भूकंप तैयारी पर दिशानिर्देश; राज्य DMA कार्यान्वयन; NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) बचाव के लिए तैनात
NRSC – राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र	ISRO का पृथ्वी अवलोकन डेटा केंद्र; हैदराबाद; ग्लेशियर निगरानी, GLOF जोखिम मानचित्रण, आपदा मूल्यांकन के लिए उपग्रह इमेजरी; CARTOSAT, RISAT डेटा
उच्च पर्वतीय एशिया ग्लेशियर	हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, तिब्बती पठार = ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर द्रव्यमान; 'तीसरा ध्रुव'; 10 प्रमुख एशियाई नदियाँ पोषित; जलवायु परिवर्तन ग्लेशियर पीछे हटने को तेज कर रहा है
SASE – हिमस्खलन अध्ययन संस्थान	हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान; DRDO; चंडीगढ़ में मुख्यालय; हिमस्खलन पूर्वानुमान और चेतावनी; BRO (सीमा सड़क संगठन) के साथ काम करता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण/आपदा प्रबंधन: GLOF; चमोली 2021; South Lhonak 2023; NDMA; NDRF; हिमालयी ग्लेशियर पीछे हटना; हिमस्खलन तैयारी; SASE
- Prelims: GLOF = हिमनदी झील विस्फोट बाढ़; NDMA = PM की अध्यक्षता में; NRSC = ISRO का पृथ्वी अवलोकन केंद्र, हैदराबाद; SASE = हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (DRDO); BRO = सीमा सड़क संगठन

भारत-जर्मन पर्यावरण फोरम – ज्ञान, समाधान, संस्थागत क्षमता

मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

PIB तिथि: 1 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भूपेंद्र यादव (केंद्रीय पर्यावरण मंत्री) ने 4थे भारत-जर्मन पर्यावरण फोरम में पर्यावरण संरक्षण में ज्ञान आदान-प्रदान, समाधानों को बड़े पैमाने पर फैलाने और संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करने का आह्वान किया। भारत-जर्मनी पर्यावरण सहयोग ठोस है: जर्मनी EU में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (द्विपक्षीय व्यापार ~€30 अरब); और

KfW (जर्मन विकास बैंक) और GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) के माध्यम से यह भारत का सबसे बड़ा विकास सहयोग भागीदार भी है। भारत-जर्मन पर्यावरण सहयोग क्षेत्र: नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक कार्बन-मुक्तीकरण, हरित हाइड्रोजन (भारत-जर्मनी हरित H₂ साझेदारी), शहरी जल प्रबंधन, और जैव विविधता संरक्षण।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
भारत-जर्मन पर्यावरण फोरम	पर्यावरण सहयोग का द्विपक्षीय मंच; 4थाँ संस्करण सितंबर 2026; ज्ञान आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संस्थागत क्षमता निर्माण; नई दिल्ली में आयोजित
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (पुनर्निर्माण क्रेडिट संस्थान); जर्मनी का राज्य-स्वामित्व वाला विकास बैंक; भारत = KfW के सबसे बड़े उधारकर्ता देशों में; नवीकरणीय ऊर्जा, पानी, शहरी विकास वित्त; भारत को €10+ अरब प्रतिबद्ध
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit; जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी; द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यान्वयन; सौर ऊर्जा, शहरी जल, वानिकी में भारत-जर्मन साझेदारी
Energiewende	जर्मनी का 'ऊर्जा संक्रमण' – परमाणु और कोयला चरणबद्ध, नवीकरणीय बढ़ाना; जर्मनी को यूक्रेन प्रतिबंधों के बाद चुनौतियों का सामना; भारत के लिए सबक: क्या दोहराना है, ऊर्जा संक्रमण में क्या नहीं
हरित हाइड्रोजन सहयोग	जर्मनी = प्रमुख हरित हाइड्रोजन आयातक; भारत = संभावित निर्यातक (NGHM – राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ₹17,490 करोड़); जर्मनी-भारत हरित हाइड्रोजन साझेदारी = तार्किक
CBAM – कार्बन सीमा समायोजन तंत्र	EU का कार्बन आयात शुल्क; कार्बन मूल्य निर्धारण के बिना देशों से आयात पर; भारत चिंतित; स्टील, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक पर लागू; भारत-EU BTIA वार्ता में स्थिरता अध्याय शामिल

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: भारत-जर्मनी द्विपक्षीय; KfW और GIZ विकास सहयोग उपकरण के रूप में; भारत-जर्मन पर्यावरण फोरम
- GS3 पर्यावरण: हरित हाइड्रोजन (NGHM); भारत-जर्मनी ऊर्जा सहयोग; Energiewende सबक; CBAM और भारत
- Prelims: KfW = जर्मनी का विकास बैंक; GIZ = जर्मनी की विकास एजेंसी; Energiewende = जर्मनी का ऊर्जा संक्रमण; NGHM = राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (₹17,490 करोड़)

संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा शिक्षा – UGC ने NCAHP के तहत 33 नई डिग्री अधिसूचित की

मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

PIB तिथि: 2 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने NCAHP (राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग) नियामक ढाँचे के तहत UGC द्वारा 33 नई स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम अधिसूचित करवाए। संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर (AHP) स्वास्थ्य सेवा की अदृश्य रीढ़ हैं: फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, पोषण विशेषज्ञ, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन – वे अधिकांश उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में डॉक्टरों की संख्या से अधिक होते हैं (USA में ~6 AHP प्रति डॉक्टर बनाम भारत में ~1.2)। भारत में AHP की गंभीर कमी है – अनुमानित 20 लाख+ की कमी। NCAHP अधिनियम 2021 भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए पहला विशिष्ट कानून था।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
NCAHP	राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग; NCAHP अधिनियम 2021 के तहत स्थापित; 56 संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों को विनियमित करता है; डॉक्टरों के लिए NMC के समान
संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर (AHP)	गैर-चिकित्सक, गैर-नर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी; फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट; भारत में ~1.2 AHP प्रति डॉक्टर बनाम USA में ~6

NCAHP अधिनियम 2021	भारत में संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायों के लिए पहला व्यापक कानून; राष्ट्रीय रजिस्ट्री, शैक्षणिक मानक, पेशेवर आचार नियम बनाता है; भारत की AHP कमी को संबोधित करता है
UGC	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; उच्च शिक्षा विनियमन का शीर्ष निकाय; डिग्री नाम और ढाँचे अधिसूचित करता है; NCAHP के तहत 33 नई डिग्री = भारत के डिग्री शिक्षा प्रणाली में औपचारिक एकीकरण
भारत की स्वास्थ्य सेवा कार्यबल कमी	डॉक्टर (वर्तमान ~13.5 लाख, WHO मानदंड = ~18.5 लाख), नर्स (~35.5 लाख, कमी ~28 लाख), AHP (कमी अनुमानित 20+ लाख); AHP कमी सबसे गंभीर और सबसे कम संबोधित
SUMAN रोडमैप 2030 (उसी सप्ताह)	मातृ और नवजात स्वास्थ्य देखभाल; AHP (दाइयाँ, ANM, लेबर रूम तकनीशियन) मातृ स्वास्थ्य परिणामों के लिए महत्वपूर्ण; दोनों टुकड़े जुड़ते हैं

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 स्वास्थ्य/शासन: NCAHP अधिनियम 2021; भारत की स्वास्थ्य सेवा कार्यबल कमी; संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर; स्वास्थ्य सेवा शिक्षा विनियमन में UGC की भूमिका
- Prelims: NCAHP = राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग; NCAHP अधिनियम = 2021; UGC = विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; NCAHP ढाँचे के तहत 33 नई डिग्री अधिसूचित

मिशन रंगीन मछली 2031 – सजावटी मत्स्य पालन के लिए रणनीतिक कार्ययोजना

मंत्रालय: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

PIB तिथि: 30 अगस्त 2026

सरल भाषा में समझें

उपराष्ट्रपति ने 'मिशन रंगीन मछली 2031' जारी किया – 2031 तक सजावटी मत्स्य पालन विकास के लिए भारत की रणनीतिक कार्ययोजना। सजावटी मत्स्य पालन = एक्वेरियम और सजावटी उद्देश्यों के लिए जीवित मछली, मूंगा और

अन्य जलीय जीवों का व्यापार। वैश्विक सजावटी मछली व्यापार ~\$15-20 अरब प्रति वर्ष का है; भारत का हिस्सा एक नगण्य ~\$20-25 मिलियन है बावजूद इसके कि भारत में असाधारण मीठे पानी की जैव विविधता (हिमालयी धाराएं, पश्चिमी घाट की नदियाँ, पूर्वोत्तर भारत की नदियाँ) और विस्तृत समुद्री तट है। मिशन रंगीन मछली 2031 के लक्ष्य: 2031 तक भारत के सजावटी मछली निर्यात को \$500 मिलियन तक बढ़ाना; सजावटी प्रजातियों की मछली पालन विकसित करना; और तटीय और नदी समुदायों के लिए आजीविका बनाना।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
सजावटी मत्स्य पालन	एक्वेरियम के लिए जीवित मछली, अकशेरुकी, मूंगा, जलीय पौधों का व्यापार; वैश्विक व्यापार ~\$15-20 अरब; भारत का वर्तमान निर्यात ~\$20-25 मिलियन (विशाल कम-प्रदर्शन); प्राथमिक निर्यातक: सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका
मिशन रंगीन मछली 2031	भारत की सजावटी मत्स्य पालन के लिए रणनीतिक कार्ययोजना; लक्ष्य: 2031 तक \$500 मिलियन निर्यात; मीठे पानी + समुद्री सजावटी मछली; सजावटी प्रजातियों का जलीय कृषि; सामुदायिक आजीविका
भारत की सजावटी मछली जैव विविधता	पश्चिमी घाट की नदियाँ = स्थानिक साइप्रिनिड (डेनियो, रास्बोरा, लोच); पूर्वोत्तर भारत = शानदार शीतल जल प्रजातियाँ; अंडमान सागर = समुद्री सजावटी; हिमालयी धाराएं; अधिकांश प्रजातियाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अज्ञात
PM मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)	₹20,050 करोड़, 2020-25; भारत की प्रमुख मत्स्य पालन योजना; मत्स्य पालन बुनियादी ढाँचा, जलीय कृषि, निर्यात प्रोत्साहन, मछुआरा कल्याण; सजावटी मत्स्य पालन = एक घटक
MPEDA	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण; सजावटी सहित समुद्री उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन; कोच्चि-आधारित; भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात ~\$7.38 अरब (FY2024)

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था/पर्यावरण: भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र; PMMSY; सजावटी मत्स्य पालन क्षमता; जैव विविधता संरक्षण + आर्थिक उपयोग; MPEDA
- Prelims: मिशन रंगीन मछली 2031 = सजावटी मत्स्य पालन रणनीतिक योजना; 2031 तक \$500 मिलियन लक्ष्य; MPEDA = समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण; PMMSY = ₹20,050 करोड़ मत्स्य पालन योजना

PM-JANMAN समीक्षा + DA-JGUA – जनजातीय विकास पहल

मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने PM-JANMAN (पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) और DA-JGUA की प्रगति की समीक्षा की और जनजातीय विकास को मजबूत करने के लिए मुख्य पहल की घोषणा की। PM-JANMAN नवंबर 2023 में विशेष रूप से अति संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTG) को लक्षित करके लॉन्च किया गया था। PVTG 18 राज्यों में 75 समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, पूर्व-कृषि प्रौद्योगिकी है, अत्यंत कम साक्षरता है, और निर्वाह अर्थव्यवस्था है। PM-JANMAN PVTG के लिए 3 वर्षों में ₹24,104 करोड़ आवंटित करता है – आवास (PMAY), सड़क (PMGSY), शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल और मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ कवर करता है। DA-JGUA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) व्यापक जनजातीय विकास के लिए एक पूरक पहल है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
PM-JANMAN	पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान; नवंबर 2023 में लॉन्च; 75 PVTG (अति संवेदनशील जनजातीय समूह) को लक्षित; 3 वर्षों में ₹24,104 करोड़; 9 मंत्रालय अभिसरण; PVTG के लिए आवास, सड़क, स्वच्छ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य
PVTG	अति संवेदनशील जनजातीय समूह; 18 राज्यों में 75 समुदाय; पूर्व-कृषि प्रौद्योगिकी, घटती जनसंख्या, बहुत कम साक्षरता, निर्वाह अर्थव्यवस्था; Sentinelese (अंडमान), Shompens, Baigas, Bondas, Birhor, Chenchus PVTG में

DA-JGUA	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान; 'धरती आबा' = बिरसा मुंडा की उपाधि; व्यापक जनजातीय विकास (केवल PVTG नहीं); 63,000+ जनजातीय गाँव; 25 योजनाओं का अभिसरण; ₹79,156 करोड़ परिव्यय
बिरसा मुंडा	जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी (1875-1900); झारखंड में ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ उलगुलान (विद्रोह); धरती आबा = उनकी मानद उपाधि; 15 नवंबर (जन्म वर्षगाँठ) = जनजातीय गौरव दिवस; PM-JANMAN इसी तारीख पर लॉन्च
PESA अधिनियम 1996	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम; पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार; ग्राम सभा की शक्तियाँ भूमि, संसाधन, लघु वन उत्पाद पर; जनजातीय स्वशासन
FRA 2006	वन अधिकार अधिनियम; वन भूमि, सामुदायिक संसाधनों पर जनजातीय अधिकार; व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR), सामुदायिक वन अधिकार (CFR); PVTG = वन-निवासी जनजातियों को अन्य विकास से पहले FRA की जरूरत

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS1/GS2 समाज/राजव्यवस्था: जनजातीय समुदाय; PVTG; PM-JANMAN; DA-JGUA; PESA 1996; FRA 2006; बिरसा मुंडा; पाँचवीं अनुसूची
- Prelims: PM-JANMAN नवंबर 2023 में लॉन्च; PVTG = 75 समुदाय, 18 राज्य; ₹24,104 करोड़; DA-JGUA = धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान; धरती आबा = बिरसा मुंडा की उपाधि

SUMAN रोडमैप 2030 – मातृ और नवजात देखभाल में तेजी

मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'SUMAN रोडमैप 2030 – देखभाल की निरंतरता में तेजी लाना' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। SUMAN = सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। SUMAN एक सरकारी पहल है जो सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात शिशु को मुफ्त, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देती है। SUMAN रोडमैप 2030 देखभाल की निरंतरता में तेजी लाता है – यह सुनिश्चित करना कि एक महिला को गर्भावस्था से प्रसव पूर्व देखभाल → संस्थागत प्रसव → प्रसवोत्तर देखभाल → नवजात देखभाल तक जुड़ी, निर्बाध स्वास्थ्य सेवा मिले। भारत का MMR 254 (2004-06) से 97 (2018-20) तक कम हुआ – SDG लक्ष्य 2030 तक 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म के लिए तेजी की जरूरत है। उच्च-बोझ राज्यों (असम, MP, UP, राजस्थान, ओडिशा) को प्राथमिकता।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
SUMAN	सुरक्षित मातृत्व आश्वासन; सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर हर गर्भवती महिला और बीमार नवजात को मुफ्त, सम्मानजनक, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की गारंटी; सेवाओं से इनकार के प्रति शून्य सहिष्णुता
देखभाल की निरंतरता	निर्बाध स्वास्थ्य सेवा यात्रा: गर्भपूर्व → प्रसव पूर्व → प्रसव → प्रसवोत्तर → नवजात → शिशु → बाल; चरणों के बीच अंतराल = रोकथाम योग्य मौतें; SUMAN रोडमैप 2030 इन अंतरालों को संबोधित करता है
MMR – मातृ मृत्यु अनुपात	प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु; भारत MMR: 254 (2004-06) → 167 (2011-13) → 130 (2014-16) → 113 (2016-18) → 97 (2018-20); SDG लक्ष्य = 2030 तक 70; उच्च MMR राज्य: असम (195), MP (173), UP (167)
LaQshya कार्यक्रम	श्रम कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल; सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में श्रम कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थियेटर में गुणवत्ता सुधार; प्रसव के दौरान रोकथाम योग्य मातृ और नवजात मृत्यु दर कम करता है
जननी सुरक्षा योजना (JSY)	संस्थागत प्रसव के लिए नकद हस्तांतरण; अस्पताल जन्म को घरेलू प्रसव पर बढ़ावा देती है; ~1.13 करोड़ लाभार्थी सालाना; माँग-पक्ष वित्त पोषण

PMSMA	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान; हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त प्रसव पूर्व देखभाल; विशेषज्ञ डॉक्टर परीक्षण; दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को लक्षित
--------------	---

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 स्वास्थ्य: SUMAN; भारत में MMR रुझान; SDG 3 लक्ष्य (2030 तक MMR < 70); JSY; LaQshya; PMSMA; उच्च-बोझ राज्य (असम, MP, UP)
- Prelims: SUMAN = सुरक्षित मातृत्व आश्वासन; भारत MMR = 97 (2018-20); SDG लक्ष्य MMR = 2030 तक 70; NMR = 20 (2020); LaQshya = श्रम कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल

नागरिक विमानन – अहमदाबाद से हब एंड स्पोक अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन

मंत्रालय: नागरिक विमानन मंत्रालय

PIB तिथि: 1 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

नागरिक विमानन मंत्रालय ने अहमदाबाद (सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) से हब एंड स्पोक अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन लॉन्च किया। यह भारत की विमानन वास्तुकला में एक संरचनात्मक बदलाव है: केवल टियर-1 हवाई अड्डों (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता) से बिंदु-से-बिंदु अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बजाय, एयरलाइन अब अहमदाबाद को एक हब के रूप में उपयोग करके छोटे टियर-2/3 शहरों से यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक जोड़ सकती हैं। हब एंड स्पोक मॉडल: राजकोट या सूरत का यात्री अहमदाबाद (स्पोक) के लिए उड़ता है, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर (हब) जुड़ता है। अहमदाबाद की पदोन्नति भारत के कई टियर-2 अंतरराष्ट्रीय हब विकसित करने की योजना को भी दर्शाती है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
हब एंड स्पोक मॉडल	विमानन नेटवर्क मॉडल: कई सीधे मार्गों वाला हब हवाई अड्डा + ट्रेफिक को हब तक फीड करने वाले स्पोक हवाई अड्डे; एयरलाइन के लिए कुशल (उच्च लोड फैक्टर) और यात्रियों के लिए (अधिक गंतव्यों तक संपर्क)

SVPIA – अहमदाबाद	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा; T1 (घरेलू) और T2 (अंतरराष्ट्रीय) टर्मिनल; अडानी एयरपोर्ट्स द्वारा संचालित; भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हवाई अड्डों में; नया ग्रीनफील्ड टर्मिनल निर्माणाधीन
UDAN योजना	उड़े देश का आम नागरिक; क्षेत्रीय संपर्क योजना; असेवित/कम-सेवित हवाई अड्डों के लिए सब्सिडी मार्ग; 500+ मार्ग; हब एंड स्पोक की पूरकता करती है: UDAN क्षेत्रीय फीड ट्रेफिक, हब = अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन
गुजरात की विमानन माँग	GIFT IFSC (गांधीनगर) = अंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र; सूरत = हीरा, वस्त्र, रासायनिक उद्योग; वडोदरा/आनंद = दवा (अमूल मुख्यालय, IIMA); राजकोट = SME विनिर्माण; बड़ा गुजराती NRI समुदाय = अंतरराष्ट्रीय यात्रा माँग
अडानी एयरपोर्ट्स	7 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डे 50-वर्षीय रियायत में संचालित (मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी); हवाई अड्डा बुनियादी ढाँचे में महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र की भूमिका

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढाँचा: हब एंड स्पोक विमानन मॉडल; भारत का हवाई अड्डा बुनियादी ढाँचा; UDAN योजना; अडानी एयरपोर्ट्स; अहमदाबाद की रणनीतिक भूमिका
- Prelims: SVPIA = सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद; UDAN = क्षेत्रीय संपर्क योजना; हब एंड स्पोक = विमानन नेटवर्क मॉडल; अडानी एयरपोर्ट्स 7 प्रमुख हवाई अड्डे संचालित करता है

LESS NOISE. MORE RETENTION.

पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना + प्रति बूंद अधिक फसल

मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

PIB तिथि: 29 अगस्त 2026

सरल भाषा में समझें

PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना): 2016 में लॉन्च, भारत की प्रमुख फसल बीमा योजना। किसान प्रीमियम:

खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, व्यावसायिक/बागवानी फसलों के लिए 5%; सरकार (केंद्र + राज्य बराबर-

बराबर) बाकी देती है। कवरेज: प्राकृतिक आपदाओं, कीट/बीमारी से उपज हानि; बोआई रोकना; कटाई के बाद हानि।

FY2023-24 में: 5.56 करोड़ किसान आवेदन, ₹15,027 करोड़ दावे भुगतान। सुधार: YES-TECH (उपग्रह इमेजरी और फसल कटाई प्रयोगों का उपयोग करके उपज अनुमान प्रणाली); PMFBY अब स्वैच्छिक (2020 तक कर्जदार किसानों के लिए अनिवार्य था)। प्रति बूंद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई): PMKSY (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) का घटक; ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई; 90% सब्सिडी (SC/ST/लघु/सीमांत किसान), 80% अन्य; लक्ष्य: सूक्ष्म-सिंचित क्षेत्र विस्तार; भारत में 220 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई के तहत (लक्ष्य: 260 लाख हेक्टेयर)।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
PMFBY	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना; 2016 लॉन्च; 2% खरीफ/1.5% रबी किसान प्रीमियम; केंद्र+राज्य शेष देते हैं; 5.56 करोड़ आवेदक FY2023-24; ₹15,027 करोड़ दावे; YES-TECH दूर संवेदन-आधारित दावों के लिए
RWBCIS	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना; मौसम सूचकांक (तापमान, वर्षा, आर्द्रता) आधारित – फसल कटाई नहीं; तेज दावा निपटान; PMFBY की पूरक
YES-TECH	प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उपज अनुमान प्रणाली; उपग्रह + ड्रोन + स्मार्टफोन आधारित फसल उपज आकलन; पारंपरिक फसल कटाई प्रयोगों पर निर्भरता कम; तेज, अधिक सटीक दावा निपटान
प्रति बूंद अधिक फसल / PMKSY	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना; 4 घटक: AIBP (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम), हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई), वाटरशेड विकास; ₹93,068 करोड़ (2015-26)
सूक्ष्म सिंचाई लाभ	ड्रिप: 40-50% पानी बचत; 25-35% उपज सुधार; उर्वरक दक्षता (फर्टिगेशन); स्प्रिंकलर: 25-30% पानी बचत; भारत: 220 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचित, चीन के बाद वैश्विक दूसरा

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 कृषि: PMFBY यांत्रिकी; फसल बीमा चुनौतियाँ; YES-TECH नवाचार; प्रति बूंद अधिक फसल; PMKSY घटक; सूक्ष्म सिंचाई लाभ
- Prelims: PMFBY प्रीमियम = 2% खरीफ, 1.5% रबी, 5% व्यावसायिक; YES-TECH = उपग्रह-आधारित उपज अनुमान; PMKSY = 4 घटक; प्रति बूंद अधिक फसल = सूक्ष्म सिंचाई; भारत = 220 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचित

पृष्ठभूमि: भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र

मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय

PIB तिथि: 30 अगस्त 2026

सरल भाषा में समझें

भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र: 1,113 विश्वविद्यालय, 43,796 कॉलेज, 4.3 करोड़ नामांकित छात्र (GER = 28.4%, 2022-23)। भारत संस्थाओं की संख्या के हिसाब से USA और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है। NEP 2020 सुधार: बहु-विषयक शिक्षा, कई निकास बिंदुओं के साथ 4-वर्षीय UG डिग्री, शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC), और शीर्ष-प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं के लिए स्वायत्तता। प्रमुख निकाय: UGC (नियामक, वित्त पोषण), AICTE (तकनीकी शिक्षा), NMC (चिकित्सा शिक्षा), BCI (कानूनी शिक्षा)। राष्ट्रीय रैंकिंग: NIRF (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचा) – 2024: IIT Madras (#1 समग्र 6वें लगातार वर्ष), IISc बेंगलुरु (#1 शोध), AIIMS दिल्ली (#1 चिकित्सा)। चुनौतियाँ: कम GER (वैश्विक औसत ~40% बनाम भारत 28.4%), संकाय कमी, नियोजनीयता अंतर (केवल ~47% स्नातक नियोजनीय)।

SWAYAM ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ABC = NEP 2020 के डिजिटल शिक्षा स्तंभ।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
GER – सकल नामांकन अनुपात	18-23 आयु जनसंख्या के % में नामांकित छात्र; भारत GER = 28.4% (2022-23); NEP 2020 लक्ष्य = 2035 तक 50%; वैश्विक औसत ~40%; कम GER = पहुँच और समानता चुनौती
NEP 2020	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020; 5+3+3+4 स्कूल संरचना; बहु-विषयक उच्च शिक्षा; कई निकास विकल्पों के साथ 4-वर्षीय UG; शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट; मातृभाषा माध्यम; शोध विश्वविद्यालय पर ध्यान

NIRF	राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचा; MoE; HEI की वार्षिक रैंकिंग; श्रेणियाँ: समग्र, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, कानून; IIT Madras = #1 समग्र (2024, 6वाँ वर्ष)
शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)	राष्ट्रीय क्रेडिट ढाँचा; छात्र कई संस्थाओं से क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं; DigiLocker-लिंकड खाते में संग्रहीत; संस्थाओं के बीच क्रेडिट स्थानांतरण; लचीली, बहु-संस्था शिक्षा सक्षम
SWAYAM	युवा आकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षा के अध्ययन जाल; भारत का MOOC (बड़े पैमाने पर ऑनलाइन खुले पाठ्यक्रम) मंच; IITs, IIMs, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम; ~5 करोड़ नामांकन
PM Research Fellowship (PMRF)	शीर्ष BTech स्नातकों का IIT/IISc में सीधे PhD प्रवेश; ₹70,000-80,000/माह वजीफा; 3,000 फेलोशिप; अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ स्नातक प्रतिभा आकर्षित करने का लक्ष्य

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 शिक्षा: भारत का उच्च शिक्षा अवलोकन; NEP 2020 प्रमुख विशेषताएं; UGC, AICTE, NMC, BCI; NIRF रैंकिंग; GER चुनौती; SWAYAM
- Prelims: भारत के विश्वविद्यालय = 1,113; नामांकित छात्र = 4.3 करोड़; GER = 28.4%; NEP 2020 GER लक्ष्य = 2035 तक 50%; NIRF = राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचा; ABC = शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट

LESS NOISE. MORE RETENTION.

पृष्ठभूमि: साइबर-भौतिक प्रणालियाँ

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

PIB तिथि: 31 अगस्त 2026

सरल भाषा में समझें

साइबर-भौतिक प्रणालियाँ (CPS) कम्प्यूटेशनल एल्गोरिदम को भौतिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करती हैं – जहाँ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर भौतिक प्रणालियों की निगरानी और नियंत्रण करते हैं, डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच फीडबैक लूप के साथ। उदाहरण: स्मार्ट पावर ग्रिड (सेंसर + एल्गोरिदम वास्तविक समय में बिजली प्रवाह की निगरानी और

समायोजन), स्वायत्त वाहन (कैमरे + LIDAR + AI एल्गोरिदम भौतिक वाहन नियंत्रित करते हैं), औद्योगिक स्वचालन (Industry 4.0 रोबोट), और परिशुद्धि कृषि (ड्रोन + सेंसर + AI सिंचाई नियंत्रित करते हैं)। CPS IoT से अलग है: IoT = 'इंटरनेट से जुड़ी चीजें'; CPS = 'वास्तविक समय नियंत्रण के साथ कम्प्यूटेशन और भौतिक प्रक्रिया का घनिष्ठ एकीकरण।' भारत का NM-ICPS: DST पहल, ₹3,660 करोड़, IIT और अन्य संस्थाओं में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (TiH)।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
साइबर-भौतिक प्रणालियाँ (CPS)	कम्प्यूटेशनल एल्गोरिदम का भौतिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकरण; डिजिटल और भौतिक के बीच फीडबैक; वास्तविक समय नियंत्रण; उदाहरण: स्मार्ट ग्रिड, स्वायत्त वाहन, Industry 4.0 रोबोटिक्स
NM-ICPS	अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन; DST; ₹3,660 करोड़; IITs + अन्य संस्थाओं में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र; थीम: AI, रोबोटिक्स, IoT, क्वांटम, ब्लॉकचेन, स्मार्ट विनिर्माण
प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (TiH)	NM-ICPS के तहत IIT में बनाए गए; प्रत्येक TiH का विशिष्ट फोकस (AI-TiH IIT खड़गपुर, रोबोटिक्स के लिए CoE IIT कानपुर); उद्योग-अकादमी इंटरफेस; स्टार्टअप ऊष्मायन; ज्ञान अनुवाद
Industry 4.0	चौथी औद्योगिक क्रांति; साइबर-भौतिक उत्पादन प्रणालियाँ; विनिर्माण में IoT, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग; डिजिटल ट्विन; योगात्मक विनिर्माण (3D प्रिंटिंग); भारत का NM-ICPS + PLI = Industry 4.0 धक्का
डिजिटल ट्विन	एक भौतिक प्रणाली की आभासी प्रतिकृति जो भौतिक प्रणाली से वास्तविक समय डेटा प्राप्त करती है; निगरानी, सिमुलेशन, भविष्यसूचक रखरखाव के लिए; विनिर्माण, बुनियादी ढाँचा प्रबंधन में प्रमुख CPS अनुप्रयोग
SCADA प्रणालियाँ	सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन; बिजली संयंत्र, जल उपचार, तेल/गैस पाइपलाइन के लिए औद्योगिक CPS; महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा; SCADA में साइबर सुरक्षा भेद्यता = राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान/प्रौद्योगिकी: CPS परिभाषा; NM-ICPS; TiH; Industry 4.0; डिजिटल ट्विन; SCADA सुरक्षा; भारत के प्रौद्योगिकी मिशन परिदृश्य
- Prelims: NM-ICPS = अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन; DST; ₹3,660 करोड़; 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र; CPS = साइबर-भौतिक प्रणालियाँ; SCADA = सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन

पृष्ठभूमि: भूतापीय ऊर्जा

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय / नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

PIB तिथि: 4 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप का उपयोग करती है – जो मैटल और कोर में यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होती है। तीन मुख्य उपयोग: बिजली उत्पादन (उच्च-तापमान $>150^{\circ}\text{C}$ – आइसलैंड, USA, फिलीपींस, केन्या); प्रत्यक्ष उपयोग ($20-150^{\circ}\text{C}$ – अंतरिक्ष हीटिंग, ग्रीनहाउस वार्मिंग); और भूतापीय ताप पंप ($<20^{\circ}\text{C}$ – भवन हीटिंग/कूलिंग)। भारत की भूतापीय क्षमता: अनुमानित 10,600 MW लेकिन काफी हद तक अप्रयुक्त। भारत में 340+ गर्म झरने स्थान (सात भूतापीय प्रांत): हिमालय (पुगा घाटी, लद्दाख – उच्चतम क्षमता), Cambay (गुजरात), गोदावरी बेसिन, महानदी, पश्चिमी तट, सोन-नर्मदा, अंडमान-निकोबार। पुगा घाटी, लद्दाख में उथली गहराई पर 84°C तापमान है – बिजली के लिए व्यावहारिक। ONGC ने खोजी काम किया है। भारत ने इसे क्यों नहीं अपनाया: लागत, कठिन इलाका, ग्रिड संपर्क, सक्षम नीति की कमी।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
भूतापीय ऊर्जा	पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप; मैटल में U/Th/K का रेडियोधर्मी क्षय + आदिम ताप; तीन उपयोग: बिजली ($>150^{\circ}\text{C}$), प्रत्यक्ष उपयोग ($20-150^{\circ}\text{C}$), ताप पंप ($<20^{\circ}\text{C}$); नवीकरणीय, बेसलोड (सौर/पवन के विपरीत)
भारत की भूतापीय क्षमता	~10,600 MW अनुमानित; 340+ गर्म झरने; 7 भूतापीय प्रांत: हिमालय (पुगा), Cambay, गोदावरी, महानदी, पश्चिमी तट, सोन-नर्मदा, अंडमान-निकोबार; काफी हद तक अप्रयुक्त

पुगा घाटी, लद्दाख	भारत का उच्चतम भूतापीय क्षमता क्षेत्र; उथली गहराई पर 84-100°C तापमान; ONGC खोजी काम; पायलट बिजली परियोजना प्रस्तावित; दूरस्थ स्थान = ग्रिड संपर्क चुनौती; सामरिक महत्व (सीमा क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा)
Enhanced Geothermal Systems (EGS)	गर्म शुष्क चट्टान से भूतापीय ऊर्जा निकालने की प्रौद्योगिकी; हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग दरारें बनाता है → पानी इंजेक्ट → भाप निकाली जाती है; अभी तक व्यावसायिक नहीं; USA, EU निवेश कर रहे हैं
भूतापीय बनाम अन्य नवीकरणीय	फायदे: बेसलोड (24x7), छोटा भूमि क्षेत्र, कम पानी उपयोग (बंद लूप); नुकसान: उच्च अग्रिम लागत, स्थान-विशिष्ट, भूकंपीय जोखिम (EGS); सौर/पवन के गैर-अंतराल पूरक
वैश्विक नेता	आइसलैंड: 25% बिजली भूतापीय से (ज्वालामुखी द्वीप); केन्या: 46% भूतापीय बिजली; USA: सबसे बड़ा भूतापीय उत्पादक (3,676 MW); फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड भी महत्वपूर्ण; भारत वैश्विक नेताओं में अनुपस्थित

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 ऊर्जा/पर्यावरण: भूतापीय ऊर्जा के प्रकार; भारत की क्षमता (पुगा घाटी, 7 प्रांत); अप्रयुक्त क्यों; EGS; सौर/पवन से तुलना; NEP 2023
- Prelims: भूतापीय ऊर्जा = पृथ्वी के आंतरिक भाग की ताप; पुगा घाटी = भारत में उच्चतम क्षमता; ONGC = खोजी काम; आइसलैंड = 25% भूतापीय बिजली; केन्या = 46%; भारत में 7 भूतापीय प्रांत; EGS = Enhanced Geothermal Systems

पृष्ठभूमि: सहकारी क्षेत्र में विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना

मंत्रालय: सहयोग मंत्रालय / उपभोक्ता कार्य मंत्रालय

PIB तिथि: 3 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

सहकारी क्षेत्र में विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना दुनिया के सबसे बड़े खाद्य भंडारण बुनियादी ढाँचा कार्यक्रमों में से एक है – भारत देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) स्तर पर अनाज भंडारण क्षमता का निर्माण कर रहा है। पैमाना: ~2 लाख PACS के माध्यम से 5 वर्षों में 700 लाख मीट्रिक टन (LMT) अतिरिक्त भंडारण क्षमता। वर्तमान में भारत की ~85% अनाज भंडारण क्षमता FCI (खाद्य निगम) गोदामों में केंद्रित है। PACS-स्तरीय भंडारण का अर्थ है किसान: स्थानीय रूप से तुरंत अनाज भंडारित कर सकते हैं; संकटपूर्ण बिक्री से बच सकते हैं; वेयरहाउस रसीद-आधारित ऋण प्राप्त कर सकते हैं (अनाज संपार्श्विक के रूप में); और कीमतें बेहतर होने पर बेच सकते हैं। सहकारी क्षेत्र का पहलू: PACS → जिला सहकारी बैंक → राज्य सहकारी बैंक = भारत की ग्रामीण सहकारी ऋण श्रृंखला; PACS में भंडारण = ऋण + भंडारण + विपणन का अभिसरण।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
PACS	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ; ग्राम-स्तरीय सहकारी ऋण संस्थाएं; ~1.02 लाख PACS भारत में; सदस्य = किसान; अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करती हैं; PACS कम्प्यूटरीकरण = हाल का सुधार; अब भंडारण कार्य जोड़ रहे हैं
विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण	प्रमुख मंडियों में केंद्रीकृत के बजाय उत्पादन/गाँव स्तर पर भंडारण; फसल के बाद की हानि कम (भारत में ~10-15%), संकटपूर्ण बिक्री, परिवहन लागत; किसानों को लाभ: मूल्य वसूली, MSP सुरक्षा
FCI	खाद्य निगम; केंद्र सरकार की अनाज खरीद, भंडारण और वितरण एजेंसी; ~700 LMT भंडारण क्षमता; केंद्रीय पूल (गेहूं, चावल); PDS वितरण; केंद्रीकृत भंडारण = रसद चुनौती
वेयरहाउस रसीद प्रणाली	किसान पंजीकृत गोदाम में अनाज जमा करता है → वेयरहाउस रसीद मिलती है → बैंक ऋण के लिए रसीद संपार्श्विक के रूप में उपयोग; अनुकूल कीमत पर बेच सकता है; WDRA विनियमित करता है
फसल के बाद की हानि	भारत की कुल फसल के बाद की हानि = ~₹90,000 करोड़ सालाना; अनाज भंडारण हानि ~6-7%; फल/सब्जी हानि बहुत अधिक (~40%); अपर्याप्त शीत श्रृंखला और भंडारण = प्रमुख कृषि अक्षमता

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस	सहयोग मंत्रालय (नया मंत्रालय, 2021); सहकार मित्र पोर्टल; PACS ऑडिट; PACS + जिला सहकारी बैंक + राज्य सहकारी बैंक = ग्रामीण सहकारी ऋण श्रृंखला; विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण = नए सहयोग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम
--------------------------	--

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 कृषि/अर्थव्यवस्था: PACS; विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण; फसल के बाद की हानि; वेयरहाउस रसीद; FCI; WDRA; सहयोग मंत्रालय
- Prelims: PACS = प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ; ~1.02 लाख PACS; FCI = खाद्य निगम; WDRA = भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण; NABARD PACS को वित्त पोषण करता है

पृष्ठभूमि: निर्यात केंद्र के रूप में जिले

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / DGFT

PIB तिथि: 2 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' (DEH) पहल – 2020 में विदेश व्यापार नीति ढाँचे के तहत लॉन्च – प्रत्येक जिले में निर्यात-योग्य उत्पादों और सेवाओं की पहचान करने और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य रखती है। भारत के निर्यात अत्यधिक केंद्रित हैं: शीर्ष 5 बंदरगाह (JNPT, मुंद्रा, चेन्नई, विजाग, कोलकाता) ~85% निर्यात कार्गो संभालते हैं; शीर्ष 5 राज्य (महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश) ~65% वस्तु निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। DEH हर जिले से निर्यात क्षमता खोलना चाहता है – विशेष रूप से विनिर्माण समूहों (मुरादाबाद का पीतल, तिरुपुर की बुनाई, आगरा का जूता, फिरोजाबाद का कांच, जोधपुर का हस्तशिल्प) और GI-टैग उत्पादों में। तंत्र: जिला निर्यात कार्य योजना (DEAP) – जिला-स्तरीय समिति शीर्ष 3-5 निर्यात उत्पाद/सेवाएं पहचानती है; बुनियादी ढाँचा कमियाँ मानचित्रण; लक्षित समर्थन।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
-----------	---------

निर्यात केंद्र के रूप में जिले (DEH)	FTP 2023 पहल; प्रत्येक जिला शीर्ष निर्यात उत्पाद/सेवाएं पहचानता है; जिला निर्यात कार्य योजना (DEAP); जिला-स्तरीय कार्यान्वयन समिति; DGFT + निर्यात संवर्धन परिषद; भौगोलिक निर्यात एकाग्रता खोलना
DEAP	जिला निर्यात कार्य योजना; प्रति जिला शीर्ष 3-5 निर्यात उत्पाद/सेवाएं; अंतर विश्लेषण (बुनियादी ढाँचा, प्रमाणीकरण, रसद); DIC (जिला उद्योग केंद्र) + DGFT द्वारा कार्यान्वित
निर्यात की भौगोलिक एकाग्रता	शीर्ष 5 बंदरगाह ~85% निर्यात कार्गो संभालते हैं; शीर्ष 5 राज्य = ~65% वस्तु निर्यात; DEH आंतरिक जिलों को निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र में लाने का लक्ष्य; जिला स्तर पर 'आत्मनिर्भर भारत'
GI टैग और जिला निर्यात	भौगोलिक संकेत (GI) स्थानीय उत्पादों की रक्षा करते हैं; भारत के पास 400+ GI टैग; दार्जिलिंग चाय, कोल्हापुरी चप्पल, कांचीपुरम सिल्क, बनारस ब्रोकेड; DEH GI उत्पादों को प्रीमियम निर्यात बाजारों के लिए लाभ उठाता है
निर्यात संवर्धन परिषद (EPC)	DGFT/MoC के अंतर्गत क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात संवर्धन निकाय; APEDA (कृषि), MPEDA (समुद्री), EEPC (इंजीनियरिंग), FIEO (छाता निकाय); 26 EPC; जिला निर्यातकों को वैश्विक बाजारों से जोड़ते हैं
भारत का \$2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य	\$1 ट्रिलियन वस्तु + \$1 ट्रिलियन सेवाएं 2030 तक; FY2024-25 = ~\$820 अरब (वस्तु + सेवाएं); महत्वपूर्ण अंतर; DEH = भौगोलिक रूप से निर्यात आधार विस्तार की रणनीति

LESS NOISE. MORE RETENTION.

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था: निर्यात केंद्र के रूप में जिले; विदेश व्यापार नीति 2023; DEAP; निर्यात की भौगोलिक एकाग्रता; GI टैग; EPC; भारत का \$2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य
- Prelims: DEH = निर्यात केंद्र के रूप में जिले; DEAP = जिला निर्यात कार्य योजना; DGFT = विदेश व्यापार महानिदेशालय; FIEO = भारतीय निर्यात संगठन महासंघ; One District One Product (ODOP) जोड़ता है

पृष्ठभूमि: Q1 FY2026-27 GDP अनुमान को समझना

मंत्रालय: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

PIB तिथि: 2 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत की Q1 FY2026-27 (अप्रैल-जून 2026) GDP 7.8% बढ़ी – छह तिमाहियों में सबसे तेज। क्षेत्रीय विभाजन (GVA): कृषि ~3.5%; उद्योग: विनिर्माण 7.2%, निर्माण 10.1% (सरकारी पूँजी व्यय संचालित), खनन 4.8%; सेवाएं: वित्तीय, अचल संपत्ति, और पेशेवर सेवाएं 8.5%, व्यापार, होटल, परिवहन 7.8%, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा 6.2%। वैश्विक संदर्भ में 7.8% का अर्थ: भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था; चीन 4.7%, USA 2.1%, EU 1.3%, जापान 0.8%। निवेश पहलू: सकल स्थिर पूँजी निर्माण (GFCF) 9.5% बढ़ा – मजबूत निवेश गतिविधि का संकेत। उपभोग पहलू: निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) 7.1% बढ़ा। सतर्कता: भारत की GDP पद्धति = 2011-12 को आधार वर्ष मानकर बाजार मूल्य पर GDP; अग्रिम/प्रथम अनुमान अक्सर महत्वपूर्ण रूप से संशोधित होते हैं।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
GDP 7.8% Q1 FY26-27	अप्रैल-जून 2026; छह तिमाहियों में सबसे तेज; FY25-26 पूर्ण वर्ष (6.4%) से ऊपर; MoSPI जारी; आधार वर्ष 2011-12; बाजार मूल्य पर GDP
GVA – सकल मूल्य वर्धन	क्षेत्र-वार आर्थिक उत्पादन; कृषि ~3.5%, विनिर्माण 7.2%, निर्माण 10.1%, सेवाएं 7-8%; GDP = GVA + उत्पाद कर - उत्पाद सब्सिडी
GFCF – सकल स्थिर पूँजी निर्माण	अचल संपत्तियों (मशीनरी, भवन, बुनियादी ढाँचा) में निवेश; Q1 FY26-27 GFCF 9.5% बढ़ा; सरकारी पूँजी व्यय + निजी निवेश शामिल; उच्च GFCF = भविष्य उत्पादक क्षमता निर्माण
PFCE – निजी अंतिम उपभोग व्यय	घरेलू खर्च; Q1 FY26-27 PFCE 7.1% बढ़ा; शहरी उपभोग मजबूत; ग्रामीण उपभोग धीरे-धीरे सुधर रहा; PFCE = सबसे बड़ा GDP घटक (~60%)

भारत बनाम वैश्विक विकास	भारत 7.8% बनाम चीन 4.7%, USA 2.1%, EU 1.3%, जापान 0.8%; भारत = सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था; जनसांख्यिकीय लाभांश, विनिर्माण PLI, सेवा निर्यात
GDP अनुमान पद्धति	उत्पादन पद्धति (GVA दृष्टिकोण): क्षेत्र-वार उत्पादन; व्यय पद्धति (C+I+G+NX): उपभोग + निवेश + सरकार + शुद्ध निर्यात; भारत दोनों का उपयोग करता है; आधार वर्ष 2011-12

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था: GDP पद्धति (GVA, व्यय विधि); क्षेत्रीय विभाजन; GFCF; PFCE; भारत का Q1 FY26-27 विकास कहानी; भारत बनाम वैश्विक तुलना
- Prelims: GDP आधार वर्ष = 2011-12; GFCF = सकल स्थिर पूँजी निर्माण; PFCE = निजी अंतिम उपभोग व्यय; GVA + शुद्ध उत्पाद कर = GDP; MoSPI GDP डेटा जारी करता है

SITOK IAS
LESS NOISE. MORE RETENTION.

सम्माननीय उल्लेख

वे तथ्य जो मुख्य लेखों में नहीं आए – लेकिन UPSC Prelims में सीधे पूछे जाते हैं।

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
RAKSHA दस्तावेज़	भारत का पहला औपचारिक रक्षा कूटनीति ढाँचा; 10-वर्षीय दृष्टि; रक्षा निर्यात, सह-विकास; सितंबर 2026 जारी	GS3 रक्षा; DPEPP 2020; \$5 अरब निर्यात लक्ष्य; भारत आयातक से रणनीतिक साझेदार बन रहा है; आत्मनिर्भर भारत रक्षा
भारत-बेल्जियम रक्षा	सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए द्विपक्षीय आह्वान; NATO/EU केंद्र (ब्रसेल्स); FN Herstal, Safran Belgium	GS2 IR + GS3 रक्षा; सह-उत्पादन मॉडल; RAKSHA ढाँचा व्यवहार में; बेल्जियम = NATO मुख्यालय + EU संस्थागत केंद्र
16वाँ एयरो इंडिया 2027	येलहंका, बेंगलुरु; 8-12 फरवरी 2027; एशिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस प्रदर्शनी; द्विवार्षिक; मेक इन इंडिया + रक्षा निर्यात प्रदर्शन	GS3 रक्षा; DPEPP 2020 कार्यान्वयन वाहन; iDEX; एयरो इंडिया 2025 में ₹1 लाख करोड़ के MoU
INS सुदर्शिनी – LOKAYAN 2026	नौपरिवहन प्रशिक्षण जहाज (बाक्वेटोन); बार्सिलोना, स्पेन पहुँचा; LOKAYAN = 'लोक' + 'यान'; नौसैनिक कूटनीति	GS3 रक्षा; INS सुदर्शिनी 2012 में कमीशन, कोच्चि आधारित; नरम शक्ति के रूप में पाल जहाज; LOKAYAN = भारतीय नौसेना की सद्भावना तैनाती
PM उज़्बेकिस्तान यात्रा	'ओली दाराजली दोस्तलिक' आदेश; INSTC, चाबहार, दवा, IT परिणाम; UPI उज़्बेकिस्तान में UZQR के माध्यम से	GS2 IR; भारत-उज़्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2022; INSTC; ताशकंद घोषणा 1966; NPCI International

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
26वाँ SCO शिखर, बिश्केक	भारत का रूस, किर्गिज़, आर्मेनिया, ईरान के साथ द्विपक्षीय; SCO = 9 पूर्ण सदस्य; RATS = ताशकंद	GS2 IR; SCO पूर्ण सदस्य; भारत 2017 से; सचिवालय बीजिंग; RATS (आतंकवाद-रोधी); भारत-आर्मेनिया पिनाका MBRL सौदा
भारत-चिली CEPA	वार्ता आगे बढ़ी; चिली = दुनिया का सबसे बड़ा ताँबा + लिथियम उत्पादक; लिथियम त्रिभुज (चिली+अर्जेंटीना+बोलीविया)	GS2 IR + GS3 अर्थव्यवस्था; CEPA = दक्षिण अमेरिका में पहला; महत्वपूर्ण खनिज; अटाकामा = 42% विश्व लिथियम
भारत GDP Q1 FY26-27	7.8% वृद्धि; छह तिमाहियों में सबसे तेज; विनिर्माण 7.2%, निर्माण 10.1%; GFCF 9.5%; PFCE 7.1%	GS3 अर्थव्यवस्था; GDP पद्धति; आधार वर्ष 2011-12; भारत = सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था; चीन उसी अवधि में 4.7%
भारत साख रेटिंग – JCR	जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत को A- (स्थिर परिदृश्य) तक उन्नत; किसी भी प्रमुख CRA से पहली 'A' श्रेणी	GS3 अर्थव्यवस्था; संप्रभु साख रेटिंग; 'बिग थ्री' अभी भी BBB; JCR = जापानी संस्थागत निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण; राजकोषीय समेकन पथ
GIFT IFSC	\$52.8 अरब FCNR(B); \$11.62 अरब ECB; \$11.12 अरब बॉन्ड; विमान पट्टा केंद्र उभर रहा है; IFSCA द्वारा विनियमित	GS3 अर्थव्यवस्था; GIFT IFSC = गांधीनगर; IFSCA = एकीकृत नियामक (2020); FCNR(B) = NRI विदेशी मुद्रा जमा
NLMC – RINL भूमि नीलामी	459 RINL (विजाग स्टील) भूमि पार्सल ई-नीलाम; NLMC CPSE भूमि मुद्रीकरण करता है; DIPAM पर्यवेक्षण	GS3 अर्थव्यवस्था; NLMC = राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (2022); RINL घाटा ₹16,000+ करोड़; रणनीतिक विनिवेश रुका

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
GSLV-F17 / EOS-05	GSLV-F17 ने EOS-05 GTO में स्थापित; क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (CE-20); GSLV = मध्यम-उठान (GTO को 2.5T)	GS3 विज्ञान; GSLV बनाम LVM3 (भारी उठान); क्रायोजेनिक चरण विकास इतिहास (1990 के दशक में रूस का इनकार); EOS = ISRO की पृथ्वी अवलोकन श्रृंखला
C-DOT क्वांटम उत्पाद	14 स्वदेशी क्वांटम उत्पाद; QKD, QRNG, क्वांटम-सुरक्षित संचार; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (₹6,003 करोड़, 2023-31)	GS3 विज्ञान; QKD = क्वांटम कुंजी वितरण; क्वांटम के बाद क्रिप्टोग्राफी; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 4 थीम; 'अभी हार्वेस्ट करो बाद में डिक्क्रिप्ट करो' खतरा
ऊष्मा-विद्युत सफलता	Seebeck प्रभाव की सदी-पुरानी सीमा पार; ZT आकृति of merit; अति-संवेदनशील तापमान संवेदन	GS3 विज्ञान; Seebeck प्रभाव; ऊष्मा-विद्युत सामग्री (Bi_2Te_3); अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति; $ZT = S^2\sigma T/\kappa$
IST नियम 2026	विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम 2026; एक राष्ट्र एक समय; NPL के साथ NTP समकालीकरण	GS2/GS3; IST = UTC+5:30; 82.5°E मिर्ज़ापुर; NPL = भारत का प्राथमिक समय मानक; विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009; NTP
CSIR-CRRI RAP प्रौद्योगिकी	NH-716 पर 60% पुनर्नवीनीकृत डामर फुटपाथ; भारत वर्तमान में 10-20% RAP उपयोग करता है; बिटुमेन (पेट्रोलियम) उपयोग कम करता है	GS3 पर्यावरण/बुनियादी ढाँचा; CSIR-CRRI = केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान; हरित राजमार्ग नीति 2015; निर्माण में चक्रीय अर्थव्यवस्था
BIO-NIVESH	जैव-प्रौद्योगिकी निवेश प्रेरित करने का मंच; BIRAC + DBT निवेशकों के साथ इंटरफेस; भारत जैव-प्रौद्योगिकी = \$130 अरब, 2030 लक्ष्य \$300 अरब	GS3 विज्ञान/अर्थव्यवस्था; BIRAC = जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद; भारत = दुनिया का सबसे बड़ा बायोसिमिलर उत्पादक; BioE3 नीति 2024

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
आणविक स्विच – जैव-सामग्री	लघु आणविक स्विच स्व-संचालित स्वास्थ्य सेवा जैव-सामग्री सक्षम करता है; पीजोइलेक्ट्रिक (गति→विद्युत); शरीर की गर्मी → पहनने योग्य सेंसर को शक्ति	GS3 विज्ञान; पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव; स्मार्ट जैव-सामग्री; ANRF (₹50,000 करोड़); ABDM संबंध; स्व-संचालित प्रत्यारोपण
शून्य-उत्सर्जन शिपिंग	बंदरगाह मंत्रालय: शून्य-उत्सर्जन शिपिंग गलियारे; हरित ईंधन (अमोनिया, मेथनॉल, LNG, H ₂); IMO GHG रणनीति 2023 लक्ष्य	GS3 पर्यावरण; IMO = अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन; IMO 2023 = 2050 तक शुद्ध-शून्य; सागरमाला; JNPT = भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह
एजेंटिक AI कौशल	NIELIT + Intel India एजेंटिक AI कौशल कार्यक्रम लॉन्च; एजेंटिक AI = स्वायत्त बहु-चरणीय AI	GS3 विज्ञान; NIELIT = राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT संस्थान; IndiaAI मिशन (₹10,372 करोड़); NPU = न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट
स्वच्छ सागर 2026	5वाँ संस्करण; महासागर संरक्षण आंदोलन; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण; SDG 14 (समुद्री जीवन)	GS3 पर्यावरण; भारत नदियाँ = 0.4MT प्लास्टिक/वर्ष; वैश्विक प्लास्टिक संधि INC; गहरे महासागर मिशन ₹4,077 करोड़; INCOIS
बाघ परिदृश्य कार्यशाला	संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी पर्यटन; भारत 3,682 बाघ (2022) = 70% विश्व; 54 बाघ अभयारण्य; NTCA पर्यवेक्षण	GS3 पर्यावरण; Project Tiger (1973); NTCA; M-STrIPES निगरानी; बाघ वनों से कार्बन क्रेडिट; मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान
GLOF तैयारी समीक्षा	गृह सचिव ने हिमालयी राज्यों की GLOF और हिमस्खलन समीक्षा; चमोली 2021, Lhonak 2023 = हाल की प्रमुख GLOF	GS3 आपदा प्रबंधन; GLOF = हिमनदी झील विस्फोट बाढ़; NDMA; NDRF; SASE (DRDO) हिमस्खलन के लिए; NRSC उपग्रह निगरानी

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
भारत-जर्मन पर्यावरण फोरम	4थाँ संस्करण; KfW, GIZ द्विपक्षीय सहयोग; हरित हाइड्रोजन (भारत NGHM जर्मनी आयातक); Energiewende सबक	GS2 IR + GS3; KfW = जर्मनी का विकास बैंक; GIZ = जर्मनी की विकास एजेंसी; NGHM = ₹17,490 करोड़; CBAM चिंता
NCAHP – 33 नई डिग्री	UGC ने NCAHP ढाँचे के तहत 33 नई डिग्री अधिसूचित; संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर; भारत में ~1.2 AHP प्रति डॉक्टर बनाम USA में ~6	GS2 स्वास्थ्य; NCAHP अधिनियम 2021; UGC; संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसाय (फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, प्रयोगशाला तकनीशियन); भारत की स्वास्थ्य सेवा कार्यबल कमी
मिशन रंगीन मछली 2031	सजावटी मत्स्य पालन के लिए रणनीतिक कार्ययोजना; 2031 तक \$500 मिलियन निर्यात लक्ष्य; वैश्विक सजावटी मछली व्यापार = \$15-20 अरब	GS3 अर्थव्यवस्था; PMMSY (₹20,050 करोड़); MPEDA; भारत का वर्तमान सजावटी निर्यात = केवल \$20-25 मिलियन
PM-JANMAN + DA-JGUA	PM-JANMAN = PVTG (75 समुदाय, 18 राज्य), ₹24,104 करोड़; DA-JGUA = धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ₹79,156 करोड़	GS2 समाज/राजव्यवस्था; PVTG; बिरसा मुंडा (धरती आबा); PESA 1996; FRA 2006; PM-JANMAN 15 नवंबर 2023 लॉन्च (जनजातीय गौरव दिवस)
SUMAN रोडमैप 2030	सुरक्षित मातृत्व आश्वासन; मातृ और नवजात स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता; भारत MMR = 97 (2018-20); SDG लक्ष्य = 70	GS2 स्वास्थ्य; MMR रुझान; LaQshya; JSY; PMSMA; उच्च-बोझ राज्य: असम (195), MP (173), UP (167)
हब & स्पोक – अहमदाबाद	SVPIA (अहमदाबाद) से अंतरराष्ट्रीय हब और स्पोक उड़ानें; अडानी एयरपोर्ट्स; UDAN योजना क्षेत्रीय फीड	GS3 अर्थव्यवस्था; UDAN = क्षेत्रीय संपर्क योजना; हब और स्पोक मॉडल; अडानी एयरपोर्ट्स = 7 प्रमुख हवाई

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
		अड्डे; भारत = 3रा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार



SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

अभ्यास प्रश्न

10 Prelims प्रश्न – UPSC शैली

प्र.1. भारत की संप्रभु साख रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (JCR) ने भारत की रेटिंग 'A-' तक उन्नत की – किसी भी प्रमुख CRA से पहली बार 'A' श्रेणी।
2. 'बिग थ्री' साख रेटिंग एजेंसियाँ (Moody's, Fitch, S&P) वर्तमान में भारत को 'A' श्रेणी में रेट करती हैं।
3. 'BBB' रेटिंग मानक रेटिंग स्केल पर न्यूनतम निवेश श्रेणी रेटिंग का प्रतिनिधित्व करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

प्र.2. अभिकथन (A): भारत शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में सक्रिय रूप से भाग लेता है, बावजूद इसके कि चीन और पाकिस्तान भी पूर्ण सदस्य हैं।

कारण (R): भारत SCO का उपयोग मुख्यतः रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ने, संपर्क और आतंकवाद-रोधी सहयोग के लिए करता है – अपनी बहु-संरक्षण नीति के भाग के रूप में।

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
- (b) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
- (c) A सही है लेकिन R गलत है
- (d) A गलत है लेकिन R सही है

प्र.3. भारत के भूतापीय प्रांतों को उनके राज्यों/क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए:

सूची I (भूतापीय प्रांत) सूची II (राज्य/क्षेत्र)

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. पुगा घाटी | P. गुजरात |
| 2. Cambay | Q. लद्दाख |
| 3. सोन-नर्मदा | R. मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ |
| 4. पश्चिमी तट | S. कर्नाटक / गोवा / केरल |

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) 1-Q, 2-P, 3-R, 4-S
 (b) 1-P, 2-Q, 3-S, 4-R
 (c) 1-Q, 2-S, 3-P, 4-R
 (d) 1-R, 2-P, 3-Q, 4-S

प्र.4. PM-JANMAN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह 18 राज्यों में 75 अति संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTG) को लक्षित करता है।
2. इसे जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) पर लॉन्च किया गया, जो बिरसा मुंडा की जन्म वर्षगांठ है।
3. PM-JANMAN के तहत वित्तीय परिव्यय 3 वर्षों में ₹79,156 करोड़ है।
4. DA-JGUA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) केवल PVTG से परे जनजातीय समुदायों की व्यापक श्रृंखला को कवर करता है।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
 (b) केवल दो
 (c) केवल तीन
 (d) सभी चार

SITOK IAS
 LESS NOISE. MORE RETENTION.

प्र.5. हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. फरवरी 2021 की चमोली आपदा एक GLOF के कारण हुई थी जिसने उत्तराखंड में Rishiganga और Dhauliganga जलविद्युत परियोजनाओं को क्षतिग्रस्त किया।
2. अक्टूबर 2023 के South Lhonak Lake GLOF ने Teesta नदी में बाढ़ और Teesta-III बाँध को क्षति पहुँचाई।
3. DRDO का हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (SASE) भारत में GLOF प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का नोडल एजेंसी है।

4. GLOF जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पीछे हटने के कारण मुख्यतः आवृत्ति में बढ़ रही हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1 और 2

(d) 1, 2, 3 और 4

प्र.6. निम्नलिखित क्वांटम प्रौद्योगिकी उत्पादों/अवधारणाओं को उनके सही विवरणों से सुमेलित कीजिए:

सूची I

सूची II

1. QKD

P. क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों के लिए वास्तविक यादृच्छिक संख्याएं उत्पन्न करने

के लिए क्वांटम घटनाओं का उपयोग

2. QRNG

Q. एन्क्रिप्शन कुंजी वितरित करने के लिए क्वांटम गुणों का उपयोग ताकि

कोई भी अवरोधन पता लगाया जा सके

3. क्वांटम के बाद क्रिप्टोग्राफी

R. क्वांटम कंप्यूटर हमलों के प्रति सुरक्षित एल्गोरिदम

4. अभी हार्वेस्ट करो, बाद में डिक्रिप्ट करो

S. भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर से डिक्रिप्ट करने के लिए आज एन्क्रिप्टेड

डेटा एकत्र करने की रणनीति

(a) 1-Q, 2-P, 3-R, 4-S

(b) 1-P, 2-Q, 3-S, 4-R

(c) 1-R, 2-S, 3-Q, 4-P

(d) 1-Q, 2-R, 3-P, 4-S

SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

प्र.7. भारत-उज़्बेकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2022 में अपने द्विपक्षीय संबंध को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया।

2. 'ओली दाराजली दोस्तलिक' आदेश उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

3. अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है।

4. ताशकंद घोषणा 1966 भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर हस्ताक्षरित हुई थी।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

प्र.8. अभिकथन (A): CSIR-CRRI का 60% पुनर्नवीनीकृत डामर फुटपाथ (RAP) प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन भारत के सड़क निर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

कारण (R): भारत वर्तमान में सड़क निर्माण में केवल 10-20% RAP का उपयोग करता है, जबकि बिटुमेन – जो इसे प्रतिस्थापित करता है – महंगा और कार्बन-गहन पेट्रोलियम-व्युत्पन्न सामग्री है, भारत अपनी लगभग 45% बिटुमेन आवश्यकताएं आयात करता है।

- (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
- (b) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
- (c) A सही है लेकिन R गलत है
- (d) A गलत है लेकिन R सही है

प्र.9. GIFT IFSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. GIFT IFSC भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, जो गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
2. IFSCA GIFT IFSC के लिए एकीकृत नियामक के रूप में काम करता है, IFSC गतिविधियों के लिए RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA की अलग-अलग नियामक भूमिकाओं को प्रतिस्थापित करता है।
3. FCNR(B) जमा NRI द्वारा किए गए रुपया-मूल्यवर्गित सावधि जमा हैं।
4. विमान पट्टा GIFT IFSC पर अनुमत वित्तीय गतिविधियों में से एक है।

ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

प्र.10. भारत की Q1 FY2026-27 GDP वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. Q1 FY2026-27 में 7.8% की GDP वृद्धि छह तिमाहियों में सबसे तेज थी।
2. निर्माण क्षेत्र ने 10.1% की वृद्धि दर्ज की – मुख्यतः सरकारी पूँजी व्यय के कारण।
3. सकल स्थिर पूँजी निर्माण (GFCF) 9.5% बढ़ा, जो मजबूत निवेश गतिविधि का संकेत देता है।
4. शुद्ध निर्यात (X-M) ने GDP वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक

2 मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 – 150 शब्द:

भारत के 3,682 बाघों का रिकॉर्ड – विश्व की जंगली बाघ आबादी का 70% – एक संरक्षण सफलता की कहानी है। हालाँकि, सरकार का बाघ परिदृश्यों को 'जैव-अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी पर्यटन संपत्ति' के रूप में प्रस्तुत करना – केवल संरक्षण के बजाय – दोनों वादा और जोखिम रखता है। चर्चा कीजिए।

आदर्श उत्तर – 150 शब्द:

भारत की बाघ सुधार – 2006 में 1,411 से 2022 में 3,682 – संरक्षण की महान सफलता की कहानियों में से एक है, जो Project Tiger (1973), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और NTCA के M-STrIPES निगरानी द्वारा संचालित है। जैव-अर्थव्यवस्था-पारिस्थितिकी पर्यटन ढाँचा वास्तविक वादा प्रदान करता है: यह संरक्षण को आजीविका के साथ संरेखित करता है, मानव-वन्यजीव संघर्ष की मूल समस्या को संबोधित करता है। जब वन-किनारे समुदाय पारिस्थितिकी पर्यटन से आयु अर्जित करते हैं (Jim Corbett: ~5 लाख वार्षिक आगंतुक), FRA 2006 के तहत गैर-इमारती वन उत्पाद एकत्र करते हैं, या बाघ वन कार्बन सिंक से कार्बन क्रेडिट राजस्व प्राप्त करते हैं, वे संरक्षण के हितधारक बन जाते हैं, पीड़ित नहीं। यह केवल बाध्यकारी संरक्षण से अधिक टिकाऊ है। हालाँकि, जोखिम विद्यमान हैं।

व्यावसायीकरण आवास अखंडता से समझौता कर सकता है – अनियमित पर्यटन गलियारे बाघ आंदोलन मार्गों को खंडित करते हैं। कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण के लिए ग्रीनवाशिंग से बचने के लिए मजबूत लेखांकन की आवश्यकता है। संतुलन सामुदायिक-नेतृत्व, सावधानीपूर्वक विनियमित पारिस्थितिकी पर्यटन में कड़ी कोर-जोन सुरक्षा के साथ है – सामूहिक पर्यटन नहीं। सरकार का ढाँचा दिशात्मक रूप से सही है लेकिन कार्यान्वयन कठोरता महत्वपूर्ण है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 – 250 शब्द:

RAKSHA दस्तावेज़ और इस सप्ताह के अन्य रक्षा कूटनीति घटनाक्रमों (भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय, DRDO ToT, OGEL सुधार) के आलोक में विश्लेषण करें कि क्या भारत वास्तव में एक रक्षा आयातक से एक रणनीतिक रक्षा साझेदार की ओर परिवर्तित हो रहा है।

आदर्श उत्तर – 250 शब्द:

भारत ऐतिहासिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है – 2006-10 की अवधि में 15% वैश्विक हथियार आयात का। परिवर्तन की कहानी डेटा में स्पष्ट है: रक्षा उत्पादन FY2014-15 में ₹54,951 करोड़ से FY2024-25 में ₹1.27 लाख करोड़ तक, और निर्यात \$44 मिलियन से \$2.8 अरब तक। इस सप्ताह के घटनाक्रम परिवर्तन के विभिन्न आयाम दिखाते हैं: नीतिगत ढाँचे में: RAKSHA = पहली बार भारत ने अपनी रक्षा जुड़ाव दर्शन को औपचारिक रूप से संहिताबद्ध किया – सह-विकास को प्राथमिकता मॉडल के रूप में घोषित करना। यह केवल नारेबाजी नहीं – भारत-GE F414 (इंजन, 80% ToT), भारत-फ्रांस MMRCA 2.0, DRDO-निजी क्षेत्र मिसाइल ToT से समर्थित। निर्यात बाजार में: आर्मेनिया (पिनाका MBRL), फिलीपींस (ब्रह्मोस), मॉरीशस/श्रीलंका/वियतनाम (गश्ती नौकाएं) – भारत के खरीदार वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं। OGEL सुधार प्रक्रियात्मक बाधाएं कम करते हैं जो निर्यात मात्रा को सीमित करती थीं। उद्योग आधार में: भारत-बेल्जियम सह-उत्पादन, निजी क्षेत्र मिसाइल ToT = भारत का रक्षा औद्योगिक आधार BDL से परे विस्तार कर रहा है। 15,000+ MSME रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में; 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे कार्यशील। हालाँकि, सावधानियाँ जरूरी हैं: \$5 अरब निर्यात लक्ष्य महत्वाकांक्षी है (वर्तमान \$2.8 अरब); प्रमुख प्रणालियाँ (Tejas GE F414, पनडुब्बियाँ) अभी भी विदेशी इंजनों पर निर्भर; कुछ 'निर्यात' अनुदान-सहायता प्राप्त सरकारी-से-सरकारी हस्तांतरण हैं जो बाजार-आधारित बिक्री नहीं। निष्कर्ष: परिवर्तन वास्तविक है लेकिन अपूर्ण। RAKSHA = आकांक्षा और

वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने का प्रयास। आयातक से साझेदार की यात्रा जारी है – गंतव्य तक पहुँचने में अभी एक दशक और लग सकता है।

Prelims उत्तर एवं व्याख्या

प्र.1. उत्तर: (a) केवल 1 और 3

कथन 1 सही है – JCR ने भारत को A- तक उन्नत किया, किसी भी प्रमुख CRA से पहली 'A' श्रेणी। कथन 2 गलत है – 'बिग थ्री' अभी भी भारत को 'BBB' श्रेणी में रेट करती हैं। कथन 3 सही है – 'BBB' (BBB-, BBB, BBB+) = न्यूनतम निवेश श्रेणी; BBB- से नीचे = सट्टा/जंक।

प्र.2. उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है

SCO में भारत की सक्रिय भागीदारी (A) वास्तव में R द्वारा समझाई जाती है – SCO का उपयोग रूस संलग्नता, मध्य एशिया संपर्क (INSTC, चाबहार), और RATS में आतंकवाद-रोधी सहयोग के लिए – सभी भारत की बहु-संरक्षण नीति की सेवा करते हैं।

प्र.3. उत्तर: (a) 1-Q, 2-P, 3-R, 4-S

पुगा घाटी = लद्दाख (Q); Cambay = गुजरात (P); सोन-नर्मदा = MP/CG (R); पश्चिमी तट = कर्नाटक/गोवा/केरल (S)। याद रखें: भारत के 7 भूतापीय प्रांत – हिमालय (पुगा, लद्दाख), Cambay (गुजरात), गोदावरी (AP/तेलंगाना), महानदी (ओडिशा), पश्चिमी तट (कर्नाटक/गोवा/केरल), सोन-नर्मदा (MP/CG), अंडमान-निकोबार।

LESS NOISE. MORE RETENTION.

प्र.4. उत्तर: (c) केवल तीन

कथन 1 (75 PVTG, 18 राज्य – सही), 2 (15 नवंबर = जनजातीय गौरव दिवस = बिरसा मुंडा जन्म वर्षगाँठ – सही), 4 (DA-JGUA व्यापक जनजातीय विकास – सही) सटीक। कथन 3 गलत – ₹24,104 करोड़ PM-JANMAN (PVTG के लिए) का परिव्यय है; ₹79,156 करोड़ DA-JGUA का है।

प्र.5. उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 4

कथन 1, 2, 4 सही। कथन 3 गलत – SASE (DRDO) हिमस्खलन पूर्वानुमान संभालता है, GLOF प्रारंभिक चेतावनी नहीं; GLOF प्रारंभिक चेतावनी NDMA, NRSC (ISRO), और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा संभाली जाती है।

प्र.6. उत्तर: (a) 1-Q, 2-P, 3-R, 4-S

QKD (क्वांटम कुंजी वितरण) = क्वांटम गुणों का उपयोग करता है ताकि अवरोधन पता लगाया जा सके (Q)। QRNG = वास्तविक यादृच्छिक संख्याओं के लिए क्वांटम घटनाओं का उपयोग (P)। क्वांटम के बाद क्रिप्टोग्राफी = क्वांटम कंप्यूटर हमलों के प्रति सुरक्षित एल्गोरिदम (R)। 'अभी हार्वेस्ट करो, बाद में डिक्रिप्ट करो' = भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर से डिक्रिप्ट करने के लिए आज डेटा एन्क्रिप्ट करना (S)।

प्र.7. उत्तर: (b) केवल दो

कथन 1 (भारत-उज़्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2022 – सही) और 3 (INSTC चाबहार के माध्यम से – सही) सटीक। कथन 2 गलत – 'ओली दाराजली दोस्तलिक' विदेशी नेताओं को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं – ये अलग हैं। कथन 4 गलत – ताशकंद घोषणा 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद शांति समझौता था, उज़्बेकिस्तान के साथ नहीं।

प्र.8. उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है

अभिकथन (60% RAP प्रदर्शन महत्वपूर्ण) सही है, और कारण सीधे समझाता है: भारत केवल 10-20% RAP उपयोग करता है; बिटुमेन = पेट्रोलियम-व्युत्पन्न, महंगा (₹40,000-50,000/टन), कार्बन-गहन, भारत ~45% आयात करता है। ये तथ्य मिलकर RAP सफलता की महत्ता को सटीक रूप से समझाते हैं।

प्र.9. उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 4

कथन 1 (GIFT IFSC = गांधीनगर, भारत का पहला – सही), 2 (IFSCA = एकीकृत नियामक, 2020 में स्थापित – सही), 4 (विमान पट्टा अनुमत, आयरलैंड और सिंगापुर हावी – सही) सटीक। कथन 3 गलत – FCNR(B) = विदेशी मुद्रा (रुपया-मूल्यवर्गित नहीं) NRI द्वारा सावधि जमा; 'FC' = विदेशी मुद्रा। NRI की रुपया जमा NRE खातों के अंतर्गत आती है।

प्र.10. उत्तर: (b) केवल तीन

कथन 1 (7.8% = छह तिमाहियों में सबसे तेज – सही), 2 (निर्माण 10.1%, सरकारी पूँजी व्यय संचालित – सही), 3 (GFCF 9.5% वृद्धि – सही) सटीक। कथन 4 गलत – शुद्ध निर्यात (X-M) ने GDP वृद्धि में नकारात्मक योगदान दिया क्योंकि आयात निर्यात की तुलना में तेजी से बढ़ रहे थे (मजबूत घरेलू माँग दर्शाता है)।



SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

SITOK IAS • PIB साप्ताहिक संकलन

अब, एक नया सप्ताह

सप्ताह 2

5 - 11 सितंबर 2026

34 PIB समाचार • सम्माननीय उल्लेख और अभ्यास प्रश्न

सप्ताह 2 / 4

01	भारत-मोरक्को प्रथम संयुक्त रक्षा समिति – नई दिल्ली.....	80
02	वीर गार्जियन-2026 – IAF और जापान वायु आत्मरक्षा बल का वायु रक्षा अभ्यास	81
03	IAF DRONATHON 2026	82
04	PM मोदी BRICS बिज़नेस फोरम 2026 में + राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय	84
05	भारत-रूस द्विपक्षीय – 2030 तक \$100 अरब व्यापार का लक्ष्य	85
06	9वीं ASEAN-भारत कृषि और वानिकी मंत्रिस्तरीय बैठक	87
07	भारत ने 6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के आह्वान का समर्थन किया.....	88
08	BRICS भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन – 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन.....	89
09	IndiaAI मिशन – भारत-स्वीडन SITAC में AI और डिजिटलीकरण सहयोग	91
10	बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 2026 – 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी.....	92
11	e-FAST India + PACT – शून्य-उत्सर्जन माल परिवहन और ZET बाज़ार	93
12	वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) – ₹5,000+ करोड़ साइबर धोखाधड़ी रोकी	95
13	जिला स्तरीय NSO अनुमान – असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के लिए पहली बार.....	96
14	भारत – जहाज स्वामित्व, पट्टे और समुद्री वित्त का वैश्विक केंद्र बनेगा	98
15	ई-कॉमर्स नियम संशोधित – उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता	99
16	ORV सागर मंथन – भारत का उन्नत महासागर अनुसंधान पोत लॉन्च.....	101
17	कार्बनिक अणुओं का स्व-संयोजन – हरित हाइड्रोजन उत्पादन का नया मार्ग	102
18	क्वांटम उलझन हानि – वैज्ञानिकों ने इसे दूर करने का तरीका खोजा.....	103
19	DILRMP 3.0 – ₹565.50 करोड़ के साथ भूमि अभिलेखों का डिजिटल उन्नयन.....	105
20	स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 – सर्वश्रेष्ठ शहर पुरस्कृत, NCAP संकलन जारी	106
21	ड्रायलैंड कांग्रेस 2026 – नई दिल्ली, 800+ वैश्विक विशेषज्ञ.....	108
22	वन अधिकार अधिनियम – पहला क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन, बेंगलुरु.....	109
23	7वाँ भारत-जापान वनों पर संयुक्त कार्य समूह – बेंगलुरु.....	111
24	HPV वैक्सीन – 80 लाख खुराक, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम में मील का पत्थर.....	112
25	राष्ट्रीय पोषण माह 2026 – 9वाँ संस्करण.....	114
26	राष्ट्रीय फ्लोरोसिस दिवस – बहु-हितधारक कार्यशाला	115
27	पृष्ठभूमि: ECLGS 5.0.....	117
28	पृष्ठभूमि: वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम	118
29	पृष्ठभूमि: भारत का नीले आकाश का मार्ग – NCAP	120
30	पृष्ठभूमि: जूट – भारत का सोने का रेशा	121
31	पृष्ठभूमि: हर स्कूल, एक मॉडल स्कूल.....	122
32	पृष्ठभूमि: BRICS और नीली अर्थव्यवस्था	124
33	पृष्ठभूमि: सम्मान के साथ किसानों के भविष्य को सुरक्षित करना	125
34	NHRC स्वतः संज्ञान – गरियाबंद, छत्तीसगढ़ में अधूरे पुल से बच्चों का आवागमन	127

सम्माननीय उल्लेख	130
अभ्यास प्रश्न	136
10 Prelims प्रश्न – UPSC शैली	136
2 मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं आदर्श उत्तर.....	140
Prelims उत्तर एवं व्याख्या	141



SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

भारत-मोरक्को प्रथम संयुक्त रक्षा समिति – नई दिल्ली

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय

PIB तिथि: 8 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत और मोरक्को ने नई दिल्ली में अपनी पहली संयुक्त रक्षा समिति (JDC) की बैठक की – अफ्रीका में भारत के रक्षा विस्तार का एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण कदम। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का सबसे रणनीतिक रूप से स्थित देश है: अटलांटिक और भूमध्यसागरीय दोनों तटरेखाएं, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के दक्षिणी प्रवेश पर नियंत्रण (एक महत्वपूर्ण समुद्री चोक बिंदु), और दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट भंडार (70% से अधिक वैश्विक)। भारत-मोरक्को रक्षा संबंध 2012 के रक्षा सहयोग समझौते के बाद से गर्म हो रहे हैं। उद्घाटन संयुक्त रक्षा समिति अब एक संरचित द्विपक्षीय तंत्र प्रदान करती है। भारत के लिए: मोरक्को उप-सहारा अफ्रीका और EU दोनों का प्रवेश द्वार है। मोरक्को के लिए: भारत का रक्षा निर्यात पोर्टफोलियो (गश्ती जहाज, तोपखाना, रडार) और उसकी गुट-निरपेक्ष साख इसे एक आकर्षक साझेदार बनाते हैं।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
भारत-मोरक्को संयुक्त रक्षा समिति	उद्घाटन बैठक, नई दिल्ली, सितंबर 2026; संरचित द्विपक्षीय रक्षा तंत्र; रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, प्रशिक्षण, अभ्यास; 2012 रक्षा सहयोग समझौते के बाद
मोरक्को की रणनीतिक भूगोल	अटलांटिक + भूमध्यसागरीय तटरेखाएं; जिब्राल्टर जलडमरूमध्य का दक्षिणी प्रवेश; उप-सहारा अफ्रीका और EU का प्रवेश द्वार; दुनिया के 70%+ फॉस्फेट भंडार
जिब्राल्टर जलडमरूमध्य	अटलांटिक महासागर को भूमध्यसागर से जोड़ने वाली संकरी जलडमरूमध्य; सबसे संकरे स्थान पर 14 किमी; मोरक्को दक्षिणी तट नियंत्रित करता है; वैश्विक शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण समुद्री चोक बिंदु
भारत-अफ्रीका रक्षा चाप	भारत-मोरक्को संयुक्त रक्षा समिति + भारत-मिस्र (रक्षा MoU) + भारत-तंजानिया (नौसेना सहयोग) + भारत-मोजाम्बिक (अड्डा पहुँच) + भारत-सेशेल्स – व्यवस्थित अफ्रीका समुद्री सुरक्षा जुड़ाव

फॉस्फेट-रक्षा संबंध	भारत मोरक्को से 30-40% फॉस्फेट आयात करता है (DAP उर्वरकों के लिए महत्वपूर्ण); गहरे रक्षा संबंध आर्थिक निर्भरता को पूरक बनाते हैं – बहु-क्षेत्रीय संबंध निर्माण
---------------------	--

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: भारत का अफ्रीका रक्षा जुड़ाव; भारत-मोरक्को द्विपक्षीय (रक्षा + व्यापार + फॉस्फेट + हरित हाइड्रोजन = बहु-क्षेत्रीय); जिब्राल्टर जलडमरूमध्य = समुद्री चोक बिंदु
- Prelims: मोरक्को = दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट भंडार (70%+); जिब्राल्टर जलडमरूमध्य = अटलांटिक-भूमध्य सागर कड़ी; भारत-मोरक्को संयुक्त रक्षा समिति = उद्घाटन 2026; 2012 रक्षा सहयोग समझौता

वीर गार्जियन-2026 – IAF और जापान वायु आत्मरक्षा बल का वायु रक्षा अभ्यास

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय / भारतीय वायु सेना

PIB तिथि: 8 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

वीर गार्जियन-2026 भारत की वायुसेना (IAF) और जापान की वायु आत्मरक्षा बल (JASDF) के बीच वायु रक्षा अभ्यास है। यह भारत के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वायु अभ्यासों में से एक है – जापान Quad का भागीदार है, यह अभ्यास Quad सदस्यों के बीच गहराते सुरक्षा संरक्षण को दर्शाता है। वीर गार्जियन 2023 में शुरू हुआ था – इसे इसका दूसरा या तीसरा संस्करण बना रहा है, जो तेज़ी से संस्थागतीकरण का संकेत देता है। अभ्यास में शामिल है: वायु युद्धाभ्यास, दृश्य सीमा से परे (BVR) युद्ध सिमुलेशन, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध – दोनों वायु सेनाएं अपने अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान उड़ाती हैं (IAF के Su-30MKI और Rafale; JASDF के F-15J और F-35A)। Quad संदर्भ में, भारत-जापान वायु सेना अंतर-संचालनीयता Indo-Pacific में चीनी वायु शक्ति के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध की सीधे सेवा करती है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
-----------	---------

वीर गार्जियन अभ्यास	IAF + JASDF द्विपक्षीय वायु अभ्यास; 2023 उद्घाटन; 2026 = दूसरा/तीसरा संस्करण; वायु युद्धाभ्यास, BVR युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध; IAF Su-30MKI/Rafale; JASDF F-15J/F-35A
जापान JASDF	जापान वायु आत्मरक्षा बल; एशिया की सबसे सक्षम वायु सेनाओं में से एक; F-15J, F-35A, F-35B (खरीद में); Patriot PAC-3 SAM; Quad वायु अंतर-संचालनीयता निर्माण में भागीदार
भारत-जापान Quad संरेखण	भारत और जापान दोनों Quad सदस्य (USA और ऑस्ट्रेलिया के साथ); Quad सैन्य अभ्यास अंतर-संचालनीयता बना रहे हैं; वीर गार्जियन = द्विपक्षीय वायु घटक; मालाबार = नौसेना घटक
भारत-जापान ACSA (2020)	अधिग्रहण और पार-सेवा समझौता; अभ्यास के दौरान रसद, ईंधन, गोला-बारूद की पारस्परिक आपूर्ति; केवल अभ्यास से परे गहरा रक्षा सहयोग
BVR – दृश्य सीमा से परे युद्ध	रडार-निर्देशित मिसाइलों (AMRAAM, R-77, Meteor) का उपयोग करके दृश्य सीमा से परे वायु-से-वायु युद्ध; आधुनिक वायु सेनाओं के लिए मुख्य दक्षता; IAF (Astra, MICA, Rafale पर Meteor) और JASDF दोनों BVR सक्षम

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: Quad सैन्य अभ्यास; भारत-जापान रक्षा संबंध; ACSA; 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता; भारत-जापान रक्षा उपकरण हस्तांतरण
- Prelims: वीर गार्जियन = IAF + JASDF; उद्घाटन 2023; ACSA = अधिग्रहण और पार-सेवा समझौता (2020); Quad सदस्य = भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया

IAF DRONATHON 2026

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय / भारतीय वायु सेना

PIB तिथि: 8 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारतीय वायु सेना ने DRONATHON 2026 लॉन्च किया – एक प्रमुख ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और नवाचार चुनौती। भारत की ड्रोन महत्वाकांक्षाएं वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वाकांक्षी में से हैं: ड्रोन के लिए PLI योजना (₹120 करोड़, 2022), और 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने का लक्ष्य। DRONATHON 2026 पर ध्यान केंद्रित है: सैन्य ड्रोन अनुप्रयोग (निगरानी UAV, loitering munitions, आक्रामक और रक्षात्मक संचालन के लिए झुंड ड्रोन); काउंटर-ड्रोन प्रणालियाँ (ड्रोन पहचान + जैमिंग + अवरोधन); और स्वदेशी विकास (इजरायली Herons और आयातित ड्रोन प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करना)। भारत का ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र तेज़ी से विकसित हुआ है: Ideaforge, Garuda Aerospace, Raphe mPhibr जैसी कंपनियां स्वदेशी सैन्य और वाणिज्यिक ड्रोन बना रही हैं।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
DRONATHON 2026	IAF ड्रोन नवाचार चुनौती और प्रदर्शनी; सैन्य + काउंटर-ड्रोन + स्वदेशी ध्यान; स्टार्टअप और उद्योग जुड़ाव; ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र त्वरण के लिए खुला नवाचार
भारत की ड्रोन PLI	ड्रोन और घटकों के लिए ₹120 करोड़ उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (2022); 23 कंपनियां चयनित; 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन निर्माता और निर्यातक बनाने का लक्ष्य
loitering munitions	'कामिकेज़ ड्रोन' – मंडराना, प्रतीक्षा, आक्रमण; इजराइल का Harop (भारत संचालित); USA का Switchblade; भारत स्वदेशी संस्करण विकसित कर रहा है (DRDO, निजी क्षेत्र); यूक्रेन-रूस युद्ध = प्रमाण
काउंटर-ड्रोन प्रणालियाँ	पहचान (रडार, RF सेंसर, ध्वनिक), जैमिंग (GPS अस्वीकृति, RF जैमिंग), अवरोधन (जाल, निर्देशित ऊर्जा, गतिज अवरोधक); भारत LoC और LAC पर CUAS तैनात कर रहा है
स्वदेशी ड्रोन कंपनियाँ	Ideaforge (भारत की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी, सूचीबद्ध); Garuda Aerospace (PM मोदी ने उड़ाया); Raphe mPhibr (रक्षा ड्रोन); Alpha Design (EW पेलोड); भारत का ड्रोन स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र = 200+ कंपनियाँ

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 रक्षा/विज्ञान: भारत का ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र; ड्रोन PLI; loitering munitions; काउंटर-ड्रोन प्रणालियाँ; झुंड ड्रोन; iDEX ढाँचा
- Prelims: भारत ड्रोन PLI = ₹120 करोड़ (2022); DRONATHON = IAF नवाचार मंच; loitering munitions = 'कामिकेज़ ड्रोन'; Ideaforge = भारत की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी

PM मोदी BRICS बिज़नेस फोरम 2026 में + राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय

मंत्रालय: प्रधानमंत्री कार्यालय / विदेश मंत्रालय

PIB तिथि: 11 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के हाशिये पर BRICS बिज़नेस फोरम 2026 को संबोधित किया और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है (भारत मंडपम, नई दिल्ली) – भारत 2026 के लिए BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। BRICS में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है: मूल BRIC (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) में 2024 में ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया, और सऊदी अरब शामिल हुए। PM का बिज़नेस फोरम में संबोधन इन पर केंद्रित था: डॉलर निर्भरता से दूर BRICS व्यापार विविधीकरण, BRICS नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन), और 'ग्लोबल साउथ की आवाज़' के रूप में भारत की भूमिका। पुतिन द्विपक्षीय में: रक्षा आपूर्ति (S-400 पुर्जे, Su-30MKI रखरखाव), Kudankulam NPP विस्तार, ऊर्जा सहयोग, और 2030 तक \$100 अरब व्यापार का लक्ष्य।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
18वाँ BRICS शिखर 2026	भारत मेजबान; भारत मंडपम, नई दिल्ली; BRICS अध्यक्षता 2026 = भारत; विषय = दक्षिण-दक्षिण सहयोग, व्यापार, नवाचार; भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन हाशिये पर
BRICS विस्तृत सदस्यता	मूल BRIC (2009): ब्राजील, रूस, भारत, चीन + दक्षिण अफ्रीका (2010) = BRICS-5; 2024 विस्तार: ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब = BRICS-10

भारत-रूस द्विपक्षीय	मोदी-पुतिन बैठक; रक्षा (S-400 पुर्जे, Su-30MKI), Kudankulam इकाई 5-6, ऊर्जा (रूस = यूक्रेन प्रतिबंधों के बाद भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता), द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य \$100 अरब
BRICS बिज़नेस फोरम	BRICS व्यापारिक समुदायों के लिए मंच; व्यापार और निवेश सुविधा; PM का संबोधन = BRICS भागीदारों के लिए भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं का संकेत; डी-डॉलरीकरण चर्चाएं
नव विकास बैंक (NDB)	BRICS विकास बैंक; मुख्यालय शंघाई; K.V. Kamath पहले राष्ट्रपति थे; \$30+ अरब वितरित; स्थानीय मुद्राओं में ऋण; भारत = प्रमुख उधारकर्ता (बुनियादी ढाँचा)
BRICS डी-डॉलरीकरण	स्थानीय मुद्राओं में व्यापार पर चल रही चर्चाएं; भारत-रूस रुपया-रुबल व्यापार; NDB ऋण स्थानीय मुद्राओं में; USA डॉलर के हथियारीकरण की चिंतित – BRICS विकल्प चला रहा है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: BRICS संरचना (मूल + विस्तारित); 18वाँ शिखर = भारत 2026 मेजबान; NDB; भारत का ग्लोबल साउथ स्थिति; यूक्रेन-उत्तर में भारत-रूस संबंध
- Prelims: BRICS-5 + 2024 विस्तार = BRICS-10; NDB = नव विकास बैंक, मुख्यालय शंघाई; भारत BRICS अध्यक्षता 2026; 18वाँ शिखर = भारत मंडपम, नई दिल्ली

भारत-रूस द्विपक्षीय – 2030 तक \$100 अरब व्यापार का लक्ष्य

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

PIB तिथि: 10 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने INNOPROM India 2026 में रूसी उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव से मुलाकात की और 2030 तक भारत-रूस व्यापार को \$100 अरब तक पहुँचाने का आह्वान किया। वर्तमान भारत-रूस व्यापार: लगभग \$65-70 अरब (FY2024-25) – मुख्यतः यूक्रेन प्रतिबंधों के बाद छूट पर भारत का रूसी कच्चे तेल का

आयात। \$100 अरब लक्ष्य के लिए ऊर्जा से परे विविधीकरण आवश्यक है: रक्षा उपकरण, उर्वरक, दवाएं, मशीनरी, हीरे, और प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्र। INNOPROM India 2026 स्वयं महत्वपूर्ण है: भारत में रूस की प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनी की मेजबानी करना द्विपक्षीय की गहराई को दर्शाता है। भुगतान तंत्र, रसद (INSTC), और इस्पात और रसायन में प्रौद्योगिकी सहयोग भी बैठक के एजेंडे में था।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
INNOPROM India 2026	भारत की पहली INNOPROM प्रदर्शनी; रूस का प्रमुख औद्योगिक व्यापार मेला (Yekaterinburg में वार्षिक) अब भारत में; भारत-रूस औद्योगिक संबंधों की गहराई का संकेत
भारत-रूस व्यापार (\$65-70 अरब)	यूक्रेन के बाद कच्चे तेल के आयात से प्रेरित (रूस = भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता); अन्य: रक्षा, उर्वरक (DAP), हीरे, दवाएं; \$100 अरब लक्ष्य के लिए गैर-ऊर्जा विविधीकरण आवश्यक
रुपया-रुबल व्यापार तंत्र	भारत रूसी तेल/माल के लिए रुपये में भुगतान करता है; रूस के पास रुपये का अधिशेष (सीमित निवेश विकल्प); SWIFT प्रतिबंधों से वैकल्पिक भुगतान प्रणाली का विकास
INSTC – अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा	रूस → अज़रबैजान → ईरान → चाबहार के माध्यम से भारत; \$100 अरब लक्ष्य के लिए प्रमुख रसद
CAATSA चिंता	अमेरिका के विरोधियों के माध्यम से प्रतिबंधों का मुकाबला अधिनियम; USA रूसी रक्षा उपकरण खरीदने वाले देशों को प्रतिबंध की धमकी देता है; भारत का S-400 खरीद = CAATSA जोखिम

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: भारत-रूस द्विपक्षीय; CAATSA; INSTC; रणनीतिक स्वायत्तता; Vladivostok समुद्री गलियारा
- Prelims: भारत-रूस व्यापार ~\$65-70 अरब (FY2024-25); \$100 अरब लक्ष्य 2030; INNOPROM = रूस का औद्योगिक व्यापार मेला; CAATSA = अमेरिका के विरोधियों के माध्यम से प्रतिबंधों का मुकाबला अधिनियम

9वीं ASEAN-भारत कृषि और वानिकी मंत्रिस्तरीय बैठक

मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

PIB तिथि: 9 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

ASEAN-भारत कृषि और वानिकी पर 9वीं मंत्रिस्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई – भारत और ASEAN के बीच उच्चतम-स्तरीय कृषि वार्ता। भारत-ASEAN कृषि सहयोग में शामिल हैं: खाद्य सुरक्षा (ASEAN को भारत का चावल और गेहूं निर्यात; भारत 'क्षेत्र के अंतिम उपाय के खाद्य आपूर्तिकर्ता' के रूप में), टिकाऊ कृषि (कृषि-वानिकी, जैविक खेती, परिशुद्धि कृषि प्रौद्योगिकी साझाकरण), मत्स्य पालन सहयोग, और वन प्रशासन। संयुक्त परिणाम ने खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि, और लचीली मूल्य श्रृंखलाओं के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत की मुख्य मांगें: ASEAN में भारतीय कृषि निर्यात के लिए तरजीही बाजार पहुँच, और जलवायु-लचीली फसल किस्मों पर सहयोगी अनुसंधान।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
ASEAN-भारत कृषि मंत्रिस्तरीय	9वाँ संस्करण, नई दिल्ली; उच्चतम-स्तरीय कृषि वार्ता; खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी; लचीली मूल्य श्रृंखलाओं पर संयुक्त परिणाम
भारत-ASEAN खाद्य व्यापार	भारत निर्यात: चावल (भारत = दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक), गेहूं, चीनी, मसाले; आयात: ताड़ तेल (इंडोनेशिया, मलेशिया = भारत के 85% ताड़ तेल की आपूर्ति), उष्णकटिबंधीय फल, समुद्री खाद्य
खाद्य सुरक्षा ASEAN संदर्भ	ASEAN खाद्य सुरक्षा रिजर्व (AFSR); भारत क्षेत्रीय खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में; ASEAN-भारत FTA (2010) के भीतर कृषि FTA
कृषि-वानिकी सहयोग	पेड़ों को फसलों/पशुधन के साथ एकीकृत करना; भारत की राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति (2014); संयुक्त अनुसंधान
ताड़ तेल की संवेदनशीलता	भारत ~90 लाख टन/वर्ष ताड़ तेल आयात करता है; मलेशिया + इंडोनेशिया आपूर्ति; भारत सूरजमुखी, सोयाबीन में विविधीकरण कर रहा है; ASEAN-India FTA में एक प्रमुख मुद्दा

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 IR: ASEAN-भारत संबंध; भारत-ASEAN FTA समीक्षा; क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत; Act East Policy का कृषि आयाम
- Prelims: भारत = दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक; भारत ~90 लाख टन ताड़ तेल/वर्ष आयात करता है (इंडोनेशिया + मलेशिया); ASEAN-भारत FTA = 2010; AFSR = ASEAN खाद्य सुरक्षा रिजर्व

भारत ने 6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के आह्वान का समर्थन किया

मंत्रालय: संचार मंत्रालय / दूरसंचार विभाग

PIB तिथि: 9 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) ने '6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान' का समर्थन किया – वैश्विक 6G मानकों और सुरक्षा ढाँचों को आकार देने में भारत को एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना। 6G 5G के बाद वायरलेस प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी है – अपेक्षित वाणिज्यिक परिनियोजन 2030-2035 के आसपास। पिछली पीढ़ियों के विपरीत जहाँ भारत केवल मानकों का अनुसरणकर्ता था, भारत 6G के लिए मानक निर्धारक बनने की कोशिश कर रहा है। भारत का BSNL के लिए 100% स्वदेशी 4G/5G कोर नेटवर्क – पहली बार किसी देश ने अपना खुद का दूरसंचार स्टैक बनाया – इस महत्वाकांक्षा को विश्वसनीयता देता है। 'सुरक्षा' आयाम में शामिल है: आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा (Huawei/ZTE जैसे चीनी दूरसंचार विक्रेताओं पर निर्भरता कम करना – भारत ने इन्हें 5G के लिए प्रतिबंधित किया), विश्वसनीय विक्रेता ढाँचे, और नेटवर्क लचीलापन मानक।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
6G प्रौद्योगिकी	6वीं पीढ़ी की वायरलेस तकनीक; वाणिज्यिक परिनियोजन 2030-2035 अपेक्षित; 5G से 100 गुना तेज़ गति; उप-मिलीसेकंड विलंब; एकीकृत संवेदन और संचार; AI-नेटिव नेटवर्क
भारत 6G दृष्टि	DoT; ₹400 करोड़ आवंटित; लक्ष्य: 6G पेटेंट और मानकों में शीर्ष देशों में भारत; C-DOT नोडल एजेंसी; IIT, उद्योग के साथ सहयोग

BSNL स्वदेशी 4G/5G स्टैक	BSNL के लिए 100% स्वदेशी 4G/5G कोर नेटवर्क; पहली बार किसी देश ने स्वयं का दूरसंचार स्टैक बनाया; TCS + C-DOT + TEJAS Networks; रणनीतिक महत्व: विदेशी विक्रेताओं पर शून्य निर्भरता
विश्वसनीय विक्रेता ढाँचा	Huawei/ZTE प्रतिबंध के बाद; भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश दूरसंचार (2021); केवल 'विश्वसनीय स्रोत' दूरसंचार उपकरण आपूर्ति कर सकते हैं; USA, EU, UK, ऑस्ट्रेलिया ('क्लीन नेटवर्क') के साथ संरेखित
ITU और 3GPP	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ICT के लिए UN एजेंसी); 3GPP = मोबाइल दूरसंचार मानक निर्धारित करता है; भारत दोनों में भागीदारी बढ़ा रहा है; 6G मानकों की लड़ाई = भूराजनीतिक

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान/प्रौद्योगिकी: 6G प्रौद्योगिकी; भारत 6G दृष्टि; BSNL स्वदेशी स्टैक; विश्वसनीय विक्रेता ढाँचा; भारत की दूरसंचार मानक महत्वाकांक्षाएं
- Prelims: DoT = दूरसंचार विभाग; भारत 6G दृष्टि = ₹400 करोड़; 3GPP = मोबाइल दूरसंचार मानक निकाय; ITU = अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ; BSNL 4G/5G = 100% स्वदेशी

BRICS भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन – 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन

मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

PIB तिथि: 11 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

BRICS भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन 11-12 सितंबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में आयोजित हुई। यह एक्सपोजिशन भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र – स्टार्टअप, डीप टेक, IIT, NIT, CSIR प्रयोगशालाएं – को BRICS भागीदारों के सामने प्रस्तुत करती है। मुख्य विषय: AI और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा (भारत का DPI स्टैक – UPI, Aadhaar, ABDM, ONDC – BRICS राष्ट्रों के लिए मॉडल के रूप में), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (ISRO की उपलब्धियाँ), स्वच्छ ऊर्जा नवाचार (हरित हाइड्रोजन, सौर प्रौद्योगिकी), और जैव-प्रौद्योगिकी (भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता, बायोसिमिलर)। 'भारत इनोवेट्स'

ब्रांडिंग G20 (2023) में भी इस्तेमाल हुई थी – यह वैश्विक बहुपक्षीय मंचों पर भारत की नवाचार कहानी को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने का भारत का प्रयास है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
BRICS भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन	11-12 सितंबर 2026; भारत मंडपम, नई दिल्ली; 18वें BRICS शिखर का हिस्सा; भारत का नवाचार प्रदर्शन; DPI, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, जैव-प्रौद्योगिकी विषय
DPI BRICS निर्यात के रूप में	भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा (UPI, Aadhaar, ABDM, ONDC, DigiLocker, PM-WANI) BRICS राष्ट्रों के लिए मॉडल के रूप में; G20 DPI ढाँचा (भारत की पहल)
ONDC – ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स	सरकार समर्थित ई-कॉमर्स प्रोटोकॉल; किसी भी विक्रेता/खरीदार ऐप को प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने की अनुमति; Amazon/Flipkart वर्चस्व का विकल्प; समावेशी डिजिटल वाणिज्य के लिए DPI मॉडल
IN-SPACE	भारत का अंतरिक्ष नियामक/सुविधाकर्ता; निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए; Agnikul, Skyroot, Pixxel; BRICS अंतरिक्ष डेटा साझाकरण संभावना
BRICS R&D सहयोग	BRICS विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) मंत्रिस्तरीय; संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं; भारत AI, जैव-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में योगदान कर रहा है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान/अर्थव्यवस्था: DPI पारिस्थितिकी तंत्र (UPI, Aadhaar, ABDM, ONDC); भारत का अंतरिक्ष वाणिज्यिक क्षेत्र; BRICS STI सहयोग; भारत की नवाचार कहानी
- Prelims: ONDC = ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स; IN-SPACE = भारत का अंतरिक्ष नियामक/सुविधाकर्ता; BRICS भारत इनोवेट्स = 11-12 सितंबर 2026, भारत मंडपम; DPI = डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा

IndiaAI मिशन – भारत-स्वीडन SITAC में AI और डिजिटलीकरण सहयोग

मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय

PIB तिथि: 7 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत के IndiaAI मिशन और स्वीडन ने SITAC (Sweden-India Tech Alliance for Cooperation – स्वीडन-भारत प्रौद्योगिकी गठबंधन सहयोग के लिए) के तहत AI और डिजिटलीकरण में रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की। स्वीडन AI और प्रौद्योगिकी में अपने आकार से कहीं अधिक प्रभाव रखता है: Spotify, Klarna, Ericsson सभी स्वीडन में निर्मित। स्वीडन AI शोध में भी अग्रणी है (KTH Royal Institute of Technology, Chalmers, AI Sweden)। भारत-स्वीडन AI सहयोग के क्षेत्र: जिम्मेदार AI ढाँचे (स्वीडन EU का सदस्य है – EU का AI अधिनियम 2024 दुनिया का पहला व्यापक AI विनियमन है; भारत इससे सीख रहा है), ओपन-सोर्स AI मॉडल, सार्वजनिक सेवाओं के लिए AI, और दूरसंचार AI (Ericsson एक प्रमुख 5G विक्रेता और नेटवर्क में AI का भागीदार है)। भारत के लिए: IndiaAI मिशन (₹10,372 करोड़) स्वीडन के लिए एक विशाल AI परिनियोजन बाज़ार और प्रतिभा पूल है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
SITAC	Sweden-India Tech Alliance for Cooperation; द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी सहयोग ढाँचा; AI, डिजिटलीकरण, स्वच्छ तकनीक, जीवन विज्ञान; IndiaAI मिशन + स्वीडन AI पारिस्थितिकी तंत्र इंटरफेस
IndiaAI मिशन	₹10,372 करोड़; 7 स्तंभ: AI कंप्यूट, शोध (AIRAWAT), डेटासेट (AIKosh), शासन में AI, कौशल, स्टार्टअप, सुरक्षित AI; कंप्यूट लक्ष्य: 10,000+ GPU क्लस्टर
EU AI अधिनियम 2024	दुनिया का पहला व्यापक AI विनियमन; जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (न्यूनतम, सीमित, उच्च, अस्वीकार्य जोखिम); सार्वजनिक में वास्तविक समय बायोमेट्रिक निगरानी पर प्रतिबंध; भारत अपने AI शासन ढाँचे के लिए इससे सीख रहा है

स्वीडन का प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र	Ericsson (5G/6G, दूरसंचार AI), Spotify (संगीत AI), Klarna (फिनटेक AI); KTH, Chalmers, AI Sweden (राष्ट्रीय AI शोध संस्थान); छोटा राष्ट्र, विशाल तकनीक उत्पादन
AIRAWAT	AI अनुसंधान, विश्लेषण और ज्ञान आत्मसात मंच; भारत का राष्ट्रीय AI कंप्यूट बुनियादी ढाँचा; MeitY; पहला चरण: 100 petaflop GPU क्लस्टर

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान/प्रौद्योगिकी: IndiaAI मिशन स्तंभ; EU AI अधिनियम 2024; AIRAWAT; AI शासन ढाँचे; भारत-स्वीडन प्रौद्योगिकी सहयोग
- Prelims: IndiaAI मिशन = ₹10,372 करोड़; AIRAWAT = भारत का AI कंप्यूट मंच; EU AI अधिनियम 2024 = दुनिया का पहला व्यापक AI विनियमन; SITAC = Sweden-India Tech Alliance; Ericsson = स्वीडिश 5G विक्रेता

बैंकर्स बुक्स एक्टिडेंस अधिनियम, 2026 – 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

PIB तिथि: 11 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

बैंकर्स बुक्स एक्टिडेंस अधिनियम, 2026 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा – औपनिवेशिक युग के बैंकर्स बुक्स एक्टिडेंस अधिनियम, 1891 की जगह लेगा। 1891 का अधिनियम तब बनाया गया था जब बैंक रिकॉर्ड भौतिक बहीखाते थे। 2026 का प्रतिस्थापन इसे डिजिटल युग के लिए आधुनिक बनाता है: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (कोर बैंकिंग सिस्टम डेटा, डिजिटल लेनदेन लॉग) अब प्रमाणित प्रतियों के रूप में औपचारिक रूप से स्वीकार्य; ब्लॉकचेन-आधारित रिकॉर्ड और AI-जनित बैंक विवरणों को कानूनी दर्जा; और बैंक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित। क्यों महत्वपूर्ण है: बैंकिंग धोखाधड़ी मामले (PMLA, IBC कार्यवाही), ऋण वसूली मामले (DRT), और आपराधिक वित्तीय जांच बैंक रिकॉर्ड पर साक्ष्य के रूप में बहुत अधिक निर्भर करती हैं। डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को स्वीकार करने में देरी ने भारत में वित्तीय अपराध अभियोजन को धीमा किया है। नया अधिनियम इसे सीधे संबोधित करता है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम 2026	1891 के औपनिवेशिक युग के अधिनियम की जगह; 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी; न्यायालय में बैंक रिकॉर्ड स्वीकार्यता का आधुनिकीकरण; डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड औपचारिक रूप से स्वीकार्य
1891 अधिनियम – औपनिवेशिक विरासत	भौतिक बहीखाता युग के लिए डिज़ाइन; कोर बैंकिंग प्रणाली, डिजिटल लेनदेन पर विचार नहीं किया; वित्तीय अपराध अभियोजन के लिए पुराना
DRT – ऋण वसूली न्यायाधिकरण	₹20 लाख से अधिक बैंक ऋण वसूली के लिए विशेष न्यायाधिकरण; DRAT (अपीलीय) ऊपर; नया अधिनियम DRT कार्यवाही में बैंक रिकॉर्ड प्रस्तुत करना तेज करता है = तेज़ ऋण वसूली
PMLA साक्ष्य	धन शोधन निवारण अधिनियम; बैंक रिकॉर्ड = धन शोधन मामलों में प्राथमिक साक्ष्य; प्रवर्तन निदेशालय बैंक रिकॉर्ड पर निर्भर करता है; नया अधिनियम ED की साक्ष्य प्रस्तुति को सुव्यवस्थित करता है
IBC – दिवाला और दिवालियापन संहिता	बैंक रिकॉर्ड IBC समाधान कार्यवाही (CIRP) के लिए केंद्रीय; दिवालिया कंपनियों के खिलाफ बैंकों के दावों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य; नया अधिनियम IBC प्रक्रिया में तेज़ दावा सत्यापन

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 राजव्यवस्था/शासन: औपनिवेशिक कानूनों का आधुनिकीकरण; बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम 2026 बनाम 1891; वित्तीय अपराध में डिजिटल साक्ष्य; DRT प्रणाली
- Prelims: बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम 1891 की जगह 2026 अधिनियम; 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी; DRT = ऋण वसूली न्यायाधिकरण; DRAT = ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण; PMLA = धन शोधन निवारण अधिनियम

e-FAST India + PACT – शून्य-उत्सर्जन माल परिवहन और ZET बाज़ार

मंत्रालय: नीति आयोग

PIB तिथि: 7 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

नीति आयोग के e-FAST India (इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन) ने भारत में शून्य-उत्सर्जन माल परिवहन की तेज़ तैनाती का समर्थन करने के लिए PACT (Pathways to Advanced Clean Transportation) लॉन्च किया, साथ में ZET (शून्य-उत्सर्जन ट्रक) बाज़ार भी। माल परिवहन कार्बन-मुक्तीकरण के लिए भारत की कमज़ोरी है: वाणिज्यिक वाहन (ट्रक, बसें) भारत के सड़क बेड़े का ~12% हैं लेकिन सड़क परिवहन CO₂ उत्सर्जन में ~40% योगदान करते हैं। यात्री EV के विपरीत (जहाँ बिक्री बढ़ रही है), माल विद्युतीकरण पीछे है क्योंकि: ट्रकों को बड़ी बैटरी पैक (वजन और रेंज चुनौतियाँ) चाहिए, लंबे चार्जिंग समय रसद समयसीमा बाधित करते हैं, और डीज़ल के साथ TCO (कुल स्वामित्व लागत) समता नहीं हुई है। PACT इसे माल गलियारों पर चार्जिंग बुनियादी ढाँचे और ZET बाज़ार के माध्यम से संबोधित करता है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
e-FAST India	इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन; नीति आयोग; शून्य-उत्सर्जन माल तैनाती में तेजी; उद्योग-सरकार इंटरफेस; रसद कंपनियों के साथ पायलट
PACT	Pathways to Advanced Clean Transportation; नीति आयोग, सितंबर 2026; बेड़ा संचालकों, OEM, वित्तपोषकों, चार्जिंग बुनियादी ढाँचा प्रदाताओं को जोड़ता है
ZET बाज़ार	शून्य-उत्सर्जन ट्रक बाज़ार; बेड़ा संचालकों को ZET खरीद के लिए मंच; ट्रक OEM (Tata Motors EV, Mahindra, Olectra, Switch Mobility) को खरीदारों से जोड़ता है
माल कार्बन-मुक्तीकरण चुनौती	वाणिज्यिक वाहन = 12% बेड़ा, 40% सड़क परिवहन CO ₂ ; विद्युतीकरण कठिन: वजन, रेंज, चार्जिंग समय, TCO समता; PACT इन बाधाओं को पायलट और बाजार विकास के माध्यम से लक्षित करता है
स्वर्णिम चतुर्भुज माल	दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता राजमार्ग नेटवर्क; भारत के सड़क नेटवर्क का ~2% लेकिन सड़क माल का ~40% वहन करता है; ZET चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के लिए रणनीतिक गलियारा

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण/अर्थव्यवस्था: माल कार्बन-मुक्तीकरण; EV पारिस्थितिकी तंत्र; ZET; चार्जिंग बुनियादी ढाँचा; नीति आयोग का e-FAST India; स्वर्णिम चतुर्भुज
- Prelims: e-FAST India = इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन (नीति आयोग); PACT = Pathways to Advanced Clean Transportation; ZET = शून्य-उत्सर्जन ट्रक; स्वर्णिम चतुर्भुज = दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) – ₹5,000+ करोड़ साइबर धोखाधड़ी रोकती

मंत्रालय: संचार मंत्रालय / DoT

PIB तिथि: 8 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

दूरसंचार विभाग के वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) ने ₹5,000 करोड़ से अधिक की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी लेनदेन को रोकता है। FRI कैसे काम करता है: DoT का दूरसंचार विश्लेषण प्रणाली साइबर धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए जा रहे मोबाइल नंबरों की पहचान करती है (I4C – भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से शिकायत डेटा, TRAI संकेत, और बैंक अलर्ट के माध्यम से); इन नंबरों को 'जोखिम स्कोर' के साथ चिह्नित किया जाता है; बैंक चिह्नित नंबरों से लेनदेन संसाधित करने से पहले इस जोखिम स्कोर की जांच करते हैं; उच्च-जोखिम लेनदेन पीड़ित के खाते से पैसा जाने से पहले चिह्नित या अवरुद्ध किए जाते हैं। FRI संचार साथी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है – DoT का नागरिक-केंद्रित दूरसंचार सुरक्षा मंच जिसमें CEIR (चोरी हुए फोन ब्लॉक करने के लिए) और TAF COP (SIM कार्ड ट्रेकिंग) भी शामिल हैं।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI)	DoT पहल; साइबर धोखाधड़ी में उपयोग मोबाइल नंबरों को जोखिम स्कोर; I4C शिकायत डेटा + TRAI संकेत + बैंक अलर्ट; ₹5,000+ करोड़ रोकें
संचार साथी पारिस्थितिकी तंत्र	DoT का नागरिक-केंद्रित दूरसंचार सुरक्षा मंच; घटक: FRI (धोखाधड़ी जोखिम स्कोरिंग), CEIR (चोरी फोन ब्लॉकिंग), TAF COP (Aadhaar पर SIM ट्रेकिंग), ASTR (AI-आधारित SIM सत्यापन)

I4C – भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र	MHA; राज्यों में साइबर अपराध जांच समन्वय; साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in); राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930; FRI को शिकायत डेटा फीड करता है
CEIR – केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर	चोरी/खोए हुए मोबाइल फोन ब्लॉक करता है (IMEI द्वारा); DoT; नागरिक चोरी फोन रिपोर्ट कर सकते हैं → CEIR सभी नेटवर्क पर ब्लॉक करता है
TAFcop	धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण के लिए दूरसंचार विश्लेषण; DoT; नागरिक जांच सकते हैं कितने SIM उनके Aadhaar पर जारी हुए; अवांछित SIM रिपोर्ट कर सकते हैं
भारत में साइबर धोखाधड़ी का पैमाना	भारत = वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत; UPI धोखाधड़ी, OTP घोटाला, फिशिंग, निवेश धोखाधड़ी, 'डिजिटल गिरफ्तारी' घोटाला; I4C डेटा: ₹1.5 लाख करोड़+ सालाना साइबर अपराध में नुकसान

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 प्रौद्योगिकी/शासन: साइबर धोखाधड़ी रोकथाम पारिस्थितिकी तंत्र; संचार साथी; FRI; CEIR; TAFcop; I4C; भारत में साइबर अपराध का पैमाना
- Prelims: FRI = वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (DoT); संचार साथी = DoT का दूरसंचार सुरक्षा मंच; CEIR = केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर; TAFcop = धोखाधड़ी प्रबंधन के लिए दूरसंचार विश्लेषण; I4C = भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (MHA); राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन = 1930

LESS NOISE. MORE RETENTION.

जिला स्तरीय NSO अनुमान – असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के लिए पहली बार

मंत्रालय: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

PIB तिथि: 10 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के लिए पहली बार जिला स्तरीय अनुमान जारी किए – भारत के सांख्यिकीय ढाँचे में एक ऐतिहासिक कदम। 'असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र' = व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं में छोटे, अनौपचारिक व्यवसाय जो कंपनियों या LLP के रूप में पंजीकृत नहीं हैं – किराना दुकानें, सड़क के किनारे के ढाबे, छोटे दर्जी, स्थानीय प्लंबर, सड़क विक्रेता। यह क्षेत्र अनुमानित 110 मिलियन श्रमिकों को रोजगार देता है (केवल कृषि के बाद) और GDP में महत्वपूर्ण योगदान करता है लेकिन जिला स्तर पर आधिकारिक सांख्यिकी में लगभग अदृश्य था। क्यों महत्वपूर्ण है: जिला स्तरीय डेटा लक्षित नीति को सक्षम करता है; राज्य वित्त आयोग आवंटन को सूचित करता है; और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के केंद्रों की पहचान करने में मदद करता है। डेटा असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) से तैयार किया गया।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र	कंपनियों के रूप में पंजीकृत नहीं छोटे अनौपचारिक व्यवसाय; किराना दुकानें, ढाबे, दर्जी, विक्रेता, मरम्मत की दुकानें; ~110 मिलियन श्रमिक; पहले केवल राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर ट्रैक किया गया
NSO – राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय	MoSPI; भारत की प्राथमिक सांख्यिकीय एजेंसी; PLFS, NSSO सर्वेक्षण, CPI, GDP अनुमान; अब जिला स्तरीय अनौपचारिक क्षेत्र डेटा = सांख्यिकीय कवरेज का विस्तार
ASUSE	असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण; NSO; अनौपचारिक व्यवसायों का आवधिक सर्वेक्षण; रोजगार, उत्पादन, निवेश ट्रैक करता है; पहली बार जिला स्तरीय अनुमान तैयार करना
जिला स्तरीय डेटा का महत्व	लक्षित MSME/औपचारिकीकरण नीति सक्षम करता है; राज्य वित्त आयोग आवंटन सूचित करता है; क्रेडिट अंतराल की पहचान; MUDRA ऋण लक्ष्यीकरण का आधार
औपचारिकीकरण एजेंडा	PM SVANidhi (सड़क विक्रेता), MUDRA (सूक्ष्म उद्यम), Udyam पंजीकरण (MSME); जिला स्तरीय डेटा दिखाता है कहाँ औपचारिकीकरण पीछे है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था: भारत का अनौपचारिक क्षेत्र का आकार और महत्व; सांख्यिकीय प्रणालियाँ (NSO, MoSPI); ASUSE; औपचारिकीकरण एजेंडा; MUDRA; PM SVANidhi
- Prelims: NSO = राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (MoSPI के अंतर्गत); ASUSE = असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण; असंगठित क्षेत्र = अनौपचारिक गैर-कृषि व्यवसाय; आर्थिक जनगणना अंतिम बार 2013-14 (6वाँ)

भारत – जहाज स्वामित्व, पट्टे और समुद्री वित्त का वैश्विक केंद्र बनेगा

मंत्रालय: बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय

PIB तिथि: 10 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जहाज स्वामित्व, जहाज पट्टे और समुद्री वित्त में वैश्विक केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा की घोषणा की। वर्तमान में भारत नौवहन में एक विरोधाभास है: भारत के पास ~2,40,000 सक्रिय नाविक (वैश्विक आपूर्ति का 9%) हैं और अपतटीय जहाजों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा है, फिर भी भारत के स्वामित्व वाले जहाज भारत के केवल 5-6% व्यापार का परिवहन करते हैं (ग्रीस के 17% और जापान के 14% की तुलना में)। इसे बदलने की रणनीति: GIFT IFSC जहाज पट्टा (विमान पट्टे के मॉडल को जहाजों पर लागू करना – समान कर/नियामक लाभ); भारतीय जहाज अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री; भारतीय बैंकों से समुद्री वित्त; और भारत में जहाज स्वामित्व और पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन। यह पिछले सप्ताह के समुद्री कार्बन-मुक्तीकरण धक्के को पूरक बनाता है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
भारत का नौवहन विरोधाभास	2,40,000+ भारतीय नाविक (वैश्विक आपूर्ति का 9%) लेकिन केवल 5-6% व्यापार भारतीय जहाजों पर; भारी माल भाड़ा भुगतान विदेश जाता है; UNCTAD डेटा
GIFT IFSC जहाज पट्टा	जहाजों के लिए विमान पट्टे का मॉडल; समान कर/नियामक लाभ (10% टनेज कर, जहाज बिक्री पर कोई पूंजीगत लाभ नहीं); जहाज पट्टा कंपनियाँ GIFT IFSC में स्थापित करने के लिए आकर्षित करना

भारतीय जहाज अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री	विकास के अधीन; पनामा, लाइबेरिया जैसे 'सुविधा के ध्वज' का विकल्प; प्रतिस्पर्धी कर/नियामक व्यवस्था के साथ भारतीय ध्वज के तहत जहाज पंजीकरण
समुद्री वित्त अंतराल	भारतीय बैंक (SBI, PNB) शायद ही जहाजों को वित्त देते हैं; नौवहन = दीर्घ-चक्र, उच्च-जोखिम संपत्ति; NDB, Exim Bank, IFSCA के माध्यम से जहाज वित्तपोषण उत्पाद विकसित करने का लक्ष्य
सागरमाला + समुद्री भारत दृष्टि 2030	₹1.2 लाख करोड़ निवेश; जहाज स्वामित्व = प्रमुख स्तंभ; भारत पूरी समुद्री मूल्य श्रृंखला में मूल्य कैप्चर करना चाहता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढाँचा: भारत का नौवहन क्षेत्र; GIFT IFSC जहाज पट्टा; समुद्री भारत दृष्टि 2030; सागरमाला; भारत का नाविक शक्ति बनाम जहाज स्वामित्व अंतराल
- Prelims: भारत के ~2,40,000 सक्रिय नाविक (वैश्विक आपूर्ति का 9%); GIFT IFSC = जहाज पट्टा केंद्र; सागरमाला = बंदरगाह-नेतृत्व विकास कार्यक्रम; भारत अपने केवल 5-6% व्यापार को भारतीय जहाजों पर ले जाता है

ई-कॉमर्स नियम संशोधित – उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता

मंत्रालय: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

PIB तिथि: 10 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में संशोधन किया। मुख्य संशोधन: सभी उत्पादों के लिए उत्पत्ति के देश का अनिवार्य प्रकटीकरण (विशेष रूप से स्पष्ट लेबलिंग के बिना मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेची जाने वाली चीनी-मूल की वस्तुओं को लक्षित करना); फ्लैश बिक्री पर सख्त नियम (छोटे खुदरा विक्रेताओं को बाहर करने वाली शिकारी मूल्य निर्धारण को रोकना); तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा बेचे गए सामान के लिए मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म की देयता; सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य शिकायत निवारण अधिकारी (भारतीय निवासी); और संबंधित पक्ष विक्रेताओं को प्राथमिकता दिए जाने का निषेध (Flipkart-WS Retail या Amazon-Cloudtail प्रकार की व्यवस्थाओं को संबोधित करना)। ये नियम ऐसे समय आए हैं जब भारत का ई-कॉमर्स क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन चीनी डंपिंग, अनुचित व्यापार प्रथाओं, और खराब उपभोक्ता शिकायत निवारण की शिकायतें आ रही हैं।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम	2026 में संशोधित; उत्पत्ति देश का अनिवार्य प्रकटीकरण; फ्लैश बिक्री विनियमन; मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म देयता; अनिवार्य शिकायत निवारण अधिकारी; संबंधित पक्ष विक्रेता को कोई प्राथमिकता नहीं
उत्पत्ति देश प्रकटीकरण	ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद मूल का अनिवार्य लेबलिंग; चीनी वस्तुओं को बिना स्पष्ट देश पहचान के बेचे जाने को लक्षित करता है; उपभोक्ता का जानने का अधिकार
मार्केटप्लेस देयता	ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहले 'केवल मध्यस्थ' के रूप में 'सेफ हार्बर' का दावा करते थे; संशोधित नियम तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा बेचे गए सामान के लिए प्लेटफॉर्म जवाबदेही बढ़ाते हैं
फ्लैश बिक्री विनियमन	फ्लैश बिक्री के दौरान शिकारी मूल्य निर्धारण (90% छूट पर उत्पाद) प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने के लिए; संशोधित नियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी फ्लैश बिक्री को परिभाषित और प्रतिबंधित करते हैं
संबंधित पक्ष विक्रेता प्राथमिकता	प्लेटफॉर्म अपनी सहायक कंपनियों का पक्ष लेते थे; CCI ने जांच की; संशोधित नियम स्पष्ट रूप से प्राथमिकता उपचार को प्रतिबंधित करते हैं
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019	मूल कानून; CCPA (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण); CCI प्रतिस्पर्धा संभालता है; उपभोक्ता न्यायालय विवादों के लिए; उपभोक्ता हेल्पलाइन = 1915

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 राजव्यवस्था/शासन: उपभोक्ता संरक्षण ढाँचा (CPA 2019, CCPA, उपभोक्ता न्यायालय); ई-कॉमर्स विनियमन; प्लेटफॉर्म देयता; CCI की भूमिका
- Prelims: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम = 2019; CCPA = केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण; CCI = भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग; ई-कॉमर्स नियम संशोधित 2026; उपभोक्ता हेल्पलाइन = 1915

ORV सागर मंथन – भारत का उन्नत महासागर अनुसंधान पोत लॉन्च

मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

PIB तिथि: 9 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'ORV सागर मंथन' (महासागर अनुसंधान पोत सागर मंथन) लॉन्च किया – भारत का सबसे उन्नत महासागर अनुसंधान पोत। 'सागर मंथन' पौराणिक समुद्र मंथन (देवों और असुरों द्वारा महासागर मंथन) का स्मरण कराता है – महासागर से ज्ञान निकालने वाले पोत के लिए उचित नाम। ORV सागर मंथन की क्षमताएं: गहरे समुद्र अनुसंधान (बैथिमेट्रिक मानचित्रण, तलछट कोरिंग, गहरे समुद्री खनिज अन्वेषण); समुद्र विज्ञान अनुसंधान (तापमान, लवणता, धाराएं, समुद्री जीव विज्ञान); वायुमंडल-महासागर अंतःक्रिया अनुसंधान (मानसून पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण); भूकंपीय सर्वेक्षण; और जलवायु अनुसंधान। यह पोत भारत के गहरे महासागर मिशन से सीधे जुड़ा है – यह समुद्रयान मानव-युक्त पनडुब्बी मिशन के लिए प्राथमिक समर्थन पोत के रूप में काम करेगा।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
ORV सागर मंथन	महासागर अनुसंधान पोत; सितंबर 2026 में लॉन्च; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; गहरे समुद्र, समुद्र विज्ञान, वायुमंडल-महासागर, भूकंपीय, जलवायु अनुसंधान; भारत का सबसे उन्नत महासागर अनुसंधान पोत
समुद्र मंथन पौराणिक संदर्भ	देवों और असुरों द्वारा महासागर का मंथन; मंदर पर्वत + वासुकी सर्प; अमृत, लक्ष्मी, हलाहल विष, खजाने उत्पन्न; पोत का नाम महासागर से ज्ञान निष्कर्षण को प्रतीकात्मक करता है
गहरे महासागर मिशन	₹4,077 करोड़; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; 6 विषय: गहरे समुद्री खनन (5,500 मीटर गहराई पर बहुधातु नोड्यूल), जलवायु सलाहकार, जैव विविधता, महासागर सर्वेक्षण, महासागर से ऊर्जा/मीठा पानी, गहरे महासागर स्टेशन; समुद्रयान = मानव-युक्त पनडुब्बी
समुद्रयान	भारत का मानव-युक्त गहरे महासागर मिशन; MATSYA 6000 = पनडुब्बी; 6,000 मीटर गहराई पर 3 व्यक्ति; NIOT निर्माण कर रहा है; लक्ष्य: मध्य हिंद महासागर बेसिन में बहुधातु नोड्यूल क्षेत्रों की खोज

NIOT – राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान	चेन्नई; MoES के अंतर्गत; महासागर अनुसंधान पोत, गहरे महासागर प्रौद्योगिकी; MATSYA 6000 पनडुब्बी यहाँ बन रही है
बहुधातु नोड्यूल	महासागर तल पर आलू के आकार की चट्टानें जिनमें मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, तांबा; भारत का अन्वेषण क्षेत्र मध्य हिंद महासागर बेसिन में = 75,000 वर्ग किमी; EV बैटरी के लिए महत्वपूर्ण खनिज

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान/पर्यावरण: गहरे महासागर मिशन; ORV सागर मंथन; समुद्रयान; MATSYA 6000; NIOT; बहुधातु नोड्यूल; भारत का महासागर अनुसंधान बेड़ा
- Prelims: गहरे महासागर मिशन = ₹4,077 करोड़; समुद्रयान = मानव-युक्त पनडुब्बी; MATSYA 6000 = भारत का गहरे समुद्री वाहन; NIOT = राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई; बहुधातु नोड्यूल = महत्वपूर्ण खनिज

कार्बनिक अणुओं का स्व-संयोजन – हरित हाइड्रोजन उत्पादन का नया मार्ग

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

PIB तिथि: 9 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया कि कार्बनिक अणुओं का स्व-संयोजन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कुशल प्रकाश-उत्प्रेरक बना सकता है। विज्ञान: कुछ कार्बनिक अणु सही परिस्थितियों में स्वतःस्फूर्त रूप से क्रमबद्ध नैनोसंरचनाओं में संगठित हो जाते हैं (स्व-संयोजन)। ये नैनोसंरचनाएं प्रकाश-उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती हैं – ऐसी सामग्री जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती हैं। सफलता: स्व-संयोजित कार्बनिक संरचनाओं ने पारंपरिक प्रकाश-उत्प्रेरक (आमतौर पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO_2) की तुलना में काफी अधिक हाइड्रोजन विकास दर दिखाई। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है: हरित हाइड्रोजन वर्तमान में \$4-7/किग्रा उत्पादन करने में लागत आती है; NGHM का 2030 तक \$1/किग्रा का लक्ष्य है; प्रकाश-उत्प्रेरक हरित हाइड्रोजन विद्युत-अपघटन के साथ-साथ एक तीसरा, संभावित रूप से सस्ता मार्ग हो सकता है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
-----------	---------

प्रकाश-उत्प्रेरक जल विभाजन	सूर्य के प्रकाश + प्रकाश-उत्प्रेरक का उपयोग करके पानी (H_2O) को हाइड्रोजन (H_2) और ऑक्सीजन में विभाजित करना; सौर ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा (हाइड्रोजन ईंधन) में परिवर्तित; विद्युत-अपघटन की तरह विद्युत मध्यस्थ कदम नहीं
कार्बनिक अणुओं का स्व-संयोजन	अणु बिना बाहरी निर्देश के क्रमबद्ध नैनोसंरचनाओं में स्वतःस्फूर्त रूप से संगठित होते हैं; गैर-सहसंयोजक अंतःक्रियाओं द्वारा संचालित; एकसमान, उच्च-सतह-क्षेत्र उत्प्रेरक संरचनाएं बनाता है
हरित हाइड्रोजन उत्पादन मार्ग	मार्ग 1: विद्युत-अपघटन (पानी को विभाजित करने के लिए नवीकरणीय विद्युत); मार्ग 2: थर्मोकेमिकल (केंद्रित सौर ताप); मार्ग 3: प्रकाश-उत्प्रेरक (प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश + उत्प्रेरक); NGHM मुख्यतः मार्ग 1
NGHM – राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	₹17,490 करोड़; लक्ष्य: 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन; \$1/किग्रा लागत लक्ष्य; इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण (10 GW क्षमता); निर्यात महत्वाकांक्षा; SECI कार्यान्वयन एजेंसी
लागत तुलना	वर्तमान हरित हाइड्रोजन: \$4-7/किग्रा (विद्युत-अपघटन); ग्रे हाइड्रोजन (प्राकृतिक गैस से): \$1-2/किग्रा; NGHM लक्ष्य: 2030 तक \$1/किग्रा; प्रकाश-उत्प्रेरक मार्ग = संभावित रूप से कम लागत

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान/ऊर्जा: हरित हाइड्रोजन उत्पादन मार्ग; प्रकाश-उत्प्रेरक जल विभाजन; NGHM; स्व-संयोजन नैनो प्रौद्योगिकी; भारत के हरित हाइड्रोजन लागत लक्ष्य
- Prelims: NGHM = राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (₹17,490 करोड़); हरित हाइड्रोजन लक्ष्य = 2030 तक 5 MMT; \$1/किग्रा लागत लक्ष्य; SECI = सौर ऊर्जा निगम; प्रकाश-उत्प्रेरक जल विभाजन = प्रत्यक्ष सौर-से-हाइड्रोजन

क्वांटम उलझन हानि – वैज्ञानिकों ने इसे दूर करने का तरीका खोजा

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

PIB तिथि: 7 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारतीय वैज्ञानिकों ने क्वांटम उलझन हानि को दूर करने की एक सफलता पद्धति प्रकाशित की – व्यावहारिक क्वांटम संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक। क्वांटम उलझन एक ऐसी घटना है जहाँ दो कण इस प्रकार सह-संबंधित हो जाते हैं कि एक की क्वांटम अवस्था तत्काल दूसरे को प्रभावित करती है, चाहे दूरी कुछ भी हो। QKD के लिए उलझन गणितीय रूप से सिद्ध सुरक्षित एन्क्रिप्शन को सक्षम करती है। समस्या: उलझन अत्यंत नाजुक है। पर्यावरण के साथ कोई भी अंतःक्रिया ('विसंगति') उलझन को तोड़ती है। यह क्वांटम संचार की सीमा ~100-200 किमी तक सीमित करता है। सफलता: वैज्ञानिकों ने एक एकल क्वांटम ऑपरेशन का उपयोग करके एक विधि तैयार की जो क्वांटम अवस्था को मापे बिना उलझन को प्रभावी ढंग से 'ताज़ा' करती है – जिसे 'उलझन शुद्धि' विधि कहा जाता है। यह क्वांटम संचार की सीमा को काफी बढ़ा सकती है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
क्वांटम उलझन	क्वांटम घटना जहाँ दो कण सह-संबंधित क्वांटम अवस्थाएं साझा करते हैं; एक को मापने से दूसरे की अवस्था तुरंत निर्धारित होती है चाहे दूरी कुछ भी हो; क्वांटम संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग का आधार
विसंगति	पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के कारण क्वांटम गुणों का नुकसान; फोटोन ऑप्टिकल फाइबर से गुजरते समय उलझन खो देते हैं; दीर्घ-दूरी क्वांटम संचार की प्राथमिक बाधा
उलझन शुद्धि	क्वांटम अवस्था को नष्ट किए बिना खराब हुई उलझन को पुनर्स्थापित करने की तकनीक; क्वांटम दोहराव नेटवर्क की मुख्य क्रिया; यह सफलता = उपन्यास एकल-ऑपरेशन विधि
क्वांटम दोहराव	उपकरण जो उलझन को 'रिले' करके क्वांटम संचार की सीमा बढ़ाते हैं; पारंपरिक ऑप्टिकल एम्पलीफायर के समान लेकिन अधिक जटिल; उलझन शुद्धि क्वांटम दोहराव का मुख्य कार्य है
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन संबंध	₹6,003 करोड़ (2023-31); 4 विषय: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम संवेदन, क्वांटम सामग्री; C-DOT QKD उत्पाद (इसी सप्ताह) + यह उलझन सफलता = क्वांटम संचार स्तंभ प्रगति

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान: क्वांटम उलझन; विसंगति; उलझन शुद्धि; क्वांटम दोहराव; क्वांटम इंटरनेट; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
- Prelims: क्वांटम उलझन = 'दूरी पर भूतिया क्रिया' (Einstein); विसंगति = क्वांटम अवस्था हानि; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन = ₹6,003 करोड़; दीर्घ-दूरी क्वांटम संचार के लिए क्वांटम दोहराव आवश्यक

DILRMP 3.0 — ₹565.50 करोड़ के साथ भूमि अभिलेखों का डिजिटल उन्नयन

मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय

PIB तिथि: 10 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने DILRMP 3.0 (डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 3.0) के लिए ₹565.50 करोड़ के साथ परिचालन दिशानिर्देश लॉन्च किए। भारत में भूमि अभिलेख एक शासन की समस्या है: विवादित भूमि स्वामित्व सभी दीवानी मुकदमों में सबसे बड़ा एकल स्रोत (अनुमानित 66%) है। DILRMP 1.0 और 2.0 ने मौजूदा अभिलेखों को डिजिटाइज किया (पेपर पट्टा/खतौनी को डिजिटल रूप में परिवर्तित)। DILRMP 3.0 आगे जाता है: रियल-टाइम अपडेटिंग (दाखिल-खारिज – स्वामित्व परिवर्तन – को डिजिटल अभिलेखों से वास्तविक समय में जोड़ना); भूमि मालिक प्रमाणीकरण के लिए Aadhaar एकीकरण; GIS मानचित्रण (हर भूमि पार्सल को भू-टैग किया गया); और NGDRS (राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली) के साथ एकीकरण ताकि संपत्ति पंजीकरण स्वचालित रूप से भूमि अभिलेख अपडेट करें।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
DILRMP 3.0	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 3.0; ₹565.50 करोड़; ग्रामीण विकास मंत्रालय; रियल-टाइम दाखिल-खारिज, Aadhaar एकीकरण, GIS मानचित्रण, NGDRS एकीकरण
ULPIN – अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या	प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए 14-अंकीय संख्या; भू-निर्देशांक पर आधारित; भूमि के लिए Aadhaar के समान; राष्ट्रव्यापी भूमि अभिलेख डेटाबेस सक्षम करता है

NGDRS – राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली	मानकीकृत संपत्ति पंजीकरण मंच; भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत; एक बार पंजीकृत होने पर भूमि अभिलेख स्वचालित रूप से अपडेट; लक्ष्य: पंजीकरण और दाखिल-खारिज के बीच कोई अंतराल नहीं
भूमि मुकदमेबाजी का पैमाना	भारत में सभी दीवानी मामलों का अनुमानित 66% भूमि विवादों से संबंधित; सुप्रीम कोर्ट + हाईकोर्ट + जिला अदालतें अवरुद्ध; DILRMP 3.0 की स्वच्छ अभिलेख = कम विवाद = तेज़ न्याय
PM-SVAMITVA योजना	ग्रामीण बसे हुए भूमि की ड्रोन मानचित्रण; ग्रामीण घर मालिकों को संपत्ति अधिकार; DILRMP 3.0 का पूरक; ग्रामीण भूमि अभिलेखों के लिए

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 शासन: भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण; DILRMP; ULPIN; NGDRS; भूमि मुकदमेबाजी का बोझ; PM-SVAMITVA
- Prelims: DILRMP = डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम; ULPIN = अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या (14-अंकीय); NGDRS = राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली; PM-SVAMITVA = ग्रामीण भूमि की ड्रोन मानचित्रण

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 – सर्वश्रेष्ठ शहर पुरस्कृत, NCAP संकलन जारी

मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

PIB तिथि: 7 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

5वें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण (स्वच्छ वायु सर्वेक्षण) 2026 के पुरस्कार स्वच्छ वायु दिवस 2026 पर प्रदान किए गए और NCAP (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रथाओं का संकलन जारी किया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 131 गैर-प्राप्ति शहरों (जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक – NAAQS – को पूरा करने में विफल रहे और NCAP के तहत हैं) में वायु गुणवत्ता सुधार पर शहरों को रैंक करता है। NCAP 2019 में 20-30% कमी लक्ष्य के साथ शुरू हुआ (2026 तक 40% कमी में संशोधित)। सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धी दबाव बनाता है: यदि शहर सुधार नहीं करते तो स्मार्ट सिटी/अन्य फंडिंग खो देते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का संकलन: सबसे बड़ी वायु गुणवत्ता सुधार दिखाने वाले शहरों ने अपनी विधियाँ साझा कीं – धूल दमन, CNG सार्वजनिक परिवहन, निर्माण धूल मानदंड, औद्योगिक स्टैक निगरानी, फसल अवशेष प्रबंधन।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण	वार्षिक वायु गुणवत्ता सुधार सर्वेक्षण; 131 गैर-प्राप्ति शहर रैंक; पर्यावरण मंत्रालय; स्वच्छ वायु दिवस (7 सितंबर); PM2.5 और PM10 में % सुधार पर शहर रैंक
NCAP – राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम	2019 में लॉन्च; 131 गैर-प्राप्ति शहरों को लक्षित; 2026 तक 40% PM10/PM2.5 कमी लक्ष्य; ₹4,507 करोड़ परिव्यय; शहरों को वायु गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं के लिए NCAP फंड
गैर-प्राप्ति शहर	PM10 और PM2.5 के लिए NAAQS पूरा करने में विफल शहर; 131 शहर; इंडो-गैंगेटिक मैदान (दिल्ली NCR, UP, बिहार) और औद्योगिक समूहों में केंद्रित
NAAQS – राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक	वार्षिक मानक: PM2.5 = 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; PM10 = 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; WHO मानक बहुत सख्त (PM2.5 = 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$); भारत के मानक = अंतरिम लक्ष्य
CAQM – वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग	NCR और आसपास के क्षेत्रों के लिए वैधानिक निकाय (2021); EPCA की जगह; श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP): चरण 1-4; इस सप्ताह HSPCB गैर-अनुपालन पर गंभीर नोट
PRANA पोर्टल	विनियमित वायुमंडल के लिए स्वच्छ वायु अधिसूचना और कार्रवाई के लिए पोर्टल; MoES; शहर-वार प्रदूषण डेटा, NCAP प्रगति ट्रैक; सार्वजनिक डैशबोर्ड

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण: वायु प्रदूषण; NCAP; गैर-प्राप्ति शहर; PM2.5 बनाम PM10; CAQM; GRAP; PRANA पोर्टल; पराली जलाना
- Prelims: NCAP = राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019); 131 गैर-प्राप्ति शहर; NAAQS PM2.5 = 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ वार्षिक; CAQM = वैधानिक निकाय (2021); PRANA पोर्टल; GRAP चरण; स्वच्छ वायु सर्वेक्षण = वार्षिक रैंकिंग

ड्रायलैंड कांग्रेस 2026 – नई दिल्ली, 800+ वैश्विक विशेषज्ञ

मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय / पर्यावरण मंत्रालय

PIB तिथि: 9 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

ड्रायलैंड कांग्रेस 2026 नई दिल्ली में 800+ वैश्विक विशेषज्ञों के साथ आयोजित हुई जो शुष्कभूमि प्रबंधन के छह प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे थे। शुष्कभूमि पृथ्वी की भूमि सतह का लगभग 41% कवर करती हैं और ~2.5 अरब लोगों का समर्थन करती हैं – जिनमें भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्कन पठार के बड़े हिस्से शामिल हैं। भारत में लगभग 228 मिलियन हेक्टेयर शुष्कभूमि है (शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों सहित)। कांग्रेस के छह विषय: भूमि क्षरण और पुनर्स्थापना; शुष्कभूमि में जल प्रबंधन; शुष्कभूमि कृषि और खाद्य सुरक्षा; चरवाहा प्रणाली और आजीविका; जलवायु परिवर्तन अनुकूलन; और शुष्कभूमि के लिए डिजिटल और नवाचार समाधान। भारत की प्रासंगिकता: भारत ने शुष्कभूमि पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण प्रगति की है (2011-2020 में 2.176 करोड़ हेक्टेयर पुनर्स्थापित)।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
ड्रायलैंड कांग्रेस 2026	नई दिल्ली; 800+ वैश्विक विशेषज्ञ; 6 विषय: भूमि क्षरण/पुनर्स्थापना, जल प्रबंधन, शुष्कभूमि कृषि, चरवाहा प्रणाली, जलवायु अनुकूलन, डिजिटल समाधान; UNCCD नीति में फीड
शुष्कभूमि – वैश्विक संदर्भ	पृथ्वी की भूमि सतह का 41%; शुष्क, अर्ध-शुष्क, शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्र; ~2.5 अरब लोग; भारत: ~228 मिलियन हेक्टेयर शुष्कभूमि
UNCCD	मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन; Rio सम्मेलनों में से एक (UNFCCC और CBD के साथ); 1994; 196 दल; भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) प्रमुख ढाँचे के रूप में
LDN – भूमि क्षरण तटस्थता	UNCCD ढाँचा: उत्पादक भूमि का कोई शुद्ध नुकसान नहीं; भारत की Bonn Challenge प्रतिबद्धता (2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर); 2011-2020 में 2.176 करोड़ हेक्टेयर पुनर्स्थापित

भारत की शुष्कभूमि राज्य	राजस्थान (थार मरुस्थल), गुजरात (कच्छ), हरियाणा, महाराष्ट्र (विदर्भ, मराठवाड़ा), कर्नाटक (उत्तरी), दक्कन पठार; ~60% भारत की फसल क्षेत्र = वर्षा-आधारित कृषि
MGNREGA और शुष्कभूमि पुनर्स्थापना	MGNREGA = भारत का प्राथमिक भूमि पुनर्स्थापना उपकरण; वाटरशेड विकास, वृक्षारोपण, मिट्टी संरक्षण कार्य; UNCCD COP17 में भारत के 2.176 करोड़ हेक्टेयर का श्रेय आंशिक रूप से MGNREGA को

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण: शुष्कभूमि; UNCCD; LDN; Bonn Challenge; भारत की पुनर्स्थापना उपलब्धियाँ; चरवाहा प्रणाली; शुष्कभूमि कृषि
- Prelims: UNCCD = मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने का UN सम्मेलन (1994); Rio सम्मेलनों में से एक; LDN = भूमि क्षरण तटस्थता; भारत की शुष्कभूमि ~228 मिलियन हेक्टेयर; Bonn Challenge = 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर (भारत)

वन अधिकार अधिनियम – पहला क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन, बेंगलुरु

मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय

PIB तिथि: 10 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के कार्यान्वयन पर पहला क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हुआ – भारत के ऐतिहासिक जनजातीय अधिकार कानून को कितनी अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है, इसकी एक दुर्लभ आधिकारिक समीक्षा। FRA 2006 (अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम) भारत के सबसे महत्वपूर्ण भूमि अधिकार कानूनों में से एक है – यह वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों (OTFD) में वन अधिकार मान्यता देता और निहित करता है। तीन प्रकार के अधिकार: व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) – वे जिस वन भूमि पर खेती करते हैं उसके लिए पट्टा; सामुदायिक वन अधिकार (CFR) – सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार (बाँस, NTFP, चराई); और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार – वन क्षेत्रों का प्रबंधन, संरक्षण और शासन करने का अधिकार। कार्यान्वयन गहरे रूप से समस्याग्रस्त रहा है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
FRA 2006	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम; ST + OTFD में वन अधिकार निहित करता है; 3 प्रकार: IFR, CFR, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार
IFR – व्यक्तिगत वन अधिकार	वन भूमि पर व्यक्तिगत खेती अधिकार; पट्टा जारी; 13 दिसंबर 2005 (कटऑफ तिथि) तक वास्तविक खेती तक सीमित; परिवार प्रति अधिकतम 4 हेक्टेयर
CFR – सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार: बाँस, NTFP, चराई क्षेत्र, जल निकाय; ग्राम सभा द्वारा प्रबंधित; लाखों जनजातीय परिवारों की आजीविका का स्रोत; कार्यान्वयन अत्यंत खराब
OTFD – अन्य परंपरागत वन निवासी	गैर-जनजातीय लेकिन परंपरागत निवासी जो कम से कम 3 पीढ़ियों (75 वर्ष) से वन में रहते हैं; FRA 2006 में स्पष्ट रूप से शामिल; OTFDs का खराब कवरेज = कार्यान्वयन विफलता
कार्यान्वयन अंतराल	44 लाख दावे दाखिल; ~21 लाख IFR पट्टे वितरित; CFR पट्टे = बहुत कम; लाखों दावे खारिज; वन विभाग प्रतिरोध; राज्य सरकारों की धीमी गति
FRA बनाम वन संरक्षण अधिनियम	FRA 2006 (जनजातीय अधिकार) और वन संरक्षण अधिनियम 1980 (वन संरक्षण) के बीच तनाव; सर्वोच्च न्यायालय के मामले; वन विभाग CFR कार्यान्वयन का विरोध करते हैं

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 राजव्यवस्था/सामाजिक न्याय: FRA 2006; जनजातीय अधिकार; ग्राम सभा शक्तियाँ; IFR बनाम CFR बनाम सामुदायिक वन संसाधन अधिकार; कार्यान्वयन विफलताएं; OTFD परिभाषा
- Prelims: FRA = वन अधिकार अधिनियम 2006; कटऑफ तिथि = 13 दिसंबर 2005; IFR सीमा = 4 हेक्टेयर; ग्राम सभा = कार्यान्वयन निकाय; OTFD = अन्य परंपरागत वन निवासी; जनजातीय कार्य मंत्रालय देखरेख करता है

7वाँ भारत-जापान वनों पर संयुक्त कार्य समूह – बेंगलुरु

मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

PIB तिथि: 8 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

वनों पर 7वीं भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह (JWG) बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुई – वन प्रशासन सहयोग के लिए द्विपक्षीय तंत्र। भारत-जापान वन सहयोग में शामिल है: टिकाऊ वन प्रबंधन, वनीकरण प्रौद्योगिकी (जापान के पास कठिन भू-भाग के लिए उन्नत तकनीकें हैं), वन-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, लकड़ी व्यापार मानक, और REDD+ कार्यान्वयन। जापान दुनिया के सबसे अधिक वनाच्छादित देशों में से एक है (67% वन आवरण) और टिकाऊ वानिकी में अग्रणी है – इसकी सातोयामा अवधारणा (माध्यमिक वनों, खेतों और बस्तियों का मोज़ेक) ने भारत की कृषि-वानिकी सोच को प्रभावित किया। द्विपक्षीय में बाँस विकास भी शामिल है (भारत = चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाँस उत्पादक, जापान के पास उन्नत बाँस उपयोग प्रौद्योगिकी है) और वन कार्बन अनुक्रमण पर संयुक्त अनुसंधान।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
भारत-जापान वन JWG	7वीं बैठक, बेंगलुरु; REDD+; सातोयामा अवधारणा; बाँस सहयोग; वन कार्बन अनुक्रमण; टिकाऊ वन प्रबंधन; आपदा जोखिम न्यूनीकरण; द्विपक्षीय वन प्रशासन तंत्र
जापान का वन प्रोफाइल	67% वन आवरण (दुनिया के सबसे अधिक वनाच्छादित विकसित देशों में से एक); टिकाऊ वानिकी = दीर्घकालीन अभ्यास; J-Credit (जापान का घरेलू कार्बन क्रेडिट); सातोयामा अवधारणा
सातोयामा अवधारणा	पारंपरिक जापानी मोज़ेक परिदृश्य: माध्यमिक वन + खेत + बस्तियाँ एक साथ प्रबंधित; माध्यमिक वन लकड़ी, ईंधन, खाद्य प्रदान करते हैं; भारत की कृषि-वानिकी नीति को प्रभावित किया; UNESCO मान्यता
REDD+	वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन में कमी; संयुक्त राष्ट्र ढाँचा; वन संरक्षण = कार्बन क्रेडिट; भारत की REDD+ राष्ट्रीय रणनीति

बाँस – भारत-जापान सहयोग	भारत = दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाँस उत्पादक (10 मिलियन हेक्टेयर); जापान = उन्नत बाँस प्रौद्योगिकी (संरचनात्मक बाँस, बाँस-आधारित सामग्री); राष्ट्रीय बाँस मिशन (भारत)
पश्चिमी घाट जैव विविधता	UNESCO विश्व विरासत स्थल (2012); दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक; भारत के 30% स्थानिक पौधे; 4 राज्य (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा); गंभीर दबाव में

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण: REDD+; सातोयामा अवधारणा; भारत-जापान वन सहयोग; राष्ट्रीय बाँस मिशन; पश्चिमी घाट जैव विविधता; NDC के लिए वन कार्बन अनुक्रमण
- Prelims: भारत = दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाँस उत्पादक; जापान वन आवरण = 67%; REDD+ = वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन में कमी; सातोयामा = पारंपरिक जापानी परिदृश्य अवधारणा; पश्चिमी घाट = UNESCO विश्व विरासत स्थल (2012)

HPV वैक्सीन – 80 लाख खुराक, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम में मील का पत्थर

मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

PIB तिथि: 11 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत ने सर्वाइकल कैंसर रोकथाम में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया: यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के तहत 80 लाख (8 मिलियन) HPV वैक्सीन खुराक दी गई। भारत ने 2023 में UIP में HPV (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) वैक्सीन शामिल की – एक ऐतिहासिक निर्णय। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है (स्तन कैंसर के बाद), हर साल लगभग 75,000-80,000 मौतें। वैक्सीन: Cervavac भारत की स्वदेशी HPV वैक्सीन है (Serum Institute of India द्वारा विकसित, 2022 में अनुमोदित) – किसी विकासशील देश से दुनिया की पहली चतुर्भुज HPV वैक्सीन। यह HPV प्रकार 16 और 18 को कवर करती है (जो ~70% सर्वाइकल कैंसर के मामलों का कारण)। लक्ष्य समूह: 9-14 वर्ष की लड़कियाँ (यौन शुरुआत से पहले, जब वैक्सीन सबसे प्रभावी है)।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
HPV वैक्सीन – UIP में शामिल	ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन 2023 में UIP में शामिल; 9-14 वर्ष की लड़कियाँ; मुफ्त; स्कूल-आधारित + ASHA/ANM वितरण; 80 लाख खुराक मील का पत्थर
भारत में सर्वाङ्कल कैंसर	भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर (स्तन कैंसर के बाद); ~1.25 लाख नए मामले/वर्ष; ~75,000-80,000 मौतें/वर्ष; HPV प्रकार 16 और 18 = ~70% मामले; वैक्सीन + जाँच से काफी हद तक रोकथाम योग्य
Cervavac – भारत की स्वदेशी वैक्सीन	चतुर्भुज HPV वैक्सीन; Serum Institute of India; CDSCO द्वारा 2022 में अनुमोदित; HPV प्रकार 6, 11, 16, 18 कवर; किसी विकासशील देश से दुनिया की पहली चतुर्भुज HPV वैक्सीन
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP)	दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम; 2.7 करोड़ शिशु/वर्ष; 12 वैक्सीन; MoHFW; ASHA/ANM वितरण; Mission Indradhanush = बिना टीकाकरण वाले बच्चों को पकड़ना; HPV = नवीनतम जोड़
WHO 90-70-90 सर्वाङ्कल कैंसर उन्मूलन रणनीति	15 वर्ष की आयु तक 90% लड़कियों को HPV वैक्सीन; 35 और 45 वर्ष की आयु में 70% महिलाओं की जाँच; 90% महिलाओं का उपचार; भारत इस वैश्विक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 स्वास्थ्य: HPV वैक्सीन; सर्वाङ्कल कैंसर का बोझ; Cervavac; UIP; WHO उन्मूलन रणनीति; Mission Indradhanush
- Prelims: HPV = ह्यूमन पैपिलोमावायरस; Cervavac = भारत की स्वदेशी HPV वैक्सीन (Serum Institute); UIP = यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम; सर्वाङ्कल कैंसर = भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर; Mission Indradhanush = कैच-अप टीकाकरण

राष्ट्रीय पोषण माह 2026 – 9वाँ संस्करण

मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

PIB तिथि: 9 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

9वाँ राष्ट्रीय पोषण माह (राष्ट्रीय पोषण माह) 2026 वाराणसी में लॉन्च हुआ – सितंबर में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला भारत का राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता और कार्रवाई अभियान। पोषण माह POSHAN अभियान का हिस्सा है – कुपोषण को लक्षित करने वाला छत्र कार्यक्रम। भारत का कुपोषण बोझ: 5 वर्ष से कम 35.5% बच्चे बौने हैं (NFHS-5); 19.3% क्षीण; 32.1% कम वजन; 5 वर्ष से कम 67.1% बच्चों और 57% प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया। 2026 का विषय: आहार विविधता, पर्याप्त प्रोटीन सेवन, और ताजा गर्म पका भोजन – कैलोरी-फोकस से आहार गुणवत्ता की ओर बदलाव। POSHAN अभियान के प्रमुख घटक: Poshan Tracker (लाभार्थी पोषण की रियल-टाइम डिजिटल निगरानी), PMMVY (गर्भवती महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण), और आँगनवाड़ी नेटवर्क (1.4 मिलियन आँगनवाड़ी केंद्र = पूरक पोषण और प्रारंभिक बाल विकास के लिए वितरण अग्रिम पंक्ति)।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
राष्ट्रीय पोषण माह	राष्ट्रीय पोषण माह; सितंबर प्रत्येक वर्ष; 9वाँ संस्करण 2026; वाराणसी; आहार विविधता, प्रोटीन, ताजा गर्म भोजन विषय; आँगनवाड़ी नेटवर्क के माध्यम से जागरूकता + कार्रवाई
POSHAN अभियान	PM का समग्र पोषण के लिए व्यापक योजना; 2018; बहु-मंत्रालय अभिसरण (WCD, स्वास्थ्य, खाद्य, ग्रामीण विकास); लक्ष्य: बौनापन, क्षीणता, कम वजन, एनीमिया कम करना; Poshan Tracker
भारत का कुपोषण डेटा (NFHS-5)	बौनापन: 35.5% 5 वर्ष से कम; क्षीणता: 19.3%; कम वजन: 32.1%; 5 वर्ष से कम बच्चों में एनीमिया: 67.1%; महिलाएं (15-49): 57% एनीमिक
आँगनवाड़ी नेटवर्क	1.4 मिलियन आँगनवाड़ी केंद्र; 2.6 करोड़ लाभार्थी; पूरक पोषण, पूर्व-विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण; ICDS वितरण बिंदु; POSHAN अभियान की अग्रिम पंक्ति

Poshan Tracker	रियल-टाइम डिजिटल मंच; आँगनवाड़ी कार्यकर्ता स्मार्टफोन पर डेटा इनपुट करती हैं; बौनापन, क्षीणता कमी की व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी; पेपर-आधारित निगरानी की जगह
PMMVY – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	पहले बच्चे के लिए गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ₹5,000 नकद हस्तांतरण; दूसरे बच्चे के लिए ₹6,000 यदि लड़की है; DBT; ~2 करोड़ लाभार्थी/वर्ष

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 स्वास्थ्य/सामाजिक: POSHAN अभियान; भारत का कुपोषण बोझ (NFHS-5 डेटा); आँगनवाड़ी प्रणाली; PMMVY; Poshan Tracker; ICDS
- Prelims: राष्ट्रीय पोषण माह = सितंबर प्रत्येक वर्ष, 9वाँ संस्करण 2026; POSHAN अभियान = 2018; आँगनवाड़ी केंद्र = 1.4 मिलियन; PMMVY = ₹5,000 नकद हस्तांतरण; Poshan Tracker = रियल-टाइम पोषण निगरानी; बौनापन (NFHS-5) = 35.5%

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस दिवस – बहु-हितधारक कार्यशाला

मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

PIB तिथि: 9 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय फ्लोरोसिस दिवस पर राष्ट्रीय बहु-हितधारक कार्यशाला आयोजित की। फ्लोरोसिस अत्यधिक फ्लोराइड उपभोग से होने वाला एक दुर्बल करने वाला रोग है – मुख्यतः दूषित भूजल के माध्यम से। भारत में फ्लोरोसिस का बोझ: अनुमानित 6.2 करोड़ लोग फ्लोरोसिस के जोखिम में हैं; 20 राज्यों में स्थानिक फ्लोरोसिस समस्या क्षेत्र हैं; सबसे प्रभावित राज्य राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब हैं। दंत फ्लोरोसिस (धब्बेदार, रंगहीन दाँत) सबसे पहली अभिव्यक्ति है; कंकाल फ्लोरोसिस (विकलांग करने वाली हड्डी विकृति) गंभीर रूप है। राष्ट्रीय सुरक्षित पेयजल सीमा फ्लोराइड के लिए 1.5 mg/litre है (WHO भी 1.5 mg/L की सिफारिश करता है)। समाधान: फ्लोराइड हटाने के लिए Nalgonda तकनीक (भारत में NGRI हैदराबाद द्वारा विकसित)।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
फ्लोरोसिस	अत्यधिक फ्लोराइड सेवन से रोग; मुख्यतः दूषित भूजल के माध्यम से; दंत फ्लोरोसिस (धब्बेदार दाँत) से कंकाल फ्लोरोसिस (विकलांग करने वाली विकृति); 6.2 करोड़ जोखिम में, 20 राज्य स्थानिक
प्रभावित राज्य	राजस्थान (उच्चतम: कुछ क्षेत्रों में ~65 mg/L), गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, UP, पंजाब, असम; इंडो-गैंगेटिक मैदान + दक्कन ट्रैप भूविज्ञान = उच्च फ्लोराइड भूजल
सुरक्षित फ्लोराइड सीमा	1.5 mg/litre (WHO; भारत का BIS मानक); दंत फ्लोरोसिस 1.5 mg/L से ऊपर शुरू; 4 mg/L से अधिक लंबे समय तक कंकाल फ्लोरोसिस
Nalgonda तकनीक	NGRI (राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान), हैदराबाद में विकसित फ्लोराइड हटाने की विधि; फिटकरी और चूना उपयोग; कम लागत, सामुदायिक स्तर; नलगोंडा जिले (तेलंगाना) के नाम पर
NPPCF	फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम; MoHFW; निगरानी, फ्लोराइड हटाना, वैकल्पिक जल स्रोत, स्वास्थ्य शिक्षा; जल जीवन मिशन के साथ एकीकृत
जल जीवन मिशन संबंध	JJM लक्ष्य: 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को नल का पानी; परीक्षित स्रोतों से पाइप जल = भूजल फ्लोरोसिस का प्रमुख समाधान; JJM के तहत जल गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु: LESS NOISE. MORE RETENTION.

- GS3 पर्यावरण/स्वास्थ्य: फ्लोरोसिस; भूजल प्रदूषण; Nalgonda तकनीक (NGRI, हैदराबाद); NPPCF; जल जीवन मिशन और जल गुणवत्ता
- Prelims: फ्लोरोसिस = अत्यधिक फ्लोराइड रोग; 6.2 करोड़ जोखिम में; Nalgonda तकनीक = फ्लोराइड हटाने की विधि (NGRI, हैदराबाद); सुरक्षित फ्लोराइड सीमा = 1.5 mg/L; NPPCF = फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम

पृष्ठभूमि: ECLGS 5.0

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय / SIDBI

PIB तिथि: 5 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 भारत की COVID-युग MSME ऋण समर्थन योजना का नवीनतम संस्करण है। ECLGS मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था – COVID-19 से तनावग्रस्त व्यवसायों को पूरी तरह से गारंटीकृत संपार्श्विक-मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करना। इतिहास: ECLGS 1.0 (मई 2020): MSME और व्यावसायिक ऋणों के लिए ₹3 लाख करोड़; ECLGS 2.0 (नवंबर 2020): 26 तनावग्रस्त क्षेत्र; ECLGS 3.0 (मार्च 2021): आतिथ्य, यात्रा; ECLGS 4.0 (अप्रैल 2021): स्वास्थ्य सेवा; ECLGS 5.0 (2026): विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नवीनीकृत समर्थन। ECLGS 5.0 प्रदान करता है: 100% NCGTC (राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी) गारंटी; कोई अतिरिक्त संपार्श्विक नहीं; अधिकतम ऋण = मौजूदा बकाया ऋण का 30%; अवधि = 72 महीने तक। 2020 से कुल ECLGS वितरण: 1.19 करोड़+ खातों में ₹3.67 लाख करोड़+ – भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सरकारी ऋण गारंटी कार्यक्रम।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
ECLGS 5.0	आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0; 100% NCGTC गारंटी; संपार्श्विक-मुक्त; अधिकतम ऋण = बकाया का 30%; 72 महीने; MSME समर्थन योजना का नवीनतम
ECLGS इतिहास	1.0 (मई 2020, ₹3 लाख करोड़, MSME); 2.0 (नवंबर 2020, 26 तनावग्रस्त क्षेत्र); 3.0 (मार्च 2021, आतिथ्य/यात्रा); 4.0 (अप्रैल 2021, स्वास्थ्य सेवा); 5.0 (2026); कुल वितरित ₹3.67 लाख करोड़+ 1.19 करोड़+ खातों में
NCGTC	राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी; वित्तीय सेवा विभाग; ECLGS गारंटियाँ प्रबंधित करता है; सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) भी प्रबंधित करता है

ऋण गारंटी तंत्र	सरकार ऋण डिफॉल्ट जोखिम (गारंटी के माध्यम से) वहन करती है; बैंक बिना संपार्श्विक के उधार देता है; उधारकर्ता को ऋण मिलता है; तंत्र = उच्च-जोखिम क्षेत्र को उधार देने में सरकार जोखिम कम करती है
MSME ऋण अंतराल	भारत का MSME ऋण अंतराल ₹25-30 लाख करोड़ अनुमानित; औपचारिक ऋण केवल ~15-20% MSME तक; ECLGS = आपातकालीन पुल; MUDRA = सामान्य चैनल; SIDBI = शीर्ष MSME वित्त संस्थान

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था: ECLGS तंत्र; NCGTC; ऋण गारंटी; MSME ऋण अंतराल; MUDRA बनाम ECLGS; IBC तनाव और ECLGS
- Prelims: ECLGS = आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना; NCGTC = राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी; ECLGS कुल वितरित = ₹3.67 लाख करोड़+ (1.19 करोड़+ खाते); अधिकतम ऋण = बकाया का 30%; SIDBI = लघु उद्योग विकास बैंक

पृष्ठभूमि: वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम

मंत्रालय: गृह मंत्रालय / ग्रामीण विकास मंत्रालय

PIB तिथि: 6 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (VVP) भारत की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास पहलों में से एक है – विशेष रूप से उत्तरी सीमा (चीन सीमा) के साथ सीमावर्ती गाँवों को लक्षित करती है जो संपर्क, आर्थिक अवसर और बुनियादी सेवाओं की कमी के कारण जनसंख्या खो रहे थे। सुरक्षा तर्क: खाली सीमावर्ती गाँव एक कमज़ोरी हैं। चीन LAC के ठीक उस पार आक्रामक रूप से 'मॉडल गाँव' (Xiaokang गाँव) बना रहा है – VVP आंशिक रूप से भारत की प्रतिक्रिया है। VVP कवरेज: 19 जिले, 46 सीमा ब्लॉक; अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और लद्दाख में; ~2,967 पहचाने गए गाँव (पहले 663 प्राथमिकता)। ₹4,800 करोड़ परिव्यय (चरण 1, 2022-26)।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
-----------	---------

वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम	VVP; MHA + ग्रामीण विकास मंत्रालय; 19 जिले, 46 ब्लॉक; अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख; 2,967 गाँव (663 प्राथमिकता); ₹4,800 करोड़ चरण 1; सीमावर्ती गाँव विकास + सुरक्षा
सुरक्षा तर्क	सीमावर्ती गाँवों से जनसंख्या हानि = निगरानी अंतराल; LAC के उस पार चीन के Xiaokang गाँव = रणनीतिक दर्पण; आबाद सीमावर्ती गाँव = प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली + नरम सुरक्षा
चीन के Xiaokang सीमावर्ती गाँव	LAC के साथ मॉडल गाँव कार्यक्रम; बुनियादी ढाँचा, सुविधाएं, स्थायी बसने वाले; कुछ भारत के दावा किए गए क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) के अंदर बने; VVP = भारत की अपनी तरफ प्रति-रणनीति
BRO – सीमा सड़क संगठन	DGBR; MoD; सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाता और रखरखाव करता है; DSDBO सड़क, अटल सुरंग – ऐतिहासिक BRO परियोजनाएं; VVP BRO संपर्क का पूरक
BSNL SATCOM	दूरदराज सीमावर्ती गाँवों के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट; BSNL का VSAT/SATCOM; VVP इंटरनेट फाइबर के बिना क्षेत्रों में भी प्रदान करता है
McMahon रेखा	अरुणाचल प्रदेश-चीन सीमा; 1914 शिमला कन्वेंशन में खींची गई; चीन विवाद करता है; VVP मैकमोहन रेखा के दक्षिण में नागरिक उपस्थिति स्थापित करता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु: CHOISE. MORE RETENTION.

- **GS2 IR/आंतरिक सुरक्षा:** VVP सीमा सुरक्षा रणनीति के रूप में; चीन के Xiaokang गाँव; LAC; McMahon रेखा; BRO; भारत की उत्तरी सीमा कमज़ोरियाँ
- **Prelims:** VVP = वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम; 19 जिले, 46 ब्लॉक; 5 राज्य/UT; ₹4,800 करोड़ चरण 1; BRO = सीमा सड़क संगठन; Xiaokang = चीन का सीमावर्ती गाँव कार्यक्रम; McMahon रेखा = अरुणाचल प्रदेश-चीन सीमा

पृष्ठभूमि: भारत का नीले आकाश का मार्ग – NCAP

मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

PIB तिथि: 7 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) – 2019 में लॉन्च – 131 गैर-प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए देश का व्यापक ढाँचा है। भारत की वायु गुणवत्ता संकट: IQAir 2023 रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं; सर्दियों के दौरान इंडो-गैंगेटिक मैदान में PM2.5 का स्तर नियमित रूप से WHO दिशानिर्देशों से 10 गुना अधिक होता है। प्रमुख स्रोत: वाहन उत्सर्जन (शहरों में 30-40%), उद्योग (30%), निर्माण धूल (15-20%), फसल अवशेष जलाना (मौसमी, अक्टूबर-नवंबर में पंजाब/हरियाणा → दिल्ली), और बायोमास जलाना। NCAP संरचना: ₹4,507 करोड़; 131 गैर-प्राप्ति शहर; 2026 तक 40% PM10/PM2.5 कमी लक्ष्य; शहर कार्य योजनाएं; स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग; PRANA पोर्टल। प्रगति मिश्रित है: 131 में से 95 शहरों ने सुधार दिखाया।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
NCAP – राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम	2019 में लॉन्च; 131 गैर-प्राप्ति शहर; 2026 तक 40% PM10/PM2.5 कमी; ₹4,507 करोड़; शहर कार्य योजनाएं; स्वच्छ वायु सर्वेक्षण; PRANA पोर्टल
भारत की प्रदूषण रैंकिंग	दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 = भारत (IQAir 2023); Byrnihat (मेघालय, 2023 #1), गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, मुजफ्फरपुर; इंडो-गैंगेटिक मैदान = सबसे खराब वायु गुणवत्ता क्षेत्र
PM2.5 बनाम PM10	PM2.5 (सूक्ष्म कण, <2.5 माइक्रोन): फेफड़ों में प्रवेश, रक्तप्रवाह में, सबसे हानिकारक; PM10 (2.5-10 माइक्रोन): श्वसन समस्याएं; NAAQS: PM2.5 = 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; PM10 = 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; WHO = PM2.5 = 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
पराती जलाने की समस्या	पंजाब: 1.5-2 करोड़ टन/वर्ष; हरियाणा: 1 करोड़ टन/वर्ष; अक्टूबर-नवंबर जलाना → दिल्ली वायु संकट; Happy Seeder (इन-सिटू पुआल प्रबंधन), बायोगैस; किसानों को प्रोत्साहन; अभी भी प्रमुख स्रोत

CAQM – वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग	वैधानिक निकाय (2021); NCR + आसपास के क्षेत्र; GRAP: चरण 1 (मध्यम-खराब), चरण 2 (बहुत खराब), चरण 3 (गंभीर), चरण 4 (गंभीर+); उच्च चरणों में आपातकालीन उपाय
--	---

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण: NCAP वास्तुकला; भारत की प्रदूषण रैंकिंग; PM2.5 बनाम PM10; पराली जलाना; CAQM; GRAP; PRANA पोर्टल; वाहन बनाम औद्योगिक बनाम कृषि स्रोत
- Prelims: NCAP = 2019; 131 गैर-प्राप्ति शहर; NAAQS PM2.5 = 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; CAQM = वैधानिक निकाय (2021); PRANA पोर्टल; GRAP चरण; स्वच्छ वायु सर्वेक्षण; Happy Seeder = इन-सिटू पुआल प्रबंधन

पृष्ठभूमि: जूट – भारत का सोने का रेशा

मंत्रालय: कपड़ा मंत्रालय

PIB तिथि: 7 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का ~60-65%) और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जूट – अपने रंग और आर्थिक महत्व के लिए 'सोने का रेशा' कहलाता है – मुख्यतः पश्चिम बंगाल (भारत के जूट का 85%), बिहार, असम, ओडिशा और त्रिपुरा में उगाया जाता है। भारत का जूट उद्योग: 70+ जूट मिलें (अधिकतर पश्चिम बंगाल के हुगली बेल्ट में), ~3.7 लाख मिल श्रमिक। प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप: जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 – खाद्यान्न (उत्पादन का न्यूनतम 90%) और चीनी पैकेजिंग के लिए जूट बैग का उपयोग अनिवार्य; राष्ट्रीय जूट बोर्ड; JMDC (जूट निर्माण विकास परिषद)। वैश्विक अवसर: बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग विकल्पों की बढ़ती मांग; जूट भू-वस्त्र; और जूट कंपोजिट। भारत की चुनौती: बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा, मिल उत्पादकता में गिरावट।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
जूट प्रोफाइल	भारत = दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक (60-65% वैश्विक) और उपभोक्ता; 'सोने का रेशा'; पश्चिम बंगाल = 85% भारत का जूट; हुगली बेल्ट = मिल सांद्रता; 70+ जूट मिलें; ~3.7 लाख मिल श्रमिक

जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987	खाद्यान्न पैकिंग (उत्पादन का 90%) और चीनी के लिए जूट बैग अनिवार्य; जूट उद्योग के लिए सुरक्षात्मक तंत्र; WTO विवाद; जूट निगम खरीद
राष्ट्रीय जूट बोर्ड	कपड़ा मंत्रालय; बाजार विकास, R&D, जूट क्षेत्र के लिए कौशल विकास; निर्यात प्रोत्साहन; विविध उत्पाद (जूट भू-वस्त्र, कंपोजिट, फैशन); JCI = जूट निगम
जूट भू-वस्त्र	मिट्टी स्थिरीकरण, सड़क निर्माण, ढलान संरक्षण के लिए बुना हुआ जूट कपड़ा; 2-3 वर्षों में बायोडिग्रेडेबल, मिट्टी को समृद्ध करता है; NHA राष्ट्रीय राजमार्गों पर जूट भू-वस्त्र; ₹150 करोड़+ बाजार
बांग्लादेश प्रतिस्पर्धा	बांग्लादेश = वैश्विक जूट उत्पादन का 25-30%; कम श्रम लागत; EU तक शुल्क-मुक्त पहुँच; भारत-बांग्लादेश जूट व्यापार जटिल – भारत कच्चा जूट आयात करता है, निर्मित वस्तुएं निर्यात करता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था/कृषि: जूट उद्योग; जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987; राष्ट्रीय जूट बोर्ड; भू-वस्त्र; जूट कंपोजिट; भारत-बांग्लादेश जूट व्यापार
- Prelims: भारत = दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक (60-65% वैश्विक); 'सोने का रेशा'; पश्चिम बंगाल = 85% भारत का जूट; जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम = 1987; राष्ट्रीय जूट बोर्ड = कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत; JCI = जूट निगम

LESS NOISE. MORE RETENTION.

पृष्ठभूमि: हर स्कूल, एक मॉडल स्कूल

मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय

PIB तिथि: 9 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

'हर स्कूल, एक मॉडल स्कूल' NEP 2020 और PM SHRI (PM Schools for Rising India) योजना के तहत व्यक्त दृष्टिकोण है – यह महत्वाकांक्षा कि भारत का प्रत्येक स्कूल, 2030 तक, NEP 2020 के सिद्धांतों को साकार करे: समग्र, बहु-विषयक, गतिविधि-आधारित शिक्षा; 21वीं सदी के कौशल (आलोचनात्मक सोच, सहयोग, रचनात्मकता, संचार); प्रारंभिक

ग्रेड में मातृभाषा माध्यम; डिजिटल साक्षरता; खेल और कला एकीकरण; और बैगलेस दिन। PM SHRI योजना (2022): ₹27,360 करोड़; 14,500 PM SHRI स्कूलों को NEP 2020 के लिए मॉडल स्कूलों और आसपास के स्कूलों के लिए मार्गदर्शक के रूप में विकसित करना। 'मॉडल स्कूल' अवधारणा का एक लंबा इतिहास है: केंद्रीय विद्यालय (1,251 स्कूल) और नवोदय विद्यालय (649 JNV) भारत के मूल मॉडल स्कूल नेटवर्क थे। NEP की दृष्टि आगे जाती है: हर सरकारी स्कूल, न केवल चुने हुए स्कूल।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
PM SHRI योजना	PM Schools for Rising India; 2022; ₹27,360 करोड़; 14,500 स्कूल NEP 2020 के मॉडल और मार्गदर्शक; बुनियादी ढाँचा, स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान; विद्या समीक्षा केंद्र स्कूलों का चयन करता है
NEP 2020 स्कूल दृष्टिकोण	5+3+3+4 संरचना (आधारभूत 5-8 वर्ष, प्रारंभिक 8-11, मध्य 11-14, माध्यमिक 14-18); मातृभाषा माध्यम (ग्रेड 1-5); गतिविधि-आधारित शिक्षा; 21वीं सदी के कौशल; बैगलेस दिन; कला एकीकरण
केंद्रीय विद्यालय (KV)	1,251 KV; मुख्यतः केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए; MoE; स्वायत्त; CBSE; KV संगठन; SC/ST/BPL के लिए शुल्क छूट के माध्यम से समानता
नवोदय विद्यालय (NV)	649 JNV; प्रत्येक जिले में एक (कुछ राज्यों को छोड़कर); आवासीय; ग्रामीण मेधावी छात्रों के लिए; मुफ्त शिक्षा + बोर्डिंग; नवोदय विद्यालय समिति (NVS)
विद्या समीक्षा केंद्र	राज्य-स्तरीय शिक्षा डेटा विश्लेषण केंद्र; छात्र उपस्थिति, शिक्षण परिणाम, शिक्षक तैनाती की रियल-टाइम ट्रैकिंग; Diksha प्लेटफॉर्म को डेटा फीड करता है; PM SHRI स्कूल चयन
NIPUN Bharat	ग्रेड 3 तक आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान 2026-27 तक; MoE; FLN (Foundational Literacy and Numeracy) मिशन; DIKSHA प्लेटफॉर्म सामग्री; प्रारंभिक बचपन शिक्षा में कमजोरी को संबोधित

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 शिक्षा: NEP 2020 स्कूल संरचना; PM SHRI; KV बनाम JNV; विद्या समीक्षा केंद्र; DIKSHA; NIPUN Bharat; भारत की स्कूल प्रणाली का पैमाना (1.48 मिलियन स्कूल)
- Prelims: PM SHRI = PM Schools for Rising India (₹27,360 करोड़, 14,500 स्कूल); KV = 1,251 स्कूल; JNV = 649 स्कूल; NEP 2020 स्कूल संरचना = 5+3+3+4; NIPUN Bharat = ग्रेड 3 तक आधारभूत साक्षरता

पृष्ठभूमि: BRICS और नीली अर्थव्यवस्था

मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय / विदेश मंत्रालय

PIB तिथि: 11 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

18वें BRICS शिखर सम्मेलन का BRICS और नीली अर्थव्यवस्था पृष्ठभूमि BRICS सहयोग के समुद्री और महासागर अर्थव्यवस्था आयामों को संदर्भित करता है। BRICS राष्ट्र सामूहिक रूप से: दुनिया की 10 सबसे बड़ी समुद्री अर्थव्यवस्थाओं में से 5; विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) कवर करते हुए; महत्वपूर्ण मत्स्य पालन उद्योग; गहरे समुद्री खनन महत्वाकांक्षाएं; और प्रमुख शिपिंग मार्ग। भारत की नीली अर्थव्यवस्था योगदान: GDP का ~4% (~\$200 अरब), 2030 तक 10% लक्ष्य। BRICS नीली अर्थव्यवस्था सहयोग क्षेत्र: गहरे समुद्री खनिज अन्वेषण (बहुधातु नोड्यूल, कोबाल्ट-समृद्ध क्रस्ट); टिकाऊ मत्स्य पालन (IUU मछली पकड़ने का मुकाबला); समुद्री संपर्क; महासागर जलवायु अनुसंधान (नीला कार्बन – तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कार्बन अनुक्रमण: मेंग्रोव, समुद्री घास, नमक के दलदल); और समुद्री सुरक्षा सहयोग।

मुख्य शब्द: LESS NOISE. MORE RETENTION.

शब्द / पद	परिभाषा
BRICS नीली अर्थव्यवस्था	5 में से 10 सबसे बड़ी समुद्री अर्थव्यवस्थाएं; विशाल EEZ; मत्स्य पालन, गहरे समुद्री खनन, शिपिंग, महासागर जलवायु अनुसंधान; NDB वित्त पोषण; भारत की नीली अर्थव्यवस्था = ~\$200 अरब, 2030 तक 10% GDP

नीला कार्बन	तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहीत कार्बन: मैंग्रोव, समुद्री घास, नमक के दलदल, ज्वारीय मैदान; वनों की तुलना में तेज़ कार्बन अनुक्रमण; भारत: 4,975 वर्ग किमी मैंग्रोव (वैश्विक 3rd); UNFCCC नीला कार्बन क्रेडिट
IUU मत्स्य पालन	अवैध, अनिर्धारित, अनियमित मत्स्य पालन; मछली भंडार को समाप्त करता है; दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर = प्रमुख IUU क्षेत्र; चीन का दूरस्थ जल मछली पकड़ने का बेड़ा = दुनिया का सबसे बड़ा, IUU का आरोप
EEZ – अनन्य आर्थिक क्षेत्र	आधार रेखा से 200 समुद्री मील; तटीय राज्य को संसाधन अन्वेषण/दोहन के लिए संप्रभु अधिकार; भारत का EEZ = 2.37 मिलियन वर्ग किमी
गहरे समुद्री खनन	भारत (मध्य हिंद महासागर बेसिन), ब्राजील (अटलांटिक), रूस (प्रशांत, आर्कटिक) के पास ISA-आवंटित अन्वेषण क्षेत्र हैं; BRICS गहरे समुद्री खनिज प्रौद्योगिकी पर सहयोग कर सकता है

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण/अर्थव्यवस्था: नीली अर्थव्यवस्था; नीला कार्बन (मैंग्रोव, समुद्री घास, नमक के दलदल); IUU मत्स्य पालन; EEZ; गहरे समुद्री खनन; NDB की भूमिका
- Prelims: नीला कार्बन = मैंग्रोव + समुद्री घास + नमक के दलदल; भारत का मैंग्रोव = 4,975 वर्ग किमी (वैश्विक 3rd); EEZ = 200 समुद्री मील; IUU = अवैध अनिर्धारित अनियमित मत्स्य पालन; भारत की नीली अर्थव्यवस्था = ~\$200 अरब

LESS NOISE. MORE RETENTION.

पृष्ठभूमि: सम्मान के साथ किसानों के भविष्य को सुरक्षित करना

मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

PIB तिथि: 11 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

यह BRICS-सप्ताह की पृष्ठभूमि भारत की कृषि आय समर्थन और सामाजिक सुरक्षा वास्तुकला को संदर्भित करती है।

प्रमुख स्तंभ: PM-KISAN (किसान परिवारों को ₹6,000/वर्ष प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण); PM फसल बीमा योजना (फसल

बीमा, खरीफ के लिए 2% प्रीमियम, रबी के लिए 1.5%); PM किसान मानधन योजना (PM-KMDY – छोटे/सीमांत किसानों के लिए पेंशन: 60 वर्ष की आयु में ₹3,000/माह, सरकार द्वारा स्व-योगदान के बराबर); eNAM (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार – फसल मूल्य खोज के लिए ऑनलाइन मंच, 1,000+ मंडियाँ जुड़ी); किसान क्रेडिट कार्ड (KCC, 7% ब्याज पर खेती की जरूरतों के लिए घूर्णन ऋण – ब्याज सब्सिडी के बाद प्रभावी 4%); और PM किसान सम्मान सम्मेलन (वार्षिक कार्यक्रम जहाँ PM KISAN किस्ते हस्तांतरित करते हैं)। पृष्ठभूमि में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी शामिल है – 23 फसलों के लिए (बुआई से पहले घोषित) और CACP (कृषि लागत और मूल्य आयोग) की सलाहकार भूमिका।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
PM-KISAN	PM किसान सम्मान निधि; ₹6,000/वर्ष 3 किस्तों में ₹2,000; 8.5 करोड़+ किसान परिवार; बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण; छोटे और सीमांत किसान (भूमि जोत 2 हेक्टेयर तक, अब सभी)
PM किसान मानधन योजना (PM-KMDY)	छोटे/सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना; 60 वर्ष पर ₹3,000/माह; स्व-योगदान ₹55-200/माह (आयु-संबद्ध), सरकार बराबर मिलाती है; स्वैच्छिक; LIC कार्यान्वयन; 5 करोड़ किसानों का लक्ष्य
eNAM	इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार; ऑनलाइन मंच; 1,000+ APMC मंडियाँ जुड़ी; मूल्य खोज; बिचौलियों को कम करता है; किसान पूरे भारत में खरीदारों को बेच सकते हैं
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	खेती के लिए अल्पकालिक घूर्णन ऋण; 7% ब्याज (₹3 लाख तक समय पर चुकाने पर सब्सिडी के बाद 4%); खेती + संबद्ध + गैर-खेती गतिविधियाँ; 7+ करोड़ KCC धारक
MSP तंत्र	23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य; CACP सिफारिश करता है; कैबिनेट अनुमोदन; C2+50% फॉर्मूला स्वामीनाथन आयोग द्वारा सिफारिश; वास्तविक खरीद: FCI (गेहूँ/चावल), NAFED (तिलहन/दालें)

CACP	कृषि लागत और मूल्य आयोग; सलाहकार निकाय; MSP की सिफारिश करता है; उत्पादन लागत (A2, A2+FL, C2), बाजार रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता विचार करता है; वैधानिक नहीं
------	--

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 कृषि: PM-KISAN; PM-KMDY; eNAM; KCC; MSP तंत्र; CACP; किसान आय समर्थन वास्तुकला; स्वामीनाथन आयोग (C2+50% फॉर्मूला)
- Prelims: PM-KISAN = ₹6,000/वर्ष (3 किस्में); PM-KMDY = 60 पर ₹3,000/माह पेंशन; eNAM = 1,000+ मंडियाँ; KCC ब्याज = 7% (सब्सिडी के बाद 4%); CACP = कृषि लागत और मूल्य आयोग; MSP 23 फसलों को कवर करता है

NHRC स्वतः संज्ञान – गरियाबंद, छत्तीसगढ़ में अधूरे पुल से बच्चों का आवागमन

मंत्रालय: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

PIB तिथि: 9 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में एक अधूरे पुल से गुजरने के लिए मजबूर स्कूली बच्चों द्वारा उठाए जा रहे खतरों के बारे में स्वतः संज्ञान लिया। बच्चों को कमर तक गहरे पानी में चलते या अधूरी पुल संरचनाओं से लटकते हुए दिखाने वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए थे। NHRC ने छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन को 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगते हुए नोटिस जारी किए। स्वतः संज्ञान का अर्थ है NHRC ने बिना किसी औपचारिक शिकायत के स्वयं कार्रवाई शुरू की – एक शक्ति जिसका वह मानवाधिकार उल्लंघन की मीडिया रिपोर्ट मिलने पर प्रयोग करता है। यह मामला दर्शाता है: बुनियादी ढांचा वितरण की विफलता; शिक्षा का अधिकार और सुरक्षित आवागमन; और LWE-प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी बुनियादी ढांचे के लिए राज्य सरकारों की जवाबदेही। गरियाबंद जिले में महत्वपूर्ण जनजातीय जनसंख्या है और यह छत्तीसगढ़ में LWE-प्रभावित जिला है।

मुख्य शब्द:

शब्द / पद	परिभाषा
-----------	---------

NHRC स्वतः संज्ञान	NHRC बिना औपचारिक शिकायत के स्वयं कार्रवाई शुरू करता है; मीडिया रिपोर्ट पर आधारित; राज्य/जिला अधिकारियों को नोटिस जारी करता है; अनुपालन रिपोर्ट मांगता है; अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ; मुआवजे की सिफारिश कर सकता है
NHRC – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	वैधानिक निकाय; मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993; अध्यक्ष = सेवानिवृत्त CJI; सदस्य = सेवानिवृत्त SC न्यायाधीश + अन्य विशेषज्ञ; मानवाधिकार उल्लंघन की जांच; उपचार की सिफारिश; दंडित करने की कोई शक्ति नहीं
गरियाबंद, छत्तीसगढ़	LWE (वामपंथी उग्रवाद/नक्सल) प्रभावित जिला; महत्वपूर्ण जनजातीय जनसंख्या; बुनियादी ढाँचा घाटा = विकास विफलता और नक्सल भर्ती चालक दोनों; PMGSY (ग्रामीण सड़क संपर्क) लक्ष्य क्षेत्र
सुरक्षित आवागमन का अधिकार	अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) में निहित; बच्चों का शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A); अधूरा बुनियादी ढाँचा = मूल अधिकारों का उल्लंघन; NHRC का हस्तक्षेप = बुनियादी ढाँचे के प्रति अधिकार-आधारित दृष्टिकोण
PMGSY और पुल पूर्णता	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना; ग्रामीण सड़क संपर्क; पुल शामिल; LWE-प्रभावित जिलों को PMGSY-III के तहत प्राथमिकता; अपूर्णता = कार्यान्वयन विफलता
LWE जिले और बुनियादी ढाँचा	76 LWE-प्रभावित जिले; बुनियादी ढाँचा = प्रतिउग्रवाद उपकरण; NHRC LWE क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा विफलताओं को उजागर करना = अधिकारों और सुरक्षा प्रवचन का अभिसरण

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 राजव्यवस्था: NHRC स्वतः संज्ञान शक्तियाँ; मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993; NHRC संरचना (अध्यक्ष = सेवानिवृत्त CJI); अर्ध-न्यायिक प्रकृति; अनुच्छेद 21 और मूल बुनियादी ढाँचा
- GS3 आंतरिक सुरक्षा: LWE (नक्सलवाद); LWE जिलों में बुनियादी ढाँचा प्रतिउग्रवाद के रूप में; PMGSY संघर्ष क्षेत्रों में

- Prelims: NHRC = राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित; अध्यक्ष = सेवानिवृत्त CJI; स्वतः संज्ञान = स्व-प्रारंभिक; गरियाबंद = छत्तीसगढ़ LWE जिला
-



SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

सम्माननीय उल्लेख

वे तथ्य जो मुख्य लेखों में नहीं आए – लेकिन UPSC Prelims में सीधे पूछे जाते हैं।

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
भारत-मोरक्को संयुक्त रक्षा समिति	उद्घाटन JDC, नई दिल्ली; मोरक्को = 70%+ विश्व फॉस्फेट भंडार; जिब्राल्टर = अटलांटिक-भूमध्यसागरीय चोक बिंदु	GS2 IR: भारत-अफ्रीका रक्षा; मोरक्को-EU-अफ्रीका प्रवेश द्वार; भारत-मोरक्को बहु-क्षेत्रीय संबंध
वीर गार्जियन-2026	IAF + JASDF द्विपक्षीय वायु अभ्यास; उद्घाटन 2023; BVR, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध; Quad वायु अंतर-संचालनीयता	GS2/GS3: Quad सैन्य अभ्यास; ACSA (2020); 2+2 मंत्रिस्तरीय; IAF Su-30MKI/Rafale; JASDF F-15J/F-35A
IAF DRONATHON 2026	IAF ड्रोन नवाचार मंच; loitering munitions, काउंटर-ड्रोन, झुंड ड्रोन; ड्रोन PLI = ₹120 करोड़ (2022)	GS3: ड्रोन PLI; DRONATHON; loitering munitions; काउंटर-ड्रोन; iDEX; Ideaforge = सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी
BRICS बिज़नेस फोरम + पुतिन	PM मोदी 18वें BRICS शिखर पर; पुतिन द्विपक्षीय; रक्षा, Kudankulam, ऊर्जा; BRICS-10 (2024 विस्तार)	GS2: BRICS-10 सदस्य; NDB; भारत की ग्लोबल साउथ स्थिति; भारत-रूस यूक्रेन-उत्तर; डी-डॉलरीकरण
भारत-रूस \$100 अरब व्यापार	गोयल INNOPROM India 2026 में; वर्तमान ~\$65-70 अरब; रुपया-रुबल; INSTC; Vladivostok समुद्री गलियारा	GS2: CAATSA; भारत-रूस द्विपक्षीय; रणनीतिक स्वायत्तता; INSTC; Vladivostok-चेन्नई समुद्री गलियारा
9वीं ASEAN-भारत कृषि मंत्रिस्तरीय	नई दिल्ली; खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि; भारत = दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक; ताड़ तेल (~90 लाख टन/वर्ष)	GS2/GS3: ASEAN-भारत FTA (2010); ताड़ तेल (इंडोनेशिया + मलेशिया); भारत क्षेत्रीय खाद्य प्रदाता; Act East Policy

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
6G कार्रवाई का आह्वान	DoT ने अंतर्राष्ट्रीय 6G नेतृत्व और सुरक्षा ढाँचे का समर्थन; भारत 6G दृष्टि (₹400 करोड़); BSNL 100% स्वदेशी 4G/5G	GS3: 6G; भारत 6G दृष्टि; विश्वसनीय विक्रेता ढाँचा (Huawei/ZTE प्रतिबंध); ITU; 3GPP मानक निकाय
BRICS भारत इनोवेट्स	11-12 सितंबर, भारत मंडपम; DPI (UPI, Aadhaar, ABDM, ONDC); IN-SPACE; जैव-प्रौद्योगिकी; DPI = BRICS 'निर्यात'	GS2/GS3: भारत BRICS अध्यक्षता 2026; DPI पारिस्थितिकी तंत्र; ONDC = ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स; IN-SPACE
IndiaAI Mission- स्वीडन SITAC	AI और डिजिटलीकरण रणनीतिक सहयोग; IndiaAI Mission (₹10,372 करोड़); AIRAWAT; EU AI अधिनियम 2024	GS3: IndiaAI Mission स्तंभ; AIRAWAT; EU AI अधिनियम 2024 = जोखिम-आधारित; Ericsson-भारत 5G; AI शासन
बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम 2026	1891 के औपनिवेशिक अधिनियम की जगह; 1 अक्टूबर 2026 से; डिजिटल बैंक रिकॉर्ड स्वीकार्य; DRT, PMLA, IBC सहायता	GS2: औपनिवेशिक कानून आधुनिकीकरण; DRT = ऋण वसूली न्यायाधिकरण; PMLA; IBC; डिजिटल साक्ष्य
e-FAST India + PACT	नीति आयोग; शून्य-उत्सर्जन माल; ZET बाज़ार; वाणिज्यिक वाहन = 12% बेड़ा, 40% सड़क CO ₂ ; स्वर्णिम चतुर्भुज माल	GS3: माल कार्बन-मुक्तीकरण; EV; ZET; नीति आयोग e-FAST; स्वर्णिम चतुर्भुज = दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता
FRI – ₹5,000+ करोड़ रोका	DoT; साइबर धोखाधड़ी मोबाइल नंबरों को जोखिम स्कोर; संचार साथी (FRI + CEIR + TAF COP)	GS3: संचार साथी; CEIR = चोरी फोन ब्लॉकिंग; TAF COP = SIM ट्रेकिंग; I4C (MHA); साइबर अपराध हेल्पलाइन = 1930

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
NSO जिला स्तरीय अनौपचारिक डेटा	पहली बार असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के जिला अनुमान; ASUSE; ~110 मिलियन अनौपचारिक श्रमिक; लक्षित MSME नीति	GS3: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था; NSO; ASUSE; औपचारिकीकरण; MUDRA; PM SVANidhi; सांख्यिकीय कवरेज
भारत – वैश्विक जहाज केंद्र	सोनोवाल; 2,40,000+ नाविक (9% वैश्विक) लेकिन केवल 5-6% व्यापार भारतीय जहाजों पर; GIFT IFSC जहाज पट्टा	GS3: समुद्री भारत दृष्टि 2030; सागरमाला; GIFT IFSC; भारत का नौवहन विरोधाभास; ग्रीक/जापानी मॉडल
ई-कॉमर्स नियम संशोधित 2026	उत्पत्ति देश अनिवार्य; फ्लैश बिक्री विनियमन; मार्केटप्लेस देयता; कोई संबंधित पक्ष वरीयता नहीं; CCPA; CCI	GS2/GS3: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019; CCPA; CCI; डिजिटल बाजार विनियमन; Amazon-Flipkart प्रकार की व्यवस्थाएं
ORV सागर मंथन	भारत का सबसे उन्नत महासागर अनुसंधान पोत; गहरे महासागर मिशन + समुद्रयान (MATSYA 6000); बहुधातु नोड्यूल; NIOT	GS3: गहरे महासागर मिशन (₹4,077 करोड़); समुद्रयान; MATSYA 6000 (6,000 मीटर); बहुधातु नोड्यूल = महत्वपूर्ण खनिज
कार्बनिक अणु स्व- संयोजन – हरित H ₂	प्रकाश-उत्प्रेरक जल विभाजन; स्व-संयोजित नैनोसंरचनाएं; संभावित सस्ता हरित हाइड्रोजन मार्ग; NGHM (\$1/किग्रा)	GS3: हरित हाइड्रोजन मार्ग; NGHM (₹17,490 करोड़); प्रकाश-उत्प्रेरक बनाम विद्युत-अपघटन; भारत की कार्बनिक रसायन शक्ति
क्वांटम उलझन सफलता	उलझन शुद्धि – क्वांटम अवस्था मापे बिना 'ताज़गी'; क्वांटम संचार सीमा बढ़ाता है; क्वांटम दोहराव	GS3: क्वांटम उलझन; विसंगति; क्वांटम दोहराव; क्वांटम इंटरनेट; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (₹6,003 करोड़)

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
DILRMP 3.0	₹565.50 करोड़; रियल-टाइम दाखिल-खारिज, Aadhaar, GIS, NGDRS; ULPIN (14-अंकीय); 66% दीवानी मामले = भूमि विवाद	GS2 शासन: DILRMP; ULPIN; NGDRS; भूमि अभिलेख; PM-SVAMITVA; भूमि मुकदमेबाजी बोझ
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026	131 गैर-प्राप्ति शहर रैंक; NCAP सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं; CAQM HSPCB गैर-अनुपालन पर गंभीर नोट; PRANA पोर्टल	GS3: NCAP; गैर-प्राप्ति शहर; PM2.5 NAAQS = 40 µg/m³; GRAP; स्वच्छ वायु दिवस = 7 सितंबर
ड्रायलैंड कांग्रेस 2026	नई दिल्ली, 800+ वैश्विक विशेषज्ञ; UNCCD; LDN; भारत की ~228 मिलियन हेक्टेयर शुष्कभूमि; Bonn Challenge	GS3: UNCCD (1994); LDN; Bonn Challenge; भारत के शुष्कभूमि राज्य; चरवाहा समुदाय; Rio सम्मेलन
वन अधिकार अधिनियम – क्षेत्रीय समीक्षा	पहला क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन, बेंगलुरु; FRA 2006; IFR (4 हेक्टेयर सीमा) + CFR + सामुदायिक वन संसाधन; ~21 लाख पट्टे	GS2 राजव्यवस्था: FRA 2006; IFR बनाम CFR; ग्राम सभा; OTFD; कटऑफ तिथि = 13 दिसंबर 2005
7वाँ भारत-जापान वन JWG	बेंगलुरु; REDD+; सातोयामा अवधारणा; बाँस (भारत = 2nd सबसे बड़ा); पश्चिमी घाट; वन कार्बन अनुक्रमण	GS3: REDD+; सातोयामा; राष्ट्रीय बाँस मिशन; पश्चिमी घाट = UNESCO WH (2012)
HPV वैक्सीन – 80 लाख खुराक	Cervavac (Serum Institute); UIP में 2023; 9-14 वर्ष की लड़कियाँ; सर्वाइकल कैंसर = महिलाओं में दूसरा सबसे आम; ~75,000 मौतें	GS2 स्वास्थ्य: HPV वैक्सीन; Cervavac; UIP; WHO 90-70-90; Mission Indradhanush

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
राष्ट्रीय पोषण माह 2026	9वाँ संस्करण; सितंबर; वाराणसी; आहार विविधता, प्रोटीन; POSHAN अभियान (2018); आँगनवाड़ी = 1.4 मिलियन; NFHS-5 बौनापन = 35.5%	GS2 स्वास्थ्य: POSHAN अभियान; ICDS; Poshan Tracker; PMMVY; भारत का कुपोषण डेटा
राष्ट्रीय फ्लोरोसिस दिवस	6.2 करोड़ जोखिम में; 20 स्थानिक राज्य; Nalgonda तकनीक (NGRI, हैदराबाद); सुरक्षित सीमा = 1.5 mg/L; NPPCF; JJM समाधान	GS3/GS2: फ्लोरोसिस; भूजल प्रदूषण; Nalgonda तकनीक; NGRI; जल जीवन मिशन; NPPCF
ECLGS 5.0	100% NCGTC गारंटी; अधिकतम 30% बकाया; 72 महीने; कुल वितरित ₹3.67 लाख करोड़ 1.19 करोड़+ खातों में	GS3: NCGTC; ऋण गारंटी; MSME ऋण अंतराल; IBC कुशन; MUDRA बनाम ECLGS; आत्मनिर्भर भारत पैकेज
वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम	19 जिले, 46 ब्लॉक; AP, सिक्किम, उत्तराखंड, HP, लद्दाख; ₹4,800 करोड़; चीन के Xiaokang गाँव; BRO + SATCOM + सौर	GS2: VVP; सीमा सुरक्षा; चीन Xiaokang; LAC; McMahon रेखा; BRO; PMGSY सीमावर्ती क्षेत्रों में
NCAP – नीले आकाश का मार्ग	131 गैर-प्राप्ति शहर; 2026 तक 40% PM10/PM2.5; CAQM; GRAP चरण 1-4; PRANA पोर्टल; Happy Seeder; Byrnihat = 2023 सबसे प्रदूषित	GS3: NCAP; PM2.5 बनाम PM10; पराली जलाना; वाहन/औद्योगिक/कृषि स्रोत; CAQM (वैधानिक, 2021)
जूट – सोने का रेशा	भारत = सबसे बड़ा उत्पादक (60- 65%); पश्चिम बंगाल 85%; हुगली बेल्ट; जूट पैकेजिंग अधिनियम 1987; भू-वस्त्र; जूट कंपोजिट	GS3: जूट उद्योग; जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987; राष्ट्रीय जूट बोर्ड; भू- वस्त्र; JCI; भारत-बांग्लादेश व्यापार

विषय	मुख्य तथ्य	UPSC कोण
हर स्कूल, मॉडल स्कूल	PM SHRI (₹27,360 करोड़, 14,500 स्कूल); NEP 2020 दृष्टिकोण; KV (1,251) + JNV (649); विद्या समीक्षा केंद्र; NIPUN Bharat	GS2: NEP 2020 स्कूल संरचना (5+3+3+4); PM SHRI; KV संगठन; NVS; NIPUN Bharat; DIKSHA
BRICS और नीली अर्थव्यवस्था	समुद्री सहयोग; नीला कार्बन (मैंग्रोव + समुद्री घास + नमक के दलदल); IUU मत्स्य पालन; भारत मैंग्रोव = 4,975 वर्ग किमी (3rd); EEZ = 200 nm	GS3: नीली अर्थव्यवस्था; नीला कार्बन; IUU; EEZ; गहरे समुद्री खनन; NDB वित्त पोषण
किसानों का भविष्य	PM-KISAN (₹6,000/वर्ष, 8.5 करोड़ परिवार); PM-KMDY (60 पर ₹3,000 पेंशन); eNAM (1,000+ मंडियाँ); KCC; MSP 23 फसलें	GS3: CACP; स्वामीनाथन C2+50%; eNAM; KCC; PM-KISAN; PM-KMDY
NHRC स्वतः संज्ञान – गरियाबंद	बच्चे अधूरे पुल से; मैनपुर ब्लॉक, गरियाबंद, छत्तीसगढ़; NHRC नोटिस; LWE प्रभावित जिला; अनुच्छेद 21	GS2: NHRC शक्तियाँ; मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993; अध्यक्ष = सेवानिवृत्त CJI; स्वतः संज्ञान; LWE बुनियादी ढाँचा

SITOK IAS
LESS NOISE. MORE RETENTION.

अभ्यास प्रश्न

10 Prelims प्रश्न – UPSC शैली

प्र.1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) परिवार प्रति अधिकतम 4 हेक्टेयर तक सीमित हैं।
2. IFR के लिए वन भूमि कब्जे का कटऑफ तिथि 13 दिसंबर 2005 है।
3. सामुदायिक वन अधिकार (CFR) सामुदायिक संसाधनों पर सामूहिक अधिकारों के रूप में ग्राम सभा में निहित हैं।
4. यह अधिनियम केवल अनुसूचित जनजातियों को कवर करता है और अन्य परंपरागत वन निवासियों (OTFD) तक विस्तारित नहीं होता।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक

प्र.2. अभिकथन (A): 6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के आह्वान का भारत का समर्थन महत्वपूर्ण है क्योंकि 6G मानक-निर्धारण के भूराजनीतिक निहितार्थ हैं।

कारण (R): BSNL के लिए निर्मित भारत का स्वदेशी 4G/5G कोर नेटवर्क (100% घरेलू प्रौद्योगिकी) और भारत 6G दृष्टिकोण (₹400 करोड़) भारत को प्रौद्योगिकी मानक-अनुसरणकर्ता के बजाय प्रौद्योगिकी मानक-निर्धारक के रूप में स्थापित करते हैं।

- (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
- (b) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
- (c) A सही है लेकिन R गलत है
- (d) A गलत है लेकिन R सही है

प्र.3. निम्नलिखित योजनाओं को उनके सही विवरणों से सुमेलित कीजिए:

सूची I (योजना)

सूची II (विवरण)

1. PM-KISAN P. छोटे/सीमांत किसानों को 60 वर्ष पर ₹3,000/माह पेंशन
 2. PM-KMDY Q. किसान परिवारों को ₹6,000/वर्ष प्रत्यक्ष आय सहायता
 3. eNAM R. मूल्य खोज के लिए 1,000+ कृषि मंडियाँ जोड़ने वाला ऑनलाइन मंच
 4. किसान क्रेडिट कार्ड S. 7% ब्याज पर खेती के लिए घूर्णन ऋण (सब्सिडी के बाद 4%)
- (a) 1-Q, 2-P, 3-R, 4-S
 (b) 1-P, 2-Q, 3-S, 4-R
 (c) 1-Q, 2-R, 3-P, 4-S
 (d) 1-R, 2-S, 3-Q, 4-P

प्र.4. BRICS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. BRICS का 2024 में ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया और सऊदी अरब को शामिल करते हुए BRICS-10 में विस्तार हुआ।
2. नव विकास बैंक (NDB) का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
3. भारत 2026 के लिए BRICS की अध्यक्षता करता है और उसने 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन आयोजित किया।
4. नव विकास बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर में ऋण देता है।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल दो
 (b) केवल तीन
 (c) सभी चार
 (d) केवल एक

SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

प्र.5. अभिकथन (A): Nalgonda तकनीक भारत की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

कारण (R): भारत में अनुमानित 6.2 करोड़ लोग मुख्यतः भूजल में अत्यधिक फ्लोराइड से फ्लोरोसिस के जोखिम में हैं, और NGRI हैदराबाद में विकसित Nalgonda तकनीक एक कम लागत वाली सामुदायिक स्तरीय फ्लोराइड हटाने की विधि प्रदान करती है।

- (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
 (b) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
 (c) A सही है लेकिन R गलत है

(d) A गलत है लेकिन R सही है

प्र.6. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. NCAP 2019 में 131 गैर-प्राप्ति शहरों को लक्षित करते हुए शुरू किया गया था।
2. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) NCR और आसपास के क्षेत्रों के लिए 2021 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
3. PM_{2.5} (वार्षिक माध्य) के लिए भारत का NAAQS मानक $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जो WHO दिशानिर्देश के समान है।
4. श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) CAQM द्वारा लागू की जाती है।

ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

प्र.7. निम्नलिखित महासागर-संबंधी शब्दों को उनके सही विवरणों से सुमेलित कीजिए:

सूची I (पद)

सूची II (विवरण)

- | | |
|--------------------|--|
| 1. नीला कार्बन | P. अवैध, अनिर्धारित, अनियमित मत्स्य पालन प्रथाएं |
| 2. IUU मत्स्य पालन | Q. तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहीत कार्बन: मैंग्रोव, समुद्री घास, नमक के दलदल |
| 3. EEZ | R. मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, तांबे युक्त गहरे समुद्री चट्टानें |
| 4. बहुधातु नोड्यूल | S. 200 समुद्री मील क्षेत्र जहाँ तटीय राज्य को संप्रभु संसाधन अधिकार हैं |

- (a) 1-Q, 2-P, 3-S, 4-R
- (b) 1-P, 2-Q, 3-R, 4-S
- (c) 1-Q, 2-S, 3-P, 4-R
- (d) 1-R, 2-P, 3-Q, 4-S

प्र.8. वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (VVP) के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. VVP अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में सीमावर्ती गाँवों को कवर करता है।
2. LAC के साथ चीन का 'Xiaokang गाँव' कार्यक्रम VVP के पीछे रणनीतिक विचारों में से एक था।

3. कार्यक्रम का चरण 1 परिव्यय ₹4,800 करोड़ है और 19 जिले और 46 सीमा ब्लॉक को कवर करता है।

4. VVP विशेष रूप से गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1 और 2

(d) सभी चार

प्र.9. अभिकथन (A): दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित भारत का वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निवारक उपकरण है।

कारण (R): FRI साइबर धोखाधड़ी में उपयोग मोबाइल नंबरों को जोखिम स्कोर प्रदान करता है और बैंकों को पीड़ित के खाते से पैसा जाने से पहले उच्च-जोखिम लेनदेन को चिह्नित या अवरुद्ध करने में सक्षम बनाता है, व्यापक संचार साथी पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में।

(a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है

(b) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

(c) A सही है लेकिन R गलत है

(d) A गलत है लेकिन R सही है

प्र.10. भारत में HPV वैक्सीन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने 2023 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) में HPV वैक्सीन शामिल की।

2. Cervavac Serum Institute of India द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी HPV वैक्सीन है और किसी विकासशील देश से दुनिया की पहली चतुर्भुज HPV वैक्सीन है।

3. UIP के तहत HPV टीकाकरण का लक्ष्य समूह 9-14 वर्ष की लड़कियाँ हैं।

4. भारतीय महिलाओं में सर्वाङ्कल कैंसर सबसे आम कैंसर है।

कितने कथन सही हैं?

(a) केवल दो

(b) केवल तीन

(c) सभी चार

(d) केवल एक

2 मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 – 150 शब्द:

वन अधिकार अधिनियम, 2006 को परिवर्तनकारी बताया गया है लेकिन खराब कार्यान्वयन के लिए आलोचना की गई है। FRA कार्यान्वयन पर पहले क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन (सितंबर 2026) ने लगातार अंतराल पहचाने। FRA के वादे बनाम उसके कार्यान्वयन रिकॉर्ड की आलोचनात्मक जाँच करें और सुधार सुझाएं।

आदर्श उत्तर – 150 शब्द:

वन अधिकार अधिनियम 2006 वन-निवासी समुदायों के साथ 'ऐतिहासिक अन्याय' के सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। यह तीन स्तरीय अधिकार बनाता है: व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR, अधिकतम 4 हेक्टेयर, 13 दिसंबर 2005 से पहले का कब्जा), सामुदायिक वन अधिकार (CFR, साझे संसाधन), और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (संपूर्ण वन क्षेत्र का स्व-शासन)। वादा काफी हद तक अधूरा रहा है। 44 लाख दावों में से केवल 21 लाख IFR पट्टे वितरित – 50% से अधिक अस्वीकृति दर, अक्सर प्रक्रियागत आधार पर। CFR पट्टे नाममात्र। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार – सबसे सशक्त प्रावधान – मुश्किल से लागू। वन विभाग, जिसका अधिकार FRA सीधे चुनौती देता है, ने कार्यान्वयन का विरोध किया है। आवश्यक सुधार: CFR मान्यता के लिए समयबद्ध लक्ष्य; ग्राम सभा क्षमता निर्माण; FRA-वन संरक्षण अधिनियम तनावों का विधायी समाधान; और स्वतंत्र निगरानी। क्षेत्रीय समीक्षा एक अच्छा पहला कदम है – लेकिन प्रवर्तन के दांत, केवल विचार-विमर्श नहीं, की जरूरत है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 – 250 शब्द:

भारत 2026 BRICS की अध्यक्षता कर रहा है, 'भारत इनोवेट्स' प्रदर्शनी प्रस्तुत कर रहा है और नीली अर्थव्यवस्था एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। BRICS में भारत के रणनीतिक हितों, BRICS के भीतर भारत के

सामने चुनौतियों (विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान गतिशीलता) का विश्लेषण करें और आकलन करें कि क्या BRICS भारत के विदेश नीति उद्देश्यों की सेवा करता है।

आदर्श उत्तर – 250 शब्द:

BRICS में भारत के रणनीतिक हित बहुआयामी और अन्य सदस्यों से अलग हैं: सकारात्मक हित: BRICS भारत को एक गैर-पश्चिमी, गुट-निरपेक्ष मंच प्रदान करता है जहाँ वह रूस के साथ जुड़ सकता है (पूरी तरह से पश्चिमी ढाँचे से बचते हुए जो भारत को 'पक्ष चुनने' की माँग करेंगे), मध्य एशिया और अफ्रीका से जुड़ सकता है, NDB वित्त तक पहुँच बना सकता है, और खुद को 'ग्लोबल साउथ की आवाज़' के रूप में पेश कर सकता है। 2026 अध्यक्षता और 'भारत इनोवेट्स' DPI, अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए BRICS का लाभ उठाती है। चुनौती 1 – चीन: चीन BRICS पर आर्थिक रूप से हावी है और इसका उपयोग RMB अंतर्राष्ट्रीयकरण, BRI संबंध, और भारत-विरोधी पश्चिमी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए करता है। चीन ने सीमा घटनाओं पर BRICS विज्ञप्तियों में भारत की स्थिति को वीटो किया। चुनौती 2 – पाकिस्तान: BRICS दर्जा (पर्यवेक्षक, भागीदार राज्य) पाने के पाकिस्तान के बार-बार प्रयासों का भारत विरोध करता है और अब तक पाकिस्तान को बाहर रखने में सफल रहा है। चुनौती 3 – BRICS की सीमाएं: कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं; आम सहमति-चालित; NDB में चीन का वर्चस्व; डी-डॉलरीकरण चर्चाएं भारत के अपने डॉलर-आधारित विदेशी भंडार के लिए जोखिम पैदा करती हैं। आकलन: BRICS भारत के विदेश नीति उद्देश्यों को एक पूरक, न कि प्राथमिक, मंच के रूप में सेवा करता है। भारत BRICS का चयनात्मक उपयोग करता है – रूस जुड़ाव, ग्लोबल साउथ स्थिति, NDB पहुँच, और बहुपक्षीय वैधता के लिए – जबकि Quad और पश्चिमी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखता है। चुनौती BRICS को एक पश्चिमी-विरोधी गुट बनने से रोकना है जो भारत के बहु-संरेखण को बाधित करे। अब तक भारत ने इसे सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है।

Prelims उत्तर एवं व्याख्या

प्र.1. उत्तर: (b) केवल तीन

कथन 1 (IFR सीमा = 4 हेक्टेयर – सही), 2 (कटऑफ तिथि = 13 दिसंबर 2005 – सही), 3 (CFR ग्राम सभा में निहित – सही) सटीक। कथन 4 गलत है – FRA 2006 अनुसूचित जनजाति AND अन्य परंपरागत वन निवासियों

(OTFD) दोनों को कवर करता है जो कम से कम 3 पीढ़ियों (75 वर्ष) से वन में रहते हैं लेकिन जनजातीय नहीं हो सकते। OTFD स्पष्ट रूप से शामिल हैं।

प्र.2. उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है

6G मानक-निर्धारण के भूराजनीतिक निहितार्थ हैं (A) क्योंकि मानक निर्धारित करते हैं किस देश की प्रौद्योगिकी हावी होती है। भारत की BSNL स्वदेशी स्टैक + भारत 6G दृष्टि (R) सीधे समझाते हैं कि भारत का समर्थन क्यों मायने रखता है – भारत अब एक विश्वसनीय मानक भागीदार है, न केवल अपनाने वाला।

प्र.3. उत्तर: (a) 1-Q, 2-P, 3-R, 4-S

PM-KISAN = ₹6,000/वर्ष आय सहायता (Q); PM-KMDY (PM किसान मानधन योजना) = 60 पर ₹3,000/माह पेंशन (P); eNAM = 1,000+ मंडियाँ जोड़ने वाला ऑनलाइन बाजार (R); किसान क्रेडिट कार्ड = 7%/4% सब्सिडी के बाद घूर्णन ऋण (S)।

प्र.4. उत्तर: (a) केवल दो

कथन 1 (BRICS-10: 2024 विस्तार – सही) और 3 (भारत BRICS अध्यक्षता 2026, 18वाँ शिखर – सही) सटीक। कथन 2 गलत – NDB का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। कथन 4 गलत – NDB स्पष्ट रूप से स्थानीय मुद्राओं में ऋण देता है (डॉलर पर निर्भरता कम करना इसके संस्थापन उद्देश्यों में से एक है)।

प्र.5. उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है

Nalgonda तकनीक का महत्व (A) R द्वारा सीधे समझाया गया है: 6.2 करोड़ जोखिम में + भूजल स्रोत + Nalgonda तकनीक = कम लागत, सामुदायिक-उपयुक्त फ्लोराइड हटाना = भारत की जल सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। R सही और पूरी तरह से A को समझाता है।

प्र.6. उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 4

कथन 1 (NCAP = 2019, 131 शहर – सही), 2 (CAQM = वैधानिक निकाय, 2021 – सही), 4 (GRAP CAQM द्वारा – सही) सटीक। कथन 3 गलत – भारत का NAAQS वार्षिक PM2.5 मानक = $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, जो WHO दिशानिर्देश $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (2021 अपडेट) से कहीं कमज़ोर है। WHO दिशानिर्देश 8 गुना सख्त है, समान नहीं।

प्र.7. उत्तर: (a) 1-Q, 2-P, 3-S, 4-R

नीला कार्बन = तटीय पारिस्थितिकी तंत्र (मैंग्रोव, समुद्री घास, नमक के दलदल) में कार्बन (Q); IUU मत्स्य पालन = अवैध, अनिर्धारित, अनियमित (P); EEZ = 200 समुद्री मील सीमा (S); बहुधातु नोड्यूल = मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, तांबे वाली गहरे समुद्री चट्टानें (R)।

प्र.8. उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 3

कथन 1 (5 राज्य/UT – सही), 2 (चीन के Xiaokang गाँव = रणनीतिक संदर्भ – सही), 3 (₹4,800 करोड़, 19 जिले, 46 ब्लॉक – सही) सटीक। कथन 4 गलत – VVP गृह मंत्रालय AND ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों की संयुक्त पहल है; यह विशेष रूप से MHA नहीं है।

प्र.9. उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है

FRI का महत्व (A) R द्वारा ठीक समझाया गया है: जोखिम-स्कोरिंग तंत्र जो मोबाइल नंबरों को चिह्नित करता है बैंकों को धोखाधड़ी पूरी होने से पहले निवारक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। यही वह तंत्र है जो FRI को प्रभावी बनाता है – और संचार साथी पारिस्थितिकी तंत्र संदर्भ सही है।

प्र.10. उत्तर: (b) केवल तीन

कथन 1 (UIP में 2023 शामिल – सही), 2 (Cervavac = Serum Institute, विकासशील देश से पहली चतुर्भुज – सही), 3 (लक्ष्य = 9-14 वर्ष की लड़कियाँ – सही) सटीक। कथन 4 गलत – सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है, स्तन कैंसर के बाद। स्तन कैंसर सबसे आम है। यह एक सामान्य UPSC जाल है।

SITOK IAS
LESS NOISE. MORE RETENTION.

SITOK IAS • PIB साप्ताहिक संकलन

अब, एक नया सप्ताह

सप्ताह 3

12 - 18 सितंबर 2026

28 PIB समाचार • सम्माननीय उल्लेख और अभ्यास प्रश्न

सप्ताह 3 / 4

रक्षा एवं सुरक्षा (DEFENSE AND SECURITY)

01	BRICS नई दिल्ली घोषणापत्र: रक्षा व सुरक्षा आयाम.....	147
02	BRICS के इतर भारत-चीन द्विपक्षीय बैठक.....	148
03	पूर्वी नौसेना कमान में कोलंबो सुरक्षा संधिवृत्त की टेबल-टॉप अभ्यास.....	150
04	औली व महाजन में युद्ध अभ्यास 2026.....	152

विदेश मामले एवं बहुपक्षवाद (FOREIGN AFFAIRS AND MULTILATERALISM)

05	BRICS नई दिल्ली घोषणापत्र: भारत की 2026 अध्यक्षता के परिणाम.....	153
06	BRICS के इतर प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक.....	155
07	भारत-MERCOSUR PTA का विस्तार व पहला अतिरिक्त प्रोटोकॉल.....	157
08	भारत-न्यूजीलैंड FTA लागू होने की दिशा में आगे बढ़ा.....	158
09	आर्थिक व विदेश व्यापार गतिविधियों पर SCO मंत्री.....	160
10	पारंपरिक चिकित्सा पर तीसरा BIMSTEC सम्मेलन.....	162

अर्थव्यवस्था एवं वित्त (ECONOMY AND FINANCE)

11	अप्रैल-अगस्त 2026-27 में भारत के निर्यात में वृद्धि.....	163
12	SEMICON इंडिया 2026 और सेमीकॉन 2.0 रोडमैप.....	165
13	नया UPI ढांचा: P2P व अधिकांश व्यापारी भुगतान मुफ्त बरकरार.....	166
14	विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026.....	168
15	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना.....	169
16	इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण योजना.....	171

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

17	संबलपुर में भारत का 51वां डॉपलर मौसम रडार.....	173
18	जलवायु-सहनशील फसल विकास के लिए SPROUT सुविधा.....	174
19	स्टील स्लैग सड़क प्रौद्योगिकी.....	176
20	टिकाऊ चमड़े व हरित सड़कों के लिए CSIR तकनीक-हस्तांतरण.....	177
21	किसानों को भारत का पहला मृदा-कार्बन भुगतान.....	179
22	भारत में डेटा सेंटर.....	180

पर्यावरण (ENVIRONMENT)

23	गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण.....	182
24	विश्व ओज़ोन दिवस व नए जलवायु-शासन पोर्टल.....	183

शासन एवं सामाजिक मुद्दे (GOVERNANCE AND SOCIAL ISSUES)

25	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन.....	185
26	अगस्त 2026 के लिए PLFS मासिक बुलेटिन.....	186
27	जनऔषधि केंद्रों के ज़रिए नुस्खे से आगे की देखभाल.....	188
28	सिलिकॉन सपने और भारत का सेमीकंडक्टर-स्टार्टअप पारितंत्र.....	189

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Prelims Practice Questions).....	191
मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं आदर्श उत्तर (Mains Questions and Model Answers).....	194
प्रारंभिक परीक्षा उत्तर एवं व्याख्या (Prelims Answers and Explanations).....	196



SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

रक्षा एवं सुरक्षा (Defense And Security)

1. BRICS नई दिल्ली घोषणापत्र: रक्षा व सुरक्षा आयाम

मंत्रालय: प्रधानमंत्री कार्यालय / विदेश मंत्रालय

PIB तिथि: 12 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

भारत की 2026 की अध्यक्षता में हुए 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणापत्र स्वीकार किया गया। आर्थिक-वित्तीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ-साथ सुरक्षा सहयोग BRICS के तीन मुख्य स्तंभों में से एक बना रहा। घोषणापत्र में संप्रभु समानता, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका को दोहराया गया, ताकि उभरते व विकासशील देशों को वैश्विक शासन में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। आतंकवाद को लेकर BRICS ने इसके हर रूप की निंदा की और कहा कि इसे किसी धर्म, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसमें शून्य-सहनशीलता, दोषियों व मददगारों की जवाबदेही, और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि (CCIT) को जल्द अपनाने की मांग की गई। नेताओं ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का समर्थन किया और सीमापार संगठित अपराध, अवैध वित्तीय प्रवाह, मादक पदार्थों की तस्करी तथा डिजिटल तकनीक के दुरुपयोग के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आपदा-सहनशीलता को व्यावहारिक सहयोग की ज़रूरत वाले क्षेत्र बताया गया।

BRICS की शुरुआत एक आर्थिक-राजनीतिक समूह के तौर पर हुई थी, लेकिन अब इसके एजेंडे में एक ठोस राजनीतिक-सुरक्षा स्तंभ भी शामिल है। इससे NATO जैसी सामूहिक-रक्षा बाध्यता नहीं बनती; सहयोग परामर्श, सहमति और स्वैच्छिक अनुपालन पर आधारित है। सदस्यता बढ़ने का मतलब यह भी है कि सदस्यों के गठबंधन, खतरे को लेकर नज़रिया और क्षेत्रीय हित अलग-अलग हैं। इसलिए साझा भाषा अहम हो जाती है, क्योंकि यह उस न्यूनतम स्थिति को दर्शाती है जिसे भारत, चीन, रूस व नए सदस्यों समेत सभी सदस्य स्वीकार करने को तैयार थे।

BRICS कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। इसकी सुरक्षा भूमिका मुख्यतः राजनीतिक समन्वय, सूचना का आदान-प्रदान और आतंकवाद, साइबर अपराध व संगठित अपराध जैसे खतरों पर साझा रुख तक सीमित है। भारत इस मंच का इस्तेमाल वैश्विक संस्थाओं में सुधार और आतंकवाद पर एक मज़बूत, गैर-चयनात्मक वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए करता है, साथ ही अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी बनाए रखता है।

भारत के लिए इस घोषणापत्र का सबसे अहम सुरक्षा-मूल्य मानक-निर्धारण में है। शून्य-सहनशीलता, मददगारों की जवाबदेही और प्रस्तावित CCIT का जिक्र भारत के इस पुराने कूटनीतिक रुख को समर्थन देता है कि आतंकवाद को किसी राजनीतिक कारण से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र सुधार व संप्रभु समानता का समर्थन, अधिक

प्रतिनिधित्व वाली सुरक्षा परिषद की भारत की मांग को पूरक बनाता है। साथ ही, व्यापक घोषणाएं साझा कार्रवाई की गारंटी नहीं देती: सदस्य संगठनों के नामकरण, प्रतिबंधों, क्षेत्रीय संघर्षों या साइबर-संप्रभुता के अर्थ को लेकर असहमत हो सकते हैं। असली कसौटी सूचना-आदान-प्रदान, आतंक-वित्तपोषण व साइबर अपराध के खिलाफ सहयोग, और यह होगी कि सुरक्षा-भाषा चयनात्मक तरीके से नहीं बल्कि लगातार एक समान रूप से लागू होती है या नहीं।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
BRICS	बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह, जो सहमति के आधार पर काम करता है।
CCIT	अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र व्यापक संधि, जिसे सबसे पहले भारत ने 1996 में आगे बढ़ाया था।
रणनीतिक स्वायत्तता	किसी एक शक्ति-गुट से बंधे बिना स्वतंत्र रूप से विदेश-नीति के फैसले लेने की क्षमता।
सीमापार संगठित अपराध	राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार चलने वाली आपराधिक गतिविधि, जिसमें तस्करी व मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है।
BRICS सुरक्षा स्तंभ	राजनीतिक-सुरक्षा सहयोग BRICS के तीन मुख्य स्तंभों में से एक है। इसमें आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध, संघर्ष और बहुपक्षीय सुधार पर परामर्श शामिल है, लेकिन यह कोई सैन्य गठबंधन या सामूहिक-रक्षा गारंटी नहीं बनाता।
संप्रभु समानता	संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत कि आकार या शक्ति चाहे जो हो, सभी राष्ट्रों की कानूनी हैसियत बराबर होती है। घोषणापत्र इसका इस्तेमाल गैर-हस्तक्षेप, क्षेत्रीय अखंडता और अधिक प्रतिनिधित्व वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थन में करता है।
आतंक-वित्तपोषण	आतंकी गतिविधि के समर्थन में इस्तेमाल होने वाले धन का संग्रह या स्थानांतरण। इस पर असरदार कार्रवाई के लिए वित्तीय खुफिया जानकारी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रतिबंधों का अनुपालन और दोषियों व मददगारों दोनों पर मुकदमा ज़रूरी है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं व समूह
- GS III: आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा व आतंकवाद। प्रारंभिक परीक्षा: BRICS की संरचना व सहमति-आधारित कार्यप्रणाली।
मुख्य परीक्षा: BRICS को सैन्य या पश्चिम-विरोधी गुट बनाए बिना ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व के लिए भारत का इस्तेमाल।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2309505®=48&lang=1>

2. BRICS के इतर भारत-चीन द्विपक्षीय बैठक

मंत्रालय: प्रधानमंत्री कार्यालय / विदेश मंत्रालय

PIB तिथि: 12 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अगस्त 2025 की तियानजिन बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का स्वागत किया और सहमति जताई कि इन रिश्तों को एक रणनीतिक व दीर्घकालिक नज़रिए से देखा जाना चाहिए। भारत ने तीन 'म्युचुअल' सिद्धांत – पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित – दोहराए। दोनों पक्षों ने कहा कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। सीमावर्ती इलाकों में शांति व स्थिरता को संबंधों के सतत विकास का ज़रूरी आधार बताया गया। नेताओं ने मौजूदा सीमा-समझौतों के पालन और सीमा-प्रश्न के निष्पक्ष, तर्कसंगत व आपसी रूप से स्वीकार्य समाधान का समर्थन किया। साथ ही जन-संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, व्यापारिक आवागमन, संरचनात्मक व्यापार-असंतुलन, आपूर्ति-शृंखला से जुड़ी चिंताओं और अनुमानित बाज़ार-पहुंच पर भी चर्चा हुई। चीन ने भारत की BRICS अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन जताया।

भारत-चीन संबंधों में गहरा आर्थिक अंतर्संबंध, एक अनसुलझा सीमा-विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा – तीनों साथ-साथ मौजूद हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) एक व्यावहारिक सीमांकन है, न कि संयुक्त रूप से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय सीमा। सैन्य तनाव की घटनाएं बार-बार दिखा चुकी हैं कि अस्पष्टता, बुनियादी ढांचे का विकास और गश्ती-दलों की मुठभेड़ पूरे रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए भारत सामान्य द्विपक्षीय प्रगति को सीमा पर शांति से जोड़कर देखता है, जबकि चीन अक्सर सीमा-मुद्दे को व्यापक संबंधों के एक हिस्से के तौर पर देखता रहा है।

यह बैठक सतर्क स्थिरीकरण को दिखाती है, पूर्ण सामान्यीकरण को नहीं। भारत का रुख है कि आर्थिक व राजनीतिक सहयोग को सीमा पर शांति से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों देश मतभेदों को बढ़ने से रोकना चाहते हैं, फिर भी व्यापार-असंतुलन व बाज़ार-पहुंच चिंता का विषय बने हुए हैं।

'मतभेद विवाद न बनें' वाली भाषा और तीन म्युचुअल सिद्धांत, मूल समस्याओं के खत्म होने का दिखावा किए बिना रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश को दर्शाते हैं। अंतिम सीमा-समझौते के लिए सामरिक पीछे हटने से कहीं आगे की राजनीतिक सहमति चाहिए होगी। आर्थिक चिंताएं भी उतनी ही अहम हैं: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सौर उपकरण व दवाओं के लिए चीनी आयात पर निर्भर है, लेकिन ज़्यादा संतुलित व्यापार और भारतीय कंपनियों के लिए अनुमानित पहुंच चाहता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान, वीज़ा और व्यापारिक यात्रा घर्षण कम कर सकते हैं, पर ये सैन्य विश्वास-निर्माण और समझौतों के पालन का विकल्प नहीं बन सकते। इसलिए इस बैठक को 'नियंत्रित जुड़ाव' के तौर पर देखा जाना चाहिए – जो तनाव रोकने में उपयोगी है, पर सीमा पर लगातार अच्छे आचरण पर निर्भर है।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)	भारत व चीन के बीच व्यावहारिक सीमा; यह आपसी सहमति वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है।

शब्द	परिभाषा
तीन म्युचुअल सिद्धांत	पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित।
व्यापार-असंतुलन	चीन से भारत के आयात और निर्यात के मूल्य के बीच बड़ा अंतर।
सीमा-प्रश्न	भारत-चीन सीमा के अंतिम सीमांकन व कानूनी निपटारे का अनसुलझा मुद्दा।
सीमा पर शांति	भारत का यह रुख कि LAC पर शांति सामान्य द्विपक्षीय संबंधों का ज़रूरी आधार है। चुनिंदा स्थानों पर सामरिक पीछे हटना, सीमा के अंतिम सीमांकन या निपटारे से अलग बात है।
संरचनात्मक व्यापार-असंतुलन	एक स्थायी पैटर्न, जिसमें भारत चीन से निर्यात के मुकाबले कहीं ज़्यादा आयात करता है, खासकर मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर उपकरण व दवा-कच्चे माल में; इसलिए बाज़ार-पहुंच व घरेलू क्षमता बड़ी चिंताएं हैं।
विश्वास-निर्माण उपाय	बलों के बीच गलतफहमी घटाने के लिए बनाए गए समझौते, हॉटलाइन, बैठक-तंत्र व परिचालन नियम। इनकी प्रभावशीलता निरंतर पालन व घटनाओं के समय पर स्पष्टीकरण पर निर्भर करती है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: भारत व उसका पड़ोस
- द्विपक्षीय संबंध। GS III: सीमा-प्रबंधन व आपूर्ति-शृंखला सुरक्षा। मुख्य परीक्षा: बताएं कि सीमा पर शांति को व्यापक भारत-चीन संबंधों का आधार क्यों माना जाता है।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2309538®=48&lang=1>

3. पूर्वी नौसेना कमान में कोलंबो सुरक्षा संधिवृत्त की टेबल-टॉप अभ्यास

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय / भारतीय नौसेना

PIB तिथि: 12 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

कोलंबो सुरक्षा संधिवृत्त (CSC) के तहत तीन-दिवसीय टेबल-टॉप अभ्यास विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में संपन्न हुआ। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध समुद्री गतिविधियों पर समन्वित प्रतिक्रिया का अनुकरण किया गया। सदस्य व पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव-तस्करी और अवैध, अनियमित व अनियंत्रित (IUU) मछली-पकड़ने से जुड़े परिदृश्यों पर काम किया। प्रतिभागियों ने सामूहिक समुद्री-क्षेत्र जागरूकता (MDA) बेहतर बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) और सूचना-साझाकरण व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अभ्यास में समुद्र में बलों की तैनाती नहीं, बल्कि योजना व निर्णय-प्रक्रिया शामिल थी। यह गतिविधि MAHASAGAR – यानी क्षेत्रों में सुरक्षा व विकास के लिए पारस्परिक व समग्र प्रगति – और एक स्थिर, सुरक्षित हिंद महासागर के लक्ष्य से जुड़ी है।

हिंद महासागर से होकर ऊर्जा व व्यापार के प्रमुख मार्ग गुजरते हैं, लेकिन कई खतरे पारंपरिक नौसैनिक संघर्ष के स्तर से नीचे होते हैं। तस्करी नेटवर्क, समुद्री डकैती, मानव-तस्करी, समुद्री आतंकवाद, अवैध मछली-पकड़ना और आपदाएं अधिकार-क्षेत्रों की सीमाओं को पार कर जाती हैं। कोई भी अकेला देश सिर्फ अपने जहाजों व सेंसरों के भरोसे पर्याप्त परिचालन-चित्र नहीं बना सकता। इसीलिए क्षेत्रीय सहयोग तेज़ी से साझा सूचना, सुसंगत प्रक्रियाओं और संपर्क के तेज़ माध्यमों पर केंद्रित होता जा रहा है।

टेबल-टॉप अभ्यास नक्शों, योजनाओं व संचार-प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाने वाला एक संकट-अनुकरण है। इससे किसी असली घटना से पहले देशों को समन्वय की कमियां पहचानने में मदद मिलती है। भारत के लिए, CSC गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा का एक व्यावहारिक पड़ोसी-तंत्र है।

इस अभ्यास ने युद्ध की बजाय निर्णय-प्रक्रिया की परख की। प्रतिभागियों को यह तय करना था कि किसी घटना का पता कौन लगाएगा, सूचना की पुष्टि कैसे होगी, कौन-सी एजेंसी अगुआई करेगी, और क्षेत्रीय जल व विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) में कार्रवाई का समन्वय कैसे होगा। SOP की समीक्षा इसलिए अहम है क्योंकि असंगत रिपोर्टिंग-प्रारूपों या अस्पष्ट अधिकार-क्षेत्र से होने वाली देरी किसी संदिग्ध जहाज़ को भागने का मौका दे सकती है। समुद्री-क्षेत्र जागरूकता का एक नागरिक पहलू भी है: यह मत्स्य-प्रबंधन, खोज व बचाव, पर्यावरणीय प्रतिक्रिया और शिपिंग की सुरक्षा में मदद करती है। CSC परिचालन सहयोग के लिहाज़ से पर्याप्त छोटा बना रहकर व्यापक हिंद महासागर संस्थाओं का पूरक बनता है, हालांकि विश्वास, डेटा-संवेदनशीलता और सदस्यों के बीच असमान निगरानी-क्षमता जैसी सीमाएं बनी हुई हैं।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
टेबल-टॉप अभ्यास	योजनाओं व समन्वय की परख के लिए किया जाने वाला चर्चा-आधारित अनुकरण।
समुद्री-क्षेत्र जागरूकता (MDA)	समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों, जहाजों व खतरों की समझ।
IUU मछली-पकड़ना	अवैध, अनियमित व अनियंत्रित मछली-पकड़ना।
पूर्वी नौसेना कमान	विशाखापत्तनम मुख्यालय वाली भारतीय नौसेना की कमान, जिसका झुकाव बंगाल की खाड़ी की ओर है।
कोलंबो सुरक्षा संधिवृत्त	हिंद महासागर क्षेत्र का एक सुरक्षा-तंत्र, जो समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, तस्करी, आपदा-प्रतिक्रिया व अन्य गैर-पारंपरिक खतरों में व्यावहारिक सहयोग पर केंद्रित है।
मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	पहले से तय कार्य, जिम्मेदारियों व संचार-माध्यमों का क्रम। किसी समुद्री घटना में सुसंगत SOP देरी घटाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि कौन-सी राष्ट्रीय एजेंसी अगुआई करेगी।
MAHASAGAR	क्षेत्रों में सुरक्षा व विकास के लिए पारस्परिक व समग्र प्रगति; समुद्री सुरक्षा, क्षमता-निर्माण, विकास-भागीदारी व क्षेत्रीय समृद्धि को जोड़ने वाला भारत का व्यापक दृष्टिकोण।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: क्षेत्रीय समूह
- GS III: समुद्री सुरक्षा व गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे। प्रारंभिक परीक्षा: पूर्वी नौसेना कमान का स्थान और IUU मछली-पकड़ने का अर्थ।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2309385®=48&lang=1>

4. औली व महाजन में युद्ध अभ्यास 2026

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय / भारतीय थलसेना

PIB तिथि: 15 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

भारत-अमेरिका थलसेना अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' का 22वां संस्करण उत्तराखंड के औली विदेशी प्रशिक्षण नोड और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। दोनों देशों ने लगभग 600-600 सैनिक तैनात किए। अभ्यास का फोकस पर्वतीय व अर्ध-पर्वतीय भूभाग में एकीकृत युद्ध समूहों (Integrated Battle Groups) के इस्तेमाल पर था, जिसमें पैदल-सेना-प्रधान अभियानों पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण में संयुक्त योजना, सामरिक प्रक्रियाएं, निगरानी व टोही के लिए ड्रोन व स्वायत्त प्रणालियां, आधुनिक हथियार-प्रणालियां और बहु-क्षेत्रीय युद्ध पर आदान-प्रदान शामिल था। दो स्थानों का इस्तेमाल करने से दोनों सेनाओं को ऊंचाई वाले व अर्ध-रेगिस्तानी प्रशिक्षण-हालात को जोड़ने का मौका मिला, साथ ही अंतर-संचालनीयता व परिचालन-अभ्यासों का आदान-प्रदान भी बेहतर हुआ।

भारत व अमेरिका तीनों सेनाओं में कई द्विपक्षीय व बहुपक्षीय अभ्यास करते हैं। अभ्यास अपने आप में सैन्य गठबंधन नहीं बनाते; ये सामरिक तौर-तरीकों के आदान-प्रदान, संचार-प्रणालियों की परख और उपकरण व कमान-प्रणालियों के साथ काम करने के तरीके सीखने के नियंत्रित अवसर होते हैं। युद्ध अभ्यास मुख्य द्विपक्षीय थलसेना अभ्यास है और धीरे-धीरे ज़्यादा जटिल परिदृश्यों व तकनीक के इस्तेमाल की ओर बढ़ा है।

युद्ध अभ्यास एक सेना-से-सेना अभ्यास है, कोई संधिगत प्रतिबद्धता नहीं। औली पर्वतीय हालात देता है जबकि महाजन फायरिंग व मोर्चाबंदी के लिए बड़ा क्षेत्र देता है। मकसद है कि दोनों सेनाएं विविध वातावरणों में मिलकर योजना बनाने व काम करने में बेहतर बनें।

दो-स्थानों वाला यह ढांचा परिचालन की दृष्टि से सार्थक था। औली ऊंचाई वाले पर्वतीय हालात देता है, जबकि महाजन अर्ध-रेगिस्तानी वातावरण में फील्ड फायरिंग व मोर्चाबंदी की जगह देता है। एकीकृत युद्ध समूहों को एक समन्वित इकाई के तौर पर काम करने के लिए पैदल-सेना, तोपखाना, बख्तरबंद दस्ते, इंजीनियर, संचार, साजो-सामान व हवाई सहयोग की ज़रूरत होती है। ड्रोन व स्वायत्त प्रणालियां निगरानी व लक्ष्य-निर्धारण में बढ़त देती हैं, पर इनसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, हवाई-

क्षेत्र प्रबंधन व ड्रोन-रोधी सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी पैदा होती हैं। भारत के लिए, ऐसा प्रशिक्षण आधुनिक तरीकों से परिचय बढ़ाता है और व्यापक रणनीतिक साझेदारी मज़बूत करता है। हालांकि इसकी उपयोगिता वास्तविक सीखों, भारतीय भूभाग व सिद्धांत के अनुरूप ढलने, और किसी दूसरी सेना के परिचालन-मॉडल की महज़ नकल से बचने पर निर्भर करती है।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
एकीकृत युद्ध समूह	पैदल-सेना, बख्तरबंद दस्ते, तोपखाना व सहायक तत्वों को मिलाकर बना एक लचीला, अभियान-केंद्रित बल।
अंतर-संचालनीयता	अलग-अलग देशों की सेनाओं की मिलकर योजना बनाने, संवाद करने व काम करने की क्षमता।
बहु-क्षेत्रीय युद्ध	थल, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष व साइबर क्षेत्रों में समन्वित अभियान।
स्वायत्त प्रणालियां	सीमित प्रत्यक्ष मानवीय नियंत्रण के साथ कार्य करने में सक्षम मंच।
औली विदेशी प्रशिक्षण नोड	उत्तराखंड में स्थित भारतीय थलसेना का एक ऊंचाई वाला प्रशिक्षण केंद्र। पर्वतीय भूभाग सैनिकों को कठिन हालात में गतिशीलता, निगरानी, साज़ो-सामान व पैदल-सेना अभियानों का अभ्यास करने देता है।
महाजन फील्ड फायरिंग रेंज	राजस्थान में स्थित एक प्रमुख प्रशिक्षण क्षेत्र, जो लाइव फायरिंग व बड़े मोर्चाबंदी अभ्यासों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका अर्ध-रेगिस्तानी वातावरण औली के पर्वतीय प्रशिक्षण का पूरक है।
टोही ड्रोन	बिना सैनिकों को तुरंत जोखिम में डाले भूभाग व लक्ष्यों का अवलोकन करने वाली मानवरहित प्रणालियां। इनकी युद्धक्षेत्र-उपयोगिता सुरक्षित संचार, इलेक्ट्रॉनिक-युद्ध सहनशीलता व कमान-निर्णयों के साथ एकीकरण पर निर्भर करती है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: भारत-अमेरिका संबंध
- GS III: रक्षा तकनीक व सुरक्षा। प्रारंभिक परीक्षा: भाग लेने वाले देश, संस्करण व स्थान। मुख्य परीक्षा: अंतर-संचालनीयता व रणनीतिक साझेदारी के औज़ार के तौर पर रक्षा अभ्यास।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2310476®=48&lang=1>

विदेश मामले एवं बहुपक्षवाद (Foreign Affairs And Multilateralism)

5. BRICS नई दिल्ली घोषणापत्र: भारत की 2026 अध्यक्षता के परिणाम

मंत्रालय: प्रधानमंत्री कार्यालय / विदेश मंत्रालय

PIB तिथि: 12-13 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

BRICS नेता 'सहनशीलता, नवाचार, सहयोग व स्थिरता के निर्माण' विषय के तहत 18वें शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में मिले। भारत की अध्यक्षता में 30 शहरों में 400 से ज्यादा बैठकें व आयोजन हुए। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र व वैश्विक शासन में सुधार, उभरते व विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व और निर्णय-प्रक्रिया में ग्लोबल साउथ की मज़बूत भागीदारी की मांग की गई। आर्थिक प्राथमिकताओं में सहनशील आपूर्ति-शृंखलाएं, जहां संभव हो वहां स्थानीय मुद्राओं का ज्यादा इस्तेमाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के ज़रिए सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, व्यापार-सुविधा, टिकाऊ वित्त और MSME के लिए समर्थन शामिल रहे। भारत की अध्यक्षता ने स्वास्थ्य, कृषि, आपदा-सहनशीलता, जलवायु कार्रवाई, महत्वपूर्ण खनिजों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार, कौशल और जन-संपर्क में व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाया। BRICS साझेदार देशों को साझा हित वाले क्षेत्रों में और गहराई से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। घोषणापत्र BRICS की सीमाओं और उसके मूल्य, दोनों को दर्शाता है: यह कानूनी रूप से बाध्यकारी फैसलों के बजाय सहमति से तय की गई राजनीतिक प्रतिबद्धताएं देता है।

कोई भी BRICS घोषणापत्र एक बातचीत से तय राजनीतिक दस्तावेज़ होता है, जो उन्हीं क्षेत्रों को कवर करता है जिन पर सदस्य सहमति बना सकें। यह कोई संधि नहीं है और सीधे लागू होने वाली बाध्यताएं नहीं बनाता। इसलिए नई दिल्ली घोषणापत्र को इस नज़रिए से पढ़ना ज़रूरी है कि इसमें क्या शामिल है और बड़ी सदस्यता के चलते किन समझौतों की ज़रूरत पड़ी। भारत की अध्यक्षता ने अपने विषय में निहित चार विचारों – सहनशीलता, नवाचार, सहयोग व स्थिरता – के ज़रिए समूह को विकास-केंद्रित बनाए रखने की कोशिश की।

भारत ने BRICS को पश्चिम-विरोधी गठबंधन के बजाय एक विकास-केंद्रित ग्लोबल साउथ मंच के तौर पर पेश किया। इसकी ताकत एजेंडा तय करने, विकास-वित्त और राजनीतिक समन्वय में है। इसकी कमज़ोरी यह है कि बड़ी हुई सदस्यता सहमति बनाना कठिन बना देती है।

इसके परिणाम भारत की घरेलू क्षमताओं को ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों से जोड़ते हैं। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सहयोग, आपदा-सहनशीलता, कृषि तकनीक, कौशल व MSME समर्थन ऐसे क्षेत्र हैं जहां व्यावहारिक परियोजनाएं दिखने लायक फायदे दे सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र व बहुपक्षीय वित्तीय ढांचे में सुधार, विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग को आगे बढ़ाता है। स्थानीय-मुद्रा निपटान चुनिंदा व्यापार में लेनदेन-जोखिम घटा सकता है, पर यह किसी साझा BRICS मुद्रा बनाने या डॉलर को अचानक बदलने जैसा नहीं है। NDB बुनियादी ढांचा-वित्त का दायरा बढ़ा सकता है, हालांकि परियोजना की गुणवत्ता, शासन-व्यवस्था और चीन का आर्थिक वज़न चिंता के विषय बने हुए हैं। भारत की बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि BRICS शब्दों में पश्चिम-विरोधी न बने, जबकि इसका इस्तेमाल विकासशील देशों के लिए नीतिगत गुंजाइश बढ़ाने में हो।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
ग्लोबल साउथ	विकासशील व उभरते देशों के लिए एक व्यापक राजनीतिक शब्द।
न्यू डेवलपमेंट बैंक	BRICS द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक; इसका मुख्यालय शंघाई में है।
स्थानीय-मुद्रा वित्तपोषण	सिर्फ अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहने के बजाय राष्ट्रीय मुद्राओं में उधार लेना या लेनदेन निपटाना।
सहमति (Consensus)	एक निर्णय-पद्धति, जिसमें औपचारिक बहुमत-मतदान के बिना सदस्यों को साझा स्थिति स्वीकार करनी होती है।
BRICS साझेदार देश	पूर्ण सदस्यता से नीचे भागीदारी का एक रूप, जो चुनिंदा देशों को आयोजनों व व्यावहारिक सहयोग में शामिल होने देता है। यह किसी सदस्य के पूर्ण अधिकार दिए बिना BRICS की पहुंच बढ़ाता है।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग	विकासशील देशों के बीच वित्त, तकनीक, कौशल व नीतिगत अनुभव का आदान-प्रदान। भारत इसे दाता-प्राप्तकर्ता पदानुक्रम के बजाय विकास-प्राथमिकताओं पर आधारित सहयोग के तौर पर बढ़ावा देता है।
BRICS स्थानीय-मुद्रा सहयोग	लेनदेन-जोखिम व किसी तीसरी मुद्रा पर निर्भरता घटाने के लिए चुनिंदा व्यापार, ऋण या निपटान में राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल। यह किसी सहमत साझा BRICS मुद्रा जैसा नहीं है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: वैश्विक समूह व संस्थाएं
- GS III: विकास-वित्त व डिजिटल बुनियादी ढांचा। निबंध/मुख्य परीक्षा: BRICS विस्तार, ग्लोबल साउथ नेतृत्व और भारत का बहु-संरेखण।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2309505®=48&lang=1>

6. BRICS के इतर प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें

मंत्रालय: प्रधानमंत्री कार्यालय / विदेश मंत्रालय

PIB तिथि: 12-13 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

दक्षिण अफ्रीका: नेताओं ने अपनी रणनीतिक साझेदारी, ऐतिहासिक रिश्तों व बहुपक्षीय समन्वय की समीक्षा की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल होने पर विचार करने का न्योता दिया। फिलीपींस: रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक, शिक्षा, पर्यटन व तकनीक में सहयोग की समीक्षा हुई। उस समय ASEAN अध्यक्ष रहे फिलीपींस ने आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे के गठबंधन (CDRI) में शामिल होने का फैसला किया। कज़ाख़स्तान: चर्चा में व्यापार, रक्षा, संपर्क, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, उभरती तकनीक व रचनात्मक अर्थव्यवस्था शामिल रही, जो मध्य एशिया में भारत की सक्रियता को दर्शाती है। वियतनाम: दोनों पक्षों ने संवर्धित व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की।

वियतनाम को भारत की एकट ईस्ट नीति का एक अहम स्तंभ बताया गया, और उसने BRICS साझेदार देश के तौर पर हिस्सा लिया। मलेशिया: नेताओं ने व्यापार, रक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व फिनटेक पर चर्चा की। मलेशिया साबाह के कोटा किनाबालु में भारतीय महावाणिज्य दूतावास खोलने पर सहमत हुआ। इथियोपिया: बैठक आर्थिक सहयोग, रक्षा, क्षमता-निर्माण और ग्लोबल साउथ की साझा आवाज़ पर केंद्रित रही। इथियोपिया BRICS का पूर्ण सदस्य है। अफ्रीकी संघ व बुर्ंडी: नेताओं ने भारत-अफ्रीकी संघ सहयोग, जल्द भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, अफ्रीका CDC के ज़रिए स्वास्थ्य सहायता, कृषि, विकास-भागीदारी व क्षमता-निर्माण पर चर्चा की।

बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन केंद्रित द्विपक्षीय कूटनीति के मंच भी बन जाते हैं। नेता अलग-अलग यात्राओं की व्यवस्था किए बिना कई रिश्तों की समीक्षा कर सकते हैं, जबकि अधिकारी लंबित समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए शिखर सम्मेलन की समय-सीमा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बैठकों का मूल्य औपचारिक तस्वीरों से कम और उन क्षेत्रों, इलाकों व संस्थाओं के पैटर्न से ज़्यादा है, जिन पर भारत ज़ोर देना चुनता है।

शिखर-कूटनीति कम समय में कई द्विपक्षीय बैठकें करना संभव बनाती है। पैटर्न दिखाता है कि भारत शिखर सम्मेलन को एक अकेले मुद्दे वाले आयोजन के बजाय, BRICS को एकट ईस्ट, मध्य एशिया, अफ्रीका, महत्वपूर्ण खनिजों, आपूर्ति-शृंखलाओं व आपदा-सहनशीलता से जोड़ता है।

ये बैठकें एक जुड़ी हुई विदेश-नीति रणनीति को उजागर करती हैं। दक्षिण अफ्रीका व अफ्रीकी संघ भारत की ग्लोबल साउथ व संरक्षण-कूटनीति को समर्थन देते हैं; इथियोपिया व बुर्ंडी BRICS को विकास-भागीदारी व क्षमता-निर्माण से जोड़ते हैं। फिलीपींस, वियतनाम व मलेशिया भारत की एकट ईस्ट सक्रियता, रक्षा-सहयोग व सेमीकंडक्टर संपर्कों को मज़बूत करते हैं। कज़ाख़स्तान भारत को मध्य एशिया, ऊर्जा व महत्वपूर्ण खनिजों से जोड़ता है। CDRI व अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस दिखाते हैं कि भारत घरेलू स्तर पर बनाई गई अंतरराष्ट्रीय पहलों का इस्तेमाल बाहरी जुड़ाव के औज़ार के तौर पर कर रहा है। चुनौती है क्रियान्वयन की: सहयोग के क्षेत्रों की व्यापक सूचियां तब तक आकांक्षा मात्र रह सकती हैं जब तक इन्हें वित्तपोषण, संपर्क, संस्थागत बैठकों व नापने योग्य परियोजनाओं का साथ न मिले। शिखर-कूटनीति राजनीतिक दिशा तय करती है; मंत्रालयों व व्यवसायों को इसे परिणामों में बदलना होगा।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
शिखर सम्मेलन के इतर बैठकें	किसी बड़े बहुपक्षीय आयोजन के साथ होने वाली बैठकें।
एकट ईस्ट नीति	दक्षिण-पूर्व व पूर्वी एशिया के साथ गहरे रणनीतिक व आर्थिक जुड़ाव की भारत की नीति।
CDRI	आपदा-सहनशील बुनियादी ढांचे का गठबंधन, जिसे भारत ने 2019 में शुरू किया था।
IBCA	अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस, भारत की अगुआई वाली एक संरक्षण-पहल।
अफ्रीका CDC	अफ्रीकी संघ की सार्वजनिक-स्वास्थ्य एजेंसी।

शब्द	परिभाषा
शिखर-कूटनीति	किसी बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल कर कम समय में कई द्विपक्षीय बैठकें करना। यह राजनीतिक समीक्षा को तेज़ करता है, पर क्रियान्वयन अब भी मंत्रालयों, वित्तपोषण व अनुगामी तंत्र पर निर्भर करता है।
भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन	अफ्रीकी देशों के साथ भारत का प्रमुख नेतृत्व-स्तरीय मंच। यह विकास-भागीदारी, ऋण, क्षमता-निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, तकनीक व राजनीतिक समन्वय को कवर करता है।
महत्वपूर्ण-खनिज कूटनीति	स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स व रक्षा के लिए ज़रूरी खनिजों को सुनिश्चित करने वाला बाहरी जुड़ाव। इसमें निवेश, प्रसंस्करण, परिवहन गलियारे, तकनीक व भरोसेमंद आपूर्ति-समझौते शामिल हैं।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय समूह और अफ्रीका, ASEAN व मध्य एशिया के साथ भारत का जुड़ाव। मुख्य परीक्षा: बहु-संरेखण के औज़ार के तौर पर शिखर-कूटनीति।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2309803®=48&lang=1>

7. भारत-MERCOSUR PTA का विस्तार व पहला अतिरिक्त प्रोटोकॉल

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

PIB तिथि: 14 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

भारत व MERCOSUR ने अपने वरीयता व्यापार समझौते (PTA) को विस्तार देने के लिए बातचीत शुरू की।

MERCOSUR की घूर्णी अध्यक्षता संभाल रहे उरुग्वे ने इस प्रक्रिया की घोषणा की। संदर्भ-शर्तें (Terms of Reference) विस्तारित समझौते के दायरे को तय करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मूल-प्रमाणपत्रों (Certificates of Origin) को कागज़ी प्रमाणपत्रों जितनी ही कानूनी वैधता देने के लिए एक पहला अतिरिक्त प्रोटोकॉल भी हस्ताक्षरित हुआ। यह मूल-नियमों (Rules of Origin) से जुड़े अनुबंध-III के अनुच्छेद 16 में संशोधन करता है। मूल PTA 2004 में हस्ताक्षरित हुआ था और 2009 में लागू हुआ। भारत 450 टैरिफ-लाइनों पर और MERCOSUR 452 टैरिफ-लाइनों पर रियायतें देता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्रों से प्रसंस्करण-समय व लेनदेन-लागत घटने, सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और कागज़-रहित व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रोटोकॉल दोनों पक्षों की आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी होने व अधिसूचना के बाद लागू होगा।

MERCOSUR के साथ भारत का PTA एक आधुनिक मुक्त-व्यापार समझौते (FTA) से संकरा है, क्योंकि यह सीमित संख्या में टैरिफ-लाइनों पर ही रियायत देता है। MERCOSUR भारत को दक्षिण अमेरिका के बड़े बाज़ारों, खासकर ब्राज़ील व अर्जेंटीना तक पहुंच देता है, जबकि भारत एक बड़ा एशियाई बाज़ार पेश करता है। दूरी, लॉजिस्टिक्स, उत्पाद-कवरेज व जटिल दस्तावेज़ीकरण ने व्यापार-संभावना को सीमित रखा है।

PTA चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ-रियायत देता है; FTA आमतौर पर व्यापार के कहीं बड़े हिस्से को कवर करता है। विस्तार-वार्ता उत्पाद व नीति-कवरेज बढ़ा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मूल-प्रमाणपत्र सीमा-शुल्क को यह जांचने में मदद करते हैं कि कोई सामान वरीयता-टैरिफ के योग्य है या नहीं।

इलेक्ट्रॉनिक Certificate of Origin सुधार व्यापार-सुविधा का एक ठोस कदम है। मूल-नियम यह रोकते हैं कि किसी गैर-सदस्य देश का सामान महज़ कम टैरिफ पाने के लिए किसी साझेदार देश के रास्ते न भेजा जाए। यदि सीमा-शुल्क प्रणालियां आपस में जुड़ी हों और हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता जांची जा सके, तो डिजिटल प्रमाणपत्र देरी व धोखाधड़ी घटा सकते हैं। विस्तार-वार्ता रियायतें बढ़ा सकती है और सेवाओं या गैर-टैरिफ बाधाओं को संबोधित कर सकती है, पर संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सावधानीपूर्वक क्रम तय करना होगा। भारत को दवा, इंजीनियरिंग व वाहन निर्यात के अवसरों को प्रतिस्पर्धी कृषि व संसाधन-आधारित निर्यातों से पड़ने वाले समायोजन-दबाव के साथ तौलना होगा। बेहतर शिपिंग संपर्क, मानक-सहयोग व व्यावसायिक जागरूकता, टैरिफ-अनुसूचियों जितनी ही अहम होंगी।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
MERCOSUR	अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे व उरुग्वे से बना दक्षिण अमेरिकी सीमा-शुल्क संघ; बोलीविया इस गुट की एकीकरण-प्रक्रिया में शामिल हुआ है।
PTA	चुनिंदा उत्पादों पर कम टैरिफ देने वाला समझौता।
मूल-नियम (Rules of Origin)	यह तय करने के मानदंड कि कोई उत्पाद कहां बना।
घूर्णी अध्यक्षा	किसी क्षेत्रीय संगठन की बारी-बारी बदलने वाली अस्थायी अध्यक्षता।
इलेक्ट्रॉनिक Certificate of Origin	डिजिटल रूप से जारी व प्रमाणित दस्तावेज़, जो बताता है कि सामान कहां बना। सीमा-शुल्क इसका इस्तेमाल यह तय करने के लिए करता है कि कोई खेप व्यापार-समझौते के तहत वरीयता-टैरिफ की हकदार है या नहीं।
टैरिफ-रियायत	किसी साझेदार देश से योग्य सामान पर दी गई कम सीमा-शुल्क दर। PTA के तहत यह आमतौर पर सिर्फ सूचीबद्ध टैरिफ-लाइनों पर ही लागू होती है, लगभग पूरे व्यापार पर नहीं।
संयुक्त प्रशासनिक समिति	द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र, जो PTA के संचालन की समीक्षा करता है, क्रियान्वयन-संबंधी मुद्दे सुलझाता है और इलेक्ट्रॉनिक मूल-दस्तावेज़ों को स्वीकार करने जैसे बदलावों की सिफारिश करता है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: क्षेत्रीय समूह
- GS III: अंतरराष्ट्रीय व्यापार। प्रारंभिक परीक्षा: MERCOSUR के सदस्य, PTA बनाम FTA, और Certificates of Origin।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2310166®=48&lang=1>

8. भारत-न्यूज़ीलैंड FTA लागू होने की दिशा में आगे बढ़ा

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

न्यूजीलैंड की संसद ने 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित भारत-न्यूजीलैंड FTA को लागू करने के लिए कानून पारित किया। समझौता लागू होने से पहले दोनों पक्षों को अपनी घरेलू प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। यह समझौता लागू होने की तारीख से न्यूजीलैंड को भारत के 100% निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच देता है। संभावित लाभार्थियों में वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, दवाएं व प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं। न्यूजीलैंड को लकड़ी, ऊन, भेड़ के मांस व चमड़े के कच्चे खाल जैसे उत्पादों के लिए भारत में बेहतर पहुंच मिलती है। समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्रों व युवाओं की आवाजाही को भी संबोधित करता है। यह भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश को सुगम बनाने का एक ढांचा और कृषि-उत्पादकता, चिकित्सा उपकरण, आयुष, तकनीक व व्यापार-सुविधा में सहयोग भी उपलब्ध कराता है।

व्यापार समझौते बातचीत, हस्ताक्षर, घरेलू मंजूरी और लागू होने जैसे चरणों से गुजरते हैं। इसलिए न्यूजीलैंड का कानून अंतिम परिचालन घटना के बजाय एक ज़रूरी कानूनी कदम था। यह समझौता इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्थाएं काफी अलग हैं: भारत के पास बड़ा श्रमबल व विविध विनिर्माण-आधार है, जबकि न्यूजीलैंड कृषि, वानिकी व डेयरी-संबद्ध क्षेत्रों में काफी प्रतिस्पर्धी है।

FTA पर हस्ताक्षर होने से यह अपने आप लागू नहीं हो जाता। हर देश को अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यह समझौता सामान, सेवाओं, आवाजाही व निवेश को एक साथ जोड़ता है, जो दिखाता है कि आधुनिक व्यापार-समझौते सिर्फ टैरिफ से कहीं आगे तक फैले होते हैं।

सभी भारतीय निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच श्रम-गहन क्षेत्रों को फायदा पहुंचा सकती है, पर वास्तविक लाभ मूल-नियमों, मानकों, माल-भाड़े की लागत व वितरण-नेटवर्क बनाने की कंपनियों की क्षमता पर निर्भर करेगा। न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए भारत की नियंत्रित पहुंच कृषि को लेकर घरेलू संवेदनशीलता को दर्शाती है। सेवाएं, पेशेवर आवाजाही व शिक्षा, माल-व्यापार से परे भी फायदे दे सकते हैं। निवेश-सुविधा का लक्ष्य एक सक्षम-कारक महत्वाकांक्षा के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि तय पूंजी-प्रवाह के तौर पर। क्रियान्वयन के लिए सीमा-शुल्क मार्गदर्शन, जहां उपयुक्त हो वहां पारस्परिक मान्यता और छोटे निर्यातकों के लिए समर्थन ज़रूरी होगा। भारत को आयात में उछाल पर भी नज़र रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल-नियम तीसरे देश से होने वाले पुनर्निर्यात को रोकें।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
FTA	एक संधि, जो भाग लेने वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार-बाधाओं को काफी हद तक घटाती है।
लागू होना (Entry into force)	वह तारीख, जिस दिन से कोई संधि कानूनी रूप से प्रभावी हो जाती है।
टैरिफ लाइन	सीमा-शुल्क अनुसूची में एक उत्पाद-श्रेणी।

शब्द	परिभाषा
आवाजाही-मार्ग (Mobility Pathway)	छात्रों, पेशेवरों या श्रमिकों की अस्थायी आवाजाही को सुगम बनाने वाले नियम।
घरेलू अनुसमर्थन प्रक्रिया	किसी संधि पर हस्ताक्षर के बाद हर देश को पूरी करनी होने वाली कानूनी प्रक्रिया। न्यूज़ीलैंड के कानून पारित होने से FTA परिचालन के करीब पहुंचा, पर लागू होने के लिए अब भी दोनों पक्षों द्वारा पूर्णता व अधिसूचना चाहिए थी।
मूल-नियम सुरक्षा उपाय	उत्पाद-विशिष्ट शर्तें, जो किसी तीसरे देश के सामान को महज़ न्यूनतम प्रसंस्करण या पुनर्माग के ज़रिए FTA के तहत शुल्क-मुक्त पहुंच पाने से रोकती हैं।
सेवा व्यापार	पेशेवर, डिजिटल, शैक्षणिक, वित्तीय व अन्य सेवाओं की सीमापार आपूर्ति। आधुनिक FTA अक्सर सामान पर टैरिफ के साथ-साथ सेवाओं, निवेश व आवाजाही को भी संबोधित करते हैं।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: द्विपक्षीय संबंध
- GS III: व्यापार-समझौते व निर्यात-प्रतिस्पर्धात्मकता। मुख्य परीक्षा: FTA से मिलने वाले लाभ व समायोजन-लागत।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2311537®=48&lang=1>

9. आर्थिक व विदेश व्यापार गतिविधियों पर SCO मंत्री

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

PIB तिथि: 18 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

25वीं मंत्रिस्तरीय बैठक ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित हुई। भारत ने क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को तीन स्तंभों – सुरक्षा, संपर्क और अवसर – के इर्द-गिर्द रखा। भारत ने SCO के भीतर ज़्यादा व्यापार, कम व्यापार-लागत, सहनशील आपूर्ति-शृंखलाओं, भरोसेमंद संपर्क, सरल सीमा-शुल्क, कागज़-रहित व्यापार और दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की मांग की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि, महत्वपूर्ण खनिज, दवाएं, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा-सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा व ग्रीन हाइड्रोजन शामिल थे। भारत ने डिजिटल व सीमापार भुगतान तथा MSME व स्टार्टअप के लिए सुगम व्यापार-वित्त का भी समर्थन किया। मंत्रियों ने एक वक्तव्य अपनाया, बहुपक्षीय व्यापार व आर्थिक सहयोग के लिए 2026-2030 की कार्य-योजना पर सहमति जताई, और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर एक विशेष कार्य-समूह के नियमों को मंजूरी दी। 2027 की बैठक की मेज़बानी उज़्बेकिस्तान करेगा।

SCO की शुरुआत यूरोशियाई सुरक्षा-प्रक्रिया से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे इसका विस्तार आर्थिक, संपर्क व सांस्कृतिक सहयोग तक हुआ। इसके भूगोल में बड़े ऊर्जा-उत्पादक, विशाल बाज़ार व अहम भूमार्ग शामिल हैं। फिर भी राजनीतिक

तनाव, प्रतिबंध, कमजोर अंतर-क्षेत्रीय संपर्क व प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचा-दृष्टिकोण इस समूह के आर्थिक एकीकरण को सीमित करते हैं।

SCO की शुरुआत एक सुरक्षा-समूह के तौर पर हुई थी, पर अब यह व्यापार व संपर्क पर भी चर्चा करता है। भारत संपर्क का समर्थन तभी करता है जब वह भरोसेमंद, पारदर्शी हो और संप्रभुता का सम्मान करे। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि कुछ प्रस्तावित क्षेत्रीय गलियारे विवादित क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।

भारत का सुरक्षा-संपर्क-अवसर वाला फॉर्मूला वाणिज्य को रणनीतिक शर्तों से जोड़ता है। संपर्क तभी व्यापार-लागत घटा सकता है जब मार्ग भरोसेमंद, पारदर्शी व संप्रभुता का सम्मान करने वाले हों। यही अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) व चाबहार जैसी परियोजनाओं के लिए भारत की प्राथमिकता, और भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र से गुजरने वाले गलियारों पर उसकी आपत्ति को स्पष्ट करता है। जहां एक व्यापक क्षेत्रीय व्यापार-समझौता अव्यावहारिक है, वहां कागज-रहित सीमा-शुल्क, व्यापार-वित्त व डिजिटल भुगतान क्रमिक फायदे दे सकते हैं। दवाओं, महत्वपूर्ण खनिजों व ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग भारत की आपूर्ति-शृंखला प्राथमिकताओं से मेल खाता है। हालांकि, भारत को ऐसे ढांचों से बचना होगा जो कंपनियों को अपारदर्शी मानकों या भू-राजनीतिक निर्भरता के सामने ला खड़ा करें।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
SCO	शंघाई सहयोग संगठन, एक यूरेशियाई राजनीतिक, सुरक्षा व आर्थिक समूह।
भरोसेमंद संपर्क	पारदर्शिता, वित्तीय व्यवहार्यता और संप्रभुता के सम्मान के साथ बनाया गया संपर्क।
व्यापार-सुविधा	व्यापार में लगने वाले समय व लागत घटाने के लिए सीमा व सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
वैश्विक मूल्य शृंखला	एक उत्पादन-नेटवर्क, जिसके अलग-अलग चरण अलग-अलग देशों में होते हैं।
सुरक्षा-संपर्क-अवसर	SCO आर्थिक जुड़ाव के लिए भारत का त्रि-आयामी फॉर्मूला। सुरक्षा वाणिज्य को सक्षम बनाती है, भरोसेमंद संपर्क व्यापार-लागत घटाता है, और व्यापक बाजार-पहुंच व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करती है।
बहु-विधि संपर्क	जुड़ी हुई सड़क, रेल, समुद्री व अंतर्देशीय-जलमार्ग प्रणालियों के जरिए माल की आवाजाही। भूमि से घिरे यूरेशिया में कुशल स्थानांतरण व साझा दस्तावेजीकरण, पारगमन-समय घटा सकते हैं।
रचनात्मक अर्थव्यवस्था	संस्कृति, डिजाइन, मीडिया, कला, डिजिटल सामग्री व बौद्धिक संपदा पर आधारित आर्थिक गतिविधि। SCO ने इस क्षेत्र के लिए एक विशेष कार्य-समूह ढांचे को मंजूरी दी।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: क्षेत्रीय समूह
- GS III: बुनियादी ढांचा, व्यापार व महत्वपूर्ण खनिज। मुख्य परीक्षा: भारत के SCO जुड़ाव में अवसर व सीमाएं।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2311874®=48&lang=1>

10. पारंपरिक चिकित्सा पर तीसरा BIMSTEC सम्मेलन

मंत्रालय: आयुष मंत्रालय

PIB तिथि: 16-17 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

यह सम्मेलन और दूसरी BIMSTEC नोडल समूह बैठक गोवा में सभी सातों सदस्य देशों की भागीदारी के साथ आयोजित हुई। आयुष मंत्रालय ने इस आयोजन का प्रबंधन किया, जिसमें AIIA गोवा नोडल संस्थान रहा। चर्चाओं में पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण, बौद्धिक-संपदा अधिकार, आनुवंशिक संसाधन, पहुंच व लाभ-साझाकरण, पूर्व-सूचित सहमति, सामुदायिक अधिकार तथा WIPO व WHO की भूमिका शामिल रही। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (TKDL) पर नियंत्रित-पहुंच दस्तावेजीकरण और पूर्व-कला (prior-art) साक्ष्य के ज़रिए ग़लत पेटेंट रोकने के एक मॉडल के तौर पर चर्चा हुई। गोवा निष्कर्षों ने सहयोग के चार क्षेत्र चिह्नित किए: संस्थागत व नीतिगत सहयोग; मानक व व्यापार; दस्तावेजीकरण व क्षमता-निर्माण; और क्रियान्वयन-तंत्र। सदस्यों ने बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों व पारंपरिक चिकित्सा-ज्ञान पर सहयोग का समर्थन किया।

BIMSTEC बंगाल की खाड़ी के इर्द-गिर्द दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है। इसके सदस्यों के पास विविध चिकित्सा-परंपराएं व जैविक संसाधन हैं, पर पारंपरिक ज्ञान अक्सर मौखिक रूप से हस्तांतरित होता है, असमान रूप से दस्तावेजीकृत होता है और व्यावसायिक हड़प के प्रति संवेदनशील होता है। अंतरराष्ट्रीय पेटेंट-नियम तब विवाद पैदा कर सकते हैं जब कोई आवेदक किसी जानी-मानी सामुदायिक प्रथा को नई खोज बताकर पेश करता है।

पारंपरिक ज्ञान स्वास्थ्य-सेवा व अनुसंधान को समर्थन दे सकता है, पर अगर ज्ञान या जैविक संसाधनों का व्यावसायिक इस्तेमाल बिना सहमति के हो, तो समुदाय अपना नियंत्रण खो सकते हैं। दस्तावेजीकरण जैव-हड़प रोकने में मदद करता है, जबकि पहुंच व लाभ-साझाकरण के नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि समुदायों को लाभ का उचित हिस्सा मिले।

इस सम्मेलन ने स्वास्थ्य, जैव-विविधता व बौद्धिक संपदा को एक ही ढांचे में जोड़ा। TKDL जैसा दस्तावेजीकरण पूर्व-कला स्थापित कर ग़लत पेटेंट रोक सकता है, पर डेटाबेस को गोपनीय या पवित्र ज्ञान की भी रक्षा करनी होगी। जब शोधकर्ता या कंपनियां आनुवंशिक संसाधनों व संबद्ध ज्ञान का इस्तेमाल करती हैं, तब पूर्व-सूचित सहमति व आपसी सहमति वाली शर्तों के सिद्धांत ज़रूरी हैं। क्षेत्रीय मानक अनुसंधान व वैध व्यापार को समर्थन दे सकते हैं, जबकि कमज़ोर या समय-पूर्व मानकीकरण स्थानीय प्रथाओं को हाशिए पर डाल सकता है। इसलिए प्रस्तावित सहयोग में वैज्ञानिक सत्यापन, फार्माकोविजिलेंस, सामुदायिक अधिकार, लाभ-साझाकरण और राष्ट्रीय जैव-विविधता कानूनों का सम्मान – सबको साथ जोड़ना होगा।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
BIMSTEC	बहु-क्षेत्रीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल।
TKDL	भारत का पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय।
पूर्व-कला (Prior art)	यह परखने के लिए इस्तेमाल होने वाला मौजूदा ज्ञान कि कोई पेटेंट-दावा वाकई नया है या नहीं।
लाभ-साझाकरण	आनुवंशिक संसाधनों या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के इस्तेमाल से होने वाले लाभ को साझा करना।
पूर्व-सूचित सहमति	किसी आनुवंशिक संसाधन या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंचने से पहले, प्रस्तावित इस्तेमाल की पर्याप्त जानकारी देकर, प्रदाता देश या ज्ञान-धारक समुदाय से ली गई अनुमति।
आपसी सहमति वाली शर्तें	आनुवंशिक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी पहुंच, अनुसंधान, व्यावसायिक इस्तेमाल व लाभ-साझाकरण को नियंत्रित करने वाली संविदात्मक शर्तें।
जैव-हड़प (Biopiracy)	वैध सहमति, मान्यता या उचित लाभ-साझाकरण के बिना जैविक संसाधनों या सामुदायिक ज्ञान का व्यावसायिक या पेटेंट-आधारित हड़प।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: क्षेत्रीय सहयोग
- GS III: बौद्धिक संपदा अधिकार व जैव-प्रौद्योगिकी। प्रारंभिक परीक्षा: BIMSTEC सदस्य व TKDL।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2310942®=48&lang=1>

अर्थव्यवस्था एवं वित्त (Economy And Finance)

11. अप्रैल-अगस्त 2026-27 में भारत के निर्यात में वृद्धि

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

PIB तिथि: 15 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

अप्रैल-अगस्त 2026-27 के दौरान वस्तु व सेवाओं का संयुक्त निर्यात लगभग 399.27 अरब डॉलर आंका गया, जो पिछले साल के 345.55 अरब डॉलर से 15.55% ज्यादा है। वस्तु-निर्यात 17.85% बढ़कर 215.91 अरब डॉलर पहुंचा। सेवा-निर्यात लगभग 183.36 अरब डॉलर रहा। कुल आयात 459.65 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिससे कुल व्यापार-घाटा 60.38 अरब डॉलर हो गया। अगस्त 2026 में कुल निर्यात लगभग 82.68 अरब डॉलर और आयात 92.09 अरब डॉलर रहा। संयुक्त घाटा 9.41 अरब डॉलर रहा। वस्तु-निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और कपास/हथकरघा उत्पाद प्रमुख चालक रहे। अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात साल-दर-साल 89.82% बढ़कर 5.55 अरब डॉलर पहुंच गया। हाल के महीने के सेवा-आंकड़ों में अनुमान शामिल थे क्योंकि RBI का अंतिम डेटा अभी उपलब्ध नहीं था।

मासिक व्यापार-आंकड़े वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क डेटा और सेवाओं के लिए RBI-आधारित अनुमानों को जोड़ते हैं। वस्तु-आंकड़े जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि हालिया सेवा-मूल्य अनुमानित हो सकते हैं और बाद में संशोधित किए जा सकते हैं। इसलिए संयुक्त हेडलाइन एक अंतिम भुगतान-शेष विवरण के बजाय शुरुआती तस्वीर देता है।

निर्यात-वृद्धि सकारात्मक है, पर पांच महीने की अवधि में आयात तेज़ी से बढ़ा, जिससे संयुक्त घाटा और चौड़ा हुआ। वस्तु-व्यापार में आमतौर पर घाटा रहता है, जबकि भारत का सेवा-अधिशेष इसे आंशिक रूप से संतुलित करता है। अनुमानित सेवा-आंकड़ों को अंतिम के बजाय अस्थायी मानकर पढ़ा जाना चाहिए।

15.55% की निर्यात-वृद्धि मज़बूत बाहरी मांग व आपूर्ति-क्षमता, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स व इंजीनियरिंग में, दिखाती है। हालांकि कुल आयात इससे तेज़ी से बढ़ा, जिससे पांच महीने का घाटा चौड़ा हुआ। पेट्रोलियम निर्यात सिर्फ मात्रा के बजाय मूल्य व रिफाइनिंग कारकों के चलते बढ़ सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स की वृद्धि में अब भी आयातित कल-पुर्जे शामिल हो सकते हैं। एक टिकाऊ निर्यात-रणनीति के लिए घरेलू मूल्य-वर्धन, विविधीकृत बाज़ार, लॉजिस्टिक्स-दक्षता, स्थिर व्यापार-नीति व प्रतिस्पर्धी सेवाएं ज़रूरी हैं। नीति-निर्माताओं को नाममात्र मूल्य-वृद्धि को मात्रा-वृद्धि से अलग करके देखना चाहिए और यह जांचना चाहिए कि निर्यात-टोकरी तकनीकी रूप से ज़्यादा परिष्कृत हो रही है या नहीं। सेवा-अधिशेष भारत के वस्तु-घाटे के खिलाफ एक बड़ा सहारा बना हुआ है।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
वस्तु-व्यापार	भौतिक सामान का व्यापार।
सेवा-व्यापार	IT, वित्त, परिवहन व पर्यटन जैसी सीमापार सेवाएं।
व्यापार-शेष	निर्यात घटा आयात।
गैर-पेट्रोलियम निर्यात	पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर निर्यात, जिसका इस्तेमाल व्यापक निर्यात-प्रदर्शन आंकड़े के लिए होता है।
संयुक्त व्यापार-घाटा	वस्तु व सेवाओं को जोड़ने के बाद कुल आयात व कुल निर्यात के बीच का अंतर। भारत का सेवा-अधिशेष इसके वस्तु-घाटे का एक हिस्सा भरता है, पूरा नहीं।
अस्थायी सेवा-अनुमान	पूर्ण RBI डेटा उपलब्ध होने से पहले अनुमानित किया गया हालिया महीने का सेवा-आंकड़ा। अंतिम भुगतान-शेष जानकारी जारी होने पर ऐसे अनुमान संशोधित हो सकते हैं।
निर्यात मूल्य बनाम मात्रा	निर्यात-आय इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि ज़्यादा सामान बिका, कीमतें बढ़ीं या उत्पाद-मिश्रण बदला। सिर्फ मूल्य-वृद्धि से निर्यात की भौतिक मात्रा का पता नहीं चलता।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार व भुगतान-संतुलन। प्रारंभिक परीक्षा: व्यापार-शेष की गणना और वस्तु व सेवाओं के बीच अंतर।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2310636®=48&lang=1>

12. SEMICON इंडिया 2026 और सेमीकॉन 2.0 रोडमैप

मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

PIB तिथि: 17 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

SEMICON इंडिया 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली के यशोभूमि में 'सिलिकॉन से सिस्टम तक: पारितंत्र का निर्माण' विषय के तहत हुआ। इस आयोजन में 600 से ज्यादा प्रदर्शक, लगभग 300 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी, छह देश-पवेलियन और बारह राज्य-पवेलियन शामिल रहे। सेमीकॉन 2.0 छह स्तंभों में समर्थन बढ़ाता है: डिज़ाइन; उपकरण व सामग्री; फैब्रिकेशन; उन्नत पैकेजिंग; व्यावहारिक अनुसंधान व विकास; और प्रतिभा। घोषित मिशन-बजट सेमीकॉन 1.0 के लगभग 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर हो गया है। भारत ने 70,000 प्रशिक्षित डिज़ाइन इंजीनियर और 500 से ज्यादा संस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक-डिज़ाइन-ऑटोमेशन (EDA) उपकरणों की तैनाती की जानकारी दी। स्वीकृत बारह इकाइयों में से पांच वाणिज्यिक ATMP इकाइयां चालू हो चुकी हैं। CDIL मोहाली व सूचि सेमीकॉन सूरत में वाणिज्यिक उत्पादन-लाइनों का उद्घाटन हुआ। सानंद में माइक्रॉन का DRAM व NAND उत्पादन जारी होने की जानकारी मिली, जबकि टाटा का धोलेरा फैब्रिकेशन संयंत्र व जागीरोड OSAT सुविधा अब भी निर्माणाधीन हैं। उपकरण, सामग्री, लिथोग्राफी, पैकेजिंग, प्रशिक्षण व आपूर्ति-शृंखलाओं को लेकर बड़ी औद्योगिक प्रतिबद्धताएं सामने आईं, जो इस बात पर जोर देती हैं कि एक व्यवहार्य सेमीकंडक्टर पारितंत्र के लिए महज़ फैब्रिकेशन संयंत्र से कहीं ज्यादा चाहिए।

सेमीकंडक्टर उत्पादन एक अकेली फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक शृंखला है। यह वास्तुकला व चिप-डिज़ाइन से शुरू होकर मास्क, सामग्री व वेफर-फैब्रिकेशन से गुजरता है, और असेंबली, पैकेजिंग, परीक्षण व सिस्टम में एकीकरण पर समाप्त होता है। हर चरण की पूंजी, तकनीक व कौशल-ज़रूरतें अलग होती हैं। गिने-चुने देशों में यह वैश्विक संकेंद्रण व्यवधानों को एक रणनीतिक जोखिम बनाता है।

एक चिप-पारितंत्र में डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, विशेष रसायन व गैसों, मशीनरी, वेफर-फैब्रिकेशन, परीक्षण, पैकेजिंग, भरोसेमंद बिजली व कुशल कामगार – सब शामिल हैं। सेमीकॉन 2.0 इन आपस में जुड़ी कमियों को भरने और भारत को प्रोत्साहनों व मंज़ूरियों से आगे बढ़ाकर वाणिज्यिक उत्पादन की ओर ले जाने की कोशिश करता है।

सेमीकॉन 2.0, मुख्यतः बड़े फैब्रिकेशन आकर्षित करने पर केंद्रित प्रोत्साहन-नीति की कमज़ोरी को सुधारने की कोशिश करता है। संयंत्रों को वाणिज्यिक उत्पादन-क्षमता तक पहुंचाने के लिए उपकरण, रसायन, गैसों, पैकेजिंग, व्यावहारिक अनुसंधान व प्रतिभा – सबको साथ-साथ विकसित होना होगा। भारत के पास डिज़ाइन-क्षमता व घरेलू मांग है, पर फैब्रिकेशन के लिए भरोसेमंद उपयोगिताओं, अनुभवी प्रक्रिया-इंजीनियरों व बार-बार तकनीकी उन्नयन की ज़रूरत होती है। सार्वजनिक समर्थन

को मील के पत्थरों, घरेलू मूल्य-सृजन व पर्यावरणीय सुरक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। भारत मैच्योर नोड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर व उन्नत पैकेजिंग जैसे यथार्थवादी क्षेत्रों को अपना सकता है, साथ ही उपकरण व तकनीक के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां भी बनाए रख सकता है जिन्हें जल्दी स्वदेशी बनाना संभव नहीं।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
फैब	एक सेमीकंडक्टर वेफर-फैब्रिकेशन सुविधा।
ATMP/OSAT	असेंबली, परीक्षण, मार्किंग व पैकेजिंग; आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली व परीक्षण।
EDA उपकरण	इलेक्ट्रॉनिक चिप डिजाइन व सत्यापन के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर।
लिथोग्राफी	वेफर पर बेहद छोटे सर्किट-पैटर्न स्थानांतरित करने की प्रक्रिया।
DRAM व NAND	सेमीकंडक्टर मेमोरी के प्रमुख प्रकार।
सेमीकॉन 2.0 के छह स्तंभ	डिजाइन; उपकरण व सामग्री; फैब्रिकेशन; उन्नत पैकेजिंग; व्यावहारिक अनुसंधान व विकास; और प्रतिभा। यह ढांचा मानता है कि आसपास के पारितंत्र के बिना कोई फैब सफल नहीं हो सकता।
प्रक्रिया-उपज (Process yield)	निर्मित चिप्स में से उतना अनुपात जो निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है। वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थिर उपकरण, सामग्री, प्रक्रिया-नियंत्रण व अनुभवी इंजीनियरों के ज़रिए उपज बढ़ाने पर निर्भर करती है।
कंपाउंड सेमीकंडक्टर	सिलिकॉन कार्बाइड या गैलियम नाइट्राइड जैसी सामग्रियों से बनी चिप्स। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, संचार व उच्च-तापमान अनुप्रयोगों के लिए अहम हैं।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: विज्ञान-तकनीक, औद्योगिक नीति, आपूर्ति-शृंखला सहनशीलता व रणनीतिक क्षेत्र। मुख्य परीक्षा: एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारितंत्र बनाने में अवसर व बाधाएं।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2311726®=48&lang=1>

13. नया UPI ढांचा: P2P व अधिकांश व्यापारी भुगतान मुफ्त बरकरार

LESS NOISE. MORE RETENTION.

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

PIB तिथि: 15 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) UPI लेनदेन मूल्य चाहे जो हो, मुफ्त बने रहेंगे। 2,000 रुपये तक के व्यापारी लेनदेन और योग्य छोटे व्यापारियों को मिलने वाले भुगतान भी शून्य MDR के दायरे में रहेंगे, जिससे लगभग 96% व्यापारी लेनदेन अप्रभावित रहेंगे। 2,000 रुपये से ऊपर के निर्दिष्ट व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन पर 0.4% व्यापारी छूट दर (MDR) लागू होगी, जो 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगी। रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन व कृषि-आदानों जैसे ज़रूरी व कम-मार्जिन वाले क्षेत्रों में 2,000 रुपये से ऊपर के लागू लेनदेन पर 5 रुपये की समान

MDR लगेगी। पूंजी-बाज़ार लेनदेन पर 0.02% MDR लगेगा, जो अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा। MDR को बैंकों, भुगतान-सेवा प्रदाताओं व UPI ऐप प्रदाताओं के बीच बांटा जाता है; यह कोई सरकारी कर नहीं है और इसे ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह ढांचा भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत लाया गया।

UPI एक शून्य-शुल्क ढांचे के तहत तेज़ी से बढ़ा, जिसने उपभोक्ताओं व व्यापारियों दोनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी मॉडल ने एक नीतिगत सवाल भी खड़ा किया: उपयोगकर्ताओं से कुछ न लिए जाने के बावजूद बैंकों, स्विचिंग बुनियादी ढांचे व भुगतान-ऐप्स को परिचालन, सुरक्षा व विवाद-निपटान की लागत उठानी पड़ती है। नई व्यवस्था सामान्य हस्तांतरण व छोटे भुगतानों पर बोझ डाले बिना इस पारितंत्र को वित्तपोषित करने की कोशिश करती है।

ग्राहक बिना किसी लेनदेन-शुल्क के UPI इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। MDR व्यापारी लेनदेन के एक सीमित वर्ग पर लगने वाला एक पारितंत्र-शुल्क है। यह नीति व्यक्तियों व छोटे व्यापारियों की रक्षा करते हुए भुगतान बुनियादी ढांचे के रख-रखाव व विस्तार के लिए राजस्व बनाने की कोशिश करती है।

P2P को मुफ्त रखना UPI के बुनियादी सार्वजनिक-उपयोगिता स्वरूप की रक्षा करता है। 2,000 रुपये तक के भुगतान व योग्य छोटे व्यापारियों को छूट देने से रेहड़ी-पटरी वालों व मोहल्ले के कारोबारों पर असर सीमित रहता है। जोखिम यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से यह बोझ आगे बढ़ाया जा सकता है: व्यापारी कीमतें बढ़ा सकते हैं, UPI को हतोत्साहित कर सकते हैं या निर्देशों के बावजूद अनौपचारिक अधिभार लगा सकते हैं। पारदर्शी निपटान, शिकायत-निवारण तंत्र व ऐप्स के बीच प्रतिस्पर्धा अहम होगी। MDR से मिलने वाला राजस्व छिपे उपभोक्ता-शुल्क बनाने के बजाय अपटाइम, धोखाधड़ी-नियंत्रण व नवाचार को समर्थन देना चाहिए। सुरक्षा-लेनदेन सीमाओं व शुल्क-सीमाओं के बीच का अंतर प्रारंभिक परीक्षा और आम समझ, दोनों के लिए अहम है।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
UPI	यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस, जिसे NPCI तुरंत बैंक-से-बैंक भुगतान के लिए संचालित करता है।
P2P	व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान।
P2M	व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतान।
MDR	व्यापारी छूट दर, जो व्यापारी-भुगतान संसाधित करने वाले भागीदारों के बीच बांटी जाती है।
NPCI	नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
शून्य-MDR ढांचा	वह नीति, जिसके तहत निर्दिष्ट UPI व्यापारी भुगतानों पर व्यापारी छूट दर नहीं लगती। यह छोटे-मूल्य के डिजिटल भुगतानों की रक्षा करती है, पर पारितंत्र की परिचालन-लागत का सवाल अनसुलझा छोड़ देती है।
P2PM श्रेणी	QR कोड के ज़रिए भुगतान पाने वाले योग्य छोटे व्यापारियों के लिए व्यक्ति-से-व्यक्ति-व्यापारी वर्गीकरण, जिसमें यह नई व्यवस्था तय मासिक स्तर तक की प्राप्तियों की रक्षा करती है।

शब्द	परिभाषा
भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	भारत में भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून, जो RBI को प्रणाली-प्रदाताओं को अधिकृत, निगरानी व मानक तय करने का अधिकार देता है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन व भुगतान प्रणालियाँ। प्रारंभिक परीक्षा: NPCI, MDR व भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2310586®=48&lang=1>

14. विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026

मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

PIB तिथि: 15-16 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

भारत ने गांधीनगर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच (WCEF) की मेज़बानी की, जो दक्षिण एशिया में इसका पहला संस्करण था। इसका विषय था 'चक्रीय अर्थव्यवस्था: लोगों व समृद्धि के लिए बदलाव'। इस मंच में 65 से ज़्यादा देशों के 2,000 से अधिक हितधारक शामिल हुए और 125 से ज़्यादा प्रदर्शक मौजूद रहे। इसका संयुक्त आयोजन भारतीय संस्थानों, गुजरात सरकार, फिनलैंड व फिनिश इनोवेशन फंड सित्रा ने किया। चर्चाओं में चक्रीय वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोज़गार, टिकाऊ उत्पाद, औद्योगिक समाधान, शासन-व्यवस्था, स्टार्टअप व युवा-भागीदारी शामिल रही। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत उपभोग व उत्पादन पर 10-वर्षीय कार्यक्रम ढांचे (10YFP) से जुड़ी एक बैठक भी आयोजित की, जिसके बोर्ड की सह-अध्यक्षता भारत करता है। समापन आह्वान में समावेशी व विस्तार-योग्य चक्रीय समाधान, मज़बूत संस्थाएं व क्षमता, और निर्णय-प्रक्रिया में चक्रीयता के एकीकरण की मांग की गई। WCEF 2027 की मेज़बानी की बागडोर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय को सौंपी गई।

पारंपरिक उत्पादन संसाधन निकालता है, सामान बनाता है और इस्तेमाल के बाद उसे फेंक देता है। चक्रीयता उत्पाद के जीवन को बढ़ाकर, सामग्री की पुनर्प्राप्ति करके और नई सामग्री की मांग घटाकर इस प्रवाह को फिर से डिज़ाइन करती है। यह रीसाइक्लिंग से आगे जाती है: मरम्मत-योग्यता, लीज़िंग, पुनर्निर्माण, औद्योगिक सहजीविता (symbiosis) और उत्पाद-सेवा मॉडल, कचरा बनने से पहले ही उसे रोक सकते हैं।

एक रैखिक अर्थव्यवस्था 'लो-बनाओ-फेंको' पैटर्न का पालन करती है। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था टिकाऊपन, मरम्मत, पुनः-उपयोग, पुनर्निर्माण व रीसाइक्लिंग के ज़रिए उत्पादों व सामग्रियों को इस्तेमाल में बनाए रखने की कोशिश करती है। यह कचरा व कच्चे माल की मांग घटा सकती है, पर सिर्फ तभी जब उत्पाद-डिज़ाइन, वित्त, मानक व बाज़ार साथ-साथ बदलें।

दक्षिण एशिया में WCEF की मेज़बानी अक्सर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा तय बहस में विकासशील देशों की चिंताओं को शामिल करती है। भारत के अनौपचारिक मरम्मत व रीसाइक्लिंग नेटवर्क पहले से ही सामग्री-मूल्य को बचाते हैं, पर श्रमिकों को अक्सर असुरक्षित हालात व कम आय का सामना करना पड़ता है। एक न्यायसंगत चक्रीय परिवर्तन में औपचारिक मानकों को आजीविका व सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ना ज़रूरी है। द्वितीयक सामग्रियों के लिए वित्त व भरोसेमंद बाज़ार चाहिए; खराब ढंग से डिज़ाइन किए गए अनिवार्य नियम डाउनसाइक्लिंग या ग्रीनवॉशिंग की ओर ले जा सकते हैं। डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट, विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR) व सार्वजनिक खरीद, ट्रेसबिलिटी व मांग बेहतर बना सकते हैं। इस मंच का वास्तविक मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वैश्विक चर्चा निवेश-योग्य परियोजनाओं, तकनीक तक पहुंच व नापने योग्य सामग्री-दक्षता परिणामों में तब्दील होती है या नहीं।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
चक्रीय अर्थव्यवस्था	एक आर्थिक मॉडल, जो कचरा कम करता है और सामग्रियों को संचरण में बनाए रखता है।
संसाधन-दक्षता	कम सामग्री, ऊर्जा व पर्यावरणीय प्रभाव के साथ मूल्य पैदा करना।
विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी	एक नीति, जो उत्पादकों को उपभोक्ता-उपयोग के बाद उत्पाद-प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार बनाती है।
सित्रा	फिनिश इनोवेशन फंड और WCEF का एक संस्थापक भागीदार।
औद्योगिक सहजीविता	एक व्यवस्था, जिसमें एक उद्योग का कचरा, गर्मी, पानी या उप-उत्पाद किसी दूसरे उद्योग के लिए आदान बन जाते हैं, जिससे निपटान व नई सामग्री की मांग घटती है।
उत्पाद जीवन विस्तार	डिज़ाइन, मरम्मत, रख-रखाव, नवीनीकरण व पुनर्निर्माण, जो सामग्री-रीसाइक्लिंग ज़रूरी होने से पहले किसी उत्पाद को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखते हैं।
10YFP	सतत उपभोग व उत्पादन पर संयुक्त राष्ट्र का 10-वर्षीय कार्यक्रम ढांचा, जो संसाधन-दक्ष व कम-प्रभाव वाले उत्पादन व उपभोग पैटर्न को तेज़ करने के लिए बनाया गया है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: पर्यावरण, संसाधन-दक्षता व सतत विकास। निबंध: कचरा-प्रबंधन से चक्रीय उत्पादन प्रणालियों की ओर बढ़ना।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2311052®=48&lang=1>

15. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

मंत्रालय: खान मंत्रालय / PIB बैकग्राउंडर

PIB तिथि: 17 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

सितंबर 2015 में शुरू हुई PMKKKY, खनन-प्रभावित क्षेत्रों में कल्याण व विकास के लिए ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधि को निर्देशित करती है। जनवरी 2024 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। ज़िला खनिज प्रतिष्ठान, खान व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 में 2015 के संशोधन के बाद स्थापित गैर-लाभकारी न्यास हैं। DMF राज्य सरकारों के अधीन संचालित होते हैं और 23 राज्यों के 656 ज़िलों में स्थापित किए जा चुके हैं। 12 जनवरी 2015 या उसके बाद दी गई खनन-पट्टियां रॉयल्टी का 10% DMF को देती हैं; पुरानी पट्टियां रॉयल्टी का 30% देती हैं। PMKKKY सरकारी कार्यक्रमों का पूरक बनना, खनन के पर्यावरणीय व स्वास्थ्य प्रभावों को घटाना और टिकाऊ आजीविका बनाना चाहती है। कम से कम 70% निधि उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर निर्देशित की जाती है। अनुसूचित क्षेत्रों में क्रियान्वयन को PESA व वन अधिकार अधिनियम का सम्मान करना होगा।

खनन व्यापक अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाता है, पर पर्यावरणीय व सामाजिक लागत मेज़बान समुदायों पर केंद्रित हो जाती है। रॉयल्टी मुख्यतः सरकार के पास जाती है, जबकि विस्थापन, धूल, जल-संकट व आजीविका-व्यवधान स्थानीय स्तर पर झेले जाते हैं। 2015 के DMF तंत्र ने खनन-गतिविधि से जुड़ा एक ज़िला-स्तरीय कोष बनाया, और PMKKKY उस कोष के इस्तेमाल का मार्गदर्शन करती है।

खनन सार्वजनिक राजस्व पैदा करता है, पर इसकी स्थानीय लागतें – प्रदूषण, विस्थापन व आजीविका की हानि – मेज़बान ज़िलों में केंद्रित होती हैं। DMF निधि-कोष बनाता है; PMKKKY प्रभावित लोगों व स्थानों पर उसे खर्च करने का ढांचा देती है।

यह योजना सामान्य विभागीय बजट का इंतज़ार किए बिना स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पोषण, कौशल-विकास व आजीविका-बहाली को वित्तपोषित कर सकती है। फिर भी बड़ी वसूली अपने आप अच्छे नतीजे सुनिश्चित नहीं करती। ज़िला-योजनाओं पर ठेकेदारों या सामान्य बुनियादी ढांचे का दबदबा हो सकता है, बजाय सबसे प्रभावित बस्तियों के। PESA के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भागीदारी खासतौर पर अहम है। सार्वजनिक डैशबोर्ड, सामाजिक अंकेक्षण, स्वतंत्र प्रभाव-आकलन और नियमित सरकारी खर्च को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसके साथ अभिसरण ज़रूरी है। योजना-निर्माण को खनन-बंदी और निष्कर्षण घटने के बाद की दीर्घकालिक आजीविका को भी कवर करना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
DMF	ज़िला खनिज प्रतिष्ठान, खनन-प्रभावित लोगों के लिए एक ज़िला-स्तरीय गैर-लाभकारी न्यास।
रॉयल्टी	किसी खनिज संसाधन के निष्कर्षण के अधिकार के लिए किया गया भुगतान।
PESA	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996।
MMDR अधिनियम	भारत में खनिज विकास व विनियमन को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून।

शब्द	परिभाषा
खनन-प्रभावित क्षेत्र	प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित इलाका, जो विस्थापन, प्रदूषण, जल व सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव, परिवहन-क्षति या आजीविका-व्यवधान जैसे परिणाम झेलता है।
उच्च-प्राथमिकता क्षेत्र	PMKKKY कम से कम 70% निधि पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कल्याण, कौशल-विकास व पर्यावरणीय उपायों जैसी प्राथमिकता वाली ज़रूरतों के लिए अनिवार्य करती है।
खान-बंदी योजना	निष्कर्षण घटने या रुकने के बाद पर्यावरणीय पुनर्वास व आजीविका की तैयारी। DMF योजना-निर्माण को खनन-चरण के दौरान सिर्फ बुनियादी ढांचे के बजाय दीर्घकालिक परिवर्तन को भी संबोधित करना चाहिए।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: कल्याण व विकेंद्रीकृत शासन
- GS III: खनन व समावेशी विकास। प्रारंभिक परीक्षा: DMF अंशदान व संस्थागत स्थिति।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2311538®=48&lang=1>

16. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण योजना

मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय / PIB बैकग्राउंडर

PIB तिथि: 17 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

ECMS का लक्ष्य महज़ अंतिम असेंबली से आगे बढ़कर, कल-पुर्ज़ी, उप-असेंबली, आपूर्ति-शृंखला उत्पादों व संबंधित पूंजीगत सामान का समर्थन कर घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को गहराई देना है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि निर्यात 38,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 4.24 लाख करोड़ रुपये हो गया। कई अहम कल-पुर्ज़ी व सामग्रियों के लिए आयात-निर्भरता अब भी ऊंची बनी हुई है। यह योजना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा व डिस्प्ले मॉड्यूल, कनेक्टर, कैपेसिटर, लिथियम-आयन सेल व दुर्लभ-मृदा चुंबक जैसे उत्पादों को कवर करती है। ECMS को 8 अप्रैल 2025 को 22,919 करोड़ रुपये के शुरुआती परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। केंद्रीय बजट 2026-27 ने परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया। अगस्त 2026 तक, 15 राज्यों में 106 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी थीं, जिनमें 69,548 करोड़ रुपये का स्वीकृत निवेश शामिल है।

अंतिम असेंबली रोज़गार व निर्यात तो पैदा कर सकती है, पर उत्पाद-मूल्य का बड़ा हिस्सा आयातित डिस्प्ले, कैमरा-मॉड्यूल, बैटरी, सर्किट बोर्ड व कल-पुर्ज़ी में ही अंतर्निहित रह जाता है। इससे विनिर्माता मुद्रा-उतार-चढ़ाव, शिपिंग-व्यवधान

व विदेशी आपूर्ति-प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ECMS भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य-शृंखला में और आगे ले जाने की कोशिश करती है।

भारत, खासकर मोबाइल फोन में, एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलर बन चुका है। ECMS कल-पुर्जों व उत्पादन-उपकरणों की गहरी परत को लक्षित करती है। ज्यादा घरेलू मूल्य-वर्धन आयात-कमजोरी घटा सकता है और निर्यात को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकता है।

कल-पुर्जा विनिर्माण मोबाइल फोन, वाहन, दूरसंचार उपकरण व उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के इर्द-गिर्द आपूर्तिकर्ता-समूह बना सकता है। पैमाना, गुणवत्ता-प्रमाणन व भरोसेमंद मांग अहम हैं, क्योंकि कल-पुर्जे कम मार्जिन व वैश्विक मानकों पर काम करते हैं। प्रोत्साहनों को स्थायी रूप से गैर-प्रतिस्पर्धी क्षमता को बचाए रखने के बजाय कंपनियों को शुरुआती पैमाने व तकनीकी बाधाओं को पार करने में मदद करनी चाहिए। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ-मृदा प्रसंस्करण, बैटरी आपूर्ति-शृंखला व पूंजीगत सामान के साथ जुड़ाव लाभ को कई गुना बढ़ा सकता है। नीति-निर्माताओं को सिर्फ स्वीकृत निवेश के बजाय वास्तविक उत्पादन, घरेलू मूल्य-वर्धन व निर्यात पर नजर रखनी होगी। कौशल, लॉजिस्टिक्स व अनुसंधान-समर्थन यह तय करेंगे कि स्थानीय आपूर्तिकर्ता वैश्विक मूल्य-शृंखलाओं में शामिल हो पाते हैं या नहीं।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
कल-पुर्जा पारितंत्र	कल-पुर्जे, सामग्री, उप-असेंबली व विनिर्माण-उपकरण बनाने वाला नेटवर्क।
घरेलू मूल्य-वर्धन	किसी उत्पाद के मूल्य का वह हिस्सा, जो देश के भीतर बनाया जाता है।
PCB	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कल-पुर्जों को यांत्रिक रूप से थामता व विद्युतीय रूप से जोड़ता है।
पूंजीगत सामान	अन्य सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी व उपकरण।
आयात-निर्भरता	अहम कल-पुर्जों व सामग्रियों के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता। यह भारतीय असेंबली संचालन को मुद्रा-बदलाव, लॉजिस्टिक्स-व्यवधान व निर्यात-नियंत्रण के प्रति संवेदनशील बना सकती है।
आपूर्ति-शृंखला उत्पाद	एक सामग्री, कल-पुर्जा या उप-असेंबली, जिसका इस्तेमाल कोई अन्य विनिर्माता करता है, न कि जो सीधे अंतिम उपभोक्ता को बेचा जाए; उदाहरणों में PCB, कनेक्टर व डिस्प्ले मॉड्यूल शामिल हैं।
स्वीकृत निवेश	मंजूर परियोजनाओं के तहत प्रस्तावित निवेश। इसे वास्तव में किए गए निवेश, हासिल हुए वाणिज्यिक उत्पादन व वाकई बने घरेलू मूल्य से अलग समझा जाना चाहिए।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: औद्योगिक नीति, विनिर्माण, आयात व वैश्विक मूल्य-शृंखलाएं। मुख्य परीक्षा: असेंबली-आधारित वृद्धि बनाम गहरी तकनीकी क्षमता।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2311234®=48&lang=1>

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science And Technology)

17. संबलपुर में भारत का 51वां डॉपलर मौसम रडार

मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

PIB तिथि: 17 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

भारत ने संबलपुर में अपना 51वां डॉपलर मौसम रडार चालू किया, जिससे गोपालपुर व पारादीप के बाद ओडिशा में अब तीन रडार हो गए हैं। यह प्रणाली पश्चिमी ओडिशा और झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के सटे हिस्सों में निगरानी मज़बूत करेगी। राष्ट्रीय रडार नेटवर्क 2014 के 14 से बढ़कर 51 हो गया है। मिशन मौसम के तहत लगभग 40 और रडार लगाने की योजना है, जिससे नेटवर्क लगभग 81 तक पहुंच जाएगा। यह रडार आंधी-तूफान, बिजली गिरने, भारी बारिश व अन्य खतरनाक मौसम का पता लगाने व तात्कालिक-पूर्वानुमान (nowcasting) को बेहतर बनाएगा। यह एक बहुस्तरीय अवलोकन-नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें स्वचालित मौसम-स्टेशन, वर्षामापी, रेडियोसॉड व माइक्रोवेव रेडियोमीटर भी शामिल हैं। भारत 13 पड़ोसी देशों को मौसम, चक्रवात व फ्लैश-फ्लड पूर्वानुमान सहायता भी देता है, जो घरेलू क्षमता को क्षेत्रीय आपदा-सहनशीलता से जोड़ती है।

जब अवलोकन कई स्तरों व स्थानों पर हालात दर्ज करते हैं, तो मौसम-पूर्वानुमान बेहतर होते हैं। उपग्रह व्यापक कवरेज देते हैं, जबकि रडार किसी क्षेत्र में वर्षा व तूफान की गति के बारे में उच्च-आवृत्ति जानकारी देता है। ज़मीनी स्टेशन, गुब्बारे व रेडियोमीटर संख्यात्मक मॉडलों के लिए ज़रूरी पूरक चर उपलब्ध कराते हैं।

एक डॉपलर रडार सिर्फ बारिश का पता ही नहीं लगाता। परावर्तित तरंगों की आवृत्ति में बदलाव मापकर, यह तूफानों के भीतर बारिश की बूंदों व हवा की गति का अनुमान लगाता है। इससे पूर्वानुमानकर्ताओं को तूफान की गति ट्रैक करने और कम-दूरी की चेतावनियां जारी करने में मदद मिलती है।

संबलपुर रडार एक ऐसे क्षेत्र में कवरेज-कमी को भरता है जहां गंभीर आंधी-तूफान, बिजली व तेज़ बारिश का खतरा रहता है। बेहतर तात्कालिक-पूर्वानुमान निकासी, कृषि-निर्णयों, विमानन, बिजली-उपयोगिताओं व जलाशय-प्रबंधन में मदद कर सकता है। सिर्फ बड़ा नेटवर्क होना काफी नहीं है: रडारों को कैलिब्रेट, रख-रखाव व पूर्वानुमान-मॉडलों तथा अंतिम-छोर चेतावनी-प्रणालियों के साथ एकीकृत करना होगा। चेतावनियां स्थानीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचनी चाहिए और स्पष्ट कार्रवाइयों में बदलनी चाहिए। ग़लत अलार्म व चूकी हुई घटनाएं जनता के भरोसे को प्रभावित करती हैं, इसलिए प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान – यानी सिर्फ मौसम क्या होगा नहीं, बल्कि इसका असर क्या होगा – अगला ज़रूरी कदम है।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
डॉपलर प्रभाव	स्रोत व पर्यवेक्षक के बीच सापेक्ष गति से होने वाला आवृत्ति में परिवर्तन।
तात्कालिक-पूर्वानुमान (Nowcasting)	आमतौर पर अगले कुछ घंटों के लिए बेहद कम-दूरी का पूर्वानुमान।
रेडियोसॉड	ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय हालात मापने वाला गुब्बारा-आधारित उपकरण।
मिशन मौसम	मौसम-अवलोकन, मॉडलिंग व पूर्वानुमान बेहतर बनाने का भारत का कार्यक्रम।
रडार परावर्तनशीलता	लौटी हुई रडार-ऊर्जा से प्राप्त एक माप, जो वर्षा की स्थिति व सापेक्ष तीव्रता दर्शाता है; तेज़ प्रतिध्वनि भारी बारिश या ओलावृष्टि का संकेत दे सकती है।
प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान	एक चेतावनी, जो सिर्फ बारिश या हवा के मान बताने के बजाय संभावित परिणामों – जैसे बाढ़, फसल-नुकसान या यातायात-व्यवधान – को समझाती है।
अवलोकन-नेटवर्क	रडार, उपग्रह, स्वचालित स्टेशन, वर्षामापी, गुब्बारों व अन्य सेंसरों की संयुक्त प्रणाली, जो पूर्वानुमानकर्ताओं व संख्यात्मक मॉडलों को डेटा देती है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS I: जलवायु-विज्ञान
- GS III: आपदा-प्रबंधन व विज्ञान। प्रारंभिक परीक्षा: डॉपलर सिद्धांत व रडार के उपयोग।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2311270®=48&lang=1>

18. जलवायु-सहनशील फसल विकास के लिए SPROUT सुविधा

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय / जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

PIB तिथि: 15 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

नई दिल्ली स्थित BRIC-राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (NIPGR) में स्वदेशी SPROUT सुविधा का उद्घाटन हुआ। SPROUT का मतलब है 'स्पीडसीड फेनोटाइपिंग व एकीकृत गुण-विश्लेषण के लिए संसाधन-अनुकूलन'। यह एक मौसम-निरपेक्ष नियंत्रित वातावरण है, जो उच्च-गति फेनोटाइपिंग, सटीक तनाव-परीक्षण और जननद्रव्य, प्रजनन-आबादी, उत्परिवर्ती, ट्रांसजेनिक पौधों व जीनोम-संपादित रेखाओं के मूल्यांकन के लिए बनाया गया है। शुरुआती फोकस मुख्यतः चना पर है। यह सुविधा जीन-खोज व जीनोम-संपादन को तेज़ गुण-सत्यापन से जोड़ती है। NIPGR का अलग SpeedSeed प्रोटोकॉल चने के प्रजनन-चक्र को लगभग 40 दिन तक घटा सकता है। यह परियोजना BioE3 नीति के जलवायु-सहनशील कृषि विषय को समर्थन देती है। 2014 से 2026 के बीच DBT-समर्थित शोध ने कृषि-जैव-प्रौद्योगिकी की 300 से ज़्यादा परियोजनाओं को समर्थन दिया और 50 से अधिक बेहतर किस्में विकसित कीं, जिनमें 17 जलवायु-सहनशील धान की किस्में शामिल हैं, जो लगभग 15 लाख हेक्टेयर में उगाई जा रही हैं।

पारंपरिक प्रजनन के लिए कई मौसमों व स्थानों पर बार-बार फसल-पीढ़ियों की ज़रूरत होती है। जलवायु परिवर्तन उन गुणों की संख्या बढ़ा देता है जिन्हें प्रजनकों को परखना पड़ता है, जिनमें गर्मी, सूखा, लवणता, बाढ़, कीट व अस्थिर वर्षा के प्रति सहनशीलता शामिल है। नियंत्रित-वातावरण फेनोटाइपिंग एक ही तनाव को सटीक रूप से लागू कर सकती है और बड़े पैमाने पर पौधों की प्रतिक्रिया माप सकती है।

एक उपयोगी जीन खोजना काफी नहीं; वैज्ञानिकों को यह भी परखना होता है कि क्या यह गर्मी, सूखा, लवणता या अन्य तनाव में वांछित गुण पैदा करता है। SPROUT पर्यावरणीय हालात को नियंत्रित करता है और पौध-पीढ़ियों को तेज़ करता है, जिससे प्रयोगशाला-खोज से बेहतर किस्म तक का रास्ता छोटा हो जाता है।

SPROUT भारत के जीनोमिक शोध को प्रजनन-परिणामों से जोड़ता है। SpeedSeed पीढ़ी-समय घटाता है, जबकि फेनोटाइपिंग यह परखती है कि कोई आशाजनक आनुवंशिक बदलाव वाकई प्रदर्शन सुधारता है या नहीं। यह तरीका चना-सुधार तेज़ कर सकता है, जो पोषण व दाल-सुरक्षा के लिए अहम है। प्रयोगशाला-सफलता के बावजूद बहु-स्थान क्षेत्र-परीक्षण अब भी ज़रूरी हैं, क्योंकि नियंत्रित हालात हर मिट्टी, कीट व मौसम की परस्पर-क्रिया को दोहरा नहीं सकते। उन्नत आनुवंशिकी के साथ जैव-सुरक्षा, बीज-पहुंच व किसान-उपयुक्तता भी साथ चलनी चाहिए। सार्वजनिक शोध को सिर्फ उपज पर ही नहीं, बल्कि विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए जल-उपयोग, पोषण-गुणवत्ता व सहनशीलता पर भी ध्यान देना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
फेनोटाइपिंग	किसी जीव के दृश्य गुणों को मापना।
जननद्रव्य (Germplasm)	प्रजनन व अनुसंधान में इस्तेमाल होने वाले जीवित आनुवंशिक संसाधन।
जीनोम संपादन	DNA में लक्षित बदलाव।
स्पीड ब्रीडिंग	पौध-पीढ़ी का समय घटाने के लिए नियंत्रित हालात का इस्तेमाल।
BioE3	अर्थव्यवस्था, पर्यावरण व रोज़गार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी नीति।
उच्च-गति फेनोटाइपिंग	आनुवंशिक भिन्नता को उपयोगी गुणों से जोड़ने के लिए नियंत्रित हालात, सेंसर व इमेजिंग का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में पौधों का तेज़ व बार-बार मापन।
सटीक तनाव-परीक्षण	निर्धारित गर्मी, सूखा, लवणता या अन्य तनाव लागू करना, ताकि पौधों की प्रतिक्रियाओं की भरोसेमंद तुलना हो सके और आशाजनक रेखाएं चुनी जा सकें।
गुण-सत्यापन	यह परखना कि कोई जीन, संपादन या प्रजनन-रेखा फील्ड-परीक्षण व किस्म-विकास तक बढ़ने से पहले लगातार इच्छित विशेषता देती है या नहीं।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: जैव-प्रौद्योगिकी, खाद्य-सुरक्षा व जलवायु-सहनशील कृषि। प्रारंभिक परीक्षा: फेनोटाइप बनाम जीनोटाइप और NIPGR/DBT की भूमिका।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2310460®=48&lang=1>

19. स्टील स्लैग सड़क प्रौद्योगिकी

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय / CSIR

PIB तिथि: 12 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

CSIR-CRRI की प्रसंस्कृत स्टील-स्लैग सड़क प्रौद्योगिकी निर्माण-लागत लगभग 40% घटा सकती है और उपयुक्त अनुप्रयोगों में पारंपरिक सड़कों की तुलना में चार गुना तक मज़बूती दे सकती है। बड़ी मरम्मत में लगभग 15 साल की देरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बनी 1.85 किलोमीटर लंबी सड़क को प्रसंस्कृत स्टील-स्लैग एग्रीगेट से बनी सबसे लंबी सड़क के तौर पर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। CSIR-CRRI व जिंदल स्टील ने एक तकनीक-हस्तांतरण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। स्टील-स्लैग इस्पात-निर्माण का एक उप-उत्पाद है। इसे सड़क-एग्रीगेट में प्रसंस्कृत करना, खनन व उत्खनन से मिलने वाले प्राकृतिक पत्थर के एक हिस्से का विकल्प बन जाता है, जिससे औद्योगिक कचरा बुनियादी ढांचे की सामग्री में बदल जाता है। इस तकनीक को ओडिशा में प्रस्तावित 40 किलोमीटर सड़क तक बढ़ाया जा रहा है और यह उचित प्रसंस्करण व इंजीनियरिंग मानकों के अधीन उच्च-भार, भारी-वर्षा व कठिन-भूभाग वाले अनुप्रयोगों के लिए प्रासंगिक है।

भारत का इस्पात-उद्योग बड़ी मात्रा में स्लैग पैदा करता है, जबकि सड़क-निर्माण उत्खनन से मिलने वाले प्राकृतिक एग्रीगेट की खपत करता है। उपयुक्त स्लैग को उपचारित करना इन दोनों सामग्री-प्रवाहों को जोड़ सकता है। इंजीनियरिंग चुनौती यह है कि स्लैग की संरचना व आयतन-स्थिरता अलग-अलग होती है, इसलिए प्रसंस्करण व गुणवत्ता-नियंत्रण ज़रूरी हैं।

अनुपचारित औद्योगिक कचरा सीधे सड़कों पर नहीं बिछाया जा सकता। स्टील-स्लैग को प्रसंस्कृत व इंजीनियर करना होगा ताकि यह स्थिर व सुरक्षित बना रहे। सही तरीके से इस्तेमाल होने पर, यह कचरा-निपटान घटाता है, प्राकृतिक एग्रीगेट बचाता है और सड़क-टिकाऊपन बढ़ा सकता है।

शुरुआती प्रसंस्करण की ज़रूरत के बावजूद, ज़्यादा मज़बूती व लंबे मरम्मत-चक्र जीवन-चक्र लागत घटा सकते हैं। प्राकृतिक एग्रीगेट की जगह लेने से उत्खनन-दबाव व लैंडफिल-मांग भी घटती है। लेकिन 'चार गुना मज़बूत' जैसे दावे तय परीक्षण व डिज़ाइन-हालात के तहत लागू होते हैं; अलग-अलग जलवायु, यातायात-भार व स्लैग-स्रोतों के लिए प्रदर्शन सत्यापित किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय निगरानी में रिसाव (leaching) व विस्तार के जोखिमों की जांच होनी चाहिए। मानक, प्रमाणन व तकनीक-हस्तांतरण, अनुपचारित कचरे को निर्माण में आने दिए बिना, इसे अपनाना संभव बना सकते हैं। सुरक्षा व जीवन-चक्र के प्रमाण स्थापित होने के बाद सार्वजनिक खरीद पैमाना बना सकती है।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
स्टील-स्लैग	इस्पात-निर्माण के दौरान अलग किया गया खनिज-समृद्ध उप-उत्पाद।

शब्द	परिभाषा
एग्रीगेट	सड़क-परतों व कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाला कुचला हुआ पत्थर जैसा दानेदार पदार्थ।
कचरे से संपदा	कचरा-प्रवाहों को उपयोगी आर्थिक आदानों में बदलना।
CSIR-CRRI	वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान।
प्रसंस्कृत स्टील-स्लैग एग्रीगेट	इंजीनियरिंग उपयोग के लिए उपचारित, स्थिरीकृत व श्रेणीबद्ध इस्पात-स्लैग। प्रसंस्करण ज़रूरी है क्योंकि अनुपचारित स्लैग की संरचना अलग-अलग हो सकती है या यह फैल सकता है।
जीवन-चक्र लागत	सड़क के उपयोगी जीवनकाल में निर्माण, रख-रखाव, व्यवधान व प्रतिस्थापन की कुल लागत; एक टिकाऊ सामग्री, प्रसंस्करण से शुरुआती लागत बढ़ने पर भी किफायती हो सकती है।
सामग्री-रिसाव (Leaching)	जब पानी किसी सामग्री से होकर गुजरता है तो रासायनिक तत्वों का बाहर निकलना। बुनियादी ढांचे में औद्योगिक उप-उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाने से पहले पर्यावरणीय परीक्षण आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: बुनियादी ढांचा, कचरा-प्रबंधन व स्वदेशी तकनीक। मुख्य परीक्षा: भारी उद्योग में चक्रीय अर्थव्यवस्था के अनुप्रयोग।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2309474®=48&lang=1>

20. टिकाऊ चमड़े व हरित सड़कों के लिए CSIR तकनीक-हस्तांतरण

मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय / CSIR

PIB तिथि: 16 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

CSIR ने CSIR-CLRI व CSIR-CRRI द्वारा विकसित तकनीकें उद्योग को हस्तांतरित कीं, ताकि प्रयोगशाला के समाधान व्यावसायिक उपयोग की ओर बढ़ सकें। CLRI की एक प्रक्रिया क्रोम-शेविंग्स से क्रोमियम-मुक्त प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट पुनर्प्राप्त करती है और इसे चमड़े की पुनः-टैनिंग में इस्तेमाल होने वाले सिटैन में बदल देती है। वाणिज्यिक-स्तर के सत्यापन ने 1,500 किलोग्राम तक पहुंच बनाई और टैनिंग-बाद के अपशिष्ट में कुल घुले ठोस पदार्थ को 50% तक घटा सकती है। एक अन्य प्रक्रिया इस्तेमाल हो चुके स्टील-पिकलिंग एसिड से लोहा व क्लोराइड पुनर्प्राप्त करती है और उन्हें पिगमेंट-श्रेणी के आयरन ऑक्साइड व अमोनियम क्लोराइड में बदल देती है। CRRI ने ClariVisor – एक वाहन-भीतरी चमक-न्यूनीकरण उपकरण – और एक विलायक-मुक्त दो-पैक ठंडा पॉटहोल-भरने वाला मिश्रण हस्तांतरित किया, जिसमें न तो हॉट-मिक्स प्लांट चाहिए, न गर्म करने की ज़रूरत, और यह सड़कों को तेज़ी से फिर से खोलने की अनुमति देता है।

सार्वजनिक प्रयोगशालाएं तभी सामाजिक मूल्य पैदा करती हैं जब उपयोगी शोध उत्पादन व उपयोगकर्ताओं तक पहुंचता है। तकनीक-हस्तांतरण में लाइसेंसिंग, प्रदर्शन, इंजीनियरिंग-समर्थन व औद्योगिक सत्यापन शामिल हो सकता है। चुनी गई CSIR तकनीकें चमड़े व इस्पात प्रसंस्करण से निकलने वाले कचरे के साथ-साथ सड़क-सुरक्षा व रख-रखाव की व्यावहारिक समस्याओं को भी संबोधित करती हैं।

तकनीक-हस्तांतरण सार्वजनिक शोध व औद्योगिक उत्पादन के बीच का पुल है। ये उदाहरण प्रदूषण-नियंत्रण को संसाधन-पुनर्प्राप्ति से जोड़ते हैं: चमड़े व इस्पात का कचरा आदान बन जाता है, जबकि सड़क-मरम्मत तकनीक ताप, ऊर्जा-उपयोग व मरम्मत-समय घटाती है।

क्रोम-शेविंग्स से प्रोटीन पुनर्प्राप्त करना, टेनरी की एक स्थायी समस्या घटाता है और पुनः-टैनिंग के लिए एक आदान बनाता है। इस्तेमाल हो चुके पिकलिंग एसिड से उत्पाद पुनर्प्राप्त करना भी उसी तरह खतरनाक कचरे को औद्योगिक सामग्री में बदल देता है। व्यावसायिक व्यवहार्यता लगातार कचरा-संग्रह, उत्पाद-गुणवत्ता व अनुपालन-लागत पर निर्भर करती है। ठंडा पॉटहोल-मिश्रण खासकर आपातकाल या मानसून के हालात में, ऊर्जा-गहन हॉट-मिक्स प्लांट के बिना तेज़ मरम्मत संभव बनाता है। ClariVisor वाहन के भीतर ही चमक को संबोधित करता है। उद्योग द्वारा अपनाए जाने की निगरानी पर्यावरणीय प्रदर्शन, लागत, लाइसेंसिंग-पहुंच व वास्तविक तैनाती के ज़रिए होनी चाहिए – महज़ हस्तांतरण-समझौतों पर हस्ताक्षर से नहीं।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
सिटैन	चमड़े की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाला एक सिंथेटिक टैनिंग एजेंट।
क्रोम-शेविंग्स	टैनिंग के बाद पैदा होने वाला क्रोमियम-युक्त चमड़ा-कचरा।
इस्तेमाल हो चुका पिकलिंग एसिड	इस्पात से ऑक्साइड व स्केल हटाने से निकलने वाला अम्लीय कचरा।
तकनीक-हस्तांतरण	किसी शोध-संस्था से किसी औद्योगिक उपयोगकर्ता को जानकारी लाइसेंस करना या हस्तांतरित करना।
प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट	रासायनिक या एंजाइमैटिक उपचार से छोटी शृंखलाओं में तोड़ा गया प्रोटीन। CLRI चमड़े के कचरे से क्रोमियम-मुक्त सामग्री पुनर्प्राप्त कर इसे सिटैन में फिर इस्तेमाल करती है।
ठंडा पॉटहोल-मिश्रण	बिना हॉट-मिक्स प्लांट या गर्म किए लगाई जाने वाली मरम्मत-सामग्री। यह ऊर्जा-उपयोग घटा सकती है, मौके पर ही तैयारी की अनुमति दे सकती है और मरम्मत की गई सड़क को तेज़ी से फिर खोल सकती है।
वाणिज्यिक लाइसेंसिंग	सहमत शर्तों के तहत किसी उद्योग-भागीदार को संरक्षित जानकारी या पेटेंट इस्तेमाल करने की अनुमति, जो अक्सर तकनीकी समर्थन व रॉयल्टी या शुल्क व्यवस्था के साथ आती है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: अनुसंधान व विकास, बौद्धिक संपदा, उद्योग व चक्रीय अर्थव्यवस्था।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2311019®=48&lang=1>

21. किसानों को भारत का पहला मृदा-कार्बन भुगतान

मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

PIB तिथि: 17 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

पंजाब व हरियाणा के 2,500 से ज़्यादा छोटे किसानों को सत्यापित पुनरोत्पादक-खेती (regenerative farming) परिणामों के लिए डिजिटल भुगतान मिलना शुरू हुआ। लगभग 2.9 करोड़ रुपये वितरित किए जाने थे, जिसमें व्यक्तिगत भुगतान लगभग 3,000-15,000 रुपये के बीच रहा। यह भुगतान 2019 में ICAR के तकनीकी मार्गदर्शन में शुरू हुए ग्रो इंडिगो कार्यक्रम 'आदि' से आया। अपनाई गई प्रथाओं में सीधी-बिजाई धान, कम जुताई व फसल-अवशेष प्रबंधन शामिल थे। कार्बन-क्रेडिट जारी करने से पहले उत्सर्जन-कमी व मृदा-कार्बन में वृद्धि को Verra की VM0042 पद्धति के तहत स्वतंत्र रूप से मापा व सत्यापित किया गया। पहला निर्गमन लगभग 30,000 एकड़ और 50,000 से ज़्यादा कार्बन-क्रेडिट को कवर करता है। कार्यक्रम का अनुमान है कि 2019-2022 के दौरान नामांकित खेतों में 4,500 करोड़ लीटर पानी बचाया गया, दो लाख टन से ज़्यादा फसल-अवशेष जलने से बचाए गए, और लगभग 1,000 टन PM2.5 उत्सर्जन टाला गया। व्यापक कार्यक्रम सात राज्यों में 20 लाख एकड़ से ज़्यादा और एक लाख से अधिक किसानों को कवर करता है। किसान एक निश्चित अग्रिम भुगतान या बिक्री के बाद शुद्ध कार्बन-राजस्व का 75% चुन सकते थे।

गहन जुताई, अवशेष-दहन व घटते कार्बनिक पदार्थ के चलते कृषि-मिट्टी कार्बन खो सकती है। कम जुताई, अवशेष-प्रतिधारण व विविध फसल-चक्र जैसी प्रथाएं मृदा-कार्बन फिर से बना सकती हैं और उत्सर्जन घटा सकती हैं। कार्बन-बाज़ार सत्यापित जलवायु-लाभ को किसानों के लिए एक अतिरिक्त राजस्व-स्रोत में बदलने की कोशिश करते हैं।

जब खेती की प्रथाएं कार्बनिक पदार्थ जोड़ती हैं या नुकसान घटाती हैं, तो मिट्टी कार्बन जमा कर सकती है। किसी कार्बन-क्रेडिट के लिए एक विश्वसनीय आधार-रेखा, मापन व स्वतंत्र सत्यापन चाहिए। मुख्य चुनौती है additionality, स्थायित्व, किसानों को उचित भुगतान व कम निगरानी-लागत सुनिश्चित करना।

पहला भुगतान इसलिए अहम है क्योंकि यह विचार को परियोजना-पंजीकरण से किसान-आय की ओर ले जाता है। फिर भी कृषि-कार्बन मापना मुश्किल है: थोड़ी दूरी पर भी मिट्टी अलग-अलग होती है, नतीजों में समय लगता है और संग्रहीत कार्बन उलटा भी हो सकता है। आधार-रेखा, additionality, रिसाव (leakage) व स्थायित्व को पारदर्शी तरीके से संभाला जाना चाहिए। वरना छोटे किसान प्रथा-बदलाव का जोखिम उठा सकते हैं जबकि बिचौलिए ज़्यादातर राजस्व ले जाएं। स्पष्ट अनुबंध, कम-लागत वाली MRV, शिकायत-निवारण तंत्र व क्रेडिट-मूल्यों का खुलासा ज़रूरी हैं। कार्बन-आय को गारंटीशुदा

वार्षिक भुगतान के बजाय जल-बचत, मृदा-स्वास्थ्य व कम दहन जैसे कृषि-संबंधी लाभों के पूरक के तौर पर देखा जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
मृदा जैविक कार्बन	मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ में संग्रहीत कार्बन।
एडिशनैलिटी (Additionality)	यह प्रमाण कि दावा किया गया जलवायु-लाभ परियोजना के बिना नहीं होता।
MRV	मापन, रिपोर्टिंग व सत्यापन।
सीधी-बिजाई धान	लगातार जलमग्न खेतों में रोपाई के बजाय सीधे बोया गया धान।
कार्बन-क्रेडिट	एक व्यापार-योग्य इकाई, जो आमतौर पर घटाए या हटाए गए एक टन CO ₂ -समतुल्य को दर्शाती है।
Verra VM0042	बेहतर कृषि भूमि-प्रबंधन प्रथाओं से होने वाली ग्रीनहाउस-गैस कमी व मृदा-कार्बन बदलावों को मापने की एक पद्धति।
स्थायित्व-जोखिम (Permanence risk)	यह संभावना कि खेती की प्रथा बदलने, मिट्टी में गड़बड़ी होने या जलवायु-हालात पलटने से बाद में संग्रहीत मृदा-कार्बन फिर से निकल जाए।
किसान राजस्व-हिस्सा	मापन, सत्यापन व कार्यक्रम-लागत के बाद नामांकित किसानों को मिलने वाला कार्बन-क्रेडिट आय का हिस्सा; निष्पक्षता के लिए अनुबंध-पारदर्शिता ज़रूरी है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: कृषि, जलवायु-वित्त, कार्बन-बाज़ार व वायु प्रदूषण। मुख्य परीक्षा: कृषि कार्बन-बाज़ारों में अवसर व सत्यनिष्ठा-जोखिम।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2311218®=48&lang=1>

22. भारत में डेटा सेंटर

मंत्रालय: PIB बैकग्राउंडर

PIB तिथि: 14 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

डेटा सेंटर सर्वर, स्टोरेज व नेटवर्किंग प्रणालियों का आधार हैं जो डिजिटल जानकारी को प्रोसेस व वितरित करते हैं। ये बैंकिंग, UPI, ई-गवर्नेंस, क्लाउड सेवाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की नींव हैं। निरंतर संचालन के लिए भरोसेमंद बिजली, निर्बाध विद्युत-आपूर्ति, बैकअप जनरेशन, कूलिंग, भौतिक व साइबर सुरक्षा, फाइबर-संपर्क, वर्चुअलाइजेशन व स्वचालित प्रबंधन चाहिए। भारत में वृद्धि के चालकों में तेज़ी से डिजिटलीकरण, बढ़ते क्लाउड व AI वर्कलोड, डेटा-संप्रभुता से जुड़ी चिंताएं, पनडुब्बी-केबल संपर्क, और ऐसी नीति-व्यवस्था शामिल है जो बुनियादी ढांचे का दर्जा देती है व निवेश को समर्थन देती है। यह क्षेत्र पर्यावरणीय व योजना-संबंधी चुनौतियां भी पैदा करता है: ऊंची बिजली व पानी की मांग, कूलिंग की ज़रूरतें, बड़े शहरों के आसपास संकेंद्रण, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा-दक्ष डिज़ाइन की ज़रूरत।

डिजिटल सेवाएं अमूर्त सी लगती हैं, पर ये ऊर्जा-गहन भौतिक सुविधाओं पर निर्भर करती हैं। हर सर्च, भुगतान, वीडियो या AI अनुरोध, जानकारी को कंप्यूट व स्टोर करने वाले सर्वरों तक नेटवर्क के ज़रिए पहुंचता है। बिजली, कूलिंग व संचार-कड़ियों में रिडंडेंसी ज़रूरी है, क्योंकि छोटी-सी विफलता भी ज़रूरी सेवाओं में रुकावट डाल सकती है।

डेटा सेंटर क्लाउड के पीछे मौजूद भौतिक बुनियादी ढांचा है। डेटा को भारत में रखने से लेटेंसी व नियामक-नियंत्रण बेहतर हो सकता है, पर अकेले लोकलाइज़ेशन से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। सहनशीलता बिजली, नेटवर्क, रिडंडेंसी, साइबर सुरक्षा व आपदा-योजना पर निर्भर करती है।

भारत का बड़ा उपयोगकर्ता-आधार, क्लाउड अपनाता व डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, एक मज़बूत घरेलू बाज़ार बनाते हैं। स्थानीय क्षमता लेटेंसी घटा सकती है और सहनशीलता बढ़ा सकती है, पर डेटा-लोकलाइज़ेशन अकेले साइबर-हमले या दुरुपयोग को नहीं रोकती। डेटा सेंटर, खासकर शहरी समूहों में, बिजली, ज़मीन व पानी के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। नीति को नवीकरणीय बिजली, कुशल कूलिंग, जल-पुनर्चक्रण, जहां संभव हो वहां ताप-पुनर्उपयोग और पारदर्शी PUE रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना चाहिए। भौगोलिक विविधीकरण व आपदा-पुनर्प्राप्ति संकेंद्रण-जोखिम घटा सकते हैं। परिचालन व साइबर सुरक्षा में कौशल, इमारतों जितना ही अहम है, जबकि पनुडुब्बी केबल व फाइबर नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय संपर्क तय करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
लेटेंसी	किसी डिजिटल अनुरोध को भेजने व जवाब मिलने के बीच की देरी।
क्लाउड कंप्यूटिंग	दूरस्थ कंप्यूटिंग संसाधनों तक मांग पर पहुंच।
वर्चुअलाइज़ेशन	एक भौतिक मशीन पर कई वर्चुअल सिस्टम चलाना।
PUE	पावर यूसेज इफेक्टिवनेस, डेटा-सेंटर की ऊर्जा-दक्षता का एक माप।
डेटा लोकलाइज़ेशन	यह अपेक्षा कि निर्दिष्ट डेटा किसी अधिकार-क्षेत्र के भीतर संग्रहीत या प्रोसेस किया जाए।
रिडंडेंसी	बिजली, नेटवर्क, स्टोरेज व कूलिंग प्रणालियों की दोहरी व्यवस्था, ताकि किसी एक हिस्से की विफलता डिजिटल सेवाओं को न रोके।
तरल कूलिंग	सिर्फ हवा के बजाय परिसंचारी तरल से सर्वर की गर्मी हटाना; सघन AI कंप्यूटिंग वर्कलोड के लिए यह तेज़ी से अहम होता जा रहा है।
डेटा संप्रभुता	यह सिद्धांत कि डेटा जिस अधिकार-क्षेत्र में संग्रहीत या प्रोसेस होता है, वह उसी के कानूनों व शासन-व्यवस्था के अधीन रहता है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: डिजिटल बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा व तकनीक के पर्यावरणीय प्रभाव।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2309950®=48&lang=1>

पर्यावरण (Environment)

23. गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण

मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

PIB तिथि: 13-14 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

गुजरात ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर एक विज्ञान-आधारित कार्य-योजना जारी की। इसका लक्ष्य 30 से ज्यादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की न्यूनतम व्यवहार्य आबादी बनाना और 200-500 वर्ग किमी सतत आवास सुरक्षित करना है, जिसकी शुरुआत लगभग 200 वर्ग किमी के लाला-रावा परिदृश्य से होगी। नलिया के पास प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा-ग्रस्त लगभग 11 वर्ग किमी घास के मैदान को शिकारी-रोधी बाड़ के साथ बहाल किया गया है। एक 'जंप-स्टार्ट' हस्तक्षेप में जंगली घोंसलों के बांझ अंडों को संरक्षण-प्रजनन कार्यक्रम के उपजाऊ अंडों से बदला गया; दूसरे प्रयास का एक चूड़ा जीवन के अहम पहले तीन महीनों से आगे बचा रहा। नलिया के पास एक सॉफ्ट रिलीज़ सेंटर, राजस्थान से लाए गए बंदी-पालित पक्षियों को उपयुक्त प्रोटोकॉल व आवास-हालात के तहत संभावित छोड़े जाने से पहले अनुकूलित करेगा। सायरा वन कवच 9.46 वर्ग किमी में फैला है और 47 देशी प्रजातियों के 10,000 से ज्यादा पौधों के साथ घने, बहु-स्तरीय वृक्षारोपण का इस्तेमाल करता है। व्यापक दौरे में मैंग्रोव व MISHTI भी शामिल रहे, जो परिदृश्य-स्तरीय संरक्षण को दर्शाता है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खुले घास के मैदानों व झाड़ी-पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर है, जिन्हें अक्सर गलती से बंजर भूमि मान लिया गया। आवास-परिवर्तन, व्यवधान, शिकार और ओवरहेड बिजली-लाइनों से टकराव, इसकी गिरावट में योगदान करते रहे हैं। छोटी, अलग-थलग आबादियों को अतिरिक्त आनुवंशिक व प्रजनन-जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक घास-मैदानी पक्षी है, इसलिए संरक्षण सिर्फ बंदी-प्रजनन पर निर्भर नहीं हो सकता। इसके लिए बड़े, जुड़े घास के मैदान, सुरक्षित आवाजाही, शिकारी-प्रबंधन और बिजली-लाइन टकराव जैसे खतरों की रोकथाम चाहिए। सॉफ्ट रिलीज़ बंदी-पालित जानवरों को पूर्ण रिहाई से पहले ढलने का मौका देता है।

गुजरात की योजना आवास-बहाली, प्रजनन-समर्थन व अंततः रिहाई को जोड़ती है। न्यूनतम व्यवहार्य आबादी सिर्फ बंदी पक्षियों की गिनती नहीं, बल्कि एक पारिस्थितिक लक्ष्य है; छोड़े गए जानवरों को जुड़ा हुआ आवास व कम मृत्यु-दर चाहिए। आक्रामक प्रोसोपिस हटाने से खुला घास का मैदान बहाल हो सकता है, जबकि शिकारी-रोधी बाड़े संवेदनशील चरणों में मदद करते हैं। सॉफ्ट रिलीज़ पक्षियों को धीरे-धीरे ढलने देता है, पर रिहाई सिर्फ वैज्ञानिक प्रोटोकॉल व खतरा-निवारण के साथ ही आगे बढ़नी चाहिए। बिजली-लाइन प्रबंधन व भूमि-उपयोग योजना केंद्रीय बने हुए हैं। सायरा वृक्षारोपण व मैंग्रोव-कार्य परिदृश्य-महत्वाकांक्षा दिखाते हैं, हालांकि घने वृक्षारोपण को GIB के लिए ज़रूरी खुले घास-मैदान आवास की बहाली समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	गंभीर रूप से संकटग्रस्त घास-मैदानी पक्षी, जो मुख्यतः राजस्थान व गुजरात में पाया जाता है।
न्यूनतम व्यवहार्य आबादी	दीर्घकाल तक जीवित रहने की संभावना रखने वाली सबसे छोटी आबादी।
सॉफ्ट रिलीज़	किसी बंदी-पालित जानवर को जंगल में छोड़ने से पहले धीरे-धीरे अनुकूलित करना।
प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा	एक आक्रामक काष्ठीय प्रजाति, जो खुले घास-मैदान आवास को नुकसान पहुंचा सकती है।
MISHTI	तटरेखा आवासों व मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल।
लाला-रावा परिदृश्य	कच्छ में स्थित लगभग 200 वर्ग किमी का केंद्रीय परिदृश्य, जिसे गुजरात की GIB कार्य-योजना के तहत तत्काल आवास-सुरक्षा व पुनर्प्राप्ति के लिए चिह्नित किया गया है।
जंप-स्टार्ट हस्तक्षेप	जंगली घोंसले में बांझ अंडे को संरक्षण-प्रजनन के उपजाऊ अंडे से बदलना, जिससे जंगली मादा उसे सेती व पालती है।
बिजली-लाइन टकराव	सीमित सामने की दृष्टि वाले बड़े, भारी पक्षियों के लिए मृत्यु का एक बड़ा खतरा। इसे रोकने में प्राथमिकता वाली लाइनों को भूमिगत करना या वैज्ञानिक रूप से प्रभावी डायवर्टर शामिल हो सकते हैं।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: जैव-विविधता, संकटग्रस्त प्रजातियां व आवास-बहाली। प्रारंभिक परीक्षा: GIB आवास व संरक्षण-शब्दावली।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2309882®=48&lang=1>

24. विश्व ओज़ोन दिवस व नए जलवायु-शासन पोर्टल

मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

PIB तिथि: 16 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

भारत ने मुंबई में 'ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई' विषय के तहत 32वां विश्व ओज़ोन दिवस मनाया। भारत 1992 से वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व इसके सभी संशोधनों का पक्षकार रहा है। भारत ने नियंत्रित उपयोगों के लिए CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड व हैलोन को चरणबद्ध रूप से हटाया है, और त्वरित HCFC चरणबद्ध-निष्कासन के लिए अपने 2015, 2020 व 2025 के लक्ष्य पूरे किए हैं। इसने 2021 में HFC के चरणबद्ध-न्यूनीकरण के लिए किगाली संशोधन की पुष्टि की। नेट जीरो पोर्टल संस्थाओं को स्वैच्छिक रूप से लक्ष्य पंजीकृत करने, ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन की रिपोर्ट देने व वार्षिक अपडेट देने की अनुमति देता है। स्कोप 1 व स्कोप 2 रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया जाता है; स्कोप 3 स्वैच्छिक बना हुआ है। NAPCC डैशबोर्ड, भारत के राष्ट्रीय जलवायु मिशनों में संकेतकों व क्रियान्वयन-जानकारी को एक जगह लाता है, ताकि निगरानी, अंतर-मंत्रालयी समन्वय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जुड़ाव को समर्थन मिले। 12

प्रशीतन व वातानुकूलन विनिर्माताओं की एक साझेदारी ने कम-ग्लोबल-वार्मिंग-क्षमता वाली तकनीकों व सुरक्षित रेफ्रिजरेंट हैंडलिंग के साथ तकनीशियन-प्रशिक्षण को जोड़ने के लिए 248 ITI को गोद लिया।

ओज़ोन-क्षरण व जलवायु परिवर्तन जुड़ी हुई पर अलग-अलग समस्याएं हैं। समताप-मंडलीय ओज़ोन जीवन को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने इस परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को घटाया और इसे व्यापक रूप से एक सफल पर्यावरणीय संधि माना जाता है। कुछ विकल्प, खासकर HFC, ओज़ोन की रक्षा तो करते हैं पर तापन में भारी योगदान देते हैं, जिससे किगाली संशोधन की ज़रूरत पड़ी।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों को नियंत्रित कर ओज़ोन परत की रक्षा करता है। किगाली संशोधन मुख्यतः HFC को उनकी उच्च ग्लोबल-वार्मिंग-क्षमता के कारण लक्षित करता है, भले ही HFC आमतौर पर ओज़ोन को नष्ट नहीं करते। नए पोर्टल अनिवार्य नेट-ज़ीरो लक्ष्य थोपने के बजाय पारदर्शिता व समन्वय को संबोधित करते हैं।

भारत का चरणबद्ध-निष्कासन रिकॉर्ड दिखाता है कि वित्त, तकनीकी बदलाव व औद्योगिक कार्यक्रम संधि-अनुपालन को कैसे समर्थन दे सकते हैं। तकनीशियन-प्रशिक्षण ज़रूरी है क्योंकि रिसाव व असुरक्षित हैंडलिंग रेफ्रिजरेंट-नीति को कमज़ोर कर सकते हैं। नेट ज़ीरो पोर्टल स्वैच्छिक कॉर्पोरेट प्रतिबद्धताओं को दृश्यता देता है, जबकि NAPCC डैशबोर्ड मिशनों के बीच बिखरी रिपोर्टिंग घटा सकता है। इनकी विश्वसनीयता साझा परिभाषाओं, पूर्ण डेटा व सत्यापन पर निर्भर करेगी। स्वैच्छिक खुलासा कार्रवाई को प्रोत्साहित तो कर सकता है, पर यह बाध्यकारी नियमन या क्षेत्रीय नीति का विकल्प नहीं बन सकता। स्कोप 3 उत्सर्जन अक्सर सबसे बड़े व सबसे मुश्किल मापे जाने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें स्वैच्छिक छोड़ना तुलनीयता को सीमित करता है।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल	ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों को नियंत्रित करने वाली 1987 की संधि।
किगाली संशोधन	HFC के चरणबद्ध-न्यूनीकरण के लिए 2016 का संशोधन।
स्कोप 1 उत्सर्जन	किसी संस्था के स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्रोतों से सीधा उत्सर्जन।
स्कोप 2 उत्सर्जन	खरीदी गई ऊर्जा से होने वाला अप्रत्यक्ष उत्सर्जन।
स्कोप 3 उत्सर्जन	अन्य अप्रत्यक्ष मूल्य-शृंखला उत्सर्जन।
NAPCC	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य-योजना।
HCFC चरणबद्ध-निष्कासन	मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में भारत की निर्धारित कमी; ये रसायन ओज़ोन को नुकसान पहुंचाते हैं और तापन में भी योगदान दे सकते हैं।
HFC चरणबद्ध-न्यूनीकरण	किगाली संशोधन के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन व खपत में क्रमिक – न कि तत्काल – कमी, क्योंकि कई HFC की ग्लोबल-वार्मिंग-क्षमता ऊंची होती है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संधियां व शासन-व्यवस्था। प्रारंभिक परीक्षा: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाम किगाली संशोधन और उत्सर्जन-स्कोप।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2310737®=48&lang=1>

शासन एवं सामाजिक मुद्दे (Governance And Social Issues)

25. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

मंत्रालय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

PIB तिथि: 12-13 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में निर्माण श्रमिकों के कल्याण, कौशल, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबिलिटी, व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा, श्रम की गरिमा, नौकरी-चाहने वालों व नियोक्ताओं के बीच बेहतर संपर्क, और बीमांकिक विश्लेषण (actuarial analysis) से समर्थित सतत कल्याण-योजना पर जोर दिया गया। राज्यों ने डिजीवरी-नवाचार साझा किए: उत्तर प्रदेश ने कौशल-विकास पर, राजस्थान ने डिजिटल लेबर चौक पर, बिहार ने श्रम सेवा सुविधा केंद्रों पर और असम ने निर्माण सखी पोर्टल पर। चर्चा में नए श्रम-संहिता ढांचे के तहत BOCW कल्याण बोर्डों की ज़िम्मेदारियां और केंद्र-राज्य समन्वय व परस्पर-सीख को मज़बूत करने की ज़रूरत भी शामिल रही।

निर्माण-क्षेत्र रोजगार का एक बड़ा स्रोत है, पर इसका ज़्यादातर श्रमबल अनौपचारिक, परियोजना-आधारित व गतिशील है। श्रमिक अक्सर ठेकेदार व राज्य बदलते रहते हैं, जिससे नियोक्ता-जुड़े लाभों को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। BOCW कानूनों ने कल्याण-बोर्ड और एक उपकर-वित्तपोषित व्यवस्था बनाई, ताकि सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

निर्माण श्रमिक अक्सर अनौपचारिक व गतिशील होते हैं, इसलिए सिर्फ एक राज्य या नियोक्ता से जुड़ा लाभ पाना मुश्किल हो सकता है। कल्याण-बोर्ड उपकर वसूलते व लाभ वित्तपोषित करते हैं, पर पंजीकरण, पोर्टेबिलिटी, जागरूकता व संचित निधि के असरदार इस्तेमाल जैसे शासन-मुद्दे अब भी केंद्रीय बने हुए हैं।

सम्मेलन ने कल्याण को श्रम-बाज़ार तक पहुंच, कौशल व व्यावसायिक सुरक्षा से सही तरीके से जोड़ा। डिजिटल लेबर चौक सूचना-अंतर घटा सकते हैं, जबकि सुविधा-केंद्र पंजीकरण व दावों में मदद कर सकते हैं। डिजिटलीकरण को उन श्रमिकों को बाहर नहीं रखना चाहिए जिनके पास दस्तावेज़ या डिजिटल-साक्षरता नहीं है। पोर्टेबिलिटी के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल नहीं, बल्कि राज्य-बोर्डों के बीच अंतर-संचालनीय रिकॉर्ड व समन्वय चाहिए। बोर्डों को बीमांकिक योजना की भी

ज़रूरत है ताकि लाभ टिकाऊ बने रहें और संचित निधि ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल हो। कानूनी हक को वास्तविक पहुंच में बदलने के लिए श्रमिक-प्रतिनिधित्व, सरल पंजीकरण, स्थल-स्तरीय सुविधा व उपकर-उपयोग में पारदर्शिता ज़रूरी है।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
BOCW	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक।
कल्याण बोर्ड	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ देने वाली एक सांविधिक राज्य-स्तरीय संस्था।
उपकर (Cess)	किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए वसूला जाने वाला निर्धारित शुल्क।
पोर्टेबिलिटी	जगह या नौकरी बदलने के बाद भी लाभ बनाए रखने व उन तक पहुंचने की क्षमता।
बीमांकिक विश्लेषण	भविष्य की वित्तीय देनदारियों व निधि-स्थिरता का आकलन।
डिजिटल लेबर चौक	पारंपरिक श्रम-जमावड़े की जगहों का एक डिजिटल रूपांतरण, जो श्रमिकों को नियोक्ताओं, नौकरियों, पंजीकरण व कल्याण-जानकारी से जोड़ सकता है।
व्यावसायिक सुरक्षा	मानकों, प्रशिक्षण, सुरक्षा-उपकरण, निरीक्षण, रिपोर्टिंग व नियोक्ता-जवाबदेही के ज़रिए कार्यस्थल पर चोट व बीमारी की रोकथाम।
अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी	प्रवासी निर्माण श्रमिकों की राज्य की सीमा पार करने के बाद संचित हक खोए बिना पंजीकरण व लाभ तक पहुंचने की क्षमता।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: कल्याण-योजनाएं व कमज़ोर वर्ग
- GS III: श्रम व अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। मुख्य परीक्षा: प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबिलिटी व सामाजिक सुरक्षा।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2309467®=48&lang=1>

26. अगस्त 2026 के लिए PLFS मासिक बुलेटिन

मंत्रालय: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

PIB तिथि: 15 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

15 वर्ष व उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए श्रमबल भागीदारी दर (LFPR) जुलाई के 55.4% से बढ़कर अगस्त में 55.6% हो गई। ग्रामीण LFPR 58.2% तक पहुंचा जबकि शहरी LFPR 50.4% पर बना रहा। महिला LFPR बढ़कर 34.8% हुआ, जो मुख्यतः 39.4% की ग्रामीण महिला LFPR से प्रेरित रहा। समग्र LFPR अगस्त 2025 की तुलना में 0.6 प्रतिशत-अंक अधिक रहा। कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR) बढ़कर 52.8% हो गया, जो मार्च 2026 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। ग्रामीण WPR 55.8% पहुंचा, जो साल-दर-साल 1.3 प्रतिशत-अंक ज़्यादा है। कुल बेरोज़गारी दर 5.0% पर बनी रही। ग्रामीण बेरोज़गारी घटकर 4.1% हुई, जो जनवरी 2026 के बाद सबसे कम है। मासिक PLFS अनुमान 'वर्तमान

साप्ताहिक स्थिति' (CWS) दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं। जनवरी 2025 से पद्धति में बदलाव किया गया ताकि मासिक व त्रैमासिक संकेतक मिल सकें।

रोज़गार-आंकड़े परिभाषाओं व संदर्भ-अवधि पर निर्भर करते हैं। 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' के तहत, किसी व्यक्ति की गतिविधि का आकलन पिछले सात दिनों के आधार पर होता है, जिससे यह माप अल्पकालिक बदलाव के प्रति संवेदनशील बन जाता है। मासिक राष्ट्रीय अनुमान समयबद्धता बढ़ाते हैं, पर इन्हें त्रैमासिक व वार्षिक डेटा, नमूना-भिन्नता व क्षेत्रीय जानकारी के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए।

LFPR उन लोगों को मापता है जो काम कर रहे हैं या काम ढूँढ रहे हैं; WPR वास्तव में काम कर रहे लोगों को मापता है; बेरोज़गारी दर श्रमबल में बेरोज़गार लोगों के हिस्से को मापती है। यदि लोग खोजना बंद कर श्रमबल से बाहर हो जाएं, तो कम बेरोज़गारी दर अपने आप ज़्यादा रोज़गार का मतलब नहीं रखती, इसलिए इन संकेतकों को साथ-साथ पढ़ना ज़रूरी है।

LFPR व WPR में एक साथ हुई वृद्धि उत्साहजनक है, क्योंकि ज़्यादा लोग श्रमबल में शामिल हुए और वास्तव में काम करने वालों का हिस्सा भी बढ़ा। महिला LFPR बेहतर हुआ, खासकर ग्रामीण इलाकों में, पर भागीदारी नौकरी की गुणवत्ता, वेतन, काम के घंटे या यह काम अवैतनिक पारिवारिक श्रम है या नहीं, यह नहीं बताती। स्थिर बेरोज़गारी दर के साथ अल्प-रोज़गार भी मौजूद रह सकता है। ग्रामीण व शहरी बदलाव मौसमी बदलाव, कृषि व प्रवास को दर्शा सकते हैं। नीति-निर्माताओं को किसी एक महीने के बदलाव से श्रम-बाज़ार का आकलन करने के बजाय दीर्घकालिक रुझानों, युवा-बेरोज़गारी, शिक्षा-स्तर व औपचारिकीकरण की जांच करनी चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
LFPR	जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में श्रमबल।
WPR	जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कार्यरत व्यक्ति।
बेरोज़गारी दर	श्रमबल के प्रतिशत के रूप में बेरोज़गार व्यक्ति।
CWS	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, जो पिछले सात दिनों की गतिविधि पर आधारित है।
PLFS	NSO द्वारा संचालित आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण।
श्रमबल	वे सभी व्यक्ति जो कार्यरत हैं या बेरोज़गार होते हुए भी सक्रिय रूप से काम ढूँढ रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं; दोनों श्रेणियों से बाहर के लोग बेरोज़गारी-दर के हर में नहीं गिने जाते।
महिला श्रमबल भागीदारी	काम कर रही या काम ढूँढ रही महिलाओं का हिस्सा। यह शिक्षा, देखभाल-ज़िम्मेदारियों, सुरक्षा, सामाजिक मानदंडों, नौकरी-उपलब्धता व अवैतनिक कार्य के मापन से प्रभावित होता है।
अल्प-रोज़गार (Underemployment)	एक ऐसी स्थिति, जिसमें व्यक्ति कार्यरत तो है पर उसे इच्छा से कम घंटे, कम उत्पादकता वाला या कम उपयुक्त काम मिलता है; हेडलाइन बेरोज़गारी दर इसे नहीं दर्शा सकती।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: रोजगार व श्रम-बाज़ार डेटा। प्रारंभिक परीक्षा: LFPR, WPR व UR के हर। मुख्य परीक्षा: श्रम-संकेतकों व महिला श्रमबल भागीदारी की व्याख्या।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2310427®=48&lang=1>

27. जनऔषधि केंद्रों के ज़रिए नुस्खे से आगे की देखभाल

मंत्रालय: फार्मास्यूटिकल्स विभाग / PIB बैकग्राउंडर

PIB तिथि: 16 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP), जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़कर 20,000 से ज़्यादा जनऔषधि केंद्रों के ज़रिए किफायती सर्जिकल, चिकित्सा व पारिवारिक-देखभाल उत्पादों की एक व्यापक टोकरी तक विस्तारित हो चुकी है। अगस्त 2026 तक, इस टोकरी में प्रमुख चिकित्सीय समूहों में 2,110 दवाएं और 315 सर्जिकल सामान, उपभोज्य वस्तुएं व उपकरण शामिल थे। 2021-22 से 2025-26 के बीच बिक्री कुल 7,873.85 करोड़ रुपये रही और अनुमान है कि इसने ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में नागरिकों के लगभग 37,200 करोड़ रुपये बचाए। उत्पादों में शिशु-देखभाल सामग्री, फीडिंग बोतलें, मैनुअल ब्रेस्ट पंप, गर्म पानी की थैलियां, पेट की पट्टी, नेब्युलाइज़र, मास्क, सर्वाइकल तकिए व रक्त-शर्करा जांच स्ट्रिप शामिल हैं। इसका मकसद प्रसव, स्वास्थ्य-लाभ, दीर्घकालिक बीमारी व बुजुर्ग-देखभाल के दौरान होने वाले जेब-खर्च को घटाना है।

जेब से किया गया स्वास्थ्य-खर्च सिर्फ नुस्खे में लिखी गोलियों से कहीं ज़्यादा शामिल करता है। उपकरण, ड्रेसिंग, डायग्नोस्टिक्स, परिवहन व देखभाल-उत्पाद बार-बार खर्च डाल सकते हैं, खासकर प्रसव, दीर्घकालिक बीमारी, दिव्यांगता व बुजुर्ग-देखभाल में। PMBJP गुणवत्ता-आशवासित उत्पादों की कीमत घटाने के लिए सामूहिक खरीद व समर्पित दुकानों का इस्तेमाल करता है।

किफायती स्वास्थ्य-सेवा सिर्फ दवाओं की कीमत से कहीं ज़्यादा व्यापक है। परिवार डायग्नोस्टिक्स, उपभोज्य वस्तुओं व उपकरणों पर भी खर्च करते हैं। केंद्रीय खरीद व एक समर्पित खुदरा नेटवर्क का इस्तेमाल कर, PMBJP गुणवत्ता-आशवासित जेनेरिक व चुनिंदा स्वास्थ्य-उत्पादों तक पहुंच बेहतर बनाने की कोशिश करता है।

टोकरी का विस्तार नेटवर्क को परिवारों के लिए ज़्यादा उपयोगी बनाता है, पर किफायत को भरोसेमंद स्टॉक व उत्पाद-गुणवत्ता के साथ जोड़ना ज़रूरी है। जेनेरिक विकल्प सबसे बेहतर तब काम करता है जब डॉक्टर व मरीज़ नियामक-परीक्षण पर भरोसा करें और स्पष्ट जानकारी पाएं। केंद्रों को स्व-चिकित्सा या अनावश्यक उपकरण-इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए; नैदानिक सलाह अनिवार्य बनी रहनी चाहिए। स्थान, खुलने का समय व आपूर्ति-शृंखला की निरंतरता, ग्रामीण व

कम-आय वाले परिवारों के लिए पहुंच तय करते हैं। रिपोर्ट की गई उपभोक्ता-बचत अहम है, पर स्वतंत्र आकलन को उपलब्धता, चिकित्सीय श्रेणियों, गुणवत्ता-शिकायतों और यह भी ट्रैक करना चाहिए कि कम कीमतें उपचार-पालन (adherence) बेहतर बनाती हैं या नहीं।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
जेनेरिक दवा	एक ऐसी दवा जिसमें ब्रांडेड संदर्भ-उत्पाद जैसा ही सक्रिय तत्व व चिकित्सीय प्रभाव हो।
PMBJP	प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना।
जनऔषधि केंद्र	PMBJP दवाएं व स्वास्थ्य-उत्पाद बेचने वाली एक समर्पित दुकान।
जेब-खर्च	परिवारों द्वारा सीधे चुकाया गया स्वास्थ्य-खर्च।
गुणवत्ता-आशवासित जेनेरिक	निर्धारित मानकों व परीक्षण-जरूरतों के तहत खरीदी गई एक गैर-ब्रांडेड या जेनेरिक दवा, जिसका मकसद कम कीमत पर वही सक्रिय तत्व व चिकित्सीय प्रभाव देना है।
स्वास्थ्य-देखभाल उपभोज्य	देखभाल के दौरान इस्तेमाल व बदला जाने वाला उत्पाद, जैसे सिरिंज, ड्रेसिंग, डायपर, टेस्ट स्ट्रिप या मास्क; बार-बार होने वाली खरीद घरेलू खर्च काफी बढ़ा सकती है।
दवा-पालन (Medicine adherence)	निर्धारित खुराक व अवधि के अनुसार उपचार लेना। कम कीमतें व भरोसेमंद उपलब्धता, खासकर दीर्घकालिक बीमारी में, पालन बेहतर बना सकती हैं।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS II: स्वास्थ्य नीति, कल्याण व पहुंच
- GS III: दवा क्षेत्र। मुख्य परीक्षा: बीमा-कवरेज से परे किफायत।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2311044®=48&lang=1>

28. सिलिकॉन सपने और भारत का सेमीकंडक्टर-स्टार्टअप पारितंत्र

मंत्रालय: PIB बैकग्राउंडर

PIB तिथि: 15 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें (Easy Explanation)

इस बैकग्राउंडर ने SEMICON इंडिया 2026 को भारत के लंबे इलेक्ट्रॉनिक्स-विनिर्माण परिवर्तन के दायरे में रखा।

‘सिलिकॉन से सिस्टम तक’ विषय, महज़ अलग-थलग फैब्रिकेशन संयंत्रों को आकर्षित करने के बजाय एक पूरा पारितंत्र बनाने की कोशिश दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपये हो गया। निर्यात लगभग 38,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 4.24 लाख करोड़ रुपये हो गया। मोबाइल-फोन उत्पादन 18,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 6.27 लाख करोड़ रुपये और निर्यात लगभग 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपये हो गया। भारत अपने इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 99.2% फोन खुद बनाता है और

मोबाइल फोन का शुद्ध निर्यातक बन गया है। सेमीकंडक्टर पारितंत्र बड़े निवेशों को डिज़ाइन स्टार्टअप, विश्वविद्यालयी प्रतिभा, चिप-डिज़ाइन उपकरणों, पैकेजिंग, सामग्री व घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स-मांग से जोड़ता है। स्टार्टअप फैब्रिकेशन संयंत्र के मालिकाना की पूरी लागत उठाए बिना, डिज़ाइन व बौद्धिक-संपदा के क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। रणनीतिक तर्क आर्थिक मूल्य, आपूर्ति-शृंखला सहनशीलता व राष्ट्रीय सुरक्षा को जोड़ता है, क्योंकि चिप्स संचार, वाहन, चिकित्सा उपकरण, रक्षा प्रणालियों व महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में समाई हुई हैं।

सेमीकंडक्टर स्टार्टअप को अरबों डॉलर के फैब का मालिक होना ज़रूरी नहीं। 'फैबलेस' कंपनियां चिप-वास्तुकला, सत्यापन, एम्बेडेड सिस्टम व पुनः-इस्तेमाल योग्य बौद्धिक संपदा में विशेषज्ञता बना सकती हैं, और फिर विनिर्माण किसी फाउंड्री को ठेके पर दे सकती हैं। यह मॉडल भारत की डिज़ाइन-प्रतिभा के अनुकूल है, पर फिर भी इसे महंगे सॉफ्टवेयर, प्रोटोटाइप-रन व धैर्यवान पूंजी तक पहुंच चाहिए।

भारत की बढ़त सिर्फ कम-लागत असेंबली तक सीमित नहीं है। इसके पास चिप-डिज़ाइन इंजीनियरों का बड़ा समूह और एक बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक्स-बाज़ार है। चुनौती है डिज़ाइन-प्रतिभा को फैब्रिकेशन, परीक्षण, बौद्धिक संपदा, धैर्यवान पूंजी व भरोसेमंद वाणिज्यिक ग्राहकों से जोड़ना।

भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स-वृद्धि, वाहनों, दूरसंचार, औद्योगिक उपकरणों, बिजली-प्रणालियों व सार्वजनिक खरीद में घरेलू डिज़ाइनों के लिए संभावित 'एंकर ग्राहक' पैदा करती है। EDA उपकरणों तक विश्वविद्यालयी पहुंच व साझा प्रोटोटाइपिंग, प्रवेश-बाधाएं घटा सकते हैं। स्टार्टअप को बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, अनुभवी सलाहकारों और टेप-आउट से लेकर योग्य वाणिज्यिक-मात्रा तक का रास्ता भी चाहिए। सरकारी समर्थन को सफलता महज़ पंजीकृत उद्यमों की संख्या से नहीं आंकनी चाहिए। टेप-आउट, पेटेंट, परीक्षित उत्पाद, घरेलू खरीद व निर्यात-राजस्व कहीं ज़्यादा मज़बूत संकेतक हैं। डिज़ाइन कंपनियों, पैकेजिंग इकाइयों, सिस्टम-विनिर्माताओं व शोध-संस्थानों के बीच घनिष्ठ जुड़ाव, सेमीकंडक्टर मिशन को सब्सिडी-प्राप्त फैक्ट्रियों के समूह के बजाय एक नवाचार-पारितंत्र में बदल सकता है।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

शब्द	परिभाषा
फैबलेस कंपनी	एक ऐसी कंपनी जो चिप्स डिज़ाइन करती है पर फैब्रिकेशन बाहर से करवाती है।
सेमीकंडक्टर IP	पुनः-इस्तेमाल योग्य चिप-डिज़ाइन बिल्डिंग-ब्लॉक या स्वामित्व वाले सर्किट-डिज़ाइन।
टेप-आउट	फैब्रिकेशन के लिए चिप-डिज़ाइन को अंतिम रूप देना।
आधारभूत उद्योग	एक ऐसा उद्योग, जिसका उत्पादन कई अन्य क्षेत्रों के लिए ज़रूरी होता है।
आपूर्ति-शृंखला सहनशीलता	व्यवधान झेलने और अहम आदान हासिल करते रहने की क्षमता।
प्रोटोटाइप शटल रन	एक साझा वेफर-फैब्रिकेशन रन, जिसमें कई डिज़ाइनर एक ही वेफर पर छोटे चिप-डिज़ाइन रखते हैं, जिससे शुरुआती प्रोटोटाइप की लागत घटती है।

शब्द	परिभाषा
डिज़ाइन सत्यापन	फैब्रिकेशन से पहले यह परखना कि चिप-डिज़ाइन सही तरीके से काम करता है या नहीं। टेप-आउट के बाद मिलने वाली खामियां बेहद महंगी पड़ती हैं, इसलिए सत्यापन-उपकरण व विशेषज्ञता अहम हैं।
एंकर ग्राहक	एक भरोसेमंद शुरुआती खरीदार – जैसे कोई वाहन, दूरसंचार या सार्वजनिक-क्षेत्र विनिर्माता – जो किसी सेमीकंडक्टर स्टार्टअप को मांग सत्यापित करने व उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- GS III: स्टार्टअप, नवाचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व रणनीतिक तकनीक। निबंध/मुख्य परीक्षा: अलग-थलग सब्सिडी के बजाय औद्योगिक पारितंत्र।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) –

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2310311®=48&lang=1>

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Prelims Practice Questions)

प्रश्न 1. कोलंबो सुरक्षा संधिवृत्त (Colombo Security Conclave) की टेबल-टॉप अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान (विशाखापत्तनम) में आयोजित किया गया था।
- संधिवृत्त का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 2. औली एवं महाजन में आयोजित 'युद्ध अभ्यास 2026' भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है?

- रूस
- फ्रांस
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- जापान

प्रश्न 3. भारत-MERCOSUR तरजीही व्यापार समझौते (PTA) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. MERCOSUR दक्षिण अमेरिका के देशों का एक क्षेत्रीय व्यापार समूह है।
2. इस विस्तार के साथ भारत ने MERCOSUR के साथ अपना पहला अतिरिक्त प्रोटोकॉल संपन्न किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 4. सेमीकॉन 2.0 रोडमैप के छह स्तंभों (pillars) में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

- (a) चिप डिज़ाइन एवं अनुसंधान
- (b) कच्चे तेल का शोधन
- (c) उन्नत पैकेजिंग
- (d) कौशल विकास एवं मानव संसाधन

प्रश्न 5. नए UPI ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिकांश पीयर-टू-पीयर (P2P) लेनदेन शुल्क-मुक्त बने रहेंगे।
2. अधिकांश छोटे व्यापारी भुगतान भी शुल्क-मुक्त श्रेणी में बरकरार रखे गए हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 6. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।
2. इसका उद्देश्य खनन-प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के हितों की रक्षा करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 7. संबलपुर में स्थापित भारत के 51वें डॉपलर मौसम रडार का प्राथमिक कार्य क्या है?

- (a) भूकंप की तीव्रता मापना
- (b) वर्षा, तूफान एवं चक्रवात जैसी मौसमी परिघटनाओं की सटीक व समय-पूर्व निगरानी करना
- (c) वायु प्रदूषण के स्तर को मापना
- (d) समुद्री जलस्तर में परिवर्तन दर्ज करना

प्रश्न 8. अभिकथन (A): भारत में किसानों को दिया जाने वाला पहला मृदा-कार्बन भुगतान (soil-carbon payment) एक महत्वपूर्ण पहल है। **कारण (R):** मृदा-कार्बन भुगतान किसानों को कार्बन-पृथक्करण बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य सुधरता है और जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान मिलता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है
- (b) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता
- (c) A सही है, परंतु R गलत है
- (d) A गलत है, परंतु R सही है

प्रश्न 9. विश्व ओज़ोन दिवस एवं ओज़ोन परत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किगाली संशोधन (Kigali Amendment) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है।
2. किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उत्पादन एवं उपभोग को चरणबद्ध रूप से कम करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 10. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

1. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) – कार्यशील आयु जनसंख्या में श्रम बल का अनुपात
2. कर्मी जनसंख्या अनुपात (WPR) – कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का अनुपात
3. बेरोजगारी दर (UR) – श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीनों
- (d) कोई भी नहीं

मुख्य परीक्षा प्रश्न एवं आदर्श उत्तर (Mains Questions and Model Answers)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1

BRICS की नई दिल्ली घोषणापत्र (2026) की पृष्ठभूमि में, वैश्विक दक्षिण (Global South) की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में BRICS समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द)

आदर्श उत्तर (Model Answer)

BRICS समूह की 2026 की अध्यक्षता के दौरान अपनाई गई नई दिल्ली घोषणापत्र वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज़ को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घोषणापत्र बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार,

समावेशी विकास और साझा समृद्धि पर बल देता है, जिससे पश्चिम-केंद्रित वैश्विक व्यवस्था के समानांतर एक विकल्प उभरता है।

रणनीतिक स्वायत्तता के दृष्टिकोण से, BRICS सदस्य देशों को अपनी विदेश नीति और आर्थिक निर्णयों में किसी एक गुट पर निर्भरता कम करने का अवसर प्रदान करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहित करने और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खोलने से विकासशील देशों की सौदेबाज़ी की क्षमता में वृद्धि होती है। हालांकि, सदस्य देशों के बीच आंतरिक हितों की विविधता और भू-राजनीतिक तनाव इस एकजुटता के लिए चुनौती बने रहते हैं। कुल मिलाकर, BRICS वैश्विक दक्षिण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हो रहा है, बशर्ते सदस्य देश आपसी मतभेदों के बावजूद साझा एजेंडे पर सहमति बनाए रखें।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2

‘सिलिकॉन से सिस्टम्स तक’ (Silicon to Systems) की अवधारणा के आलोक में सेमीकॉन 2.0 रोडमैप का विश्लेषण कीजिए तथा भारत के सेमीकंडक्टर पारितंत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

आदर्श उत्तर (Model Answer)

सेमीकॉन 2.0 रोडमैप भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है, जो केवल चिप निर्माण तक सीमित न रहकर 'सिलिकॉन से सिस्टम्स तक' की व्यापक सोच को अपनाता है। इसका आशय है कि भारत न केवल अर्धचालकों का निर्माण करेगा, बल्कि डिज़ाइन, पैकेजिंग, परीक्षण और अंतिम उत्पाद निर्माण तक की पूरी मूल्य-श्रृंखला में आत्मनिर्भरता हासिल करेगा।

इस रोडमैप के प्रमुख स्तंभों में चिप डिज़ाइन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन, उन्नत पैकेजिंग सुविधाओं का विकास, कच्चे माल एवं विशेष रसायनों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, कौशल विकास एवं मानव संसाधन तैयार करना, स्टार्टअप पारितंत्र को बढ़ावा देना और वैश्विक निवेश आकर्षित करना शामिल है। सेमीकॉन इंडिया 2026 जैसे आयोजनों ने वैश्विक निवेशकों और प्रौद्योगिकी कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया है।

फिर भी, भारत के सेमीकंडक्टर पारितंत्र के समक्ष कई चुनौतियां बनी हुई हैं। उच्च पूंजी लागत, विशेषज्ञ जनशक्ति की कमी, अनुसंधान एवं विकास में सीमित निवेश, तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भू-राजनीतिक जोखिम प्रमुख बाधाएं हैं। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक शुद्ध जल और स्थिर बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं को पूरा करना भी एक चुनौती है।

इन चुनौतियों के बावजूद, यदि भारत नीतिगत स्थिरता बनाए रखते हुए शिक्षा, अनुसंधान और अवसंरचना में निरंतर निवेश करता है, तो सेमीकॉन 2.0 रोडमैप भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य-श्रृंखला में एक विश्वसनीय एवं आत्मनिर्भर भागीदार बनाने में सफल हो सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा उत्तर एवं व्याख्या (Prelims Answers and Explanations)

प्रश्न 1. उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

कोलंबो सुरक्षा संधिवृत्त की टेबल-टॉप अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान में आयोजित हुई थी और इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना है।

प्रश्न 2. उत्तर: (c) संयुक्त राज्य अमेरिका

युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका 2026 संस्करण औली और महाजन में आयोजित हुआ।

प्रश्न 3. उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

MERCOSUR दक्षिण अमेरिकी देशों का क्षेत्रीय व्यापार समूह है, और भारत ने इस विस्तार के साथ MERCOSUR के साथ अपना पहला अतिरिक्त प्रोटोकॉल संपन्न किया है।

प्रश्न 4. उत्तर: (b) कच्चे तेल का शोधन

कच्चे तेल का शोधन सेमीकॉन 2.0 रोडमैप के छह स्तंभों में शामिल नहीं है; रोडमैप चिप डिज़ाइन, पैकेजिंग, कौशल विकास आदि से संबंधित सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर केंद्रित है।

प्रश्न 5. उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

नए UPI ढांचे में अधिकांश P2P लेनदेन और अधिकांश छोटे व्यापारी भुगतान दोनों को शुल्क-मुक्त श्रेणी में बरकरार रखा गया है।

प्रश्न 6. उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) के माध्यम से क्रियान्वित होती है और इसका उद्देश्य खनन-प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के हितों की रक्षा करना है।

प्रश्न 7. उत्तर: (b) वर्षा, तूफान एवं चक्रवात जैसी मौसमी परिघटनाओं की सटीक व समय-पूर्व निगरानी करना

डॉपलर मौसम रडार वर्षा, तूफान और चक्रवात जैसी मौसमी घटनाओं की सटीक एवं समय-पूर्व निगरानी करके पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाता है।

प्रश्न 8. उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है

मृदा-कार्बन भुगतान किसानों को कार्बन-पृथक्करण बढ़ाने वाली पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य सुधरता है और जलवायु शमन में योगदान मिलता है – यह इसके महत्व की सही व्याख्या है।

प्रश्न 9. उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उत्पादन व उपभोग को चरणबद्ध रूप से घटाना है।

प्रश्न 10. उत्तर: (c) सभी तीनों

PLFS में श्रम बल भागीदारी दर, कर्मी जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर तीनों संकेतक ऊपर बताई गई परिभाषाओं के अनुसार सही सुमेलित हैं।



SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

SITOK IAS • PIB साप्ताहिक संकलन

अब, एक नया सप्ताह

सप्ताह 4

19 - 25 सितंबर 2026

34 PIB समाचार • सम्माननीय उल्लेख और अभ्यास प्रश्न

सप्ताह 4 / 4

01	रोजगार मेला 20	201
02	भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता	202
03	स्लिनेक्स-26 समुद्री अभ्यास	203
04	एफएसएसएआई पनीर विनियमन संशोधन	205
05	एक सींग वाला गैंडा और विश्व राइनो दिवस	206
06	आईएमईआई छेड़छाड़ जागरूकता अभियान	207
07	सैटेलाइट एंटी-एयरफील्ड हथियार (आत्मनिर्भर भारत)	208
08	डीआरडीओ डीप टेक स्टार्ट-अप परियोजना (क्वांटम प्रौद्योगिकी)	210
09	डीडीयू-जीकेवाई 2.0 शुभारंभ (ग्रामीण कौशल विकास)	211
10	दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र पहल	212
11	रेलवे कवच 4.0 कमीशनिंग	213
12	उच्च गति राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एनएचएआई दिशानिर्देश	215
13	डीआरआई जब्ती और कानून प्रवर्तन	216
14	एनएलएमसी भूमि मुद्रीकरण कार्यक्रम	217
15	एनजीटी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च	218
16	ओपेक-भारत ऊर्जा वार्ता	220
17	सीएसआईआर-सीआरआरआई वैज्ञानिक सहयोग (विशाखापत्तनम सड़कें)	221
18	स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 (तटीय संरक्षण)	222
19	भारत-मंगोलिया सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफैंट	223
20	सेमीकॉन इंडिया 2026 (सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम)	225
21	तीसरा राष्ट्रीय एनटीएफ सम्मेलन	226
22	उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियां	227
23	भारत टैक्सी सेवा शुभारंभ (उत्तर प्रदेश)	228
24	कांदा एक्सप्रेस और खाद्य सुरक्षा	229
25	वर्ल्डस्क्वैड्स शंघाई 2026 (भारत का दल)	231
26	आरोग्य मंथन 2026 (स्वास्थ्य योजना समीक्षा)	232
27	भारत-नीदरलैंड जल भागीदारी (आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू 2026)	233
28	विशेष अभियान 6.0 (प्रशासनिक दक्षता)	234
29	नई ट्रेन सेवाओं का विस्तार	236
30	अग्निकुल कॉसमॉस आरडीआई सहायता (पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान)	237
31	ब्रिक्स कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक	238
32	उपासी चाय अनुसंधान शताब्दी सम्मेलन	239
33	सीसीआई प्रतिस्पर्धा कानून अनुमोदन	241
34	पीआईबी बैकग्राउंड और विशेष विषय	242



SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.

रोजगार मेला 20

मंत्रालय: प्रधानमंत्री कार्यालय / श्रम मंत्रालय | दिनांक: 20 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

रोजगार मेला को समझने के लिए पहले उस समस्या को समझना जरूरी है जिसे यह हल करने की कोशिश करता है। केंद्र सरकार के पास हजारों स्वीकृत पद ऐसे हैं जो वर्षों से खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया – विज्ञापन, परीक्षा, साक्षात्कार, सत्यापन, अंतिम चयन – धीमी होती है और एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस जैसी अलग-अलग संस्थाओं में बंटी होती है। रोजगार मेला सरकार का तरीका है इस बैकलॉग को एक साथ, दिखाई देने वाले तरीके से खत्म करने का: जिन उम्मीदवारों का चयन पहले ही हो चुका है, उन्हें एक साथ बुलाकर एक ही दिन नियुक्ति पत्र सौंपे जाते हैं, अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ताकि प्रधानमंत्री दिल्ली से ही पूरे देश के नए कर्मचारियों को संबोधित कर सकें। 20 सितंबर 2026 को आयोजित 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जो रेल मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों में समूह 'ग' (डिप्लोमा/डिग्री स्तर) और समूह 'घ' (स्कूली शिक्षा स्तर) के पदों पर नियुक्त हुए। अक्टूबर 2022 में शुरू हुए पहले रोजगार मेले से लेकर अब तक 20 संस्करणों में कुल मिलाकर कई लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं। भारत के लिए इसका महत्व दो बातों में है: खाली पड़ी सरकारी क्षमता को सामान्य प्रक्रिया से कहीं तेज़ी से काम में लाना, और बार-बार यह संकेत देना कि सरकारी भर्ती सक्रिय है, भले ही भर्ती में देरी को लेकर आलोचना होती रहे।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
रोजगार मेला	पहले से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाला सीधा सरकारी भर्ती आयोजन; 20वां संस्करण 20 सितंबर 2026, 51,000+ नियुक्तियां।
समूह ग और घ पद	समूह ग: डिप्लोमा/डिग्री स्तर के तकनीकी व लिपिकीय पद। समूह घ: स्कूली शिक्षा स्तर के सहायक पद।
एसएससी / आरआरबी / आईबीपीएस	स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान – रोजगार मेले से पहले परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं।
जनसांख्यिकीय लाभांश	युवा, कामकाजी आयु-प्रधान जनसंख्या से मिलने वाला आर्थिक विकास अवसर; तभी लाभदायक जब यह जनसंख्या उत्पादक रूप से नियोजित हो।
स्वीकृत पद	एक सरकारी नौकरी जो कागज़ पर मौजूद है और जिसके लिए बजट आवंटित है, चाहे उस पर वर्तमान में कोई कार्यरत हो या न हो।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्य सर्वेक्षण जो रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी दर मापता है।

श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)	कामकाजी आयु की उस जनसंख्या का हिस्सा जो या तो नियोजित है या सक्रिय रूप से काम खोज रही है; रोजगार योजनाओं की प्रभावशीलता मापने का प्रमुख संकेतक।
जॉबलेस ग्रोथ	ऐसा आर्थिक विकास जो अनुपातिक रोजगार सृजन में तब्दील नहीं होता; उंची जीडीपी वृद्धि के बावजूद कभी-कभी की जाने वाली आलोचना।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 शासन: रोजगार सृजन नीति प्राथमिकता; प्रत्यक्ष भर्ती रणनीति; राज्यों की भागीदारी का संघीय पहलू।
- GS3 अर्थव्यवस्था: युवा बेरोजगारी संकट; श्रम बल भागीदारी; जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग।
- प्रारंभिक परीक्षा: 20वां रोजगार मेला, 20 सितंबर 2026; 51,000+ नियुक्तियां; अक्टूबर 2022 में पहला संस्करण; समूह ग व घ पद; पीएमओ व श्रम मंत्रालय समन्वय।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | दिनांक: 20 अक्टूबर 2026

सरल भाषा में समझें

जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, तो उनकी सरकारें आमतौर पर दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाती हैं, जिससे आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) एक ऐसा समझौता है जिसमें दोनों पक्ष तय की गई वस्तुओं और सेवाओं पर इन शुल्कों को कम करने या हटाने पर सहमत होते हैं, आमतौर पर 5 से 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से। भारत-न्यूजीलैंड एफटीए 1 अक्टूबर 2026 से कानूनी रूप से लागू हो गया, जिससे न्यूजीलैंड का बाजार भारतीय आईटी सेवाओं, फार्मास्युटिकल्स और वस्त्रों के लिए और अधिक खुलेगा, जबकि भारत न्यूजीलैंड के डेयरी उत्पादों, ऊन और बागवानी निर्यात तक अधिक पहुंच देगा – ऐसे क्षेत्र जहां न्यूजीलैंड, महज 50 लाख आबादी वाला देश होते हुए भी, दुनिया के शीर्ष 3 डेयरी निर्यातकों में शामिल है। यह हिस्सा भारत के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि भारत के डेयरी क्षेत्र से 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार जुड़े हैं, इसलिए समझौते में धीमी शुल्क कटौती और कुछ संवेदनशील डेयरी उत्पादों को छूट जैसे सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। रणनीतिक रूप से, यह 2021 के बाद भारत का तीसरा प्रमुख द्विपक्षीय एफटीए है (यूई और ऑस्ट्रेलिया के बाद), जो 2019 में 15-देशीय आरसीईपी से बाहर निकलने के बाद अपनाई गई भारत की उस रणनीति को जारी रखता है जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बड़े बहुपक्षीय समझौतों की बजाय छोटे, सावधानी से तय द्विपक्षीय समझौतों को प्राथमिकता दी जाती है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
------	---------

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)	दो देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश पर शुल्क घटाने या हटाने वाली द्विपक्षीय संधि; भारत-न्यूजीलैंड एफटीए 1 अक्टूबर 2026 से लागू।
टैरिफ-रेट कोटा	एक निश्चित मात्रा तक कम शुल्क की अनुमति देने वाली सुरक्षा व्यवस्था, उसके बाद अधिक शुल्क लागू होता है; भारत के डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा हेतु प्रयुक्त।
आरसीईपी	क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी; 15-देशीय एशिया-प्रशांत व्यापार समूह, जिससे भारत 2019 में व्यापार घाटे और कृषि चिंताओं के चलते बाहर निकला।
सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN)	डब्ल्यूटीओ सिद्धांत जिसके तहत सभी सदस्य देशों को समान व्यापारिक व्यवहार देना अनिवार्य है; एफटीए इसका कानूनी अपवाद है।
मूल नियम (Rules of Origin)	किसी उत्पाद की 'राष्ट्रीयता' तय करने वाले मानदंड, जो तीसरे देशों को किसी सदस्य देश के जरिए तरजीही शुल्क का लाभ लेने से रोकते हैं।
व्यापार घाटा	जब किसी देश का किसी साझेदार से आयात निर्यात से अधिक हो; चीन के साथ भारत के घाटे ने आरसीईपी से बाहर निकलने के निर्णय को प्रभावित किया।
सीईपीए / सीईसीए	व्यापक आर्थिक भागीदारी/सहयोग समझौता; एफटीए के व्यापक रूप जो वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को एक साथ कवर करते हैं (जैसे यूई के साथ, 2022)।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत की व्यापार कूटनीति; इंडो-पैसिफिक रणनीति में स्थिति।
- GS3 अर्थव्यवस्था: भारतीय निर्यातकों (आईटी, फार्मा) पर प्रभाव; 8 करोड़ डेयरी परिवार।
- प्रारंभिक परीक्षा: भारत-एनजेड एफटीए 1 अक्टूबर 2026; 2021 के बाद तीसरा द्विपक्षीय एफटीए; भारत 2019 में आरसीईपी से बाहर।

SITOK IAS

स्लैनेक्स-26 समुद्री अभ्यास

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय | दिनांक: 23 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

अलग-अलग देशों की नौसेनाएं किसी वास्तविक संकट – खोज-बचाव अभियान, समुद्री डकैती, या चक्रवात राहत – के दौरान अपने आप एक साथ काम करना नहीं जानतीं, क्योंकि हर नौसेना अपने अलग संचार प्रोटोकॉल और कमान प्रक्रियाएं इस्तेमाल करती है। स्लैनेक्स (श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास), जो पहली बार 2005 में शुरू हुआ और अब अपने 26वें संस्करण में है, भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच इसी अंतर को पाटने के लिए नियमित संयुक्त अभ्यास आयोजित करता है – जिसमें दोनों पक्षों के युद्धपोत, समुद्री गश्ती विमान और विशेष बल शामिल होते हैं, तथा संदिग्ध जहाजों को रोकने, समुद्री डकैती विरोधी बोर्डिंग अभियान और संयुक्त खोज-बचाव जैसे परिदृश्यों का अभ्यास किया जाता

है। इस वर्ष का बंदरगाह व समुद्री चरण विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ, जो भारत की पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय है। सामरिक दृष्टि से, श्रीलंका दुनिया के सबसे व्यस्त पूर्व-पश्चिम शिपिंग मार्गों में से एक पर स्थित है, और भारत चिंता के साथ देख रहा है कि किस तरह चीन द्वारा वित्तपोषित बुनियादी ढांचा – विशेष रूप से हंबनटोटा बंदरगाह, जिसे 2017 में ऋण चूक के बाद एक चीनी सरकारी कंपनी को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया – वहां बीजिंग की उपस्थिति बढ़ा रहा है। हर साल एक वास्तव में उपयोगी, बिना शर्त वाला नौसैनिक अभ्यास आयोजित करके, भारत खुद को श्रीलंका के भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करता है, जो अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण को मजबूत करता है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
स्लिनेक्स	भारत और श्रीलंका के बीच वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, पहली बार 2005 में आयोजित; स्लिनेक्स-26 विशाखापत्तनम में संपन्न।
हंबनटोटा बंदरगाह	2017 में ऋण चूक के बाद एक चीनी सरकारी कंपनी को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया श्रीलंकाई बंदरगाह; ऋण-जाल कूटनीति का उदाहरण माना जाता है।
सागर (SAGAR)	'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' – भारत का सिद्धांत जो खुद को हिंद महासागर का पसंदीदा सुरक्षा प्रदाता बताता है।
पड़ोसी पहले नीति	श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव जैसे तत्काल पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने की भारत की विदेश नीति प्राथमिकता।
क्वाड (QUAD)	भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का समूह जो मुक्त व इंडो-पैसिफिक के लिए कार्य करता है; स्लिनेक्स जैसे द्विपक्षीय अभ्यास इसे पूरक बनाते हैं।
स्ट्रिंग ऑफ पर्स	हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बंदरगाह व बुनियादी ढांचा निवेशों के नेटवर्क को वर्णित करने वाला शब्द, जिसे भारत को रणनीतिक रूप से घेरने के रूप में देखा जाता है।
पूर्वी नौसेना कमान	भारतीय नौसेना की तीन परिचालन कमानों में से एक, मुख्यालय विशाखापत्तनम में, जहां स्लिनेक्स-26 संपन्न हुआ।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध; हिंद महासागर सुरक्षा; चीनी प्रभाव का मुकाबला।
- GS3 रक्षा: नौसैनिक अंतर-संचालन क्षमता; समुद्री डकैती विरोधी क्षमता निर्माण।
- प्रारंभिक परीक्षा: स्लिनेक्स पहली बार 2005; स्लिनेक्स-26 विशाखापत्तनम (पूर्वी नौसेना कमान) में संपन्न; हंबनटोटा 99 वर्ष का पट्टा, 2017।

एफएसएसएआई पनीर विनियमन संशोधन

मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | दिनांक: 24 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

पनीर एक ताज़ा पनीर है जिसे दूध गर्म करके नींबू या सिरके जैसे अम्ल से फाड़कर बनाया जाता है – एक सरल, सदियों पुरानी प्रक्रिया। यह प्रक्रिया जितनी सरल है, पनीर उतना ही मिलावट का लगातार निशाना भी बना है: कुछ निर्माता दूध की जगह सस्ती वनस्पति वसा, स्टार्च या सिंथेटिक मिश्रण का उपयोग करते हैं, फिर भी उत्पाद को भरोसेमंद नाम 'पनीर' के तहत ही बेचते हैं। एफएसएसएआई, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्यरत सांविधिक खाद्य नियामक है, ने अब खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों में संशोधन कर इस खामी को बंद कर दिया है: अब केवल गाय या भैंस के दूध से बना, न्यूनतम निर्धारित वसा सामग्री वाला उत्पाद ही कानूनी रूप से 'पनीर' कहलाएगा; वनस्पति वसा से बने उत्पादों को 'एनालॉग' या 'नकली' लेबल देना अनिवार्य होगा, वह भी ब्रांड नाम से छोटे आकार में नहीं, ताकि खरीदते समय उपभोक्ता को स्पष्ट दिखे। यह तीन मोर्चों पर मायने रखता है: पोषण की दृष्टि से, क्योंकि पनीर बड़ी शाकाहारी आबादी के लिए प्रमुख प्रोटीन स्रोत है; आर्थिक रूप से, क्योंकि भारत के लगभग 8 करोड़ डेयरी किसान परिवार और छोटे पनीर उत्पादक उसी नाम पर व्यापार करने वाले सस्ते मिलावटी प्रतिस्पर्धियों से व्यवसाय गंवा रहे थे; और प्रवर्तन की दृष्टि से, क्योंकि एफएसएसएआई निरीक्षकों और अदालतों के पास अब एक स्पष्ट, परीक्षण योग्य मानक है, न कि 'मिलावट' पर एक अस्पष्ट सामान्य प्रतिबंध जिसे साबित करना कठिन था।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
पनीर	अम्ल से फाड़े गए दूध से बनी ताज़ा डेयरी चीज़; एफएसएसएआई 2026 संशोधन के तहत यह लेबल केवल वास्तविक गाय/भैंस के दूध उत्पादों तक सीमित।
एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण; स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय।
एनालॉग/नकली लेबलिंग	वनस्पति वसा आधारित पनीर विकल्पों के लिए अनिवार्य लेबलिंग आवश्यकता, ब्रांड नाम से छोटे आकार में नहीं, उपभोक्ता भ्रम रोकने हेतु।
मिलावट	खाद्य पदार्थ में घटिया या हानिकारक पदार्थ मिलाकर असली बताकर बेचना, जिससे पोषण और उपभोक्ता विश्वास दोनों प्रभावित होते हैं।
ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति)	भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने वाला अभियान; इसी पृष्ठभूमि में पनीर धोखाधड़ी उपभोक्ता विश्वास को कमजोर करती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006	भारत के खाद्य विनियमन को समेकित करने वाला मूल कानून, जिसके तहत एफएसएसआई कार्य करता है और पनीर जैसे उत्पाद-विशिष्ट मानक जारी करता है।
कोडेक्स एलिमेंटेरियस	अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय (एफएओ/डब्ल्यूएचओ) जिसके मानदंड अक्सर एफएसएसआई जैसे घरेलू मानकों को प्रभावित करते हैं।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 उपभोक्ता अधिकार: खाद्य सुरक्षा विनियमन; मिलावट रोकथाम में लेबलिंग की भूमिका।
- GS3 कृषि: डेयरी क्षेत्र पर प्रभाव; छोटे पनीर उत्पादक।
- प्रारंभिक परीक्षा: एफएसएसआई संशोधन दूध-आधारित पनीर तक सीमित; खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत; एनालॉग लेबलिंग अनिवार्य।

एक सींग वाला गैंडा और विश्व राइनो दिवस

मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | दिनांक: 22 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

20वीं सदी की शुरुआत में, एक सींग वाले गैंडे का इतनी बेरहमी से शिकार किया गया था – उसके सींग के लिए, जिसे कुछ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में गलत तरीके से औषधीय माना जाता था, और शिकार की ट्रॉफी के रूप में – कि दुनिया भर में 200 से भी कम गैंडे बचे थे, जो असम और आसपास के कुछ हिस्सों में सिमट गए थे। इसके बाद जो हुआ, उसे भारत की सबसे स्पष्ट संरक्षण सफलताओं में गिना जाता है: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कठोर सुरक्षा, जो 1985 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान में लगभग 1,090 वर्ग किलोमीटर में फैला है, विशेष रूप से प्रशिक्षित और अक्सर सशस्त्र वन रक्षक दल, और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी इको-टूरिज्म राजस्व-साझाकरण व्यवस्था जिसने आसपास के समुदायों को गैंडे के अस्तित्व में सीधा आर्थिक हित दिया, न कि उसके शिकार में। जनसंख्या अब बढ़कर 2022 की जनगणना के अनुसार 3,700 से अधिक हो गई है, जिसमें अकेले काजीरंगा में 2,600 से अधिक हैं – यानी विश्व की कुल जंगली आबादी का लगभग दो-तिहाई। विश्व राइनो दिवस, जो 2010 से हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, इस प्रगति को वैश्विक स्तर पर चिह्नित करता है, साथ ही शेष खतरों की ओर भी ध्यान दिलाता है: यह प्रजाति अभी भी आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार 'सुभेद्य' (वल्नरेबल) श्रेणी में है, क्योंकि वियतनाम और चीन के अवैध बाजारों में एक गैंडे का सींग हजारों डॉलर में बिकता है, और भारत की घरेलू सुरक्षा 1975 से लागू सीआईटीईएस अंतर्राष्ट्रीय संधि के साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि शिकार को बढ़ावा देने वाली मांग लगभग पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
------	---------

एक सींग वाला गैंडा	आईयूसीएन सुभेद्य प्रजाति; जनसंख्या 1900 के लगभग 200 से बढ़कर 2022 जनगणना में 3,700+ हुई, अकेले काजीरंगा में ~2,600।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	1985 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, असम में ब्रह्मपुत्र के बाढ़ मैदान पर ~1,090 वर्ग किमी; बाघ व जंगली भैंसों का भी घर।
सीआईटीईएस	लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, 1975 से लागू; गैंडे के सींग जैसे उत्पादों के सीमा-पार व्यापार को अपराध घोषित करता है।
आईयूसीएन रेड लिस्ट	प्रजातियों की संरक्षण स्थिति की वैश्विक सूची (कम चिंताजनक से विलुप्त तक); एक सींग वाला गैंडा वर्तमान में 'सुभेद्य' श्रेणी में।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972	भारत का प्रमुख घरेलू वन्यजीव कानून; गैंडे अनुसूची I में सूचीबद्ध हैं, जो उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा देता है।
इंडियन राइनो विजन 2020	असम सरकार की डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ पहल, जिसका लक्ष्य स्थानांतरण व शिकार-रोधी उपायों से 7 संरक्षित क्षेत्रों में राज्य की गैंडा जनसंख्या 3,000 तक बढ़ाना है।
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल	असाधारण सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदनाम; काजीरंगा को यह दर्जा 1985 से प्राप्त है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 अंतर्राष्ट्रीय: सीआईटीईएस (1975); भारत की जैव विविधता प्रतिबद्धताएं।
- GS3 पर्यावरण: काजीरंगा (यूनेस्को 1985); जनसंख्या पुनर्प्राप्ति 200 से 3,700+।
- प्रारंभिक परीक्षा: विश्व राइनो दिवस, 22 सितंबर, 2010 से मनाया जा रहा; आईयूसीएन स्थिति सुभेद्य; काजीरंगा में ~2,600 गैंडे।

SITOK IAS

आईएमईआई छेड़छाड़ जागरूकता अभियान

मंत्रालय: संचार मंत्रालय | दिनांक: 21 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

हर मोबाइल फोन पर फैक्ट्री में एक विशिष्ट 15-अंकीय आईएमईआई (अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान) नंबर अंकित होता है, जो कार्यात्मक रूप से वाहन के चेसिस नंबर जैसा है, यानी यह एक विशिष्ट भौतिक उपकरण की पहचान करता है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) 2019 में शुरू किए गए केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) के जरिए इस पहचान प्रणाली को चलाता है, जिससे कोई भी नागरिक ऑनलाइन खोए या चोरी हुए फोन की रिपोर्ट कर सकता है; रिपोर्ट होते ही उस फोन का आईएमईआई ब्लैकलिस्ट हो जाता है, और जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल सहित हर दूरसंचार ऑपरेटर उसे कनेक्शन देने से इनकार कर देगा, जिससे चोरी हुआ उपकरण बेचने लायक नहीं रह जाता। डीओटी के नए जागरूकता अभियान का लक्ष्य विशेष रूप से आईएमईआई छेड़छाड़ है: विशेष फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टूल का

उपयोग करके, जो अवैध रूप से व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, चोरी हुए फोन का असली आईएमईआई मिटाकर नकली नंबर डाल दिया जाता है, जिससे वह सीईआईआर की ब्लैकलिस्ट को पूरी तरह बायपास कर सकता है और चोरी न होने जैसा बेचा जा सकता है। यह एक ही कार्य सीईआईआर द्वारा बनाई गई पूरी रोकथाम प्रणाली को विफल कर देता है। डीओटी का अभियान नागरिकों से कहता है कि कोई भी पुराना फोन खरीदने से पहले *#06# डायल कर असली आईएमईआई जांचें, और यह स्पष्ट करता है कि आईएमईआई से छेड़छाड़ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 और 66 के तहत एक विशिष्ट अपराध है, जिससे पुलिस को इस सेवा देने वाली दुकानों और तकनीशियनों पर मुकदमा चलाने का स्पष्ट कानूनी आधार मिलता है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
आईएमईआई	मोबाइल उपकरण की 15-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या; *#06# से जांची जाती है; डीओटी के सीईआईआर (2019) से ट्रैक होती है।
सीईआईआर	केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर; डीओटी का राष्ट्रीय डेटाबेस जो चोरी/खोए फोन के आईएमईआई को ब्लैकलिस्ट करता है।
आईटी अधिनियम धारा 43 और 66	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधान जिनके तहत आईएमईआई छेड़छाड़ को साइबर अपराध के रूप में दंडित किया जाता है।
संचार साथी पोर्टल	डीओटी का नागरिक-केंद्रित मंच जो चोरी फोन ब्लॉक करने और अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन जांचने की सुविधा देता है।
साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)	गृह मंत्रालय का निकाय जो राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रतिक्रिया का समन्वय करता है, सीईआईआर जैसे डीओटी उपायों का पूरक।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023	भारत का डेटा संरक्षण कानून; पहचान व डेटा-संबंधित धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य वाले दूरसंचार/उपकरण सुरक्षा उपायों की पृष्ठभूमि।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 साइबर सुरक्षा: सीईआईआर (2019) दूरसंचार सुरक्षा ढांचा; आईटी अधिनियम प्रवर्तन।
- GS3 प्रौद्योगिकी: आईएमईआई ट्रैकिंग; उपकरण-स्तरीय साइबर अपराध प्रवृत्तियां।
- प्रारंभिक परीक्षा: आईएमईआई = 15 अंक, *#06# से जांच; सीईआईआर 2019 में शुरू; छेड़छाड़ आईटी अधिनियम धारा 43/66 के तहत दंडनीय।

सैटेलाइट एंटी-एयरफील्ड हथियार (आत्मनिर्भर भारत)

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय | दिनांक: 23 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

दुश्मन की वायु सेना को निष्क्रिय करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है उसके विमानों से लड़ने की बजाय उन रनवे और जमीनी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना जहां से वे उड़ान भरते हैं – एंटी-एयरफील्ड हथियार ठीक यही करता है। 'सैटेलाइट स्मार्ट' संस्करण उपग्रह-आधारित नेविगेशन का उपयोग करता है, जो सिद्धांत रूप में जीपीएस जैसा है लेकिन भारत के अपने नाविक (NavIC) मानक पर आधारित है ताकि संघर्ष के दौरान भी उपलब्धता सुनिश्चित रहे, और लंबी दूरी से सटीक हमला कर सके। रक्षा मंत्रालय ने 23 सितंबर 2026 को 811 करोड़ रुपये का अनुबंध किया, जिसके तहत हैदराबाद स्थित रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा घरेलू स्तर पर 160 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। भारत अब तक इस श्रेणी के सटीक-निर्देशित गोला-बारूद के लिए आयात पर बहुत निर्भर रहा है, जो वास्तविक जोखिम पैदा करता है क्योंकि आपूर्तिकर्ता देश किसी राजनीतिक विवाद या वास्तविक संघर्ष के दौरान डिलीवरी में देरी कर सकता है या स्पेयर पार्ट्स रोक सकता है – ठीक उसी समय जब ऐसे हथियारों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यह अनुबंध आत्मनिर्भर भारत की उस बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसके तहत 2020 से चार क्रमिक 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां' प्रकाशित की गई हैं, जो 500 से अधिक निर्दिष्ट रक्षा वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह रोक लगाती हैं, जिससे घरेलू विकास को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
सैटेलाइट स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड हथियार	उपग्रह-निर्देशित सटीक गोला-बारूद जो एयरफील्ड बुनियादी ढांचे को नष्ट करता है; 811 करोड़ रुपये, 160 इकाइयां, 23 सितंबर 2026, निर्माता बीडीएल।
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची	2020 से रक्षा मंत्रालय की चार क्रमिक सूचियां, जो 500+ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाकर घरेलू निर्माण को बाध्य करती हैं।
नाविक (NavIC)	भारत की अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, जो रक्षा अनुप्रयोगों के लिए विदेशी जीपीएस से स्वतंत्र, गारंटीशुदा उपलब्धता देती है।
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)	हैदराबाद स्थित रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, मिसाइल व सटीक गोला-बारूद का निर्माता, नए एसएसएडब्ल्यू अनुबंध का निर्माता।
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020	भारत का रक्षा खरीद ढांचा, जो स्वदेशी डिजाइन, विकास व निर्माण (आईडीडीएम) श्रेणियों को प्राथमिकता देता है।
मेक इन इंडिया (रक्षा)	मेक इन इंडिया का क्षेत्र-विशिष्ट अनुप्रयोग जो घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देकर भारत की ऐतिहासिक रूप से उच्च आयात निर्भरता कम करता है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 रणनीतिक स्वायत्तता: सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां (2020 से, 500+ वस्तुएं); नाविक।
- GS3 रक्षा: 811 करोड़ रुपये, 160 इकाइयां, बीडीएल (हैदराबाद); आत्मनिर्भर भारत।

- प्रारंभिक परीक्षा: एसएसएडब्ल्यू अनुबंध 811 करोड़, 23 सितंबर 2026; 160 इकाइयां; निर्माता बीडीएल; 2020 से 4 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां।

डीआरडीओ डीप टेक स्टार्ट-अप परियोजना (क्वांटम प्रौद्योगिकी)

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय | दिनांक: 24 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

सामान्य कंप्यूटर जानकारी को बिट्स के रूप में संग्रहीत करते हैं जो या तो 0 या 1 होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो – क्वांटम भौतिकी के सुपरपोजिशन सिद्धांत के कारण – एक साथ 0 और 1 दोनों का मिश्रण दर्शा सकते हैं, जिससे आज की आरएसए एन्क्रिप्शन को तोड़ने या जटिल अणुओं का अनुकरण करने जैसी अत्यंत कठिन गणनाएं किसी भी शास्त्रीय कंप्यूटर से कहीं तेज़ी से हल हो सकती हैं। समस्या यह है कि क्यूबिट्स बेहद नाजुक होते हैं: उनकी क्वांटम अवस्था थोड़ी सी भी गर्मी से नष्ट हो जाती है, इसलिए क्वांटम कंप्यूटरों को लगभग 20 मिलीकेल्विन – यानी लगभग -273.13°C , परम शून्य के बेहद करीब – पर ठंडा रखना पड़ता है। डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर वह विशेष उपकरण है जो इस अत्यधिक ठंडे तापमान को प्राप्त और बनाए रखता है; इसके बिना कोई कार्यशील क्वांटम कंप्यूटर संभव ही नहीं है। डीआरडीओ ने अपनी प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के तहत पहला बड़ा अनुबंध किया है – यह योजना 2016 में लगभग 50 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ शुरू हुई थी, जो केवल डीआरडीओ की अपनी प्रयोगशालाओं की बजाय निजी स्टार्ट-अप को वित्त पोषित करती है – ताकि यह बुनियादी ढांचा घरेलू स्तर पर आयात के बजाय भारत में ही बनाया जा सके। दांव दोहरे हैं: 2023 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत, जिसका आठ वर्षों में 6,003 करोड़ रुपये का परिव्यय है, पर्याप्त शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर अंततः दुनिया भर में सैन्य और बैंकिंग डेटा की सुरक्षा करने वाली एन्क्रिप्शन को तोड़ सकता है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर	लगभग 20 मिलीकेल्विन (-273.13°C) तक पहुंचने वाला शीतलन उपकरण, क्वांटम कंप्यूटरों के लिए आवश्यक; डीआरडीओ का पहला टीडीएफ अनुबंध इसके घरेलू निर्माण पर केंद्रित।
प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ)	डीआरडीओ की 2016 में शुरू योजना, ~50 करोड़ रुपये वार्षिक परिव्यय, जो केवल डीआरडीओ प्रयोगशालाओं की बजाय निजी स्टार्ट-अप को वित्त पोषित करती है।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन	2023 में कैबिनेट स्वीकृत, आठ वर्षों में 6,003 करोड़ रुपये परिव्यय, क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सेंसिंग प्रौद्योगिकियों को कवर करता है।

क्यूबिट / सुपरपोजिशन	क्वांटम बिट जो सुपरपोजिशन सिद्धांत के जरिए एक साथ 0 और 1 दोनों दर्शा सकता है, विशिष्ट समस्याओं के लिए घातीय गति प्रदान करता है।
पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी	अगली पीढ़ी की एन्क्रिप्शन जो भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों के विरुद्ध भी सुरक्षित रहने के लिए डिज़ाइन की गई है।
आईडेक्स (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार)	डीआरडीओ/रक्षा मंत्रालय की एक अलग पहल जो टीडीएफ के साथ-साथ रक्षा नवाचार के लिए स्टार्ट-अप व एमएसएमई को वित्त पोषित करती है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023, 6,003 करोड़/8 वर्ष); टीडीएफ योजना (2016)।
- GS2 रणनीतिक स्वायत्तता: स्वदेशी क्वांटम बुनियादी ढांचा, आयात निर्भरता में कमी।
- प्रारंभिक परीक्षा: डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर ~20 mK (-273.13 °C); टीडीएफ 2016 में शुरू; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 6,003 करोड़, 8 वर्ष, 2023 में स्वीकृत।

डीडीयू-जीकेवाई 2.0 शुभारंभ (ग्रामीण कौशल विकास)

मंत्रालय: कौशल विकास मंत्रालय | दिनांक: 19 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत के श्रम बाजार में एक बार-बार दिखने वाला पैटर्न है कौशल असंतुलन: उद्योगों को आतिथ्य, खुदरा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की जरूरत है, जबकि लाखों ग्रामीण युवा केवल इसलिए बेरोजगार रह जाते हैं क्योंकि उन्हें नियोक्ताओं की जरूरत के अनुसार व्यावहारिक कौशल में प्रशिक्षित नहीं किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), जो 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू हुई, इस अंतर को 15 से 35 वर्ष के गरीब ग्रामीण परिवारों के युवाओं के लिए मुफ्त, प्लेसमेंट-लिंक्ड प्रशिक्षण से भरती है, जो व्यापार के अनुसार 576 से 984 घंटे तक चलता है, और प्रशिक्षण साझेदार अनुबंध के अनुसार कम से कम 70% प्रशिक्षुओं को नौकरी दिलाने और न्यूनतम तीन महीने बनाए रखने के लिए बाध्य है। संस्करण 2.0, जो अक्टूबर 2026 से 70,000 ग्रामीण युवाओं के लक्ष्य के साथ शुरू हो रहा है, एक दशक से अधिक के कार्यान्वयन अनुभव के आधार पर इस मॉडल को और तेज़ करता है, जिसमें महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% नामांकन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट कोटा अनिवार्य है, जो ग्रामीण गरीबों में उनकी हिस्सेदारी को दर्शाता है। इसका आर्थिक तर्क भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़ा है: लगभग 28 वर्ष की औसत आयु और 65% से अधिक कामकाजी आयु की जनसंख्या के साथ, यह युवा जनसंख्या केवल तभी आर्थिक संपत्ति है जब उत्पादक रूप से नियोजित हो।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
------	---------

डीडीयू-जीकेवाई	2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू; 15-35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के लिए मुफ्त 576-984 घंटे का प्लेसमेंट-लिंकड प्रशिक्षण; 2.0 अक्टूबर 2026 से 70,000 लक्ष्य।
प्लेसमेंट अनिवार्यता	प्रशिक्षण साझेदारों को कम से कम 70% प्रशिक्षुओं को नौकरी दिलाने और 3 महीने न्यूनतम बनाए रखने की अनुबंधित जिम्मेदारी।
डीडीयू-जीकेवाई में आरक्षण	महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% नामांकन अनिवार्य, साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशिष्ट कोटा।
कौशल भारत मिशन	2015 में शुरू व्यापक राष्ट्रीय कौशल ढांचा, जिसके तहत डीडीयू-जीकेवाई (ग्रामीण) और पीएमकेवीवाई (व्यापक) दोनों घटक योजनाएं आती हैं।
पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना; भारत की प्रमुख अल्पकालिक कौशल प्रमाणन योजना, जो डीडीयू-जीकेवाई के ग्रामीण, प्लेसमेंट-लिंकड फोकस से अलग लेकिन पूरक है।
कौशल-नौकरी असंतुलन	नौकरी चाहने वालों के पास मौजूद कौशल और नियोक्ताओं की आवश्यकता के बीच संरचनात्मक अंतर, जिसे डीडीयू-जीकेवाई जैसी लक्षित प्रशिक्षण योजनाएं भरने का लक्ष्य रखती हैं।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 सामाजिक कल्याण: डीडीयू-जीकेवाई 2014 में शुरू; 33% महिला आरक्षण; एससी/एसटी कोटा।
- GS3 अर्थव्यवस्था: भारत की औसत आयु ~28; 65%+ कामकाजी जनसंख्या; कौशल-नौकरी असंतुलन।
- प्रारंभिक परीक्षा: डीडीयू-जीकेवाई 2.0 अक्टूबर 2026 से 70,000 ग्रामीण युवा लक्ष्य; 70% प्लेसमेंट अनिवार्यता; 576-984 प्रशिक्षण घंटे।

दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र पहल

मंत्रालय: संचार मंत्रालय | दिनांक: 21 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

116 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन के साथ, दुनिया के सबसे बड़े दूरसंचार बाजारों में से एक होने के बावजूद, भारत ऐतिहासिक रूप से अपने अधिकांश नेटवर्क उपकरण – राउटर, बेस स्टेशन, स्विचिंग हार्डवेयर – आयात करता रहा है, क्योंकि इस विशिष्ट, पूंजी-गहन हार्डवेयर के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता चीन या वियतनाम जैसे पैमाने पर कभी विकसित नहीं हुई। एक दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (टीएमजेड) निर्माताओं को समर्पित औद्योगिक समूहों में केंद्रित करता है, जिसे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में ग्वालियर (मध्य प्रदेश) और बेंगलुरु (कर्नाटक) जैसे शहरों में निवेशक बैठकों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कर छूट, एकल-खिड़की नियामक मंजूरी और साझा बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। यह 2021 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर आधारित है, जिसका पांच वर्षों में 12,195 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय है, जो घरेलू

स्तर पर निर्मित उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रतिशत-आधारित प्रोत्साहन देती है। आर्थिक तर्क, जिसे 'एग्लोमरेशन' कहा जाता है, यह है कि विनिर्माण समूह इसलिए सफल होते हैं क्योंकि संबंधित व्यवसाय – घटक आपूर्तिकर्ता, रसद प्रदाता, कुशल श्रम पूल – एक ही स्थान पर साथ विकसित होते हैं, जिससे उस समूह में हर निर्माता की लागत कम होती है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र	दूरसंचार उपकरण निर्माताओं के लिए कर प्रोत्साहन वाले औद्योगिक समूह, ग्वालियर और बेंगलुरु में मंत्री सिंधिया द्वारा प्रचारित।
दूरसंचार पीएलआई योजना	2021 में कैबिनेट स्वीकृत, पांच वर्षों में 12,195 करोड़ रुपये, दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पादों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करती है।
भारत के मोबाइल कनेक्शन	116 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन, विश्व के सबसे बड़े दूरसंचार बाजारों में से एक, फिर भी नेटवर्क हार्डवेयर के लिए ऐतिहासिक रूप से आयात-निर्भर।
मेक इन इंडिया	25 सितंबर 2014 को शुरू सरकारी पहल, आयात घटाने और आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार बनाने हेतु घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है।
एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़	एक-दूसरे के पास स्थित होने से फर्मों को मिलने वाला लागत व दक्षता लाभ, जो आपूर्तिकर्ता, रसद और कुशल श्रम साझा करती हैं – विनिर्माण क्षेत्रों के पीछे का तर्क।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)	निर्यात व विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु अलग आर्थिक कानूनों (कर, सीमा शुल्क) वाला निर्दिष्ट क्षेत्र; टीएमजेड वैचारिक रूप से इसी मॉडल से प्रेरित।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था: दूरसंचार पीएलआई (2021, 12,195 करोड़/5 वर्ष); विनिर्माण एग्लोमरेशन रणनीति।
- GS2 शासन: टीएमजेड नीतिगत उपकरण के रूप में; ग्वालियर व बेंगलुरु पायलट स्थान।
- प्रारंभिक परीक्षा: टीएमजेड निवेशक बैठकें मंत्री सिंधिया द्वारा; दूरसंचार पीएलआई 12,195 करोड़ (2021, 5 वर्ष); भारत में 116 करोड़+ मोबाइल कनेक्शन।

रेलवे कवच 4.0 कमीशनिंग

मंत्रालय: रेल मंत्रालय | दिनांक: 23 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

किसी भी रेलवे नेटवर्क पर सबसे खतरनाक क्षण वह होता है जब दो ट्रेनें टकराने के कगार पर होती हैं, चाहे किसी छूटे सिग्नल या गलत गति के अनुमान से हो, और भारत जैसे लगभग 68,000 रूट किलोमीटर के विशाल नेटवर्क पर केवल

मानवीय सतर्कता पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। कवच, जिसे भारतीय रेलवे के अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा तीन भारतीय विक्रेताओं के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया – जो पहले 2012-16 के दौरान टीसीएस नाम से जाना जाता था और 2020 में कवच नाम दिया गया – भारत की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है: यह ऑनबोर्ड और ट्रैक-किनारे रेडियो-फ्रीक्वेंसी उपकरणों के जरिए ट्रेन की गति और स्थिति को लगातार ट्रैक करता है, इसे सुरक्षित सीमा और पास की अन्य ट्रेनों से जांचता है, और अगर चालक कार्रवाई करने में विफल रहता है तो स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देता है, जिससे मानवीय त्रुटि टक्कर की एकमात्र वजह नहीं रह जाती। संस्करण 4.0 की पहली तैनाती, जो दक्षिण मध्य रेलवे के लखनऊ मंडल के 607.7 रूट किलोमीटर पर 252 करोड़ रुपये की लागत से हुई, पायलट परीक्षण से व्यापक रोलआउट की ओर बढ़ने का संकेत है। जून 2023 के ओडिशा के बालासोर त्रि-ट्रेन दुर्घटना के बाद, जिसमें लगभग 296 लोगों की जान गई और यह उजागर हुआ कि उस समय नेटवर्क के कितने कम हिस्से में कवच कवरेज थी, सरकार ने इसके रोलआउट लक्ष्य को काफी तेज़ कर दिया, जिसका लक्ष्य क्रमिक रूप से उच्च-घनत्व वाले लगभग 44,000 रूट किलोमीटर को कवर करना है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
कवच	आरडीएसओ द्वारा स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, मूलतः टीसीएस (2012-16), 2020 में कवच नाम दिया गया; टक्कर रोकने हेतु स्वचालित ब्रेक लगाता है।
बालासोर रेल दुर्घटना	जून 2023 की ओडिशा में त्रि-ट्रेन टक्कर, ~296 मौतें; कवच के राष्ट्रीय रोलआउट लक्ष्य को तेज़ किया।
रूट किलोमीटर लक्ष्य	सरकार का लक्ष्य उच्च-घनत्व मार्गों के ~44,000 रूट किलोमीटर को कवच से कवर करना; कवच 4.0 लखनऊ मंडल में 607.7 किमी, 252 करोड़ रुपये में।
स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी)	ट्रेन की गति निगरानी करने वाली सुरक्षा तकनीक जो गति सीमा लागू करती है और खतरा पहचानने पर स्वचालित आपातकालीन ब्रेक लगाती है।
आरडीएसओ	अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन, लखनऊ; भारतीय रेलवे की अनुसंधान इकाई जिसने कवच विकसित किया और रोलिंग स्टॉक/सिग्नलिंग मानक तय करती है।
मिशन रफ्तार	भारतीय रेलवे की माल व यात्री ट्रेनों की औसत गति दोगुनी करने की व्यापक पहल, जिसके लिए कवच-सक्षम सुरक्षा एक पूर्वापेक्षा है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 परिवहन: बालासोर दुर्घटना (2023, ~296 मौतें) नीति ट्रिगर के रूप में; स्वदेशी एटीपी विकास।
- GS2 रणनीतिक स्वायत्तता: कवच बनाम आयातित एटीपी प्रणालियां; आरडीएसओ की भूमिका।

- प्रारंभिक परीक्षा: कवच 4.0, 607.7 आरकेएम, लखनऊ मंडल, 252 करोड़ रुपये; मूलतः टीसीएस (2012-16), 2020 में नाम बदला; लक्ष्य ~44,000 आरकेएम।

उच्च गति राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एनएचआई दिशानिर्देश

मंत्रालय: सड़क परिवहन मंत्रालय | दिनांक: 22 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

एक पहुंच-नियंत्रित राजमार्ग केवल निर्दिष्ट, इंजीनियर किए गए बिंदुओं पर वाहनों को प्रवेश या निकास की अनुमति देता है, बिना किसी सिग्नल या सड़क किनारे की बाधा के, जिससे 100-120 किमी/घंटा की निरंतर गति संभव होती है – यह डिज़ाइन मानक अब भारत के बढ़ते एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर उपयोग किया जा रहा है, जो 2026 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के तहत लगभग 5,000 किमी पहुंच-नियंत्रित गलियारों को पार कर चुका है। एनएचआई ने ऐसे गलियारों के लिए अद्यतन डिज़ाइन दिशानिर्देश जारी किए हैं जो यूएचपीएफआरसी (अल्ट्रा-हाई परफॉर्मेंस फाइबर-रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट) पर जोर देते हैं – यह सामग्री सामान्य एम25-ग्रेड कंक्रीट की तुलना में कई गुना अधिक संपीड़न शक्ति वाली है, जो स्टील माइक्रो-फाइबर मिलाकर प्राप्त की जाती है, जिससे यह भारी-धुरी-भार वाले ट्रक यातायात के प्रति कहीं अधिक प्रतिरोधी बन जाती है। यह वित्तीय दृष्टि से उतना ही मायने रखता है जितना संरचनात्मक रूप से: यूएचपीएफआरसी निर्माण की लागत शुरुआत में 20-30% अधिक हो सकती है, लेकिन यह पारंपरिक कंक्रीट फ्लाईओवर की सामान्य 30-40 वर्ष की आयु से कहीं आगे तक चलती है, जिससे कुल जीवनचक्र लागत कम हो जाती है। नागपुर में इंडोरा-दिघोरी फ्लाईओवर इसका वास्तविक उदाहरण है, जहां उन्नत निर्माण से उस हिस्से पर यात्रा का समय लगभग 60 मिनट से घटकर मात्र 10-15 मिनट रह गया – यानी लगभग 75-80% की कमी, जो ईंधन खपत और उत्सर्जन दोनों घटाती है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
एनएचआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण; उच्च गति, पहुंच-नियंत्रित गलियारों के लिए 2026 में यूएचपीएफआरसी अनिवार्य करने वाले दिशानिर्देश जारी किए।
यूएचपीएफआरसी	अल्ट्रा-हाई परफॉर्मेंस फाइबर-रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट; सामान्य एम25 कंक्रीट से कई गुना मजबूत, लागत 20-30% अधिक पर आयु कहीं अधिक लंबी।
इंडोरा-दिघोरी फ्लाईओवर	नागपुर का फ्लाईओवर उदाहरण जिसने उन्नत निर्माण से यात्रा समय ~60 मिनट से 10-15 मिनट (~75-80% कमी) कर दिया।
भारतमाला परियोजना	2017 में शुरू भारत की व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना, जिसके तहत दिल्ली-मुंबई सहित अधिकांश नए पहुंच-नियंत्रित एक्सप्रेसवे बन रहे हैं।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम)	राजमार्गों के लिए पीपीपी वित्तपोषण संरचना जिसमें सरकार और निजी डेवलपर पूंजीगत लागत साझा करते हैं, एनएचआई परियोजनाओं में सामान्य।
फास्टैग	भारतीय राजमार्गों पर अनिवार्य आरएफआईडी-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली, जो टोल-बूथ भीड़भाड़ हटाकर पहुंच-नियंत्रित डिजाइन को पूरक बनाती है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 बुनियादी ढांचा: यूएचपीएफआरसी बनाम पारंपरिक कंक्रीट; भारत का ~5,000 किमी पहुंच-नियंत्रित नेटवर्क।
- GS2 सार्वजनिक नीति: विनियामक उपकरण के रूप में डिजाइन मानक; बुनियादी ढांचे में जीवनचक्र-लागत सोच।
- प्रारंभिक परीक्षा: एनएचआई 2026 यूएचपीएफआरसी दिशानिर्देश; इंडोरा-दिघोरी फ्लाईओवर (नागपुर) 60 मिनट से 10-15 मिनट; गति 100-120 किमी/घंटा।

डीआरआई जब्ती और कानून प्रवर्तन

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय | दिनांक: 23-24 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

डीआरआई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधीन कार्य करता है, भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी खुफिया एजेंसी है। 23-24 सितंबर 2026 के दौरान की गई कार्रवाइयों का एक ही सेट दिखाता है कि यह खतरा कितना विविध है: 845 किलोग्राम मादक पदार्थ जिसमें हेरोइन शामिल है, जिसकी तस्करी संगठित अपराध और कुछ मामलों में आतंकवाद को वित्त पोषित करती है; 86 जीवित टोके गेको, एक सरीसृप प्रजाति जो सीआईटीईएस परिशिष्ट II के तहत सूचीबद्ध है, जिसकी विदेशों में एक नमूने की कीमत हजारों डॉलर तक हो सकती है; लगभग 32 करोड़ रुपये मूल्य का 21 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना, जो मुख्यतः बांग्लादेश और खाड़ी के रास्तों से भारत के 6-15% के सोने पर आयात शुल्क से बचने के लिए तस्करी किया गया; और 10,000 किलोग्राम पटाखे, जो शुल्क और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा प्रशासित सुरक्षा मानकों दोनों से बचने के लिए तस्करी किए गए। इनमें से हर श्रेणी अलग तरह का नुकसान पहुंचाती है, फिर भी सभी चार को एक ही संस्थागत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है: डीआरआई के भारत कवच सूचना-साझाकरण मंच और जीएसटी खुफिया महानिदेशालय, राज्य पुलिस तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क समकक्षों के साथ समन्वय, क्योंकि तस्करी नेटवर्क नियमित रूप से राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं के पार काम करते हैं।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
------	---------

डीआरआई	राजस्व खुफिया निदेशालय, मुख्यालय नई दिल्ली, सीबीआईसी के अधीन, वित्त मंत्रालय; भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी एजेंसी।
सोने पर आयात शुल्क	भारत का सोने पर सीमा शुल्क, हाल के वर्षों में 6-15% के बीच, जो बांग्लादेश/खाड़ी मार्गों से लगातार सोने की तस्करी की मुख्य वजह है।
पीईएसओ	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन; वैध पटाखा निर्माण के लिए सुरक्षा मानक तय करता है, जिसे तस्कर दरकिनार करते हैं।
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड; वित्त मंत्रालय का शीर्ष निकाय जो सीमा शुल्क, जीएसटी और डीआरआई की तस्करी-रोधी गतिविधियों की देखरेख करता है।
एनडीपीएस अधिनियम, 1985	नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम; डीआरआई की मादक पदार्थ जब्ती पर मुकदमा चलाने का प्रमुख कानून।
स्वर्णिम अर्धचंद्र / स्वर्णिम त्रिभुज	अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान और म्यांमार-थाईलैंड-लाओस, जहां से मादक पदार्थ भारत में और होते हुए तस्करी किए जाते हैं।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 कानून: सीबीआईसी के अधीन डीआरआई; डीजीजीआई व राज्य पुलिस के साथ तस्करी-रोधी समन्वय।
- GS3 पर्यावरण: सीआईटीईएस परिशिष्ट II (टोके गेको); वन्यजीव तस्करी।
- प्रारंभिक परीक्षा: डीआरआई 23-24 सितंबर 2026: 845 किग्रा ड्रग्स, 86 टोके गेको, 21 किग्रा सोना (~32 करोड़), 10,000 किग्रा पटाखे; सोने पर शुल्क 6-15%।

एनएलएमसी भूमि मुद्रीकरण कार्यक्रम

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय | दिनांक: 23 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

दशकों से, केंद्रीय विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों ने परिचालन आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहित की – कारखाने, कार्यालय, रेलवे यार्ड – लेकिन इसमें से बहुत सी भूमि परिचालन बदलने के साथ अधिशेष हो गई, फिर भी सरकार के स्वामित्व में बनी रही, कोई आय उत्पन्न नहीं करती, जबकि सुरक्षा, रखरखाव और अतिक्रमण मुकदमेबाजी में लगातार खर्च होता रहा। एनएलएमसी, जिसे 2022 में वित्त मंत्रालय के तहत पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में 150 करोड़ रुपये की प्रारंभिक चुकता पूंजी के साथ शामिल किया गया, विशेष रूप से सरकारी निकायों में ऐसी गैर-प्रमुख अधिशेष भूमि की पहचान करने और उसे व्यवस्थित रूप से बेचने के लिए स्थापित किया गया था, जिसका लक्ष्य 2021-22 के बजट में घोषित व्यापक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के हिस्से के रूप में चार वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के मुद्रीकरण मूल्य का है। तरीका उतना ही मायने रखता है जितना लक्ष्य: एनएलएमसी निजी बातचीत के बजाय ई-नीलामी, यानी पारदर्शी ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली को बढ़ावा देता है, क्योंकि निजी बातचीत ऐतिहासिक रूप से कम कीमत

आंकने या पक्षपात के प्रति संवेदनशील रही है। हाल की आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट संचालक) भूमि बिक्री इसी मॉडल का ठोस उदाहरण है। राजकोषीय तर्क स्पष्ट है: चूंकि यह भूमि पहले से शून्य राजस्व दे रही थी जबकि लागत वहन कर रही थी, इसे एकमुश्त नकदी में बदलना लगभग शुद्ध लाभ है, जिसे नए कर या उधार के बिना बुनियादी ढांचे की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
एनएलएमसी	राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण निगम, 2022 में शामिल, 150 करोड़ रुपये प्रारंभिक चुकता पूंजी; चार वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य।
राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन	2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित व्यापक परिसंपत्ति मुद्राकरण ढांचा, जिसका एक घटक एनएलएमसी का भूमि कार्यक्रम है।
ई-नीलामी	एनएलएमसी द्वारा निजी बातचीत के बजाय अनिवार्य पारदर्शी ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली, जैसा आरआईएनएल भूमि बिक्री में प्रयुक्त हुआ।
राजकोषीय घाटा	सरकारी व्यय और राजस्व के बीच का अंतर; एनएलएमसी जैसी परिसंपत्ति बिक्री इस अंतर को प्रबंधित करने में एकमुश्त, गैर-कर राजस्व प्रदान करती है।
आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम)	विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की संचालक राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी, जिसकी अधिशेष भूमि बिक्री एनएलएमसी के ई-नीलामी मॉडल का उदाहरण है।
विनिवेश बनाम मुद्राकरण	विनिवेश सार्वजनिक उपक्रमों में स्वामित्व हिस्सेदारी बेचता है; मुद्राकरण (एनएलएमसी जैसा) मूल परिचालन बनाए रखते हुए विशिष्ट अल्प-उपयोग परिसंपत्तियों को पट्टे पर देता/बेचता है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 शासन: एनएलएमसी (2022, 150 करोड़ पूंजी); राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (2021-22 बजट)।
- GS3 अर्थव्यवस्था: एकमुश्त परिसंपत्ति बिक्री बनाम संरचनात्मक राजकोषीय सुधार।
- प्रारंभिक परीक्षा: एनएलएमसी 2022 में शामिल; लक्ष्य 1 लाख करोड़/4 वर्ष; आरआईएनएल ई-नीलामी सितंबर 2026।

एनजीटी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च

मंत्रालय: पर्यावरण मंत्रालय | दिनांक: 22 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे एनजीटी अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित किया गया, एक विशेष न्यायिक निकाय है जो औद्योगिक प्रदूषण, अवैध खनन, अनधिकृत वनों की कटाई जैसे पर्यावरणीय मामलों को सामान्य दीवानी अदालतों की

तुलना में तेज़ी से और अधिक तकनीकी विशेषज्ञता के साथ सुनने के लिए बनाया गया। सिद्धांत रूप में यह पर्यावरणीय न्याय को अधिक सुलभ बनाता है; व्यवहार में, एनजीटी केवल 5 बेंचों से काम करता है – दिल्ली (मुख्य पीठ), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई – जिसका अर्थ है कि निकटतम बेंच से सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रदूषण से प्रभावित समुदाय को मामला दर्ज करने में वास्तविक व्यावहारिक बाधा का सामना करना पड़ता था। नया लॉन्च किया गया एनजीटी मोबाइल एप्लिकेशन डिजिटल केस फाइलिंग, वास्तविक समय स्थिति ट्रैकिंग, और फोन से सुनवाई कार्यक्रम व आदेशों तक पहुंच की अनुमति देकर सीधे इसी बाधा को लक्षित करता है। यह एक सार्थक कदम है, लेकिन इसकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है: डिजिटल फाइलिंग भौगोलिक और प्रक्रियात्मक बाधा को दूर करती है, लेकिन यह स्वयं वह वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती जो कई पर्यावरणीय मामलों में वास्तव में आवश्यक होती है, न ही यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा अनुकूल आदेशों के प्रभावी प्रवर्तन की गारंटी देती है, जिसे भारत की अपनी संसदीय स्थायी समितियों ने बार-बार असंगत बताया है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
एनजीटी	राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत स्थापित; 5 बेंचों से संचालित – दिल्ली (मुख्य), भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई।
एनजीटी मोबाइल ऐप	2026 लॉन्च, डिजिटल केस फाइलिंग, वास्तविक समय ट्रैकिंग और बिना बेंच जाए सुनवाई/आदेशों तक पहुंच सक्षम करता है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	एनजीटी आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय निकाय; प्रवर्तन में असंगति संसदीय समितियों द्वारा बार-बार चिह्नित।
प्रदूषक भुगतान सिद्धांत	कानूनी सिद्धांत, जिसे एनजीटी अक्सर लागू करता है, जो प्रदूषकों को पर्यावरणीय क्षति और सुधार लागत के लिए वित्तीय रूप से जिम्मेदार ठहराता है।
एहतियाती सिद्धांत	पर्यावरण कानून का सिद्धांत (एनजीटी द्वारा भी लागू) जो पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के बिना भी पर्यावरणीय क्षति के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की मांग करता है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	भोपाल गैस त्रासदी के बाद बना भारत का व्यापक पर्यावरण कानून, जिसके तहत एनजीटी के समक्ष कई मामलों का अंततः निर्णय होता है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण: एनजीटी अधिनियम (2010); राज्य प्रदूषण बोर्ड स्तर पर प्रवर्तन अंतर।
- GS2 शासन: डिजिटल उपकरणों से न्याय तक पहुंच; एनजीटी की 5-बेंच संरचना।
- प्रारंभिक परीक्षा: एनजीटी अधिनियम 2010; 5 बेंच (दिल्ली मुख्य + भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई); मोबाइल ऐप सितंबर 2026 में लॉन्च।

ओपेक-भारत ऊर्जा वार्ता

मंत्रालय: पेट्रोलियम मंत्रालय | दिनांक: 22 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत 2026 तक अपनी खपत का लगभग 85-88% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक तेल कीमतें सीधे मुद्रास्फीति, राजकोषीय स्थिति और चालू खाता घाटे को प्रभावित करती हैं। ओपेक, जिसकी स्थापना 1960 में हुई और जिसमें अब सऊदी अरब, ईरान, इराक और यूएई सहित 12 सदस्य देश शामिल हैं, रूस के नेतृत्व वाले ओपेक+ भागीदारों के साथ मिलकर वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 40% नियंत्रित करता है और विशेष रूप से वैश्विक कीमतों को प्रभावित करने के लिए उत्पादन कोटा का समन्वय करता है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समूह द्वारा प्रभावी रूप से तय की गई कीमतों पर कितनी निर्भर है, इसे देखते हुए, ओपेक-भारत ऊर्जा वार्ता, जो अब अपने 7वें उच्च-स्तरीय दौर में है, भारत – जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है – के लिए मांग पूर्वानुमान और मूल्य चिंताओं को सीधे उस समूह तक पहुंचाने का एक संरचित माध्यम है जो सबसे अधिक प्रभावित करता है कि भारत क्या भुगतान करता है। निरंतर संवाद दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों का भी समर्थन करता है, जो शुद्ध स्पॉट-मार्केट खरीद की तुलना में अधिक अनुमानित मूल्य निर्धारण प्रदान करते हैं, और खाड़ी देशों के साथ राजनयिक संबंधों को भी मजबूत करता है, जहां 80 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी कामगार रहते हैं। संवाद अकेले युद्ध या प्रतिबंधों के कारण होने वाले झटकों से भारत को पूरी तरह अलग नहीं कर सकता, इसीलिए भारत अलग से 3 भूमिगत स्थलों पर लगभग 53.3 लाख टन का सामरिक पेट्रोलियम भंडार बनाए रखता है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
ओपेक / ओपेक+	ओपेक (1960 में स्थापित, 12 सदस्य) और रूस के नेतृत्व वाले ओपेक+ भागीदार; मिलकर वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का ~40% नियंत्रित करते हैं।
भारत की तेल आयात निर्भरता	भारत खपत का ~85-88% कच्चा तेल आयात करता है (2026); विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक; खाड़ी में 80 लाख+ भारतीय प्रवासी।
सामरिक पेट्रोलियम भंडार	भारत का आपातकालीन तेल बफर, 3 भूमिगत भंडारण स्थलों (विशाखापत्तनम, मंगलौर, पादुर) में लगभग 53.3 लाख टन।
चालू खाता घाटा (सीएडी)	जब किसी देश का वस्तुओं/सेवाओं का आयात निर्यात से अधिक हो; तेल आयात भारत के सीएडी का सबसे बड़ा एकल कारण है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)	ओईसीडी से जुड़ा निकाय जो सदस्य देशों के आपातकालीन तेल भंडार व ऊर्जा नीति का समन्वय करता है, ओपेक का उपभोक्ता-पक्षीय समकक्ष।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

2023 में स्वीकृत भारत की समानांतर दीर्घकालिक रणनीति, हरित हाइड्रोजन के जरिए जीवाश्म ईंधन/तेल निर्भरता घटाने के लिए, ऊर्जा कूटनीति की पूरक।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक; खाड़ी कूटनीति (80 लाख+ प्रवासी)।
- GS3 अर्थव्यवस्था: ओपेक/ओपेक+ (~40% वैश्विक उत्पादन); सामरिक पेट्रोलियम भंडार (53.3 लाख टन, 3 स्थल)।
- प्रारंभिक परीक्षा: 7वीं ओपेक-भारत वार्ता; ओपेक स्थापना 1960, 12 सदस्य; भारत 85-88% कच्चा तेल आयात करता है।

सीएसआईआर-सीआरआरआई वैज्ञानिक सहयोग (विशाखापत्तनम सड़कें)

मंत्रालय: विज्ञान मंत्रालय | दिनांक: 24 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

शहर आमतौर पर स्थानीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना सामान्य इंजीनियरिंग विनिर्देशों को सड़क-निर्माण में लागू करते हैं, फिर भी स्थायित्व मिट्टी के प्रकार, वर्षा जल निकासी और वास्तविक यातायात भार पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो स्थान के अनुसार बहुत भिन्न होते हैं। सीएसआईआर-सीआरआरआई, जिसकी स्थापना 1952 में हुई और जो नई दिल्ली में स्थित सीएसआईआर की 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, सड़क योजना में कठोर, स्थान-विशिष्ट इंजीनियरिंग विज्ञान लाने के लिए मौजूद है, और विशाखापत्तनम महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (वीएमआरडीए) के साथ इसका सहयोग ठीक यही करता है: सीआरआरआई वैज्ञानिक सीधे मिट्टी-वहन क्षमता परीक्षण करते हैं, वास्तविक धुरी-भार यातायात पैटर्न का विश्लेषण करते हैं, और जीआईएस मानचित्रण का उपयोग करके यह ठीक-ठीक पता लगाते हैं कि कौन से हिस्से क्यों विफल हो रहे हैं, इससे पहले कि वे एक सामान्य राष्ट्रीय टेम्पलेट की बजाय साक्ष्य-आधारित, संदर्भ-विशिष्ट समाधान सुझाएं। भारत की पर्याप्त वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता, जो सीएसआईआर के नेटवर्क के माध्यम से सात दशकों से अधिक समय में निर्मित हुई है, हमेशा शहर और राज्य बुनियादी ढांचा एजेंसियों के दैनिक निर्णयों से व्यवस्थित रूप से नहीं जुड़ पाई है, जिनके पास अक्सर अपनी इंजीनियरिंग अनुसंधान क्षमता नहीं होती। जब ऐसा संबंध बनता है, जैसा विशाखापत्तनम में हुआ, तो परिणाम अधिक टिकाऊ बुनियादी ढांचा होता है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
सीएसआईआर-सीआरआरआई	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, 1952 में स्थापित, नई दिल्ली; सीएसआईआर की 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक, सड़क इंजीनियरिंग अनुसंधान में विशेषज्ञ।

वीएमआरडीए	विशाखापत्तनम महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण; साक्ष्य-आधारित सड़क डिजाइन हेतु सीआरआरआई के साथ भागीदार शहर निकाय।
जीआईएस-आधारित सड़क निदान	सीआरआरआई द्वारा उपयोग की जाने वाली भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण, जो विफल सड़क हिस्सों और उनके विशिष्ट कारणों की पहचान करती है।
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद; विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थाओं की श्रृंखला (37 प्रयोगशालाएं)।
जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग	निर्माण हेतु मिट्टी व चट्टान गुणों का अध्ययन; सीआरआरआई इसका उपयोग स्थान-विशिष्ट सड़क डिजाइन के लिए करता है।
स्मार्ट सिटीज मिशन	2015 में शुरू व्यापक शहरी बुनियादी ढांचा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसके तहत सीआरआरआई-वीएमआरडीए जैसे शहर-विज्ञान सहयोग वैचारिक रूप से आते हैं।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान: सीएसआईआर (37 प्रयोगशाला नेटवर्क); सीआरआरआई स्थापना 1952; अनुसंधान-से-कार्यान्वयन अंतर।
- GS2 शासन: विज्ञान-नीति इंटरफेस; 4,000+ शहरी स्थानीय निकायों में विस्तार की चुनौती।
- प्रारंभिक परीक्षा: सीआरआरआई स्थापना 1952, नई दिल्ली; सीएसआईआर की 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं; सीआरआरआई-वीएमआरडीए सहयोग सितंबर 2026।

स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 (तटीय संरक्षण)

मंत्रालय: विज्ञान मंत्रालय | दिनांक: 21 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत की तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है और मत्स्यन, पर्यटन तथा शिपिंग के माध्यम से लाखों लोगों को आजीविका देती है, फिर भी यह भारत द्वारा प्रतिवर्ष उत्पन्न अनुमानित 93 लाख टन प्लास्टिक कचरे का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित करती है, जिसका अधिकांश हिस्सा अपर्याप्त रूप से प्रबंधित होकर नदियों और समुद्र तक पहुंचता है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, जिसे पहली बार 2022 में राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए शुरू किया गया, का 5वां संस्करण 21 सितंबर 2026 को आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 15 लाख स्वयंसेवकों ने 13 तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 231 स्थानों पर एक ही दिन समन्वित सफाई अभियान में भाग लिया, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) संयुक्त रूप से चलाते हैं। इस बारे में स्पष्ट रहना जरूरी है कि ऐसा अभियान क्या कर सकता है और क्या नहीं: एक ही दिन में हटाया गया कचरा, चाहे स्वयंसेवकों की संख्या कितनी भी बड़ी हो, प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले लगभग 93 लाख टन का एक छोटा अंश है, इसलिए अभियान का सबसे मूल्यवान दीर्घकालिक योगदान शायद एकत्रित मात्रा से अधिक इससे बनने वाली सार्वजनिक जागरूकता है। जब 15 लाख नागरिक व्यक्तिगत रूप से

समुद्र तटों से प्लास्टिक हटाते हैं, तो कई लोग समस्या की ठोस समझ विकसित करते हैं, जो निष्क्रिय दर्शक से सक्रिय भागीदार में बदलाव है, जो सख्त औद्योगिक अपशिष्ट मानकों और विस्तारित नगरपालिका सीवेज उपचार क्षमता जैसे कठिन, कम दिखाई देने वाले नीतिगत बदलावों के लिए व्यापक सार्वजनिक समर्थन बना सकता है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर	2022 से वार्षिक तटीय सफाई अभियान; 5वां संस्करण 21 सितंबर 2026; 15 लाख स्वयंसेवक, 231 स्थान, 13 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश; एनसीसीआर के साथ संचालित।
एनसीसीआर	राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन; तटीय सफाई अभियान का सह-संचालक।
भारत का वार्षिक प्लास्टिक कचरा	अनुमानित 93 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पन्न, जिसका अधिकांश अपर्याप्त रूप से प्रबंधित होकर तटीय एवं समुद्री प्रदूषण में योगदान देता है।
ब्लू इकॉनमी	समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास हेतु समुद्री एवं तटीय संसाधनों का सतत उपयोग।
विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर)	नियामक सिद्धांत जो प्लास्टिक निर्माताओं को उनकी पैकेजिंग के संग्रहण/पुनर्चक्रण के लिए जिम्मेदार बनाता है, सफाई अभियानों का संरचनात्मक पूरक।
तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड)	समुद्र तटों के पास निर्माण व औद्योगिक गतिविधि को प्रतिबंधित करने वाला भारत का विनियामक ढांचा, नाजुक समुद्री व तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हेतु।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 पर्यावरण: भारत का प्लास्टिक कचरा (93 लाख टन/वर्ष); तटरेखा ~7,500 किमी।
- GS2 शासन: सामूहिक जुटान (2022 से); एनसीसीआर की समन्वयकारी भूमिका।
- प्रारंभिक परीक्षा: स्वच्छ सागर 5.0, 21 सितंबर 2026; 15 लाख प्रतिभागी, 231 स्थान, 13 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश।

भारत-मंगोलिया सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय | दिनांक: 21 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, जो पहली बार 2004 में आयोजित हुआ और हाल ही में पिथौरागढ़, उत्तराखंड में आयोजित किया गया, भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक आवर्ती द्विपक्षीय अभ्यास है, जो संयुक्त सामरिक अभ्यास, शहरी युद्ध प्रशिक्षण और समन्वित प्रतिक्रिया अभ्यासों के माध्यम से साझा आतंकवाद-रोधी क्षमता निर्माण पर

केंद्रित है। यह एक साधारण, नियमित अभ्यास जैसा लग सकता है, लेकिन इसका महत्व मंगोलिया की भौगोलिक स्थिति से स्पष्ट होता है: लगभग 33 लाख लोगों वाला एक भूमि से घिरा देश, जो सीधे रूस और चीन के बीच स्थित है, ऐतिहासिक रूप से व्यापार और ऊर्जा के लिए दोनों पर निर्भर है, जिसके कारण मंगोलिया ने जानबूझकर एक 'तीसरे पड़ोसी' नीति अपनाई है – जिसमें वह भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों के साथ साझेदारी की तलाश करता है ताकि किसी एक पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके। भारत, जिसने 2015 में मंगोलिया के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, इस भूमिका में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है क्योंकि इसका मंगोलिया के प्रति कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा का इतिहास नहीं है। भारत के लिए, यह अभ्यास दक्षिण एशिया से परे पूरे एशिया में संबंध बनाने की व्यापक रणनीति का एक जानबूझकर हिस्सा है, बिना सीधे और टकरावपूर्ण ढंग से चीनी हितों को चुनौती दिए।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट	भारत-मंगोलिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, पहली बार 2004 में आयोजित; हालिया संस्करण पिथौरागढ़, उत्तराखंड में; आतंकवाद-रोधी केंद्रित।
मंगोलिया की तीसरे पड़ोसी नीति	रूस और चीन पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए मंगोलिया की भारत, जापान, अमेरिका जैसे देशों से साझेदारी की जानबूझकर रणनीति।
भारत-मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी	2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मंगोलिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंध को रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाया गया।
रक्षा कूटनीति	औपचारिक गठबंधन के बिना संबंध बनाने के लिए विदेश नीति उपकरण के रूप में सैन्य सहयोग (अभ्यास, प्रशिक्षण, हथियार बिक्री) का उपयोग।
एकट ईस्ट नीति	पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ जुड़ाव गहरा करने वाला भारत का विदेश नीति ढांचा (लुक ईस्ट का उत्तराधिकारी), जिसमें मंगोलिया संबंध कभी-कभी शामिल किए जाते हैं।
स्थलरुद्ध विकासशील देश (एलएलडीसी)	मंगोलिया जैसे तटीय पहुंच रहित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण, जो उनकी विदेश नीति को आकार देने वाली विशिष्ट व्यापार व संपर्क चुनौतियों का सामना करते हैं।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध: मंगोलिया की तीसरे पड़ोसी नीति; भारत-मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी (2015)।
- GS3 रक्षा: आतंकवाद-रोधी संयुक्त प्रशिक्षण; भारत की मध्य एशिया पहुंच।
- प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट पहली बार 2004; हालिया संस्करण पिथौरागढ़; भारत-मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी 2015 से।

सेमीकॉन इंडिया 2026 (सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम)

मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय | दिनांक: 22 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

सेमीकंडक्टर – आमतौर पर 'चिप्स' कहे जाते हैं – स्मार्टफोन से लेकर रक्षा उपकरणों तक, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हर हिस्से को शक्ति देते हैं, जिससे वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला गंभीर सामरिक महत्व का विषय बन जाती है। एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ता होने के बावजूद, भारत घरेलू स्तर पर लगभग कोई चिप नहीं बनाता, बहुसंख्या आयात करता है – यह निर्भरता वास्तविक जोखिम रखती है क्योंकि दुनिया की 90% से अधिक सबसे उन्नत चिप निर्माण क्षमता ताइवान और दक्षिण कोरिया में केंद्रित है। सेमीकॉन इंडिया 2026 दिसंबर 2021 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के स्वदेशी सेमीकंडक्टर क्षमता निर्माण के शुरुआती प्रयासों को प्रदर्शित करता है, जिसका 76,000 करोड़ रुपये का परिव्यय है और जो चिप निर्माण एवं डिस्प्ले विनिर्माण इकाइयों के लिए 50% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। इस मिशन के तहत स्वीकृत पहला निर्माण संयंत्र, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स-पीएसएमसी की धोलेरा, गुजरात स्थित सुविधा, जिसमें लगभग 91,000 करोड़ रुपये का निवेश है, 2024 में शुरू हुआ और 2026-27 के आसपास उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। यथार्थवादी अपेक्षाएं रखना जरूरी है: एक आधुनिक चिप निर्माण संयंत्र की लागत कई अरब डॉलर हो सकती है और पूर्ण उत्पादन तक पहुंचने में वर्षों लग सकते हैं, इसलिए सेमीकॉन इंडिया एक बहु-दशकीय प्रयास के शुरुआती, बुनियादी कदम का प्रतिनिधित्व करता है, न कि आसन्न आत्मनिर्भरता का प्रमाण।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	दिसंबर 2021 में कैबिनेट स्वीकृत, 76,000 करोड़ रुपये परिव्यय; चिप निर्माण व डिस्प्ले इकाइयों के लिए 50% तक पूंजीगत सब्सिडी।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स-पीएसएमसी धोलेरा संयंत्र	भारत का पहला स्वीकृत चिप संयंत्र, धोलेरा, गुजरात; ~91,000 करोड़ रुपये निवेश; 2024 में शुरुआत, उत्पादन लक्ष्य 2026-27।
वैश्विक चिप निर्माण एकाग्रता	दुनिया की 90% से अधिक उन्नत चिप निर्माण क्षमता ताइवान और दक्षिण कोरिया में केंद्रित है।
फैबलेस बनाम फाउंड्री मॉडल	फैबलेस कंपनियां बिना फाउंड्री (निर्माण संयंत्र) के चिप डिजाइन करती हैं; भारत की प्रारंभिक सेमीकंडक्टर रणनीति फैब से पहले डिजाइन पर अधिक केंद्रित है।
चिप वॉर / निर्यात नियंत्रण	अमेरिका-नेतृत्व वाले प्रतिबंध जो चीन की उन्नत चिप-निर्माण उपकरणों तक पहुंच सीमित करते हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को पुनर्गठित करते हुए भारत जैसे विकल्पों के लिए अवसर बनाते हैं।

डिजिटल इंडिया मिशन

2015 में शुरू व्यापक कार्यक्रम जो डिजिटल बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देता है, जिसके तहत सेमीकंडक्टर मिशन एक रणनीतिक स्तंभ है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 प्रौद्योगिकी: भारत सेमीकंडक्टर मिशन (76,000 करोड़, 2021); धोलेरा संयंत्र (~91,000 करोड़)।
- GS2 रणनीतिक स्वायत्तता: 90%+ ताइवान/दक्षिण कोरिया चिप एकाग्रता का जोखिम कम करना।
- प्रारंभिक परीक्षा: सेमीकॉन इंडिया 2026; सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ (2021); धोलेरा संयंत्र उत्पादन ~2026-27।

तीसरा राष्ट्रीय एएनटीएफ सम्मेलन

मंत्रालय: गृह मंत्रालय | दिनांक: 22 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क शायद ही कभी एक राज्य तक सीमित रहते हैं, वे जानबूझकर इस बात का फायदा उठाते हैं कि विभिन्न क्षेत्राधिकारों में पुलिस, सीमा शुल्क और राजस्व एजेंसियां अक्सर वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा नहीं करतीं। मादक पदार्थ विरोधी कार्य बल (एएनटीएफ) ढांचा, जो नारको-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) के माध्यम से केंद्रीय रूप से समन्वित है – 2020 में गठित एक 4-स्तरीय तंत्र, राष्ट्रीय से जिला स्तर तक – हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाकर इसी अंतर को पाटता है। नई दिल्ली में 22 सितंबर 2026 को आयोजित तीसरा राष्ट्रीय एएनटीएफ सम्मेलन यह समन्वय मंच प्रदान करता है। यह भारत के भूगोल को देखते हुए मायने रखता है: पश्चिम में स्वर्णिम अर्धचंद्र (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) और पूर्व में स्वर्णिम त्रिभुज (म्यांमार-थाईलैंड-लाओस) से निकटता भारत को पारगमन मार्ग और बढ़ता उपभोक्ता बाजार दोनों बनाती है, जिसमें हेरोइन तस्करी के साथ-साथ मेथामफेटामाइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती में एनसीबी के आंकड़ों के अनुसार तेज़ वृद्धि दिख रही है। बेहतर समन्वित प्रवर्तन, चाहे कितना भी आवश्यक हो, केवल आपूर्ति पक्ष को संबोधित करता है; तस्करी एक लाभदायक उद्यम के रूप में इसलिए बनी रहती है क्योंकि निरंतर मांग तस्करों के प्रोत्साहन को ऊंचा बनाए रखती है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
एएनटीएफ / एनसीओआरडी	मादक पदार्थ विरोधी कार्य बल, एनसीओआरडी (नारको-समन्वय केंद्र) के जरिए समन्वित, 2020 में गठित 4-स्तरीय (राष्ट्रीय से जिला) तंत्र।
स्वर्णिम अर्धचंद्र / स्वर्णिम त्रिभुज	अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान और म्यांमार-थाईलैंड-लाओस, भारत से सटे दो प्रमुख मादक पदार्थ उत्पादक क्षेत्र।

नशा मुक्त भारत अभियान	2020 में शुरू भारत का राष्ट्रीय नशा-मुक्ति अभियान, जो आपूर्ति-पक्ष प्रवर्तन को मांग में कमी के साथ पूरक बनाता है।
नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)	गृह मंत्रालय के अधीन मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी, जो एनटीएफ और एनसीओआरडी ढांचे का समन्वय करती है।
एनडीपीएस अधिनियम, 1985	भारत का प्रमुख मादक पदार्थ-रोधी कानून, जिसके तहत एनटीएफ-समन्वित जब्ती पर मुकदमा चलाया जाता है।
सिंथेटिक ड्रग्स (एटीएस)	मेथामफेटामाइन व एमडीएमए जैसे एम्फेटामाइन-प्रकार उत्तेजक पदार्थ, हेरोइन जैसे पारंपरिक पौधा-आधारित मादक पदार्थों के साथ तेजी से बढ़ती तस्करी श्रेणी।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 कानून: एनसीओआरडी 4-स्तरीय संरचना (2020); एनसीबी की समन्वयकारी भूमिका।
- GS3 सामाजिक: स्वर्णिम अर्धचंद्र/त्रिभुज; बढ़ती सिंथेटिक ड्रग जब्ती; नशा मुक्त भारत अभियान (2020)।
- प्रारंभिक परीक्षा: तीसरा एनटीएफ सम्मेलन, नई दिल्ली, 22 सितंबर 2026; एनसीओआरडी 2020 में गठित; नशा मुक्त भारत अभियान 2020 से।

उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियां

मंत्रालय: विधि एवं न्याय मंत्रालय | दिनांक: 21 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

2026 तक भारत की अदालतों में सभी स्तरों पर 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं, और इसका एक बड़ा संरचनात्मक कारण सीधा है: कई स्वीकृत न्यायिक पद वर्षों तक खाली रहते हैं, यानी स्वीकृत क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता। भारत के 25 उच्च न्यायालयों की संयुक्त स्वीकृत संख्या 1,114 न्यायाधीशों की है, फिर भी हाल के वर्षों में रिक्ति दर अक्सर 30-40% के बीच रही है। 21 सितंबर 2026 को अधिसूचित दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (2019 से संयुक्त उच्च न्यायालय), झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति इन अंतरालों में से कुछ को भरती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे (1993) और तीसरे (1998) न्यायाधीश मामलों के जरिए औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम उम्मीदवारों की सिफारिश करता है जिसे सरकार औपचारिक रूप से पुष्टि करती है – यह प्रक्रिया अक्सर सिफारिश से पुष्टि तक कई महीने लेने के लिए आलोचना का सामना करती है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार रखते हैं, जो कुछ मायनों में सर्वोच्च न्यायालय के अपने अनुच्छेद 32 क्षेत्राधिकार से भी व्यापक है, जिससे खाली पद महंगे साबित होते हैं।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
उच्च न्यायालय रिक्ति दर	भारत के 25 उच्च न्यायालयों की संयुक्त स्वीकृत संख्या 1,114 न्यायाधीश; हाल के वर्षों में रिक्ति दर 30-40% रही।
कॉलेजियम प्रणाली	दूसरे (1993) और तीसरे (1998) न्यायाधीश मामलों से औपचारिक न्यायिक नियुक्ति तंत्र; वरिष्ठ न्यायाधीश सिफारिश करते हैं, सरकार पुष्टि करती है।
अनुच्छेद 226 बनाम अनुच्छेद 32	अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 क्षेत्राधिकार से व्यापक रिट क्षेत्राधिकार देता है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी)	कॉलेजियम को प्रतिस्थापित करने हेतु 2014 का संवैधानिक संशोधन; सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द किया।
प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी)	कॉलेजियम और सरकार के बीच न्यायिक नियुक्तियों की विस्तृत प्रक्रिया शासित करने वाला दस्तावेज़, जो अक्सर घर्षण का बिंदु रहा है।
मूल ढांचा सिद्धांत	संवैधानिक सिद्धांत (केशवानंद भारती, 1973) कि कुछ विशेषताएं, जिनमें न्यायिक स्वतंत्रता शामिल है, संसद द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती – एनजेएसी निर्णय की पृष्ठभूमि।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 शासन: कॉलेजियम प्रणाली (1993, 1998 न्यायाधीश मामले); अनुच्छेद 226 बनाम 32।
- GS3 सामाजिक: राष्ट्रीय स्तर पर 5+ करोड़ लंबित मामले; उच्च न्यायालय रिक्ति दर 30-40%।
- प्रारंभिक परीक्षा: 14 न्यायाधीश नियुक्त 21 सितंबर 2026 (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, झारखंड, कर्नाटक); 25 उच्च न्यायालय, स्वीकृत संख्या 1,114।

भारत टैक्सी सेवा शुभारंभ (उत्तर प्रदेश)

मंत्रालय: सहकारिता मंत्रालय | दिनांक: 23 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

निजी राइड-हेलिंग ऐप्स ने भारत के सबसे बड़े शहरों में गतिशीलता को बदल दिया, लेकिन उनका उद्यम पूंजी-समर्थित मॉडल, जो सबसे अधिक लाभ क्षमता वाले क्षेत्रों में आक्रामक रूप से विस्तार करता है, ने छोटे शहरों को सीमित या असंगत सेवा से वंचित छोड़ दिया है, और चालक कमीशन को लेकर बार-बार विवाद पैदा किए हैं, जो उबर और ओला जैसे प्लेटफॉर्म ऐतिहासिक रूप से प्रति सवारी 20-30% चार्ज करते रहे हैं। भारत टैक्सी, जिसे 23 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के पांच शहरों – लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज – में लॉन्च किया गया, सहकारिता मंत्रालय की सहकारी-क्षेत्र विकल्प को बढ़ावा देने की पहल के तहत आता है (यही मंत्रालय, जिसे 2021 में बनाया गया, अमूल-शैली के महासंघों के जरिए डेयरी में भी सहकारी मॉडल को बढ़ावा देता है), जो दोनों अंतरालों को एक मौलिक रूप से भिन्न स्वामित्व ढांचे के माध्यम से संबोधित करता है: एक सहकारी समिति जहां चालक-सदस्यों की सीधी हिस्सेदारी है और जो

कथित रूप से वाणिज्यिक एग्रीगेटर कमीशन ढांचे की तुलना में किराया राजस्व का अधिक हिस्सा बनाए रखते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्य टिका रहता है। यह एक वास्तव में दिलचस्प संस्थागत प्रयोग है, लेकिन वास्तविक चुनौतियां बनी हुई हैं: विश्वसनीय ऐप तकनीक और डिस्पैच सिस्टम बनाने के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है, जिसे सहकारी संरचनाएं उद्यम-पूंजी-समर्थित प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में जुटाने में अधिक कठिन पाती हैं।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
भारत टैक्सी	23 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के 5 शहरों (लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज) में सहकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च सहकारी राइड-हेलिंग सेवा।
सहकारिता मंत्रालय	2021 में गठित, डेयरी, ऋण और अब शहरी गतिशीलता (भारत टैक्सी) में सहकारी-क्षेत्र मॉडल को बढ़ावा देता है।
एग्रीगेटर कमीशन ढांचा	उबर/ओला जैसे निजी प्लेटफॉर्म आमतौर पर प्रति सवारी 20-30% कमीशन लेते हैं; भारत टैक्सी का सहकारी मॉडल चालकों के लिए अधिक हिस्सेदारी का लक्ष्य रखता है।
सहकार से समृद्धि	सहकारिता मंत्रालय का नारा/दृष्टिकोण, जो नए क्षेत्रों में सहकारी-मॉडल विस्तार को आकार देता है, जिसमें गतिशीलता भी शामिल है।
गिग इकॉनमी श्रमिक अधिकार	प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों (चालक, डिलीवरी कर्मी) के लिए सामाजिक सुरक्षा व नौकरी सुरक्षा पर जारी नीतिगत बहस, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 द्वारा आंशिक रूप से संबोधित।
अमूल मॉडल	भारत का सबसे सफल सहकारी महासंघ (डेयरी), जिसे सहकारिता मंत्रालय अन्य क्षेत्रों में दोहराने का लक्ष्य रखता है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 अर्थव्यवस्था: सहकारी बनाम उद्यम-पूंजी-समर्थित गतिशीलता मॉडल; चालक कमीशन अर्थशास्त्र।
- GS2 शासन: सहकारिता मंत्रालय (2021) और इसका क्षेत्रीय विस्तार।
- प्रारंभिक परीक्षा: भारत टैक्सी लॉन्च 23 सितंबर 2026; 5 उत्तर प्रदेश शहर; सहकारिता मंत्रालय 2021 में गठित।

कांदा एक्सप्रेस और खाद्य सुरक्षा

मंत्रालय: उपभोक्ता मामले मंत्रालय | दिनांक: 23 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत में प्याज की कीमतें एक सीजन के भीतर असामान्य रूप से तेजी से बदलती हैं, क्योंकि उत्पादन कुछ राज्यों में केंद्रित है – अकेले महाराष्ट्र राष्ट्रीय उत्पादन का 40% से अधिक हिस्सा रखता है – और असमय बारिश से हुई मामूली

कमी, प्याज के खराब भंडारण गुणों के साथ मिलकर, हफ्तों के भीतर खुदरा कीमतों को लगभग 20-30 रुपये/किलो से बढ़ाकर 80-100 रुपये/किलो से अधिक कर सकती है। इसे प्रबंधित करने के लिए, नैफेड और एनसीसीएफ संयुक्त रूप से एक सामरिक बफर स्टॉक बनाए रखते हैं, जिसका वर्तमान लक्ष्य लगभग 5 लाख टन वार्षिक है, जो रबी फसल की अधिकता के दौरान खरीदा जाता है और कमी की अवधि में आपूर्ति बढ़ाने तथा कीमतें नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। कांदा एक्सप्रेस, जो 23-24 सितंबर 2026 को बफर-स्टॉक प्याज को कोलकाता ले जाने के लिए तैनात की गई एक विशेष ट्रेन है, यह सुनिश्चित करती है कि भंडार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे उत्पादक राज्यों में पड़े रहने के बजाय पश्चिम बंगाल के कमी वाले बाजारों तक पहुंचे। एक पूर्ण तस्वीर वास्तविक सीमाओं को भी दर्ज करती है: बेहतर भंडारण स्थितियों के बावजूद प्याज में अंकुरण और सड़न से आमतौर पर 20-30% भंडारण हानि होती है, जिसका अर्थ है कि बफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपभोक्ताओं तक कभी नहीं पहुंच पाता, और रिलीज का समय कभी-कभी प्रतिक्रियात्मक होने के लिए आलोचना का शिकार हुआ है – यानी केवल तभी प्रतिक्रिया देना जब कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हों।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
नैफेड / एनसीसीएफ	राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ; संयुक्त रूप से भारत का प्याज बफर स्टॉक (~5 लाख टन) प्रबंधित करते हैं।
प्याज बफर स्टॉक	रबी फसल अधिकता के दौरान खरीदा गया ~5 लाख टन, कमी के दौरान जारी; अंकुरण/सड़न से 20-30% भंडारण हानि होती है।
महाराष्ट्र की प्याज हिस्सेदारी	महाराष्ट्र भारत के प्याज उत्पादन का 40% से अधिक हिस्सा रखता है, जिससे राष्ट्रीय आपूर्ति राज्य-विशिष्ट मौसम झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)	चुनिंदा फसलों के लिए सरकार-गारंटीड मूल्य फर्श; प्याज उल्लेखनीय रूप से एमएसपी के तहत नहीं है, जिससे यह गेहूं-चावल जैसी एमएसपी-कवर फसलों से अधिक अस्थिर है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और भंडारण को विनियमित करने का अधिकार देने वाला कानून, जमाखोरी से बचाव हेतु।
प्याज पर निर्यात प्रतिबंध/शुल्क	मूल्य वृद्धि के दौरान घरेलू आपूर्ति प्राथमिकता हेतु भारत का आवधिक व्यापार प्रतिबंध उपकरण, हालांकि इससे किसानों की निर्यात आय प्रभावित होती है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 नीति: नैफेड/एनसीसीएफ बफर स्टॉक तंत्र; मूल्य स्थिरीकरण बनाम मूल्य नियंत्रण।
- GS3 अर्थव्यवस्था: महाराष्ट्र की 40%+ हिस्सेदारी; 20-30% भंडारण हानि।
- प्रारंभिक परीक्षा: कांदा एक्सप्रेस कोलकाता, 23-24 सितंबर 2026; बफर लक्ष्य ~5 लाख टन; महाराष्ट्र >40% उत्पादन।

वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 (भारत का दल)

मंत्रालय: कौशल विकास मंत्रालय | दिनांक: 24 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

वर्ल्डस्किल्स, जिसे अक्सर वोकेशनल कौशल का 'ओलंपिक' कहा जाता है, एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है जो पहली बार 1950 में आयोजित हुई और अब 85 से अधिक सदस्य देशों को शामिल करती है, जहां युवा प्रतिभागी 60 से अधिक कौशल श्रेणियों में कठोर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारत, जो 2011 से वर्ल्डस्किल्स का सदस्य है, ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल – 60 से अधिक प्रतियोगी – शंघाई 2026 भेजा। पिछले संस्करण, ल्योन 2024 में, भारत ने कुल 8 पदक जीते जिसमें 1 स्वर्ण शामिल है, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, और शंघाई 2026 को इस बात की परीक्षा के रूप में देखा गया कि क्या उस सुधार को बनाए रखा जा सकता है। यह दो कारणों से मायने रखता है: पहला, यह घरेलू वोकेशनल प्रशिक्षण पर एक बाहरी रूप से सत्यापित गुणवत्ता जांच के रूप में कार्य करता है, जो 2009 में स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से भारत में संचालित होता है; दूसरा, यह एक गहरी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह को संबोधित करता है, क्योंकि भारत की शिक्षा संस्कृति ने लंबे समय से वोकेशनल ट्रेडों की तुलना में अकादमिक डिग्री को अधिक महत्व दिया है, भले ही देश कुशल श्रमिकों की कमी के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्नातक बेरोजगारी का सामना कर रहा हो।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता	वैश्विक द्विवार्षिक वोकेशनल कौशल प्रतियोगिता, पहली बार 1950 में आयोजित; 85+ सदस्य देश; भारत 2011 से सदस्य।
भारत का ल्योन 2024 प्रदर्शन	भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ वर्ल्डस्किल्स परिणाम: 2024 ल्योन संस्करण में 1 स्वर्ण सहित 8 पदक, शंघाई 2026 का मानदंड।
एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, 2009 में स्थापित, भारत के वोकेशनल प्रशिक्षण इकोसिस्टम और वर्ल्डस्किल्स भागीदारी का समन्वयक निकाय।
राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ)	वोकेशनल योग्यताओं को कौशल स्तर (1-10) के अनुसार श्रेणीबद्ध करने वाला भारत का ढांचा, वोकेशनल और अकादमिक प्रमाणपत्रों में समानता सक्षम करता है।
सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी)	उद्योग-नेतृत्व वाले निकाय जो विशिष्ट क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक मानक तय करते हैं, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे में योगदान करते हैं।

स्किल इंडिया डिजिटल हब

कौशल, प्रशिक्षुता और नौकरी-मिलान के लिए सरकार का एकीकृत डिजिटल मंच, वर्ल्डस्किल्स तैयारी को सहयोग देने वाले व्यापक इकोसिस्टम का हिस्सा।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 शिक्षा: एनएसडीसी (2009); भारत की वर्ल्डस्किल्स सदस्यता 2011 से।
- GS2 शासन: भारत के श्रम बाजार में वोकेशनल बनाम अकादमिक प्रतिष्ठा अंतर।
- प्रारंभिक परीक्षा: वर्ल्डस्किल्स पहली बार 1950; भारत सदस्य 2011 से; ल्योन 2024 सर्वश्रेष्ठ 8 पदक/1 स्वर्ण; शंघाई 2026 भारत का सबसे बड़ा दल।

आरोग्य मंथन 2026 (स्वास्थ्य योजना समीक्षा)

मंत्रालय: स्वास्थ्य मंत्रालय | दिनांक: 25 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

25 सितंबर को आयोजित आरोग्य मंथन 2026 ने दो महत्वपूर्ण वर्षगांठों को चिह्नित किया: 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई आयुष्मान भारत पीएम-जय के आठ वर्ष, और 27 सितंबर 2021 को शुरू हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के पांच वर्ष। पीएम-जय स्वास्थ्य देखभाल पहुंच के वित्तीय पहलू को संबोधित करता है, जो 12 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों (लगभग 55 करोड़ लोगों) को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक अस्पताल में भर्ती कवरेज प्रदान करता है, जिसमें 27 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और 8 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती अधिकृत हुई हैं, जो उस विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय को लक्षित करता है जो ऐतिहासिक रूप से परिवारों को गरीबी में धकेलता था। एबीडीएम एक अलग समस्या को संबोधित करता है: स्वास्थ्य डेटा का विखंडन, जहां एक मरीज के रिकॉर्ड विभिन्न प्रदाताओं में बिखरे होते थे बिना आसान साझाकरण के, जिससे बार-बार परीक्षण दोहराने पड़ते थे और अधूरे इतिहास से त्रुटि का जोखिम बढ़ता था। एबीडीएम 2026 तक बनाए गए 75 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) आईडी के जरिए सहमति के साथ रिकॉर्ड साझा करने में सक्षम बनाता है। साथ मिलकर ये दोनों वित्तीय सुरक्षा और सूचना बुनियादी ढांचे को पूरक स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, हालांकि पीएम-जय का बीमा कवरेज उन जिलों में बहुत कम मायने रखता है जहां पर्याप्त अस्पताल और विशेषज्ञ भौतिक रूप से उपलब्ध ही नहीं हैं।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
आयुष्मान भारत पीएम-जय	23 सितंबर 2018 को शुरू; 12+ करोड़ परिवार (~55 करोड़ लोग) कवर; 5 लाख रुपये/परिवार/वर्ष; 27+ करोड़ कार्ड जारी।

एबीडीएम / एबीएचए	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, 27 सितंबर 2021 को शुरू; आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी, 2026 तक 75+ करोड़ बनी।
विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय	इतना गंभीर चिकित्सा व्यय कि परिवार गरीबी में धकेला जाए; पीएम-जय का मूल लक्षित समस्या।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र)	आयुष्मान भारत का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा घटक, पीएम-जय के अस्पताल-बीमा फोकस को निवारक व प्राथमिक देखभाल से पूरक बनाता है।
जेब से स्वास्थ्य व्यय (ओओपीई)	बीमा या सरकार की बजाय मरीज़ द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा; भारत का ओओपीई, घटने के बावजूद, वैश्विक साथियों की तुलना में अधिक बना हुआ है।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी)	डब्ल्यूएचओ द्वारा परिभाषित लक्ष्य कि सभी लोग वित्तीय कठिनाई के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सकें; पीएम-जय व एबीडीएम इसके दो स्तंभ।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 स्वास्थ्य: पीएम-जय (2018, 55 करोड़ लाभार्थी); एबीडीएम/एबीएचए (2021, 75+ करोड़ आईडी)।
- GS3 प्रौद्योगिकी: एबीएचए स्वास्थ्य डेटा इंटरऑपरेबिलिटी बुनियादी ढांचे के रूप में।
- प्रारंभिक परीक्षा: पीएम-जय शुभारंभ 23 सितंबर 2018; एबीडीएम शुभारंभ 27 सितंबर 2021; 27+ करोड़ आयुष्मान कार्ड; 75+ करोड़ एबीएचए आईडी।

भारत-नीदरलैंड जल भागीदारी (आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू 2026)

मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय | दिनांक: 22 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारत की जल चुनौतियां गंभीर हैं: केंद्रीय भूजल बोर्ड भारत की लगभग 7,000 भूजल आकलन इकाइयों में से 1,000 से अधिक को 'अति-दोहित' या 'गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत करता है, जो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में केंद्रित है, जो दशकों के अस्थिर दोहन का परिणाम है, मुख्यतः जल-गहन धान की खेती के लिए।

नीदरलैंड, केवल 41,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला देश होते हुए भी, जिसका लगभग 26% भूभाग समुद्र तल से नीचे है, वैश्विक रूप से जल प्रबंधन में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उसने पिछले 70 वर्षों में अपनी डेल्टा वर्क्स परियोजना के माध्यम से परिष्कृत बाढ़ नियंत्रण और जल-दक्षता विशेषज्ञता विकसित की है। भारत-नीदरलैंड भागीदारी, जिसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 (22-24 सितंबर, 2015 से प्रतिवर्ष आयोजित) के दौरान औपचारिक रूप दिया गया, इस विशेषज्ञता को भारत की सटीक-कृषि और बाढ़-प्रबंधन आवश्यकताओं तक लाती है, जो 2014 में हस्ताक्षरित एक मौजूदा द्विपक्षीय समझौता जापन पर आधारित है। एक पूर्ण तस्वीर के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा को पहचानना जरूरी है: भारत के भूजल संकट का अधिकांश हिस्सा घरेलू नीतिगत विकल्पों से उपजा है, विशेष रूप से पंजाब जैसे राज्यों में कृषि पंपिंग

के लिए लगभग मुफ्त बिजली, जो अत्यधिक दोहन के खिलाफ किसी भी निरुत्साहन को हटा देती है – यह समस्या आयातित डच तकनीकी विशेषज्ञता से हल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए भारत के अपने कठिन घरेलू सब्सिडी और फसल-मूल्य निर्धारण सुधार की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
अति-दोहित भूजल इकाइयां	केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भारत की ~7,000 आकलन इकाइयों में से 1,000+ को अति-दोहित/गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में।
डेल्टा वर्क्स	नीदरलैंड की 70 वर्षों में विकसित बाढ़-नियंत्रण बुनियादी ढांचा परियोजना, उसकी वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त जल-प्रबंधन विशेषज्ञता का स्रोत।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह	2015 से आयोजित वार्षिक आयोजन; 2026 संस्करण (22-24 सितंबर) ने भारत-नीदरलैंड जल भागीदारी को औपचारिक रूप दिया, 2014 के द्विपक्षीय समझौते पर आधारित।
अटल भूजल योजना	विश्व बैंक-समर्थित केंद्रीय योजना (2020) जो पंजाब और हरियाणा जैसे अति-दोहित राज्यों में सामुदायिक-नेतृत्व वाले सतत भूजल प्रबंधन के लिए है।
जल जीवन मिशन	2019 में शुरू प्रमुख योजना जिसका लक्ष्य देशव्यापी कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन है, भारत का वर्तमान सबसे बड़ा जल-क्षेत्र कार्यक्रम।
केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)	जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय निकाय जो भारत की भूजल आकलन इकाइयों की स्थिति की निगरानी व वर्गीकरण करता है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 जल: 1,000+ अति-दोहित भूजल इकाइयां (सीजीडब्ल्यूबी); पंजाब की मुफ्त कृषि बिजली मूल कारण के रूप में।
- GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत-नीदरलैंड जल एमओयू (2014); डेल्टा वर्क्स वैश्विक मानदंड के रूप में।
- प्रारंभिक परीक्षा: आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू 2015 से; 2026 संस्करण 22-24 सितंबर; सीजीडब्ल्यूबी ने ~7,000 में से 1,000+ इकाइयों को अति-दोहित बताया।

विशेष अभियान 6.0 (प्रशासनिक दक्षता)

मंत्रालय: प्रशासनिक सुधार विभाग | दिनांक: 19 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

सरकारी कार्यालयों में समय के साथ परिचालन अक्षमता जमा होती जाती है: फाइलें और लंबित मामले ढेर हो जाते हैं, पुराने और अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अनुपयोगी पड़े रहते हैं, और भौतिक स्थान धीरे-धीरे अव्यवस्थित हो जाते हैं।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा 2021 से प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला विशेष अभियान 2026 में अपने 6.0 संस्करण तक पहुंच गया, जो एक निश्चित बहु-सप्ताह की अवधि (पिछले संस्करण लगभग 2-4 सप्ताह चले) के लिए चलता है, जिसमें हर मंत्रालय और विभाग से लंबित मामलों और सार्वजनिक शिकायतों के एक निर्दिष्ट बैकलॉग को साफ करने, प्रमाणित रीसाइक्लरों के माध्यम से संचित ई-कचरे का निपटान करने, और कार्यालय स्थान खाली करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें अकेले 2023 के संस्करण (विशेष अभियान 3.0) ने कथित तौर पर स्क्रेप और ई-कचरा निपटान से 370 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व उत्पन्न किया और राष्ट्रीय स्तर पर 900 लाख वर्ग फुट से अधिक कार्यालय स्थान खाली कराया। ये आंकड़े वास्तविक, मापने योग्य परिणाम दर्शाते हैं: तेज़ मामला समाधान उन नागरिकों को लाभ पहुंचाता है जो वर्षों से निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रमाणित ई-कचरा निपटान सीसा और पारे जैसे विषाक्त पदार्थों को मिट्टी और भूजल को दूषित करने से रोकता है। वास्तविक सीमा, जो इस बात से स्पष्ट होती है कि 6वें संस्करण की अभी भी जरूरत है, यह है कि अपर्याप्त स्टाफिंग या पुरानी प्रक्रियाओं जैसे अंतर्निहित कारणों को संबोधित किए बिना, बैकलॉग के फिर से जमा होने का जोखिम बना रहता है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
विशेष अभियान (डीएआरपीजी)	2021 से वार्षिक प्रशासनिक दक्षता अभियान; 2026 में 6.0 संस्करण; प्रत्येक 2-4 सप्ताह चलता है, लंबित मामलों, ई-कचरे और कार्यालय स्थान को लक्षित करता है।
विशेष अभियान 3.0 परिणाम (2023)	कथित तौर पर स्क्रेप/ई-कचरा निपटान से 370+ करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न किया और राष्ट्रीय स्तर पर 900+ लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया।
डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, 2021 से विशेष अभियान संस्करण चलाने वाली नोडल संस्था।
सीपीग्राम्स	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली, डीएआरपीजी का डिजिटल मंच जो नागरिक शिकायतों को ट्रैक व हल करता है।
ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022	इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रमाणित निपटान/पुनर्चक्रण को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा, जिसका पालन विशेष अभियान संस्करणों में सरकारी कार्यालयों से अपेक्षित है।
न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन	प्रशासनिक दक्षता और कम लालफीताशाही पर जोर देने वाला शासन दर्शन, जिसके तहत विशेष अभियान जैसी पहलें आती हैं।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 शासन: डीएआरपीजी; विशेष अभियान आवर्ती (2021 से) समय-बद्ध सुधार उपकरण के रूप में।

- GS3 पर्यावरण: प्रमाणित ई-कचरा निपटान; 2023 संस्करण ने 370+ करोड़ उत्पन्न किया, 900+ लाख वर्ग फुट खाली कराया।
- प्रारंभिक परीक्षा: विशेष अभियान 6.0, 2026; डीएआरपीजी; पहला संस्करण 2021; अभियान 3.0 (2023) ने 370+ करोड़ उत्पन्न किया।

नई ट्रेन सेवाओं का विस्तार

मंत्रालय: रेल मंत्रालय | दिनांक: 25 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

भारतीय रेलवे, जो लगभग 68,000 रूट किलोमीटर संचालित करता है और प्रतिदिन 2.4 करोड़ से अधिक यात्रियों को ढोता है, ने 25 सितंबर 2026 को तीन नई सेवाओं को मंजूरी दी, जिनमें से प्रत्येक एक अलग अंतराल को संबोधित करती है: कानपुर-आनंद विहार दैनिक सेवा, भुज-बरौनी त्रि-साप्ताहिक सेवा जो गुजरात से बिहार तक लगभग 2,000 किलोमीटर तक फैली है, और मौजूदा वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस का झांसी-मथुरा विस्तार, जो मथुरा – भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक, जहां प्रति वर्ष कई करोड़ आगंतुक आते हैं – के लिए तीर्थयात्री यातायात हेतु लगभग 200 किलोमीटर जोड़ता है। मौजूदा पटरियों और स्टेशनों पर सेवाएं जोड़ना समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का कुल निवेश) या हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं जैसे बड़े नए बुनियादी ढांचे की तुलना में अपेक्षाकृत तेज़ और सस्ता है, जिन्हें वर्षों और भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे रेलवे प्रणाली नई निर्माण की प्रतीक्षा किए बिना विशिष्ट पहचानी गई कमियों पर तेज़ी से प्रतिक्रिया दे सकती है। रेलवे कम संपन्न भारतीयों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि टिकट की कीमतें हवाई यात्रा की तुलना में एक अंश मात्र होती हैं, जिसका अर्थ है कि ऐसे संपर्क सुधार असमान रूप से उस जनसंख्या वर्ग को लाभान्वित करते हैं जो विकल्पों को वहन करने में सबसे कम सक्षम है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
भारतीय रेलवे का पैमाना	~68,000 रूट किलोमीटर संचालित करता है, प्रतिदिन 2.4 करोड़ से अधिक यात्री; नई सेवाएं 25 सितंबर 2026 को स्वीकृत।
भुज-बरौनी मार्ग	गुजरात से बिहार तक ~2,000 किमी फैली त्रि-साप्ताहिक सेवा, तीन नई स्वीकृत सेवाओं में से एक।
मथुरा तीर्थयात्री यातायात	भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक, प्रति वर्ष कई करोड़ आगंतुक; नए झांसी-मथुरा रेल विस्तार से सेवित।
समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी)	भारत का ~2,800 किमी का केवल-माल ढुलाई रेल नेटवर्क (पूर्वी व पश्चिमी डीएफसी), ~1.2 लाख करोड़ रुपये निवेश, माल और यात्री यातायात को अलग करता है।

अमृत भारत स्टेशन योजना	1,300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से उन्नत करने वाला रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम, नई सेवा विस्तार के साथ चल रहा।
राष्ट्रीय रेल योजना 2030	रेल माल ढुलाई हिस्सेदारी बढ़ाने और नेटवर्क क्षमता विस्तार को लक्षित करने वाला भारतीय रेलवे का दीर्घकालिक दृष्टिकोण दस्तावेज़।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 बुनियादी ढांचा: भारतीय रेलवे पैमाना (68,000 आरकेएम, 2.4 करोड़ दैनिक यात्री); समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (~1.2 लाख करोड़)।
- GS2 क्षेत्रीय विकास: तीर्थयात्रा-संबंधित संपर्क; कम आय वाले यात्रियों के लिए किफायती दर।
- प्रारंभिक परीक्षा: 3 सेवाएं स्वीकृत 25 सितंबर 2026: कानपुर-आनंद विहार (दैनिक), भुज-बरौनी (त्रि-साप्ताहिक, ~2,000 किमी), झांसी-मथुरा विस्तार।

अग्निकुल कॉसमॉस आरडीआई सहायता (पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान)

मंत्रालय: विज्ञान मंत्रालय | दिनांक: 25 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

रॉकेट पारंपरिक रूप से एकल-उपयोग रहे हैं: सैकड़ों करोड़ रुपये की लागत वाला रॉकेट बनाया जाता है, एक बार प्रक्षेपित किया जाता है, और फिर त्याग दिया जाता है – एक उड़ान के बाद पूरे विमान को नष्ट करने जैसा। एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान इसके बजाय उड़ान भरता है, सुरक्षित रूप से उतरता है, उसकी मरम्मत होती है, और फिर से उड़ान भरता है, जिससे इसकी उच्च लागत कई मिशनों में बंट जाती है – यह वह नवाचार है जिसे स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 के साथ अग्रणी बनाया, जिसने 300 से अधिक सफल बूस्टर लैंडिंग पूरी की हैं। अग्निकुल कॉसमॉस, आईआईटी मद्रास में इनक्यूबेट और 2017 में स्थापित एक चेन्नई-आधारित निजी अंतरिक्ष स्टार्ट-अप, अग्निबाण नामक एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित कर रहा है, जो अपने 3डी-प्रिंटेड, एकल-टुकड़े वाले सेमी-क्रायोजेनिक इंजन 'अग्निलेट' के लिए उल्लेखनीय है, और अब उसे 25 सितंबर 2026 को भारत के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से 200 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है ताकि पुनः प्रयोज्य संस्करण को आगे बढ़ाया जा सके। यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बदलती संरचना को दर्शाता है: 2020 के अंतरिक्ष-क्षेत्र सुधारों के बाद, जिसने इसरो के लगभग-एकाधिकार को समाप्त किया और निजी अंतरिक्ष गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए इन-स्पेस बनाया, इस तरह की सरकारी वित्त पोषण सहायता इस बात की मान्यता का संकेत देती है कि निजी उद्यमों को व्यावसायिक व्यवहार्यता से पहले लंबी विकास अवधि से गुजरने के लिए धैर्यवान पूंजी की आवश्यकता होती है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
अग्निकुल कॉसमॉस	चेन्नई-आधारित, आईआईटी मद्रास-इनक्यूबेटेड अंतरिक्ष स्टार्ट-अप, 2017 में स्थापित; 3डी-प्रिंटेड अग्निलेट इंजन के साथ अग्निबाण रॉकेट विकसित कर रहा है।
इन-स्पेस	भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, 2020 के अंतरिक्ष सुधारों के बाद बना जिसने इसरो के एकाधिकार को समाप्त किया, निजी अंतरिक्ष गतिविधि का नियामक।
स्पेसएक्स फाल्कन 9 मानदंड	पुनः प्रयोज्यता का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, 300+ सफल बूस्टर लैंडिंग पूरी; अग्निकुल के पुनः प्रयोज्य अग्निबाण का लक्ष्य मॉडल।
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल)	इसरो की वाणिज्यिक शाखा, प्रक्षेपण सेवाओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का विपणन करती है, इन-स्पेस के साथ मिलकर निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को सहयोग देती है।
सेमी-क्रायोजेनिक इंजन	अग्निकुल के अग्निलेट जैसा रॉकेट इंजन प्रकार, परिष्कृत केरोसिन और तरल ऑक्सीजन के संयोजन का उपयोग करता है, पूर्ण क्रायोजेनिक इंजनों की तुलना में सरल हैंडलिंग देता है।
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सांविधिक निकाय, जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे अग्निकुल को 200 करोड़ रुपये का अनुदान।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 विज्ञान: 2020 अंतरिक्ष सुधार; इन-स्पेस; अग्निकुल (2017, आईआईटी मद्रास)।
- GS2 रणनीतिक स्वायत्तता: भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र बनाम स्पेसएक्स जैसे स्थापित खिलाड़ी।
- प्रारंभिक परीक्षा: अग्निकुल कॉसमॉस 2017 में स्थापित; 200 करोड़ रुपये टीडीबी अनुदान 25 सितंबर 2026; अग्निबाण इंजन का नाम अग्निलेट।

SITOK IAS

ब्रिक्स कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय | दिनांक: 23 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

कई देशों में परिचालन करने वाली बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जानबूझकर अपने मुनाफे की संरचना इस तरह बना सकती हैं कि आय वहां दर्ज हो जहां कर दरें सबसे कम हों, यह एक ऐसी प्रथा है जिसे 'आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण' (बीईपीएस) कहा जाता है – यह शब्द और ढांचा ओईसीडी द्वारा 2013 से विकसित किया गया – जो देशों को उनकी वास्तविक आर्थिक गतिविधि से उत्पन्न होने वाले राजस्व से वंचित करता है। नई दिल्ली में 23 सितंबर 2026 को आयोजित और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उद्घाटित ब्रिक्स कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक ने अब 10-सदस्यीय ब्रिक्स समूह (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, तथा 2024 के विस्तार के बाद मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई

और सऊदी अरब पर्यवेक्षक के रूप में) के अधिकारियों को प्रवर्तन समन्वय के लिए एक साथ लाया, जिसमें बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट संरचनाओं की जानकारी साझा करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था लेनदेन पर कर लगाने के लिए सुसंगत नियम तलाशना शामिल है। ब्रिक्स देश सामूहिक रूप से क्रय शक्ति समता के आधार पर वैश्विक जीडीपी का 35% से अधिक और विश्व की जनसंख्या का 45% से अधिक हिस्सा रखते हैं, जो इसके समन्वित सौदेबाजी के भार का आधार है। यह समझना महत्वपूर्ण सीमा है कि परिष्कृत कर-चोरी रणनीतियां आमतौर पर पूरी वैश्विक कर प्रणाली में अंतरों का लाभ उठाती हैं, इसलिए केवल ब्रिक्स सदस्यों तक सीमित समन्वय गैर-ब्रिक्स कम-कर क्षेत्राधिकारों से गुजरने वाली खामियों को पूरी तरह बंद नहीं कर सकता।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
बीईपीएस	आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण; बहुराष्ट्रीय कर चोरी रणनीतियों का मुकाबला करने हेतु 2013 से विकसित ओईसीडी ढांचा।
ब्रिक्स (विस्तारित)	2024 विस्तार के बाद 10-सदस्यीय समूह: मूल ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, साथ ही मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब (पर्यवेक्षक)।
ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति	सामूहिक रूप से वैश्विक जीडीपी (पीपीपी शर्तों) का 35% से अधिक और विश्व जनसंख्या का 45% से अधिक, इसकी समन्वित सौदेबाजी शक्ति का आधार।
वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर	ओईसीडी-मध्यस्थ 2021 समझौता (~140 देश) 15% न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के लिए, कर पनाहगाहों में मुनाफा स्थानांतरण रोकने हेतु।
नया विकास बैंक (एनडीबी)	ब्रिक्स का अपना बहुपक्षीय विकास बैंक (2014 में स्थापित, मुख्यालय शंघाई), विश्व बैंक/आईएमएफ का ब्रिक्स का मुख्य संस्थागत समकक्ष।
दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीए)	एक ही आय पर दो देशों में दोहरा कराधान रोकने वाली द्विपक्षीय संधियां; बीईपीएस-शैली बहुपक्षीय समन्वय से अलग लेकिन संबंधित उपकरण।

LESS NOISE. MORE RETENTION.

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 अंतराष्ट्रीय संबंध: ब्रिक्स विस्तार (2024, 10 सदस्य); भारत की मेजबानी भूमिका।
- GS3 अर्थव्यवस्था: बीईपीएस (ओईसीडी, 2013); ब्रिक्स >35% वैश्विक जीडीपी (पीपीपी)।
- प्रारंभिक परीक्षा: ब्रिक्स कर बैठक, नई दिल्ली, 23 सितंबर 2026; वित्त मंत्री सीतारामण ने उद्घाटन किया; ब्रिक्स 2024 से 10 सदस्य।

उपासी चाय अनुसंधान शताब्दी सम्मेलन

मंत्रालय: कृषि मंत्रालय | दिनांक: 21 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

उपासी, जिसकी स्थापना 1893 में कुन्नूर, तमिलनाडु में हुई, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के नीलगिरि, वायनाड और कूर्ग उगाने वाले क्षेत्रों में चाय, और कुछ हद तक कॉफी व रबर, बागान मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख निकाय है। इसके चाय अनुसंधान फाउंडेशन का सम्मेलन, जो 21 सितंबर 2026 को आयोजित हुआ – फाउंडेशन की स्वयं स्थापना 1926 में हुई थी, जिससे 2026 उसकी अपनी शताब्दी बन जाती है – ने अनुसंधान की इस शताब्दी को गंभीर आधुनिक चुनौतियों की चर्चा के साथ जोड़ा: दक्षिण भारतीय चाय, मुख्यतः सीटीसी (क्रश-टियर-कर्ल) ग्रेड, का उत्पादन पिछले एक दशक में लगभग 22-23 करोड़ किलोग्राम वार्षिक पर स्थिर रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन अनियमित मानसून और बढ़ते तापमान ला रहा है जो उपज और निर्यात मूल्य निर्धारण दोनों को खतरे में डालते हैं। इसके साथ ही, वैश्विक मांग जैविक, टिकाऊ, सुगमता से पता लगाए जा सकने वाले उत्पादों की ओर स्थानांतरित हो गई है – प्रीमियम मूल्य निर्धारण का एक वास्तविक अवसर, लेकिन जैविक परिवर्तन में आमतौर पर लगभग 3 वर्ष का प्रमाणन विलंब लगता है जिसके दौरान उपज में 15-20% की गिरावट आ सकती है, जिससे ठीक उसी समय आय पर दबाव बनता है जब किसान इस परिवर्तन में निवेश कर रहे होते हैं। यह बागान मालिकों से परे भी मायने रखता है, क्योंकि दक्षिण भारत का चाय क्षेत्र 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें अधिकांश महिला बागान श्रमिक हैं।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
उपासी	दक्षिण भारतीय बागान मालिक संघ, 1893 में कुन्नूर, तमिलनाडु में स्थापित; चाय, कॉफी, रबर उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है।
चाय अनुसंधान फाउंडेशन	उपासी की अनुसंधान शाखा, 1926 में स्थापित, 2026 में अपनी शताब्दी मना रही, हालिया सम्मेलन का अवसर।
दक्षिण भारत चाय उत्पादन	मुख्यतः सीटीसी-ग्रेड चाय; पिछले दशक में उत्पादन लगभग 22-23 करोड़ किलोग्राम/वर्ष पर स्थिर; जैविक परिवर्तन में ~3 वर्ष में 15-20% उपज गिरावट।
चाय बोर्ड ऑफ इंडिया	वाणिज्य मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय जो भारत के चाय उद्योग – उत्पादन, निर्यात संवर्धन, गुणवत्ता मानक – को उपासी जैसी निजी संस्थाओं के साथ नियंत्रित करता है।
भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग	दार्जिलिंग चाय व नीलगिरि चाय जैसे क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों के लिए कानूनी सुरक्षा, उपासी की निर्यात रणनीति चर्चाओं से संबंधित प्रीमियम-पोजिशनिंग उपकरण।
प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951	बागान श्रमिकों के लिए कल्याण स्थितियां शासित करने वाला कानून, दक्षिण भारत के 20 लाख से अधिक, बहुसंख्यक महिला, चाय क्षेत्र कार्यबल के लिए प्रासंगिक।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS3 कृषि: उपासी (1893); चाय अनुसंधान फाउंडेशन शताब्दी (1926-2026); जैविक परिवर्तन में उपज व्यापार-बंद।
- GS2 क्षेत्रीय: दक्षिण भारत में 20 लाख+ चाय क्षेत्र नौकरियां, अधिकांश महिला बागान श्रमिक।
- प्रारंभिक परीक्षा: उपासी स्थापना 1893, कुन्नूर; चाय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापना 1926 (शताब्दी 2026); दक्षिण भारत उत्पादन ~22-23 करोड़ किग्रा/वर्ष।

सीसीआई प्रतिस्पर्धा कानून अनुमोदन

मंत्रालय: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय | दिनांक: 23 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

जब एक कंपनी दूसरी को खरीदती है, तो यह समेकन स्वस्थ हो सकता है, जिससे पैमाने की दक्षता और नवाचार संभव होता है, लेकिन यह इतनी अत्यधिक प्रभुत्व वाली फर्म भी बना सकता है कि उसे वास्तविक प्रतिस्पर्धा का सामना ही न करना पड़े। सीसीआई, जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया और जो 2009 से परिचालन में है, निर्दिष्ट परिसंपत्ति या टर्नओवर सीमा से अधिक के विलयों की समीक्षा करता है – वर्तमान में भारत में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक संयुक्त परिसंपत्ति मूल्य या 6,000 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर, जिसे 2024 में संशोधित करके 'डील वैल्यू' सीमा भी जोड़ी गई ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था के अधिग्रहणों को भी पकड़ा जा सके जो पुराने मानदंडों से बच सकते थे। ल'ओरियल के ओनेस्टो लैब्स (सौंदर्य प्रसाधन) अधिग्रहण और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज (वित्तीय सेवा) लेनदेन के हालिया अनुमोदन, दोनों सीसीआई की मानक 30-कार्य-दिवस चरण-1 समीक्षा अवधि के भीतर स्वीकृत हुए, यह दर्शाते हैं कि यह प्रणाली इच्छित रूप से काम कर रही है: बिना किसी महत्वपूर्ण एकाग्रता जोखिम वाले लेनदेन के लिए तेज़ मंजूरी। यह नियामक दक्षता भारत के निवेश माहौल के लिए मायने रखती है, क्योंकि व्यवसायों को यह विश्वास चाहिए कि अनुमोदन प्रक्रियाएं तेज़ और अनुमानित हैं; सीसीआई की अधिकांश अधिसूचित संयोजनों के लिए चरण-1 मंजूरी दर, जिसमें केवल एक छोटा हिस्सा अधिक विस्तृत चरण-11 जांच की आवश्यकता रखता है, यह दर्शाती है कि प्रणाली वास्तव में नियमित समेकन को गहरी जांच योग्य दुर्लभ मामलों से अलग करने के लिए अंशांकित है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित, 2009 से परिचालन में।
विलय अधिसूचना सीमाएं	भारत में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक संयुक्त परिसंपत्ति या 6,000 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर; 2024 संशोधन में डिजिटल सौदों के लिए 2,000 करोड़ रुपये 'डील वैल्यू' सीमा जोड़ी गई।

चरण-I / चरण-II समीक्षा	सीसीआई की मानक 30-कार्य-दिवस चरण-I समीक्षा अधिकांश विलयों को मंजूरी देती है; केवल एक छोटा हिस्सा गहन चरण-II जांच की आवश्यकता रखता है।
प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग	सीसीआई प्रवर्तन की एक अलग श्रेणी (विलय समीक्षा से भिन्न) जो पहले से प्रभावी फर्मों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण को लक्षित करती है।
कार्टेलीकरण	प्रतिस्पर्धी फर्मों के बीच कीमत तय करने या उत्पादन सीमित करने का अवैध समन्वय; सीसीआई प्रवर्तन का एक और मुख्य क्षेत्र, विलय जांच से परे।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002	पुराने एमआरटीपी अधिनियम, 1969 का स्थान लेने वाला; सीसीआई और उसके विलय-समीक्षा, कार्टेल व प्रभुत्व प्रावधानों को स्थापित करने वाला भारत का आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून ढांचा।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 शासन: सीसीआई (2002 अधिनियम, परिचालन 2009); 2024 डील-वैल्यू सीमा सुधार।
- GS3 अर्थव्यवस्था: चरण-I (30 दिन) बनाम चरण-II समीक्षा; डिजिटल अर्थव्यवस्था विलय जांच।
- प्रारंभिक परीक्षा: सीसीआई स्थापना 2009, 2002 अधिनियम के तहत; सीमाएं 2,000 करोड़/6,000 करोड़ रुपये; 2024 में डील-वैल्यू परीक्षण जोड़ा गया।

पीआईबी बैकग्राउंडर और विशेष विषय

मंत्रालय: प्रेस सूचना ब्यूरो | दिनांक: 19-25 सितंबर 2026

सरल भाषा में समझें

नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के साथ-साथ, पीआईबी समय-समय पर लंबे बैकग्राउंडर प्रकाशित करता है जो एक संक्षिप्त घोषणा से कहीं अधिक गहराई प्रदान करते हैं। इस सप्ताह के ग्यारह बैकग्राउंडर में मेक इन इंडिया की बारह-वर्षीय प्रगति समीक्षा शामिल थी (25 सितंबर 2014 को शुरू, जिसका अर्थ है कि यह समीक्षा इसकी 12वीं वर्षगांठ के साथ लगभग ठीक मेल खाती है), जिसमें बताया गया कि इस अवधि में विनिर्माण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) योगदान वास्तव में 2022 के लिए जीडीपी के 25% के मूल लक्ष्य के बावजूद लगभग 17% पर स्थिर बना हुआ है, साथ ही राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की व्याख्या (2021 में शुरू, 2026 तक 30 से अधिक केंद्रीय विभागों और 26 राज्यों के लिए निवेश अनुमोदन एकीकृत करती है), डीडीयू-जीकेवाई 2.0 कार्यान्वयन का और विवरण, तथा वेक्स ओटीटी और इंडिया सिने हब जैसे नए मंचों को शामिल किया गया। इन दस्तावेजों का वास्तविक मूल्य किसी नीति की मुख्य घोषणा और उसके कार्यान्वयन तथा मापने योग्य प्रगति की पूर्ण वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने में है, जो यह समझने के लिए उपयोगी है कि कोई योजना केवल मौजूद है या नहीं बल्कि उसने वास्तव में क्या हासिल किया है। एक पूर्ण और आलोचनात्मक समझ के लिए यह पहचानना जरूरी है कि चूंकि ये दस्तावेज उन्हीं सरकार द्वारा लिखे जाते हैं जो इन

योजनाओं को लागू करती है, वे स्वाभाविक रूप से उपलब्धियों पर जोर देते हैं, जैसे एकल खिड़की प्रणाली के एकीकरण आंकड़े, बजाय मेक इन इंडिया के छूटे हुए विनिर्माण-जीडीपी लक्ष्य जैसी कमियों पर, इसलिए बैकग्राउंड को स्वतंत्र विश्लेषण के साथ पढ़ना सबसे अच्छा है।

मुख्य शब्द:

शब्द	परिभाषा
मेक इन इंडिया	25 सितंबर 2014 को शुरू; 2022 तक जीडीपी के 25% तक विनिर्माण पहुंचाने का मूल लक्ष्य; वास्तविक विनिर्माण जीवीए हिस्सा लगभग 17% पर स्थिर रहा।
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली	2021 में शुरू; 2026 तक 30+ केंद्रीय विभागों और 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निवेश अनुमोदन मंजूरी एकीकृत करती है।
पीआईबी बैकग्राउंडर	नियमित प्रेस विज्ञप्तियों से परे संदर्भ प्रदान करने वाला विस्तृत व्याख्यात्मक दस्तावेज़; सप्ताह 39 की प्रमुख योजनाओं को कवर करने वाले 11 ऐसे दस्तावेज़ जारी।
सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)	किसी क्षेत्र के आर्थिक योगदान का माप (उत्पादन घटा इनपुट लागत); मेक इन इंडिया की सफलता आंकने के लिए प्रमुख मापदंड।
पीएलआई योजनाएं (क्रॉस-सेक्टरल)	उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन योजनाएं अब 14 क्षेत्रों (इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, वस्त्र आदि) में फैली हैं, मेक इन इंडिया के विनिर्माण प्रयास की मुख्य पूरक नीति।
इन्वेस्ट इंडिया	राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी, एकल खिड़की प्रणाली के साथ मिलकर भारत में घरेलू व विदेशी निवेश को सुगम बनाने का कार्य करती है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

- GS2 शासन: मेक इन इंडिया (2014) लक्ष्य बनाम वास्तविक परिणाम अंतर; एकल खिड़की प्रणाली (2021)।
- GS3 अर्थव्यवस्था: विनिर्माण जीवीए हिस्सा (~17%, लक्ष्य 2022 तक 25% था)।
- प्रारंभिक परीक्षा: मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014; एकल खिड़की प्रणाली (2021) 30+ विभाग, 26 राज्य कवर करती है।

अभ्यास प्रश्न

20 प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न (उत्तर देखे बिना हल करें)

प्रश्न 1. हाल की रोजगार एवं कौशल विकास पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रोजगार मेले के 20वें संस्करण में समूह 'ग' और 'घ' सरकारी पदों के लिए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
2. डीडीयू-जीकेवाई 2.0 का लक्ष्य अक्टूबर 2026 से 70,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना है।
3. दोनों पहलें विशेष रूप से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) तीनों
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 2. एफएसएसआई के पनीर संशोधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अनिवार्य करता है कि केवल गाय या भैंस के दूध से बने उत्पाद ही 'पनीर' लेबल किए जा सकें।
2. एफएसएसआई उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
3. यह संशोधन मुख्यतः गलत ब्रांडिंग और खाद्य मिलावट को रोकने के उद्देश्य से है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) 1 और 3 केवल
- (b) 2 और 3 केवल
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

1. एक सींग वाला गैंडा – काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में मूल आवास
2. विश्व राइनो दिवस – 22 सितंबर को मनाया जाता है
3. सीआईटीईएस – दक्षिण एशियाई देशों तक सीमित एक क्षेत्रीय संधि

उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो

- (c) तीनों
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 4. स्लिनेक्स-26 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) यह भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कोच्चि में संपन्न हुआ
- (b) यह भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ
- (c) यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित एक बहुपक्षीय क्वाड नौसैनिक अभ्यास है
- (d) यह भारतीय वायु सेना और श्रीलंका वायु सेना के बीच एक वायु रक्षा अभ्यास है

प्रश्न 5. स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कवच 4.0 पहली बार दक्षिण मध्य रेलवे के लखनऊ मंडल पर लागू किया गया।
2. कवच बिना चालक के हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर टक्कर रोकता है।
3. कवच को पूरी तरह एक विदेशी तकनीकी साझेदार द्वारा विकसित किया गया और बाद में भारतीय रेलवे को लाइसेंस दिया गया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 2 और 3 केवल
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 6. ओपेक-भारत ऊर्जा वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत और ओपेक के बीच सातवीं उच्च-स्तरीय वार्ता थी।
2. ओपेक सामूहिक रूप से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 30% नियंत्रित करता है।
3. भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 80% आयात करता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) तीनों
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 7. हाल की उच्च न्यायालय न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. राष्ट्रपति ने दिल्ली, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 नए न्यायाधीश नियुक्त किए।

2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. उच्च न्यायालयों का संवैधानिक मामलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए आरक्षित है।

सही उत्तर चुनें:

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 1 और 3 केवल
- (c) 2 और 3 केवल
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 8. अग्निकुल कॉसमॉस की अग्निबाण प्रक्षेपण यान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से 200 करोड़ रुपये का अनुदान मिला।
2. अग्निबाण को पूरी तरह पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
3. अग्निकुल कॉसमॉस पूर्णतः इसरो के अधीन एक सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) तीनों
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 9. आरोग्य मंथन 2026 के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसने आयुष्मान भारत पीएम-जय के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष चिह्नित किए।
2. पीएम-जय प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक अस्पताल में भर्ती कवरेज प्रदान करता है।
3. एबीडीएम अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाता है जो विभिन्न प्रदाताओं में इंटरऑपरेबल चिकित्सा रिकॉर्ड सक्षम करता है।

सही उत्तर चुनें:

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 2 और 3 केवल
- (c) 1 और 3 केवल
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 10. सितंबर 2026 में आयोजित ब्रिक्स कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक मुख्यतः निम्नलिखित में से किसे संबोधित करती है?

- (a) ब्रिक्स नौसैनिक बलों के बीच समन्वित सैन्य अभ्यास
- (b) कर प्रवर्तन में समन्वय और सीमा-पार कर चोरी की रोकथाम
- (c) व्यापार निपटान में अमेरिकी डॉलर को प्रतिस्थापित करने के लिए एकीकृत ब्रिक्स मुद्रा
- (d) ब्रिक्स सदस्य देशों में कृषि सब्सिडी का सामंजस्य

प्रश्न 11. भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. यह 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ।
- 2. यह वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को कवर करता है लेकिन निवेश प्रावधानों को बाहर रखता है।
- 3. न्यूजीलैंड विश्व के अग्रणी डेयरी निर्यातकों में से एक है, जिससे डेयरी भारत के लिए एक संवेदनशील वार्ता क्षेत्र बनता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) 1 और 3 केवल
- (b) केवल 1
- (c) 2 और 3 केवल
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 12. आईएमईआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- 1. आईएमईआई मोबाइल उपकरणों के लिए 15-अंकीय विशिष्ट पहचानकर्ता है।
- 2. किसी फोन का आईएमईआई *#06# कोड का उपयोग करके जांचा जा सकता है।
- 3. किसी उपकरण के आईएमईआई से छेड़छाड़ करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

सही उत्तर चुनें:

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 2 और 3 केवल
- (c) 1 और 3 केवल
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 13. डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है?

- (a) गृह मंत्रालय
- (b) वित्त मंत्रालय
- (c) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- (d) विदेश मंत्रालय

प्रश्न 14. राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. इसका उद्देश्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-प्रमुख भूमि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना है।

2. इसने चार वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

3. एनएलएमसी के ढांचे के तहत आरआईएनएल की भूमि बिक्री ई-नीलामी के बजाय बंद-दरवाजे की बातचीत के माध्यम से की गई थी।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) तीनों
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 15. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. इसे पर्यावरणीय मामलों के त्वरित निपटान हेतु एक विशेष निकाय के रूप में 2010 में स्थापित किया गया।
- 2. इसने हाल ही में पर्यावरणीय शिकायतों की डिजिटल फाइलिंग सक्षम करने वाला एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।
- 3. एनजीटी के आदेशों को केवल संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 2 और 3 केवल
- (c) 1 और 3 केवल
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 16. 'सेको इंडिया 2026' निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है?

- (a) सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
- (b) अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी
- (c) वस्त्र उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन
- (d) तटीय संरक्षण और समुद्री जैव विविधता

प्रश्न 17. हाल ही में आयोजित 'नोमैडिक एलिफेंट' अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है?

- (a) कजाकिस्तान
- (b) मंगोलिया
- (c) उज्बेकिस्तान
- (d) किर्गिस्तान

प्रश्न 18. 'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक तटीय सफाई और महासागर संरक्षण अभियान है।
2. इसके हालिया संस्करण ने 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 231 स्थानों पर लगभग 15 लाख प्रतिभागियों को जुटाया।
3. यह विशेष रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) तीनों
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 19. उपासी (दक्षिण भारतीय बागान मालिक संघ), जिसने हाल ही में अपनी शताब्दी मनाई, मुख्यतः किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है?

- (a) केवल कर्नाटक में कॉफी बागान
- (b) दक्षिण भारत में चाय बागान
- (c) केवल केरल में रबर की खेती
- (d) तमिलनाडु से मसाला निर्यात

प्रश्न 20. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह हानिकारक बाजार एकाग्रता को रोकने हेतु विलय और अधिग्रहणों की समीक्षा करता है।
2. यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
3. आकार या बाजार प्रभाव की परवाह किए बिना, प्रत्येक कॉर्पोरेट लेनदेन के लिए सीसीआई की मंजूरी आवश्यक है।

सही उत्तर चुनें:

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 2 और 3 केवल
- (c) 1 और 3 केवल
- (d) 1, 2 और 3

4 मुख्य परीक्षा प्रश्न (उत्तर देखे बिना हल करें)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: 150 शब्द

'भारत की हालिया नीतिगत घोषणाएं – रोजगार मेला और डीडीयू-जीकेवाई 2.0 से लेकर स्वदेशी रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहलों तक – रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की दोहरी रणनीति को दर्शाती हैं। इस सप्ताह के घटनाक्रमों के संदर्भ में इस कथन की समालोचनात्मक जांच करें।' (150 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: 250 शब्द

'एफएसएसएआई के पनीर विनियमन और एनजीटी के डिजिटल पहुंच सुधार से लेकर न्यायिक नियुक्तियों और प्रशासनिक विशेष अभियान 6.0 तक, इस सप्ताह की शासन घोषणाएं एक समान सूत्र प्रकट करती हैं: नियामक स्पष्टता, पहुंच और जवाबदेही के माध्यम से संस्थागत विश्वास को मजबूत करना। उपयुक्त उदाहरणों सहित इस प्रवृत्ति का विश्लेषण करें।' (250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 3: 150 शब्द

'भारत-न्यूजीलैंड एफटीए, ओपेक-भारत ऊर्जा वार्ता, और स्लिनेक्स तथा नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यासों तक फैला इस सप्ताह का भारतीय जुड़ाव, बाहरी जुड़ाव के प्रति एक कैलिब्रेटेड, बहु-ट्रैक दृष्टिकोण को दर्शाता है। चर्चा करें।' (150 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 4: 250 शब्द

'एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 जैसी संरक्षण पहलें सहभागी, समुदाय-आधारित पर्यावरणीय शासन की ओर भारत के बदलाव को प्रदर्शित करती हैं। इस बदलाव की समालोचनात्मक समीक्षा करें, इसकी शक्तियों और सीमाओं दोनों को उजागर करते हुए।' (250 शब्द)

प्रारंभिक परीक्षा उत्तर एवं व्याख्या

प्रश्न 1. उत्तर: (b) केवल दो

व्याख्या: कथन 1 (51,000+ नियुक्ति पत्र, समूह ग व घ) और कथन 2 (डीडीयू-जीकेवाई 2.0, अक्टूबर 2026 से 70,000 युवा) सही हैं। कथन 3 गलत है – रोजगार मेला पीएमओ व श्रम मंत्रालय द्वारा समन्वित होता है, केवल एमएसडीई द्वारा नहीं, जो केवल डीडीयू-जीकेवाई लागू करता है।

प्रश्न 2. उत्तर: (a) 1 और 3 केवल

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं – संशोधन पनीर लेबल को दूध-आधारित उत्पादों तक सीमित करता है और गलत ब्रांडिंग/मिलावट को लक्षित करता है। कथन 2 गलत है – एफएसएसएआई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, न कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय के।

प्रश्न 3. उत्तर: (b) केवल दो

व्याख्या: युग्म 1 (काजीरंगा आवास) और 2 (विश्व राइनो दिवस, 22 सितंबर) सही सुमेलित हैं। युग्म 3 गलत है – सीआईटीईएस एक वैश्विक संधि है, न कि दक्षिण एशिया तक सीमित क्षेत्रीय संधि; इसके हस्ताक्षरकर्ता विश्व भर में हैं।

प्रश्न 4. उत्तर: (b)

व्याख्या: स्लिनेक्स-26 भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है; 2026 संस्करण विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ, न कि कोच्चि में। यह द्विपक्षीय है, बहुपक्षीय क्वाड अभ्यास नहीं, और नौसैनिक (वायु रक्षा नहीं) अभ्यास है।

प्रश्न 5. उत्तर: (a) 1 और 2 केवल

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं – कवच 4.0 का पहला कार्यान्वयन दक्षिण मध्य रेलवे के लखनऊ मंडल पर हुआ, और यह बिना चालक हस्तक्षेप के स्वचालित ब्रेकिंग करता है। कथन 3 गलत है – कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, विदेशी साझेदार से लाइसेंस प्राप्त नहीं।

प्रश्न 6. उत्तर: (c) तीनों

व्याख्या: सभी तीन कथन सही हैं। यह वार्ता 7वीं ऐसी उच्च-स्तरीय वार्ता थी; ओपेक लगभग 30% वैश्विक तेल आपूर्ति नियंत्रित करता है; और भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 80% आयात करता है, जिससे यह वार्ता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनती है।

प्रश्न 7. उत्तर: (a) 1 और 2 केवल

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं – नामित उच्च न्यायालयों में 14 न्यायाधीश नियुक्त हुए, कॉलेजियम-सिफारिश प्रक्रिया के बाद। कथन 3 गलत है – उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार सहित संवैधानिक मामलों पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के साथ समवर्ती रूप से।

LESS NOISE. MORE RETENTION.

प्रश्न 8. उत्तर: (b) केवल दो

व्याख्या: कथन 1 (200 करोड़ रुपये टीडीबी अनुदान) और 2 (पूर्णतः पुनः प्रयोज्य अग्निबाण) सही हैं। कथन 3 गलत है – अग्निकुल कॉसमॉस एक निजी अंतरिक्ष स्टार्ट-अप है, इसरो के अधीन सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम नहीं; इसे सरकारी वित्त पोषण सहायता मिली लेकिन यह स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।

प्रश्न 9. उत्तर: (d) 1, 2 और 3

व्याख्या: सभी तीन कथन सही हैं। आरोग्य मंथन 2026 ने पीएम-जय के 8 वर्ष (50+ करोड़ कवरेज) और एबीडीएम के 5 वर्ष (डिजिटल स्वास्थ्य) की समीक्षा की; पीएम-जय 5 लाख रुपये वार्षिक अस्पताल कवरेज देता है; और एबीडीएम की एबीएचए आईडी प्रदाताओं में रिकॉर्ड इंटरऑपरेबिलिटी सक्षम करती है।

प्रश्न 10. उत्तर: (b)

व्याख्या: बैठक, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री सीतारमण ने किया, मुख्यतः बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सीमा-पार कर चोरी को रोकने और कर प्रवर्तन के समन्वय पर केंद्रित थी – सैन्य, मुद्रा या कृषि मामलों पर नहीं।

प्रश्न 11. उत्तर: (a) 1 और 3 केवल

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं – एफटीए 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ, और न्यूजीलैंड की कुशल डेयरी क्षेत्र भारत के लिए संवेदनशील है। कथन 2 गलत है – यह एफटीए व्यापक है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और निवेश तीनों शामिल हैं, निवेश को बाहर नहीं रखा गया।

प्रश्न 12. उत्तर: (d) 1, 2 और 3

व्याख्या: सभी तीन कथन सही हैं। आईएमईआई वास्तव में 15-अंकीय पहचानकर्ता है, *#06# से जांचा जाता है, और डीओटी के जागरूकता अभियान में उजागर किए अनुसार, इससे छेड़छाड़ आईटी अधिनियम के तहत दंडनीय है।

प्रश्न 13. उत्तर: (b)

व्याख्या: डीआरआई वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के तहत कार्य करता है, न कि गृह, वाणिज्य या विदेश मंत्रालय के अंतर्गत।

प्रश्न 14. उत्तर: (b) केवल दो

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है – एनएलएमसी के ढांचे के तहत आरआईएनएल की भूमि बिक्री पारदर्शी ई-नीलामी के माध्यम से की गई थी, बंद-दरवाजे की बातचीत से नहीं – यह ठीक एनएलएमसी की शासन सुरक्षा है।

प्रश्न 15. उत्तर: (a) 1 और 2 केवल

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है – एनजीटी के आदेशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, केवल राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं।

प्रश्न 16. उत्तर: (a)

व्याख्या: सेको इंडिया 2026 भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम से जुड़ा है, अंतरिक्ष, वस्त्र या तटीय संरक्षण से नहीं।

प्रश्न 17. उत्तर: (b)

व्याख्या: अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान से नहीं है।

प्रश्न 18. उत्तर: (b) केवल दो

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है – ऐसे अभियान आमतौर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) सहित कई मंत्रालयों/एजेंसियों को शामिल करते हैं, अकेले पर्यावरण मंत्रालय को नहीं।

प्रश्न 19. उत्तर: (b)

व्याख्या: उपासी मुख्यतः तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में दक्षिण भारतीय चाय बागानों का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि इसका कॉफी व रबर से भी संबंध है; इसका चाय अनुसंधान फाउंडेशन इसका प्रमाण है।

प्रश्न 20. उत्तर: (a) 1 और 2 केवल

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है – सीसीआई की मंजूरी (अनिवार्य अधिसूचना) केवल निर्दिष्ट परिसंपत्ति/टर्नओवर सीमा से अधिक के लेनदेन के लिए आवश्यक है, प्रत्येक लेनदेन के लिए नहीं।

मुख्य परीक्षा आदर्श उत्तर

SITOK IAS
LESS NOISE. MORE RETENTION.

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 – आदर्श उत्तर (150 शब्द):

इस सप्ताह की घोषणाएं रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की एक समन्वित रणनीति को उजागर करती हैं। रोजगार मेले की 51,000+ प्रत्यक्ष सरकारी नियुक्तियां और डीडीयू-जीकेवाई 2.0 का 70,000 ग्रामीण युवाओं को लक्षित करना, बेरोजगारी को तत्काल सार्वजनिक-क्षेत्र अवशोषण और बाजार-उन्मुख कौशल विकास दोनों के माध्यम से संबोधित करता है। साथ ही, स्वदेशी रक्षा विनिर्माण (सैटेलाइट स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड हथियार, डीआरडीओ के जरिए क्वांटम कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा) और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (अग्निकुल कॉसमॉस का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान) आयात निर्भरता घटाते हुए उभरते तकनीकी क्षेत्रों में उच्च-कौशल घरेलू रोजगार सृजित करते हैं। हालांकि, यह दोहरी रणनीति असमान पैमाने दिखाती है:

रोजगार योजनाएं दसियों हजार की संख्या को संबोधित करती हैं, जबकि प्रौद्योगिकी पहले विशिष्ट, छोटे-पैमाने के इकोसिस्टम तक सीमित रहती हैं। दोनों ट्रैक पूरक हैं लेकिन अभी एकीकृत नहीं – कौशल कार्यक्रम वर्तमान में सीधे स्वदेशी उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण की कार्यबल आवश्यकताओं में नहीं जुड़ते, जो सामूहिक रोजगार सृजन और रणनीतिक आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के बीच एक अंतर दर्शाता है जिसके लिए घनिष्ठ नीतिगत अभिसरण आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 – आदर्श उत्तर (250 शब्द):

इस सप्ताह की शासन घोषणाएं एक सुसंगत विषय पर एकत्रित होती हैं: सरकारी कार्यों का विस्तार करने के बजाय नियामक स्पष्टता, पहुंच और जवाबदेही के माध्यम से संस्थागत विश्वास को मजबूत करना। नियामक स्पष्टता: एफएसएसआई का पनीर संशोधन इसका उदाहरण है – इस शब्द को दूध-आधारित उत्पादों तक कानूनी रूप से सीमित करके, यह मिलावटकर्ताओं द्वारा शोषित लेबलिंग खामी को बंद करता है, उपभोक्ता स्वास्थ्य और वैध उत्पादकों दोनों की रक्षा करता है। यह नया विनियमन नहीं बल्कि मौजूदा खाद्य सुरक्षा इरादे का स्पष्टीकरण है, जो अतिरिक्त नौकरशाही बोझ के बिना प्रवर्तनीयता को मजबूत करता है। पहुंच: राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मोबाइल एप्लिकेशन उन नागरिकों तक पर्यावरणीय न्याय पहुंच का विस्तार करता है जो पहले भौगोलिक और प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना करते थे। यह डिजिटल पहुंच पहल कानूनी उपचार तलाशने की लेनदेन लागत को कम करती है, विशेष रूप से उन नागरिकों को लाभान्वित करती है जो उन महानगरीय क्षेत्रों से बाहर हैं जहां अधिकरण बेंच केंद्रित हैं। जवाबदेही: 14 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे भारत के लगातार मामले लंबितता संकट को संबोधित करती है, समय पर न्याय देने की न्यायपालिका की क्षमता को मजबूत करती है – एक मूलभूत जवाबदेही तंत्र। इसी तरह, विशेष अभियान 6.0 का प्रशासनिक मामला लंबितता कम करने और कार्यस्थल दक्षता में सुधार पर ध्यान सरकार के भीतर से नौकरशाही जवाबदेही को लक्षित करता है। सामान्य सूत्र: प्रत्येक पहल एक विशिष्ट विश्वास घाटे को संबोधित करती है – भोजन की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले उपभोक्ता, पर्यावरणीय निवारण में बाधाओं का सामना करने वाले नागरिक, विलंबित न्याय की प्रतीक्षा करने वाले वादी, और प्रशासनिक देरी का अनुभव करने वाले नागरिक। नई योजनाओं के माध्यम से राज्य क्षमता का विस्तार करने के बजाय, ये उपाय मौजूदा प्रणालियों में विशिष्ट घर्षण बिंदुओं को ठीक करते हैं। सीमा: ऐसे उपाय कार्यान्वयन गुणवत्ता पर अत्यधिक निर्भर करते हैं – प्रवर्तन क्षमता के बिना नियामक स्पष्टता, या अंतर्निहित मामला बैकलॉग को संबोधित किए बिना डिजिटल पहुंच, सीमित वास्तविक सुधार देती है। संस्थागत विश्वास निर्माण के लिए घोषणा चरण से परे निरंतर अनुसरण की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से नीति इरादे और जमीनी स्तर के निष्पादन के बीच भारत के ऐतिहासिक अंतर को देखते हुए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 3 – आदर्श उत्तर (150 शब्द):

इस सप्ताह के बाहरी जुड़ाव अलग-अलग उद्देश्यों के लिए भारत द्वारा अलग-अलग उपकरणों के उपयोग को दर्शाते हैं – एक कैलिब्रेटेड, बहु-ट्रैक विदेश नीति। भारत-न्यूजीलैंड एफटीए इंडो-पैसिफिक में आर्थिक विविधीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए बाजार पहुंच सुरक्षित करता है। ओपेक-भारत ऊर्जा वार्ता सैन्य या आर्थिक जबरदस्ती के बजाय कूटनीतिक जुड़ाव के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को संबोधित करती है, जो भारत की 80% आयात निर्भरता को देखते हुए स्थिर तेल मूल्य निर्धारण पर निर्भरता दर्शाती है। सैन्य अभ्यास – श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स और मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट – विश्वास-निर्माण और क्षमता-निर्माण कार्य करते हैं, जो क्रमशः भारत की पड़ोसी-पहले नीति और मध्य एशिया में विस्तारित रणनीतिक पहुंच को मजबूत करते हैं, बिना बड़ी शक्तियों के साथ प्रत्यक्ष टकराव को उकसाए। साथ मिलकर, ये ट्रैक – व्यापार, ऊर्जा कूटनीति, और रक्षा सहयोग – स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं लेकिन संचयी रूप से भारत को आर्थिक और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में एक विश्वसनीय, गैर-जबरदस्त साझेदार के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 4 – आदर्श उत्तर (250 शब्द):

भारत का संरक्षण दृष्टिकोण विशुद्ध प्रवर्तन-संचालित मॉडलों से सहभागी, समुदाय-आधारित शासन की ओर स्पष्ट रूप से स्थानांतरित हुआ है, जैसा एक सींग वाले गैंडे की रिकवरी और स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान से प्रमाणित होता है। शक्तियां: लगभग विलुप्ति से 3,700 से अधिक व्यक्तियों तक गैंडे की रिकवरी काफी हद तक स्थानीय समुदायों को काजीरंगा के निकट संभावित शिकारियों से इको-टूरिज्म राजस्व साझाकरण के माध्यम से संरक्षण हितधारकों में बदलने से उपजी – आर्थिक प्रोत्साहन को संरक्षण परिणाम के साथ जोड़ना। इसी तरह, 231 तटीय स्थानों पर 15 लाख नागरिकों की स्वच्छ सागर की गतिशीलता दर्शाती है कि कैसे सामूहिक भागीदारी तत्काल सफाई प्रभाव और व्यापक जन जागरूकता दोनों उत्पन्न कर सकती है, नागरिकों को निष्क्रिय लाभार्थियों से सक्रिय हितधारकों में बदलती है। यह सहभागी मॉडल व्यापक जन समर्थन निर्मित करके मजबूत पर्यावरणीय विनियमन के लिए राजनीतिक वैधता भी उत्पन्न करता है। सीमाएं: सहभागी दृष्टिकोणों में अंतर्निहित सीमाएं हैं। समुदाय-आधारित गैंडा संरक्षण आंशिक रूप से भौगोलिक रूप से केंद्रित आवास (काजीरंगा) के कारण सफल रहा, जो बाघों जैसी फैली, खंडित सीमा वाली प्रजातियों के लिए दोहराना कठिन मॉडल है। सामूहिक सफाई अभियान मूल कारणों के बजाय लक्षणों (मौजूदा प्रदूषण) को संबोधित करते हैं – प्लास्टिक उत्पादन और औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन पर पूरक नियामक कार्रवाई के बिना, तटीय प्रदूषण नागरिक भागीदारी के बावजूद फिर से उभरेगा। इसके अलावा, सहभागी मॉडल निरंतर आर्थिक प्रोत्साहन संरेखण पर निर्भर करते हैं; यदि इको-टूरिज्म राजस्व घटता है या समुदाय लाभ-साझाकरण व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं, तो संरक्षण सहयोग उलट सकता है। निष्कर्ष: सहभागी संरक्षण प्रवर्तन और नियामक दृष्टिकोणों का एक मूल्यवान पूरक है, विकल्प नहीं। स्थायी पर्यावरणीय शासन के लिए सामुदायिक स्वामित्व को संरचनात्मक प्रदूषण और आवास खतरे के स्रोतों को संबोधित करने वाली निरंतर

नियामक कार्रवाई के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सहभागी सफलता को पूर्ण समस्या समाधान न समझा जाए।



SITOK IAS

LESS NOISE. MORE RETENTION.